राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या: 15

गुरुवार,

27 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

पुलिस थानों में स्वागत कक्ष हेतु बजट का आबंटन

219. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो अब तक कितने पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये गये व कितनों में कार्य प्रगति पर है तथा कितनों में बनना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के थानों में बनने वाले स्वागत कक्ष के लिये सरकार द्वारा बजट आबंटन किया गया है? यदि हां तो किस-किस जिले में कितना-कितना बजट आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। राज्य के 893 पुलिस थानों में से 869 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने हैं। इनमें से 95 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आहाहाहा। वाह, क्या बात है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या तकलीफ हो गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं तो तारीफ कर रहा हूं। तारीफ करते हैं तो तकलीफ होती है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो और क्या? जब आदमी को तकलीफ होती है, तभी तो कहता है आहाहाहा ...(व्यवधान) और किस बात के लिए कहता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दुबारा से बोल देता हूं।

(1) जी हां। राज्य के 893 पुलिस थानों में से 869 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने हैं। इनमें से 95 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जा चुके हैं। 317 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है जो क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है एवं 457 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाना शेष है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश के पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाने हेतु पत्र क्रमांक एफ.17(क)(7)गृह-2/2019 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा 63 पुलिस थानों के लिए 441 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया है, जिसका विवरण जिलेवार परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जब बजट में घोषणा की थी, तब इन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि हम जन सहयोग से भी स्वागत कक्ष बनाएंगे। ठीक है, जन सहयोग से भी आपने बनाये, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 869 थानों में आपको स्वागत कक्ष बनाने हैं। सात लाख रुपये के लगभग एक थाने के स्वागत कक्ष की कीमत है। अगर इन 869 थानों में सात लाख रुपये के हिसाब से देखें तो सरकार को 60 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करानी चाहिए थी और आपने सिर्फ 4 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी है। ठीक है, सरकार की जो भी मंशा है, वह करे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उन स्वागत कक्षों में फर्नीचर भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, लाइट भी है, पंखा भी है। और दूसरे जो खर्चे होंगे, क्या सरकार उनके लिए भी बजट उपलब्ध कराएगी या वह भी आप एसएचओ के ऊपर छोड़ेंगे कि वे उन लोगों का भी सहयोग लें, जिनसे वे लेना नहीं चाहते। कम से कम उन्हें नीचा देखकर उन लोगों से सहयोग न लेना पड़े, जिनसे वे लेना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सरकार उसके लिए पैसे उपलब्ध कराएगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब तक 398 स्वागत कक्षों में से 135 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के अंतर्गत, 91 जन सहभागिता के अंतर्गत, 66 स्टेट प्लान के अंतर्गत, 48 कारपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी के अंतर्गत, 17 पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत, 14 नगरपालिकाओं के अंतर्गत, 10 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत, 9 नगर विकास न्यास के अंतर्गत, 4 जिला कलेक्टर के अनटाइड फण्ड एवं 4 राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है, इसमें सबका सहयोग मांगा गया है। आम जनता भी सहयोग दे सकती है, भामाशाह भी सहयोग दे सकते हैं, एमएलए-एमपी वगैरह भी सहयोग दे सकते हैं। आपका जहां तक प्रश्न है, आपके विधान सभा क्षेत्र में 4 थानों के लिए आपने 32 लाख रुपये दिये हैं। यह बात सही है कि सात लाख रुपये में वह पूरी तरह कमप्लीट नहीं हो पाता। भवन तो बन जाता है, लेकिन फर्नीचर के लिए 58 हजार रुपये की अलग से आवश्यकता पड़ती है।

आपने 8 लाख रुपये प्रति थाना के हिसाब से 4 थानों- सामोद, कालाडेरा, गोविन्दगढ़ और चौमूं के लिए दिये। अब आपने चिट्ठी तो मांड दी कि मैं 32 लाख दे रहा हूं, लेकिन 2019-20 का पैसा तो आप पहले ही फूंक चुके हैं। अब 2020-21 का पैसा जब अप्रैल में मिलेगा, तब जाकर आप वह पैसा दे पाएंगे। उसके बावजूद भी आपकी चिट्ठी पर सरकार के द्वारा इतनी त्वरित कार्रवाई की गयी है कि आपने पैसा नहीं दिया, फिर भी काम चालू कर दिया गया है, चारों का काम चालू है।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बात इसमें कही है, सरकार द्वारा आबंटित किया गया बजट, इसमें आपने 4 करोड़ 41 लाख रुपये दिये। क्या कारण है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बून्दी, कोटा शहर, भिवाड़ी, जयपुर ग्रामीण, चूरू आदि को इसमें पैसा नहीं मिला? आपने यह अंतर किस आधार पर किया कि बाकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिलों को मिला और इन जिलों को बिलकुल भी नहीं मिला? इस अंतर का आधार क्या था?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अंतर का कोई आधार नहीं होता। कोई भी योजना हम अगर चालू करेंगे तो कोई टोटलिटी में वह योजना चालू नहीं होती। पहले कुछ पार्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद में दूसरे आर्थिक वर्ष में दूसरे पार्ट्स लिये जाते हैं, फिर तीसरे वर्ष में लिया जाता है। कुल मिलाकर राज्य सरकार की सोच यह है कि हर थाने में अगर जमीन उपलब्ध है तो थाने में ही बना दिया जाए या फिर कहीं न कहीं थाने की ही बिल्डिंग में से कोई न कोई एक स्वागत कक्ष बनाया जाए। सरकार की नीयत मोटे तौर पर यह है। ऐसा तो होता नहीं है कि 869 थानों का सारा का सारा पैसा एक साथ ही बजट में दे दिया जाए। क्या ऐसा कभी होता है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जो पूछ रहा हूं, वह यह है कि आपने 63 थानों का पैसा दिया। जिन जिलों के नाम मैंने ऊपर लिये हैं, उनके थानों को पैसा नहीं देने के पीछे क्या कारण था? इन जिलों को ही छोड़ा है। इन 63 थानों में ये जिले बिलकुल छूट गये हैं। ऐसा क्या कारण था कि इन जिलों में एक भी थाने को सरकार का यह पैसा नहीं मिला?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका सवाल सही है कटारिया साहब। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि ये तो वे हैं जिन थानों को 7-7 लाख रुपये प्रति थाना के हिसाब से दिये गये हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको दी है। तीस जिले हैं ये। अब आपने यह पूछा कि साहब, जैसलमेर को, कोटा शहर को क्यों नहीं दिया तो वहां पर हमारे पास भामाशाह तैयार हैं, जन सहयोग तैयार है और वहां के विधायक पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद कोटा शहर में दो जगह पैसा दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब समझ में नहीं आया। क्या हम ऐसा मान लें कि इन जिलों में सौ परसेंट भामाशाहों की सहमति मिलने के कारण नहीं दिया, यह समझ जाऊं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अंदाजन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, अंदाजा नहीं चलेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा मतलब यह है कि जैसे कोटा है। अब कोटा में पुलिस वालों ने मुझसे कान्टेक्ट किया, मैंने दो थानों को दे दिया। पुलिस वाले दूसरे विधायकों से भी कान्टेक्ट कर रहे हैं। वहां से दे दिया गया है तो उम्मीद यह की जाती है कि इन जिलों में किसी न किसी का सहयोग लेकर काम करवाया जाएगा।

प्रश्न संख्या 220

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. राजकुमार।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। सीनियर मैम्बर हैं। बैठें प्लीज। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा हेतु विशेष कार्ययोजना

221. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पुरातत्व महत्व के विश्वविख्यात कितने दुर्ग व किले विद्यमान हैं? सरकार द्वारा उक्त का संरक्षण किस माध्यम से किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पुरातात्विकता एवं इतिहास को सुरक्षित रखने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये एवं उक्त पर सरकार द्वारा कितना व्यय किस मद से किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विगत कुछ वर्षों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास एवं पुरातात्विक एवं कलात्मक कृतियों से छेड़छाड़ की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(4) क्या सरकार उक्त दुर्ग की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए कोई विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित दुर्ग किलों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। इसकी पुरातात्विकता एवं इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना अनुसार विगत 05 वर्ष में किये गये संरक्षण कार्य एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित फतेहप्रकाश महल, संग्रहालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित है। इस संग्रहालय में गत 05 वर्षों में हुए जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार एवं विकास कार्य का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**व्यय राशि (लाखों में)**
2015-16	---
2016-17	35.91
2017-18	316.75
2018-19	123.24
2019-20	13.82
कुल योग	**489.72**

(3) जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार को भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समय-समय पर बैठक की जाती है एवं पुलिस की सहायता ली जाती है। आवश्यक जगहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गये हैं। दुर्ग की सुरक्षा हेतु स्थायी पुरातत्वकर्मियों के अतिरिक्त 12 आर्म्ड एवं 24 अनआर्म्ड सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ किला विश्व विरासत धरोहर की सूची में है, वर्ल्ड हैरिटेज की सूची में भी है और यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और सुरक्षा के नाम पर वहां बिल्कुल ही कोई देखने वाला नहीं है और वहां आए दिन चोरियां भी होती हैं। इसलिए यह भी आपको जो सूचना मिली है ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): विगत काफी वर्षों से मंदिरों में चोरियां हुई हैं, मूर्तियों की चोरियां हुई हैं काफी चोरियां हुई हैं तो आने वाले दिनों में उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अपन कोई फंड जारी करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वह बहुत बड़ा किला है और नाम मात्र के 12 सिक्योरिटी गार्ड हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): तो आगे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में या सुरक्षा के बारे में अपन क्या सोचते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि ढाई वर्ष पहले तो आर्म्ड और अनआर्म्ड फोर्स वहां पर काम ही नहीं कर रही थी। वहां पर केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर के कर्मचारी काम करते थे। अब 12 आर्म्ड गार्ड हैं वो आठ-आठ घंटे की ड्यूटी पर काम करते हैं और 24 अनआर्म्ड गार्ड आठ-आठ घंटे की ड्यूटी पर काम करते हैं। कुल मिलाकर ये 36 व्यक्ति इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह किला आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है और उन्हीं के द्वारा इसकी व्यवस्था की हुई है। यदि आप कोई स्पेसिफिक शिकायत मुझे देंगे तो मैं ए.एस.आई. को लिखकर दूंगा कि इसकी व्यवस्था में और अभिवृद्धि की जाए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किले में पर्यटन की दृष्टि से वहां आने जाने का एक ही रास्ता है, उसके लिए अपन पूर्व दिशा में सूरजपोल की तरफ गेट या सरकार की तरफ से रोपवे की, ऐसी कोई उतरने-चढ़ने की ऐसी व्यवस्था हो जाए क्योंकि आए दिन जाम लगता है, काफी लाइनें लगती हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): तो आने वाले दिनों में उसमें एक और गेट खोलना या रोपवे लगाने की सरकार की क्या मंशा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रोपवे तो अलग से प्रश्न है और चूंकि यह ए.एस.आई. का मामला है तो इसमें उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बलवान पूनियां।

भादरा में सीवरेज के निर्माण में प्राप्त शिकायतों की जांच

222. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भादरा में सीवरेज का काम कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ है तथा उक्त बकाया कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य को पूर्ण करने की अवधि कितनी निर्धारित थी और अवधिपार होने पर सीवरेज निर्माण कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य में विलम्ब व कार्य में अनियमितता की कितनी जांचें हुईं? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगरपालिका भादरा क्षेत्र में सीवरेज पाइप लाइन डालने एवं दो एस.टी.पी. के निर्माण हेतु दिनांक 19.02.2016 को कार्यादेश जारी किया गया था। सीवरेज का कार्य 80 प्रतिशत व दोनों एस.टी.पी. का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, बकाया कार्य 31 मई, 2020 तक होना संभावित है।

(2) सीवरेज का कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 25.02.2016 एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 24.08.2017 थी। कार्य विलम्ब से एवं धीमी गति से किये जाने के कारण कम्पनी के विरुद्ध 40 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सीवरेज कार्यों की जांच MBM इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 की प्रति एवं राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड (रूडसिको), जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.09.2019 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आज तक कार्य अवधि कितनी बार बढ़ा दी गई है और लास्ट कार्य अवधि हम क्या समझें? प्रश्न एक।

(श्री बलवान पूनियां)

प्रश्न दो, आपने यह कहा है कि हमने जांच करवाई है और जांच की रिपोर्ट संलग्न है। अध्यक्ष जी, बिल्कुल जांच करवाई है और यह जांच का पोथा भी है पर इसके बिंदु संख्या दो और तीन बिलकुल असत्य हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): प्रश्न यही तो है। क्या असत्य जांच पर दोबारा जांच करवाई जाएगी? मेरे ये दो सवाल हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, निश्चित तौर पर इसकी कई बार कमप्लीशन की तारीखें बढ़ाई गई और अब आखिरी तारीख जो आई है, क्योंकि यह काम नगरपालिका के मार्फत हो रहा है, नगरपालिका ने जो आखिरी तारीख लिखकर दी है, वह 31 मई, 2020 दी है।

जहां तक जांच का सवाल है, मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि डिले क्यों हुआ। डिले हुआ क्योंकि चाहे वह दो एस.टी.पी. बनने थे, चाहे सीवर लाइन खोदनी थी, जैसा भी था लेकिन हर जगह जनता के द्वारा विरोध हुआ और विरोध होने के कारण नगरपालिकाओं को दूसरे स्थान पर जाकर यह करना पड़ा। एक बात।

दूसरी बात यह है कि 25 किलोमीटर की सीवर लाइन राविल के द्वारा आज के आठ-दस साल पहले डाल दी गई थी, अब उस लाइन को इस नई लाइन से जोड़ना था, इस जोड़ने के चक्कर में कम से कम दो-तीन साल बिगड़ गए, दो साल बिगड़ गये। एक बात।

तीसरी बात यह है कि महीपालों का मौहल्ला हो और चाहे दूसरा नथवाना जोहड़े का हो, वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर का हो, हर जगह है जहां पर भी काम होना था, चाहे एस.टी.पी. का काम होना था चाहे सीवरेज का काम होना था, जनता का विरोध बराबर रहा और जनता के विरोध के बाद में सारी की सारी साइडें बदली गई, तो उसमें आखिर टाइम तो लगेगा। एक बात।

दूसरी बात, आपने जो पूछा कि, साहब, और जांच करवाई जाएगी? अब जांच करवाने का तो कोई मकसद नहीं है, दो-दो जगह से जांच हो गई। इंजीनियरिंग कालेज के बड़े-बड़े प्रोफेसर्स ने जांच कर ली और यहां के सारे इंजीनियर्स ने जांच कर ली और जांच के बाद में उस पर 40 लाख रुपये की शास्ति जोड़ी गई। 40 लाख रुपये की क्षति के अलावा भी उसके 72 लाख

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रुपये की जो अंतरिम शास्ति थी, वो और रोक करके रखी गई है कि कमप्लीशन होगा, अच्छा काम होगा तभी जाकर वो 72 लाख रुपये जारी किये जाएंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, एक तो विरोध एक जगह हुआ। सही कह रहे हैं एक जगह हुआ। एक एसटी.पी. पर विरोध हुआ और वह जगह 2016 में ही बदल दी गई।

नंबर दो बात, जांच की बात है। बिंदु संख्या दो में साकेट, मोड़, जोड़ सारे हैं। उसकी जांच उन्होंने सही बताई जबकि जो-जो पाइंट हमने बताए, उन पाइंटों पर वह जांच करने नहीं गये।

नंबर तीन, बिंदु संख्या तीन यह कह रहा है कि जो सीवरेज के बाद में सड़कें बनाई, वो बढ़िया क्वालिटी की नहीं थी, बदलेवल थी। इन्होंने उत्तर में यह कहा कि नहीं जी, हमने तो कोई सड़क बनाई नहीं, कोई नियम ही नहीं है जबकि मेरे पास जो कागज है, वह यह कह रहा है कि विश्वकर्मा चौक से वीडीएस पैलेस तक, समाज भवन से राजगढ़ रोड तक, कायमखानी बास से राम तलाई तक, मंगतु खां की दुकान से फलाने तक ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां, प्रश्न ही है। यह सात सड़कें सीवरेज के बाद बनाई तो फिर यह उत्तर मैं सही कैसे मानूं? इसलिए मेरा यह कहना है कि एक तो उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई, वह सही नहीं की गई। उसको इन्होंने जांच में सही ठहराया है। नंबर दो, सदन को यह गुमराह किया गया है ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह गुमराह किया गया है कि उन्होंने सड़कें बनाई नहीं, इसलिए मेरा दोबारा जांच का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: क्या दोबारा जांच करायेंगे? उनका सीधा प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है दोबारा जांच करवाने की।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अशोक लाहोटी।

देवस्थानों के मंदिरों की दुकानों एवं व्यावसायिक परिसरों से प्राप्त आय

223. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मंदिरों के अधीन दुकानों व आवासीय व व्यावसायिक परिसर किराये पर दिये हुए हैं? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में उक्त सम्पत्तियों से कितनी आमदनी प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मंदिरों की सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जेधारी काबिज हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौनसे देवस्थान के व्यावसायिक व आवासीय परिसरों पर किन-किन व्यक्तियों व संस्थाओं का कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमियों के कब्जे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त कब्जेधारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितनी राशि किरायेदारों पर बकाया है? उक्त बकाया राशि को वसूल किये जाने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बिंदु पर प्रश्न किया है ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर।

देवस्थान मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी हां। प्रदेश के देवस्थान मंदिरों के अधीन दुकानों, आवासीय व व्यावसायिक परिसर किराये पर दिये हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3,95,76,216/- (तीन करोड़ पिच्यानवे लाख छिहत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र) रुपये एवं वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.01.2020 तक 3,95,98,980/- (तीन करोड़ पिच्यानवे लाख अट्ठानवे हजार नौ सौ अस्सी मात्र) रुपये की आय हुई।

(2) जी हां। यह सही है कि देवस्थान विभाग के मंदिरों की व्यावसायिक व आवासीय सम्पतियों पर अनधिकृत कब्जेदार काबिज हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) उक्त अतिक्रमियों से कब्जे छुड़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8,54,25,221/- (आठ करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार दो सौ इक्कीस मात्र) रुपये व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.01.2020 तक 9,64,02,319/- (नौ करोड़ चौसठ लाख दो हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) रुपये किरायेदारों पर बकाया है। उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं तथा शीघ्र वसूली हेतु समय-समय पर सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता रहा है एवं पुन: समस्त सहायक आयुक्तगण को पत्र क्रमांक 192-202 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं, जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब भेजा है, उसका खण्ड-1 और खण्ड-4, इनमें इन्होंने लिखा है कि किराया आता है 3 करोड़ 95 लाख और 9 करोड़ 64 लाख किराया बकाया है। अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपये की सम्पत्ति में, सैकड़ों मंदिरों में सालों तक भगवान की पोशाक नहीं बदली जाती, वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। इन्होंने जयपुर में मात्र 39 दुकानें बताई हैं कि ये किरायेदार हैं, भरतपुर में 51 हैं। मैं मंत्रीजी से पूछूंगा एक सवाल कि क्या इन किरायेदारों का लास्ट किराया किसी का 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये है? पीडब्ल्यूडी एफ.एण्ड आर. से किराया हर वर्ष 11 महीने बाद रिवाइज करने का नियम है। आपने अंतिम रिवाइज कब किया है? उस एफ. एण्ड आर. से और आगे इसका नया रिवीजन कब-कब करेंगे? नम्बर एक।

नम्बर दो, आपने एक जानकारी दी हैं कि किरायेदार हैं। दूसरा, आपने क्रम संख्या-4 पर लिखा है कि अतिक्रमियों और कब्जाधारियों और उसके मालिक का नाम बताया, अध्यक्ष जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी। ये आपने क्रम संख्या-4 पर दिया है। इनको बेदखल करने की कार्यवाही जारी है। मैं यह पूछूंगा कि इनको बेदखल कब तक किया जाएगा और सरकार की इनको बेदखल करने की इच्छा है क्या? इसमें आपने लिखा है कि ये किरायेदार काबिज हैं 28.06.2011 से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो प्रश्न। कितने प्रश्न पूछेंगे?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा है कि 28.06.2011 से किरायेदार हैं। क्या यह नीति सही है? वहां जिला कांग्रेस कमेटी किरायेदार 2011 से ही है या उससे पहले से काबिज है? ये तीन प्रश्न हैं मेरे।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बकाया किराये की वसूली हेतु निरीक्षक द्वारा एलआर एक्ट के तहत सम्पादित कार्यों के यहां प्रकरण दर्ज कराये जाते हैं। किराया वसूली समय पर करने हेतु प्रबंधक, निरीक्षक, देवस्थान विभाग को समय-समय पर निर्देशित किया जाता है। जिन किरायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध निरीक्षक द्वारा राजस्थान सार्वजनिक भू-अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम,1964 के अंतर्गत बेदखली हेतु नियम (4) के अंतर्गत वाद दायर कर कार्यवाही की जाती है। किराये राशि में वृद्धि के लिए किराया नीति दिनांक 06.06.2000 के अनुसार प्रति तीन वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत किराया वृद्धि की जाती है। लेकिन, मैं एक सूचना माननीय सदस्य को देना चाहूंगा कि हमारी जो 2002 की रेंटल पालिसी है, उस पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है और नई रेंटल पालिसी का, उसकी खामियों को दूर करते हुए, नई रेंटल पालिसी का कैबिनेट मीमो बन चुका है और शीघ्र ही लागू हो जाएगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कि क्रम संख्या-4 पर जो कब्जाधारी है, उनको कब तक हटाने की, आपने लिखा है कि जिला कांग्रेस कमेटी कब्जाधारी है। एक, उसको कब तक हटाने की मंशा है? दूसरा, मैंने पूछा, आपने जो यह लिखा है। यह जो किराया आपने बताया कि इसमें हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ये नई पालिसी कब आप एक्ट के माध्यम से लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): नई पालिसी का ड्राफ्ट तैयार है। कैबिनेट मीमो बन चुका है, पालिसी को जल्दी से जल्दी लागू करेंगे और जहां तक आप कह रहे हैं कि कार्यवाही क्या हो रही है, कार्यवाही जो हम लोग कर सकते हैं, अपने विभाग की ओर से पूरी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें 2011 से ही कब्जा लिखा है जबकि काबिज है 30 साल से।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बात समाप्त हो गई। आप समझना ही नहीं चाहते। मंत्री जवाब दें, आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, प्लीज बैठें आप, प्लीज।

अगला प्रश्न, निर्मल कुमावत। मैं कटारिया जी को अलाउ करना चाह रहा हूं, आप खुद खड़े हो रहे हैं। आप समझना ही नहीं चाहते हैं। मंत्री का उत्तर सुनना ही नहीं है, अपने को तो खाली प्रश्न पूछना है। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विभाग की कमजोरी के कारण से इसकी कोई पैरवी नहीं करता। 2003 से लेकर हमारे सारे पैंडिंग केस हैं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति केवल कोर्ट में जाकर लोगों ने अटका रखी है। क्या इसके लिए योग्य वकील करने का कोई प्रावधान रखेंगे? ताकि उसको निपटाकर, प्रोपर्टी पर किसी प्रकार से हमको अधिकार मिल सके। वे जो लगे हुए लोग हैं, वे पैरवी ठीक नहीं कर पाते हैं इसलिए, वर्षों गुजार देते हैं तो क्या विभाग यह सोचता है कि केस की ग्रेविटी और उसकी उपयोगिता को देखते हुए अच्छे वकीलों को इनवाल्व करके केस का निस्तारण हो जाए? इसकी कोई चिंता करेंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिलकुल सही सवाल उठाया है लेकिन मैं आपको यह भी सूचना देना चाहूंगा कि अभी जो आप कह रहे थे कि कब्जे और अच्छे वकील किये जाएं। हमने अच्छे वकील करके ही अभी हाल ही में जयपुर में आवासीय सम्पदा मंदिर श्री रामचन्द्र जी एवं व्यावसायिक सम्पदा मंदिर श्री गोपाल जी, पुरानी बस्ती, जयपुर का वर्ष 2019 में कब्जा प्राप्त किया, वापस जीतकर लाये। उषा रानी अग्रवाल की व्यावसायिक सम्पदा मंदिर श्री गोवर्धन जी, बड़ी चौपड़ का वर्ष 2018 में हमने कब्जा वापस लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी, जो कि दो सौ करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति है, बड़ी चौपड़ का 2020 में कब्जा वापस लिया है। अलवर की तीन एवं खेतड़ी की एक सम्पदा का कब्जा वापस लिया है। एक सम्पदा का कब्जा लिया गया है कोटा में, अजमेर में किशनगढ़ स्थित राजकीय मंदिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी की चार दुकानों का कब्जा लिया गया है। ऋषभदेव में मंदिर श्री ऋषभदेव जी की 10 सम्पदाओं का कब्जा वापस लिया गया है। उदयपुर में एक होटल देव दर्शन की एक सम्पदा का कब्जा लिया गया है।

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

निरंतर प्रयास जारी है, अच्छे से अच्छे वकील भी किये जा रहे हैं और इससे रिजल्ट भी मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, निर्मल कुमावत।

सांभर को जिला बनाने की कार्ययोजना

224. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये जिलों के गठन के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नये जिलों के गठन हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर जिले के सांभर को जिला बनाने हेतु सरकार को ज्ञापन, पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सांभर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी) (1) जी हां। प्राप्त ज्ञापन का परीक्षण कर राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नये जिले के गठन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाता है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्राप्त ज्ञापन का परीक्षण कर राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नये जिले के गठन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाता है। विवरण परिशिष्ट - ब पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के active consideration में नहीं है। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक

(राजस्व मंत्री)

आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नये जिले के गठन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाता है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 5(64) सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1160 दिनांक 15.10.2019 द्वारा लेख है कि दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् राज्य में जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक तीन सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह रोक आपने लगाई है। यह आपके जन घोषणा पत्र 2008 के चुनाव में क्यों नहीं आई और 2018 का जो चुनाव घोषणा पत्र है सरकार का, जो अब सरकारी दस्तावेज बन चुका है, सदन के नेता ने कहा, इसके पृष्ठ संख्या 36 पर आपने लिखा है कि प्रदेश में नये जिले, उपखण्डों व तहसीलों के गठन हेतु कार्ययोजना तो क्या कारण है कि ये आपने रोक लगाई है? आपका यह जो जन चुनाव घोषणा पत्र है, उसका क्या होगा? जनता के साथ यह छल था क्या?

नम्बर दो, क्या आप सांभर को जिला बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? हां या ना।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, ये पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आप आरोप लगा रहे हैं कि जनता के साथ छल कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पूरी जानकारी आपको इसके बारे में नहीं है। ये राजस्थान सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है। जब-जब जनगणना होती है, भारत सरकार द्वारा यह रोक लगाई जाती है इसलिए कोई छल करने वाली बात नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा लगाई गई रोक है और दस वर्ष के अंदर जनगणना होती है। सांभर के लिए आपने बोला है। जब तक यह रोक है, कोई भी राजस्व इकाई के गठन के बारे में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा जिसमें सांभर भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो हुई नहीं..

श्री अध्यक्ष: बात हो गई। नया प्रश्न किया है।

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में रिक्त पद

225. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) (श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) के स्थान पर): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जाएगी?

(2) जिला मंचों में कितने वाद लम्बित हैं एवं उनका समय के आधार पर वर्गीकरण क्या है? लम्बित वादों के निस्तारण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

(3) उदयपुर में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की परिपथ पीठ (सर्किट बैंच) किस दिनांक से सुनवाई नहीं कर रही है तथा सरकार द्वारा नियमित सुनवाई के लिए क्या प्रयास किए गए एवं अब कब तक सुनवाई प्रारम्भ करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राज्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में अध्यक्षों के 37 एवं सदस्यों के 74 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 05 अध्यक्षों एवं 01 सदस्य का पद रिक्त है, जिनके लिए विज्ञप्ति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में दिनांक 31.01.2020 तक 36587 प्रकरण लम्बित थे, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त लम्बित परिवादों को प्राथमिकता के आधार पर/प्री लिटिगेशन एवं लोक अदालत के माध्यम से (राजीनामा) व गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) जुलाई, 2018 से उदयपुर सर्किट बैंच में सुनवाई नहीं हो सकी है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिनांक 17.02.2020 को 03 न्यायिक एवं 04 गैर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। शीघ्र ही उदयपुर सर्किट बैंच में सुनवाई पुन: संभव हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगी, यह प्रश्न रखने के बाद 10 दिन पहले ही आपने नियुक्ति कर दी, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन जो आपने पहले प्रश्न के उत्तर वाले खंड में बताया है कि 5 अध्यक्षों एवं एक सदस्य का पद रिक्त है। 37 जिला मंचों में 37 अध्यक्ष होने चाहिए तो यह पांच अध्यक्ष के पद रिक्त हैं ये कौन-कौनसे जिलों में रिक्त हैं? पहला प्रश्न तो यह है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो जिला मंच हैं, उनमें अलवर का आंकड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिएगा, अलवर में 4225 और इसी तरह से अलवर से लेकर जयपुर के तीनों ही जिला बैंचों में, जोधपुर की दोनों जिला बैंचों में, भरतपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर और गंगानगर में भी एक हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं तो मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न है कि क्या इन जिलों में जिला मंचों की 2 अतिरिक्त बैंच आप स्थापित करने की मंशा रखते हैं?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए, ऑनलाइन शिकायत उपभोक्ता डाल सकें और उनकी विभाग ठीक प्रकार से मोनिटरिंग कर सकें, उसके लिए आप कोई व्यवस्था करना चाहते हैं क्या? ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पहला प्रश्न किया है कि 10 दिन पहले ही, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रियाधीन था। पहले कोर्ट में जाने की वजह से विज्ञप्ति सही प्रोसीजर में नहीं निकल पाई थी उसके बाद विज्ञप्ति आई, जैसे ही सिस्टम आया हमने 18 जिला मंच अध्यक्ष और 38 सदस्यों की नियुक्ति की है।

सैकंड आपका है कि 5 अध्यक्ष, जिसमें आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, नागौर और एक सदस्य चूरू का जो बाकी है, इनकी प्रक्रिया में हमने विज्ञप्ति जारी कर दी है। शेष गुणावगुण के आधार पर इनका चयन होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अलवर का आंकड़ा देखिये 4225...

श्री अध्यक्ष: देख लिया मैंने।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसका जवाब दे दूं, साहब जो ऑनलाइन सिस्टम का है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, उनका प्रश्न यह नहीं है। जिन जिलों में ज्यादा केस हैं वहां सैकंड बैंच बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यह प्रश्न है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, यही मेरा प्रश्न है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): साहब, इसमें 500 से कम केसेज हैं तो...

श्री अध्यक्ष: नहीं- नहीं, जिन जिलों में 1000 से ज्यादा केसेज हैं जो जिले बताएं हैं, आपके उत्तर में है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, 11 जिले हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्या, मैं आपकी ही मदद कर रहा हूं। जिन जिलों में आपने मेंशन किया है कि 1000 से ज्यादा केसेज हैं वहां के लिए माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं कि क्या वहां सैकंड बैंच आप बनाएंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिला मंच जहां बनाने की आवश्यकता सदस्या ने...

श्री अध्यक्ष: मेरा प्रश्न आप समझे या नहीं समझे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां-हां, वह आ गया समझ में। मैं कहना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: तो आप उस पर कर रहे हैं, हां या ना?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले अभी हमारे अध्यक्ष और जिला मंच के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्तियां समय पर नहीं हो पाईं इसलिए उनका निस्तारण नहीं हो पाया और इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है इसमें थोड़ा समय लगता है और हमें आवश्यकता हुई कि यहां पर संख्या पैंडिंग ज्यादा है तो वहां निश्चित रूप से..

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेंद्र राठौड़।

कम्प्यूटर शिक्षकों के रिक्त पद

226. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है तथा कुल कितने नियमित कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में कम्प्यूटर विषय के योग्यताधारी शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में कुल कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब संचालित नहीं हैं तथा कितने कम्प्यूटर शिक्षकों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 3464 माध्यमिक एवं 11137 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-09 व कक्षा-10 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में कम्प्यूटर विज्ञान विषय विद्यालय में कार्यरत गणित/विज्ञान के कम्प्यूटर में विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक या आरकेसीएल/आरएससीआईटी प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है क्योंकि शिक्षक सेवा भर्ती में कम्प्यूटर शिक्षक पदनाम संवर्गित नहीं है।

वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या-99 द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए "कम्प्यूटर शिक्षक का कैडर" सृजन करने की घोषणा की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जिला चूरू में कुल 492 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित हैं, जिनमें से 461 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब संचालित हैं एवं 31 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब अक्रियाशील हैं, जिसको विद्यालय स्तर पर दुरुस्त करवाकर संचालन किया जायेगा। विभाग में कम्प्यूटर शिक्षक पदनाम संवर्गित नहीं है, अत: कम्प्यूटर शिक्षक का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खंड-1 में यह कहा कि 3464 माध्यमिक और 11137 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आप कम्प्यूटर शिक्षा पढ़ा रहे हैं तो क्या इन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नंबर एक बात। अगर अनिवार्य है तो इनके लिए आपके इन विद्यालयों में जिनमें, आपने खंड-1 में कहा कि हम कम्प्यूटर शिक्षा पढ़ा रहे हैं क्या आपके पास आवश्यक कम्प्यूटर और कम्प्यूटर की लैब हैं? नंबर एक बात।

नंबर दो बात, आपने कहा कि चूरू जिले के अंदर 31 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब अक्रियाशील हैं और इनको दुरुस्त कराने के लिए विद्यालय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है तो इन अक्रियाशील कम्प्यूटर लैब के लिए क्या विभाग कोई बजट आबंटित कर रहा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नाइंथ-टेंथ में कम्प्यूटर का विषय है जिसको जो शिक्षक होते हैं, वह पढ़ाते हैं। आपके समय में भी पढ़ाते रहे हैं और हमारे समय में भी पढ़ाते रहे हैं लेकिन उसके जो प्राप्तांक हैं वह श्रेणी में उसका जो प्रतिशत होता है उसमें नहीं जुड़ते हैं। एक बात।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारी क्लिक योजना है, राज्य सरकार की स्ववित्त पोषित योजना, जिसके माध्यम से जो आरकेसीएल है उसके यहां से टीचर ले करके कोई भी विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो एसडीएमसी है वह प्रस्ताव लेकर ...(व्यवधान) एक मिनट रुक जाओ न, पूरी बात बता दूंगा। एक घंटा ले लो, कहां दिक्कत आ रही है। सुन तो लो। उसमें जा सकता है, यह आपके समय में भी थी लेकिन इसमें बच्चों से पैसे लिए जाते हैं इसलिए कोई एक महीने देता है, कोई 2 महीने देता है लेकिन यह योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में नहीं है।

दूसरी चीज 11वीं में जो कम्प्यूटर विषय है वह विज्ञान वाला भी कम्प्यूटर विषय ले सकता है, आर्ट्स वाला भी ले सकता है, कामर्स वाला भी ले सकता है लेकिन आज तक किसी भी सरकारी विद्यालय में यह नहीं किया गया, क्योंकि कम्प्यूटर संवर्ग ही नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने यह सोचा आगे बढ़ करके, आपने 5 साल में नहीं किया वह हमने किया कि आज के जमाने में कम्प्यूटर पढ़ाना जरूरी है इसलिए मैं समझता हूं कि यह बजट में घोषणा की गई है इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे।

दूसरा आपने पूछा कि जो अक्रियाशील 31 हैं इनके अंदर आप क्या करोगे, किस तरह से व्यवस्था करोगे, तो आपके जो 31 हैं उसमें जो बंद किए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गए लैब 31 की सभी की डेट बता सकता हूं। किसके एसडीएमसी खाते में, किसी में 1,87,500 हैं, किसी में 28,000 हैं, किसी में 34,000 हैं, जो ठीक होने वाले हैं वह कम्प्यूटर हम लोग ठीक करवा रहे हैं इस पैसे से लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन की चर्चा में यह बात आ गई तो मैं कहना चाहता हूं कि यह 5 फेज में जो कम्प्यूटर क्रय किए गए वह जब कम्प्यूटर खरीदे और भारत सरकार जब योजना लाई तो वहां पर साथ में उसके संचालन और उनको सिखाने के लिए जो अनुदेशक देते थे वह ज्यों-ज्यों 5 साल पूरे हो गए, वह समाप्त होते गए लेकिन पिछले 5 साल में आपने एक दिन भी यह नहीं सोचा कि यह जब कार्यावधि पूरी हो गई और 5 साल समाप्त हो गए तो इन लैब का क्या होगा, इनमें कौन प्रैक्टिकल करवाएगा, कौन इनको ठीक करेगा, इसलिए यह समस्या आ गई। इसीलिए हमने यह कहा है कि हम लोग अब संवर्ग बनाएंगे, कम्प्यूटर को 11वीं में भी विषय लेकर वह कम्प्यूटर विषय से ही कर सकेगा। यह इसीलिए कर रखे हैं और आपको अगर पर्टिकुलर किसी भी, आपके विधान सभा क्षेत्र के या जिले के विद्यालय के बारे में पूछना है कि किस प्रकार से ठीक होगी लेकिन दिक्कत यह है कि 2008 में यह चली हुई योजना थी, काफी कम्प्यूटर पुराने हो गए, उन्हें वापस आपने नए करने के लिए पांच साल तक कोई योजना नहीं बनाई और वह कमरे में बंद पड़े हुए हैं कम्प्यूटर, उनको भी हम ठीक कराने का काम करेंगे और जहां पर कम्प्यूटर बिल्कुल खराब हो गए उनको भी नए लेने की योजना हमारी सरकार बनायेगी। आपने तो केवल कम्प्यूटर खरीदने का काम किया है, उनके यहां अनुदेशक लगाने का आपने सोचा तक नहीं और अभी जो 3000 के लगभग कम्प्यूटर खरीदे हैं, पहले उसके इंस्ट्रक्टर साथ में आता था उनके जो एमओयू होता था उसमें प्रावधान होता था, आपने वह प्रावधान ही नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा-सा सवाल किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उन्होंने सीधा-सा जवाब दे दिया। कम्प्यूटर कैडर पैदा करेंगे, उसके बाद व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप ही का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा, कम्प्यूटर है ही नहीं ...(व्यवधान) कम्प्यूटर कितने हैं, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: वह मान चुके हैं, प्रश्न का मतलब ही नहीं है। माननीय सदस्य, अलग ढंग से लेकर आएं। जब मालूम है कि शिक्षक हैं ही नहीं, कैडर क्रिएट कर रहे हैं। प्रश्न पूछ कर क्या करोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जवाब दे देना चाहिये इनको। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, हम कम्प्यूटर पढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न आपको पूछना है। आप ही को पूछना है अगला प्रश्न।

समदड़ी (सिवाना) में महिला महाविद्यालय खोलने की योजना

227. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) व (**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिवाना में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आगामी शिक्षा सत्र से सिवाना महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समदड़ी तहसील मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्री जी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं माननीय सदस्य, कोई बात नहीं। आप सप्लीमेंट्री पूछ लेना।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) राजकीय महाविद्यालय, सिवाना में कुल 23 पद स्वीकृत व 18 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(3) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय उक्त महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) सिवाना विधान सभा क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, सिवाना संचालित है। संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर यथासमय विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह राज्य सरकार का विजन है कि उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं? समदड़ी उपखण्ड मुख्यालय है, कब तक खोलेंगे?

दूसरा, क्या सरकार सिवाना महाविद्यालय में अतिरिक्त विषय आरम्भ करने का विचार रखती है?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ में ही तीसरा भी पूछ लेता हूं। सिवाना में जब से महाविद्यालय खुला है तब से हर महीने, दो महीने में प्रोफेसर लगाये जाते हैं, क्या उनको स्थाई करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मेरे मूल प्रश्न के जवाब में माननीय सदस्य को निवेदन किया कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में उपखण्ड मुख्यालय पर या अन्य स्थानों पर नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की नीति जारी की गई है और उसके अनुसार आगामी समय में क्षेत्र की आवश्यकताओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समदड़ी में भी नया कालेज खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

सिवाना में अतिरिक्त विषय खोले जाने की माननीय सदस्य के द्वारा जो मांग की गई है, निश्चित रूप से इसके बारे में भी जैसा मैंने पहले निवेदन किया, आगामी समय में गुणावगुण और वित्तीय संसाधनों के आधार पर इसका निर्णय होगा।

सिवाना में अस्थाई शिक्षक की जो माननीय सदस्य ने बात कही है,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सिवाना में 2015 में जब यह राजकीय महाविद्यालय खोला गया था तो उस समय सात में से चार शिक्षकों का पदस्थापन किया गया था और लगातार वह शिक्षक वहां कार्यरत हैं और आगामी समय में जब हमें आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी मिलेंगे या स्थानांतरण के माध्यम से जब ट्रांसफर होते हैं, उस समय सिवाना का ध्यान रखकर यहां पदस्थापन किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं गुणी मंत्री जी से जानना चाहूंगा, परिशिष्ट 1 पर आपने एक सूची दी है। प्राचार्य का एक पद, वह भी खाली। अंग्रेजी में एक लैक्चरर, वह भी खाली। इतिहास में खाली, हिन्दी में खाली ओर भूगोल में एक, जिसको भी आपने नावां डैपुटेशन पर भेज दिया।

दूसरा, आपने इसके साथ परिशिष्ट 2 पर बताया है, जो 13 अशैक्षणिक के पद हैं, उनमें से एक आदमी, एक यूडीसी काम कर रहा है, 12 पद खाली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि इस महाविद्यालय में आपके पधारने के बाद अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, भूगोल की कोई भी कक्षा नहीं ली जा रही है और क्या आप इन पदों को भरने के लिये कोई कार्यवाही करोगे? मैं पूछना चाहता हूं कि बिना सहायक लेखाधिकारी के आप किस प्रकार उस महाविद्यालय में वित्तीय काम कर रहे हैं, बताएं जरा।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय द्वारा जो रिक्त पदों की बात कही गई है, अध्यक्ष महोदय, चूंकि विरासत में लगभग 50 प्रतिशत रिक्त पद एक साल पहले हमें मिले हैं और 2018 में जब चुनावी दौर में इनकी सरकार थी, बजट पेश हुआ उसमें कालेजेज का प्रावधान नहीं किया और उसके बाद मार्च, 2018 के बाद आचार संहिता लगने तक इन्होंने करीब 40 नये कालेज खोल दिये। न उसमें कोई वित्तीय प्रावधान किया, न बिल्डिंग का प्रावधान किया। इस प्रकार से बड़ी संख्या में हमें रिक्त पद मिले हैं, उन रिक्त पदों को भरने के लिये हमने आरपीएससी को 920 पदों की अभ्यर्थना भेजी हुई है। अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र उन पदों को भरा जायेगा। अभी वर्तमान में हमें 50 प्रतिशत रिक्त पद मिले हैं तो उसी रेशो के अनुसार हमने सब कालेजों में शिक्षकों को लगाया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा प्रभावित होने की बात है, हमने एक रेस योजना शुरू की है, उस रेस योजना के माध्यम से जिले के जो बड़े कालेज

(श्री भंवर सिंह भाटी)

हैं, वहां से 15 दिन के लिये, एक महीने के लिये या सात दिन के लिये जिले के कालेज से, जैसे सिवाना के जिन विषयों के पद आपने खाली बताए हैं, उन विषयों के पढ़ाने के लिये हमने रेस योजना के तहत एक महीने के लिये कार्य व्यवस्था हेतु रोटेशन के आधार पर आदेश किये हैं और पूरा शिक्षण कार्य किया है। हमने सिवाना का भी पूरा सिलेबस कराया है और पूरे राजस्थान में जहां भी रिक्त पद हैं, जिला मुख्यालय पर जो कालेज हैं, जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, उनको लगाकर हम शैक्षणिक व्यवस्था पूरी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, तीन आप्शनल सब्जैक्ट होते हैं, तीनों खाली। लेकिन जो भूगोल है, उसके बारे में आपने लिखा है 16.12.2019 को नावां में कार्य व्यवस्था हेतु, तो यहां कोई कार्य व्यवस्था बाकी नहीं थी इसलिए वहां भेजा है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, चूंकि नावां का कालेज इसी शैक्षणिक सत्र से नया खोला गया था, वहां शैक्षणिक व्यवस्था हमने शुरू की है, ऐसा नहीं है। शैक्षणिक व्यवस्थाएं समय-समय पर विद्यार्थियों के हित में की जाती हैं। चूंकि नावां में भी सारे पद रिक्त होने की वजह से एक शिक्षक को हमने वहां लगाया है। भूगोल का सिलेबस हमने पूरा करवाया है और उसके बाद इस शिक्षक को वहां पदस्थापित किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

कोटा जिले में संचालित ई-मित्रों द्वारा गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरण

228. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में जिला कोटा में ई-मित्रों द्वारा गबन और अनियमितता के कितने प्रकरण हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में गबन राशि की पूरी वसूली कर ली गई है?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश के ई-मित्रों पर आधार-कार्ड बनाने और आधार अपडेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री संदीप शर्मा)

(4) विगत पांच वर्षों में जिला कोटा में ई-मित्र संचालकों द्वारा लोगों से सरकारी दर से अधिक राशि लेने की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) गत 5 वर्षों में कोटा जिले में ई-मित्र द्वारा गबन और अनियमितता के 4 ई-मित्र कियोस्कों के विरुद्ध 5 प्रकरण सामने आये हैं जो निम्नानुसार हैं:-

कियोस्क का नाम	**विभाग का नाम**
आशु चौधरी	DISCOM (JVVNL)
आशु चौधरी	PHED
अजय मित्तल	PHED
तालिब कादरी	PHED
शैलेन्द्र कुमार शर्मा	DISCOM (JVVNL)

(2) राज्य सरकार द्वारा कोटा जिले में ई-मित्र द्वारा गबन और अनियमितता के 4 ई-मित्र कियोस्कों के विरुद्ध 5 प्रकरण सामने आये हैं, जिनमें से 3 प्रकरणों में वसूली की जा चुकी है एवं 2 प्रकरण में वसूली राशि की गणना का कार्य सम्बन्धित विभाग (DISCOM & PHED) के स्तर पर प्रगति पर है। गबन राशि की गणना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार वसूली की जाएगी।

कियोस्क का नाम	**विभाग का नाम**	**विवरण**
आशु चौधरी	DISCOM (JVVNL)	Recovered
आशु चौधरी	PHED	Recovered
अजय मित्तल	PHED	Recovered
तालिब कादरी	PHED	Under Process
शैलेन्द्र कुमार शर्मा	DISCOM(JVVNL)	Under Process

(3) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश में 687 ई-मित्र कियोस्क द्वारा आधार की सभी सेवाएं (आधार कार्ड बनवाने और आधार अपडेशन) आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही है।

(4) गत 5 वर्षों में कोटा जिले में ई-मित्र संचालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने की लगभग 132 शिकायतें प्राप्त

(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री)

हुई हैं। निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने की शिकायत एवं वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाये जाने पर 4 ई-मित्र कियोस्कों को FIR दर्ज होने के उपरान्त स्थायी रूप से बन्द किया गया है तथा SDM/SDO कार्यालय द्वारा 2 ई-मित्र कियोस्कों के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने एवं कियोस्क बन्द करने की कार्यवाही की गई है।

विभाग द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर कार्यवाही के निम्न कदम उठाए गये हैं:-

(1) विभाग द्वारा सभी जिला कार्यालयों को ई-मित्र द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने की शिकायत सही पाये जाने पर कियोस्कधारक के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर स्थायी रूप से बंद करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुलग्नक (1)- ई-मित्र कियोस्क द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल किये जाने पर प्रार्थी द्वारा 181 या 'राजस्थान सम्पर्क' पर कियोस्क के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवायी जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर एसडीएम/एसईओ द्वारा शिकायत की जांच की जाती है तथा आवश्यक होने पर प्रार्थी एवं ई-मित्र कियोस्कधारक को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु बुलवाया जाता है। एस.ई.एम./एस.ई.ओ. को उक्त प्रकरण में संलग्न दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अनुलग्नक (2)- उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया ई-मित्र पोर्टल पर आनलाइन कर दी गयी है तथा ई-मित्र कियोस्कधारक द्वारा शास्ति नहीं जमा कराने की स्थिति में कियोस्क स्वत: बंद हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र खोले जाएंगे और ई-मित्र प्लस की मशीनें लगायी जाएंगी। कई जगह पर ये ई-मित्र नहीं खुले हैं। ई-मित्र प्लस की मशीनें भी नहीं लगी हैं और जहां पर लगी हैं, वहां पर प्रशिक्षित लोग नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका प्रश्न क्या है और आप क्या पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। प्रश्न में जो लिखा है, उसी के ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बायोमैट्रिक या पोस मशीनों पर किसी भी योजना के फार्म भरते समय जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनके अंगूठे के निशान नहीं आ पाते, यह बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल।

लाखेरी को पंचायत समिति बनाने की कार्ययोजना

229. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नव प्रस्तावित लाखेरी को पंचायत समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) (पंचायती राज मंत्री के स्थान पर): राज्य सरकार द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमाओं में परिवर्तन व नवसृजन किये जाने का निर्णय लिया जाकर विभागीय अधिसूचना क्रमांक 513 दिनांक 12.06.2019 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9, 10 व 101 के तहत ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/ नवसृजन के लिये वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों पर सुनवाई उपरान्त अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 93/2019 के द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया।

जिला कलेक्टर्स से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त पंचायत समिति लाखेरी के नवसृजन प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण लाखेरी को पंचायत समिति नही बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से तीन सवाल एक ही साथ करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि केशोरायपाटन पंचायत समिति की 2011 की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जो पोपुलेशन है, वह 1 लाख 99 हजार 311 है, वर्तमान में लगभग ढाई लाख है। अगर लाखेरी पंचायत समिति बनती है तो 2011 की पोपुलेशन के हिसाब से केशोरायपाटन की जनसंख्या 1 लाख 8 हजार 598 है और वर्तमान में 1 लाख 30 हजार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए। सरकार ने कह दिया, नहीं बनाना। प्रश्न क्या है, बताओ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। प्रदेश में इसी पोपुलेशन के आधार बनी हुई पंचायत समितियों की संख्या बताने का कष्ट करें कि आपने कितनी पंचायत समितियां बनायीं?

श्री अध्यक्ष: इसका कोई संबंध नहीं। यह लाखेरी के संबंध में नहीं है। अगला प्रश्न, श्री सूभाष पूनिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अगला प्रश्न। अंकित नहीं होगा।

झुंझुनूं जिले में अटल भूजल योजना में व्यय राशि

230. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के भू-जल का सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के डार्क जोन प्रभावित क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों को अटल भू-जल योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में जिला झुंझुनूं की कौन-कौनसी तहसीलों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट द्वारा सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भू-जल का सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

(भू-जल मंत्री)

(2) जी हां। वर्तमान में 'डार्क जोन' शब्द प्रचलित नहीं हैं। इसके स्थान पर 'अति दोहित श्रेणी' शब्द प्रचलित है। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की सूची संलग्नक-1 के अनुसार 'अति दोहित श्रेणी' में चिह्नित है। अटल भू-जल योजना के अन्तर्गत सूरजगढ़ पंचायत समिति की उक्त ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत झुंझुनूं जिले में कोई राशि व्यय नहीं की गई। अत: सूचना शून्य है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूंगा कि अति दोहित क्षेत्र होने के उपरांत भी सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाया गया और कब तक करेंगे?

नम्बर दो, जब क्षेत्र में पानी ही नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बजट का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? दो साल से एक रुपया भी व्यय नहीं हुआ है। बजट की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? मंत्री जी कृपया बताएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो सूरजगढ़ क्षेत्र है, वह अति दोहित क्षेत्र में है, किन्तु ये सर्वे और प्रस्ताव 2016 में मांगे गये थे। हमारे राजस्थान में 295 ब्लाकों में से 185 ब्लाक अति दोहित श्रेणी में आते हैं। झुंझुनूं में खेतड़ी को 2016 के प्रस्तावों के अनुसार अति दोहित क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया था। सूरजगढ़ में भू-जल दोहन दर 277.45 है और खेतड़ी में यह लगभग 200 है। उस समय वहां संभवत: वाटरशैड के कार्यक्रम इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इन कार्यक्रमों के आधार पर चयन किया गया था। आगे जब कभी भी नये क्षेत्र लिए जाएंगे तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में मूलभूत सुविधाओं की कार्ययोजना

231. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 से प्रारम्भ की गई पृथ्वीराज नगर योजना में अब तक कितने आबंटियों को भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया है तथा क्यों? वंचित आबंटियों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वंचित आबंटियों को कब्जा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त को भूखण्डों का कब्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना में पानी, बिजली, सड़क, नाली आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या तथा नहीं तो कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना में आबंटियों से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई तथा योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर अब तक कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) पृथ्वीराज नगर योजना में वर्तमान में कुल 567 आबंटियों को भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया है। खातेदारों के भूमि विवाद, न्यायालय के स्थगन आदेश एवं प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रहने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है। वंचित आबंटियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ऐसे विवादित भूखण्ड जिनका अवाप्त भूमि के खातेदारों के साथ प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका था, लेकिन बची हुई जमीन पर ऐसे भूखण्डधारियों को राहत प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की वैकल्पिक भूखण्ड आबंटन समिति की बैठक दिनांक 11 मई, 2018 की पालना में इसी योजना में समान क्षेत्रफल के 24 अन्य अविवादित वैकल्पिक भूखण्डों का आबंटन किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्राधिकरण में कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। प्राधिकरण एवं खातेदारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण एवं अन्य कारण से भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है। खातेदारों के साथ भूमि विवाद न्यायालय के बाहर निस्तारण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) पृथ्वीराज नगर योजना में आबंटियों को बिजली, सड़क की सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है जिसमें बिजली की 05 कि.मी. की LT Line तथा 02 कि.मी. की HT Line एवं बिजली के 350 खंभे लगा दिये गये हैं एवं 08 कि.मी. डामर सड़क एवं 02.5 कि.मी. की WBM रोड बना दी गई है। पानी का तकमीना पी.एच.ई.डी. द्वारा पुन: बनाया जा रहा है। तकमीना प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी एवं नालियों का निर्माण भूखण्डों पर निर्माण होने के पश्चात् किया जाएगा। चूंकि कुछ भूमि पर विवाद है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय में लम्बित है, अत: शेष भूमि में विवाद का समाधान होने के पश्चात् ही विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

(5) पृथ्वीराज नगर योजना में वर्तमान में कुल 2469.67 लाख रुपये राशि प्राप्त की गई है एवं योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर अब तक कुल राशि 1889.51 लाख रुपये व्यय की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हजारीमल सारण, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हजारीमल सारण के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री हजारीमल सारण का जन्म वर्ष 1937 में चूरू जिले के खेजड़ां ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री हजारीमल सारण छठी राजस्थान विधान सभा में सरदारशहर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सारण तीन बार ग्राम पंचायत खेजड़ां के सरपंच तथा लगभग 18 वर्षों तक पंचायत समिति सरदारशहर के प्रधान रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयासरत रहे श्री सारण ने

(श्री अध्यक्ष)

'जलते टीले' समाचार पत्र का सम्पादन भी किया। छात्र हितों के रक्षक रहे श्री सारण ने सरदारशहर में किसान छात्रावास की स्थापना की तथा आप इसके अध्यक्ष भी रहे।

श्री हजारीमल सारण का दिनांक 25 फरवरी, 2020 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर लाखेरी के निकट दुर्घटना के मृतक

कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर दिनांक 26 फरवरी, 2020 को एक मिनी बस के लाखेरी के निकट अनियंत्रित होकर मेज नदी में गिरने से हुई दुर्घटना में 24 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा अनेक घायल हो गये। यह सदन इस हादसे के मृतकों के प्रति भी शोक प्रकट करता है। पीड़ित परिवारों के प्रति सदन की गहरी संवेदना है।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, रतनलाल भी शहीद हुए हैं दिल्ली में।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले कई दिनों से घट रही आपराधिक घटनाओं के कारण आमजन में भय का वातावरण व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों के सब्सिडी के 833/- रु. प्रति माह बिल में समायोजित किये जाने के संबंध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सोनाई मांजी गांव के पशु चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना में जांच करने वाले टैक्निशियनों की कमी से आम जन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ शहर के महाराणा सेतु मार्ग पर शिवाजी सर्किल के पास दिनांक 25 फरवरी, 2020 को एक युवक की दिनदहाड़े जघन्य हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से डेढ़ दशक पूर्व पाकिस्तान से अजमेर आये 23 परिवारों को नागरिकता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से कल दिनांक 26 फरवरी को बूंदी के लाखेरी के पास बजरंग पुलिया से मेज नदी में बस गिरने से एक ही परिवार के 24 सदस्यों के काल कवलित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लाखेरी कस्बे के पास कोटा-माधोपुर हाईवे पर पुलिया की चौड़ाई कम होने से हुए बस हादसे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से बून्दी जिले में कल दिनांक 26 फरवरी को सड़क हादसे में काल कवलित हुए 24 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने व ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर आज शून्य काल के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में होने वाले रीट के एग्जाम में राजस्थानी भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(12) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में बिल्डिंग बाईलाज की घोषणा होने के बाद भी आबू निवासियों की समस्याओं का हल नहीं निकलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री बलवान पूनियां एवं श्री समाराम गरासिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सुभाष पूनियां, सदस्य की ओर से ग्राम ढाणा बाग, तहसील बुहाना, जिला-झुंझुनूं में खसरा नं 137 पर काबिज परिवार को बिना नोटिस बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(3) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन के प्रति उदासीनता से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कृषि कनेक्शनों में अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

(5) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नाहटा राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बालोतरा को 200 बैड में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में भूती रोडला रोड पर स्थित नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में 2 वर्ष से रिक्त पदों के S.C./S.T. के बैकलाग को समाप्त कर सामान्य वर्ग से भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों की जिला स्तर पर मीटिंग न होने से विकास कार्यों में हो रही बाधा के संबंध में।

(9) श्री महेन्द्र विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत नादड़ी में सीवरेज लाइन डाले जाने के संबंध में।

(10) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वीकृत सड़कों का निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(11) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय प्रतियोगिता परीक्षा-2013 में वंचित 583 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

(12) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांटों के द्वारा निविदाओं की पात्रता शर्तों में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से बदलाव किये जाने के संबंध में।

(13) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर चौराहे से वाया शंभुपुरा-घटियावली सड़क मार्ग का निर्माण कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में न्यायिक सेवाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के अंतर्गत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 20 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 2 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य द्वारा किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य द्वारा उदयपुर में पिछोला व फतह सागर झील को प्रदूषण से मुक्त किये जाने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जोधपुर के बारे में 295 है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन पर बोलेंगे आप? जोधपुर महात्मा गांधी चिकित्सालय पर।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अंदर 4 अस्पताल हैं। महात्मा गांधी अस्पताल सबसे पहले बना हुआ है। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने इस हास्पिटल को बनाया। किस ध्येय से बनाया? इस सोच से बनाया कि जोधपुर के अंदर जनता को सुविधा हो, जनता को आने-जाने में सुविधा हो, बस स्टैंड नजदीक हो, स्टेशन नजदीक है और मंच के अंदर बना हुआ है, सेंटर के अंदर बना हुआ है और सारे पश्चिमी राजस्थान को ये फोलो करता था। मगर आज उसकी स्थिति यह है कि वह एक डिस्पेंसरी के लायक भी नहीं रहा है। उसकी स्थिति खराब कर दी गई है। जोधपुर के अंदर मथुरादास माथुर अस्पताल है, उम्मेद अस्पताल है, कमला नेहरू अस्पताल है, सारे हैं मगर इस गांधी हास्पिटल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसी चिंताजनक है कि जिस पर कुछ कहने को नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोकोगे नहीं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक जवान व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, उसको लेकर गए तो कहा कि मथुरादास माथुर अस्पताल

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

जाओ, वह नेहरू पार्क तक भी नहीं गया और उसकी मौत हो गई। अगर गांधी अस्पताल में डाक्टर होता और उसको इलाज मिल जाता तो शायद वह जिंदा रहता। यह बहुत सोचने की बात है कि हास्पिटल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मंत्री महोदय ने हमें विश्वास दिलाया था कि मैं जोधपुर आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा और सारी व्यवस्था करवाऊंगा मगर आज दिन तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। या तो मंत्री जी ने आर्डर नहीं दिए और अगर आर्डर दिए हैं तो अफ़सरों ने माने नहीं। वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं है, एक भी यूनिट नहीं है। सारे यूनिट मथुरादास माथुर अस्पताल में भर दिए गए हैं। वहां पर भी मच्छी खाने की तरह है। मथुरा दास अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि बता नहीं सकते। वहां की जो स्थिति है, मुझे खुद को कहते हुए शर्म आती है।

गांधी हास्पिटल इतना बड़ा हास्पिटल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इतनी सुरंग है। पूरे पश्चिमी राजस्थान को कंट्रोल करता था, आज उसकी स्थिति यह कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप यह कब तक करवा दोगे? मुझे आज इसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बलवान पूनियां। बस हो गया। आप सीनियर मैम्बर हैं। बलवान पूनियां।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: इसमें जवाब नहीं आएगा। बलवान पूनियां।

रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा को वैकल्पिक भाषा का दर्जा

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, 2003 में राजस्थान की विधान सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया था। उसके बाद राजस्थान के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थानी विषय को शामिल किया गया था। हमारी शासन से मांग है कि रीट के एग्जाम में, जिस तरह से सात विषय और हैं, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, सिंधी, पंजाबी इत्यादि हैं, उसी तरह से

(श्री बलवान पूनियां)

राजस्थानी भाषा को उसमें शामिल किया जाए ताकि राजस्थानी भाषा पढ़ने वाले राजस्थान के नौजवान को मौका मिल सके।

अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे पड़ौस में गुजरात है, उसके विषय को शामिल किया गया है लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शामिल नहीं करते हुए, रीट के एग्जाम में नौजवानों को पीछे छोड़ा गया है। मेरी शासन से मांग है कि उसको शामिल करें और राजस्थान के युवाओं को मौका दें।

श्री अध्यक्ष: समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा-आबू में बिल्डिंग बायलाज से समस्या

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि आबूपर्वत नगरपालिका में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि बिल्डिंग बाईलाज पास किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आबूपर्वत पर लोगों के जर्जर अवस्था में मकान हैं, नया मकान बनाने के लिए यदि किसी के दो लड़के हो तो उसे कैसे डायवर्ट किया जाए, दीवार भी नहीं बनने देना। मेरा आपसे निवेदन है कि नगरपालिका आबूपर्वत में सहयोग करे। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां भी निवासी रहते हैं, आबूपर्वत एक हिल स्टेशन है, उसमें सरकार मदद करे।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। पानाचंद मेघवाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

किसानों की नष्ट फसलों का मुआवजा

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बारां ज़िले के किसानों की ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2019 के ख़रीफ़ सीजन में कोटा संभाग के कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में भारी बरसात व जल भराव के कारण किसानों की उड़द, सोयाबीन, मूंग की फसल सौ प्रतिशत खराब हो चुकी थी। बारां व झालावाड़ ज़िले में ख़रीफ़ के सीजन में किसान की फसल बर्बाद हुए पांच माह से अधिक का समय गुजर गया लेकिन इसके बाद भी किसानों को बीमा क्लेम की राशि नहीं मिल रही है, जबकि कोटा व बूंदी ज़िले के किसानों की फसल में खराबे का क्लेम मिल चुका है। बूंदी जिले में किसानों

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

को अब तक 9 करोड़ व कोटा में 17 करोड़ 56 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है। अधिकारियों की लापरवाही से बारां व झालावाड़ ज़िले के किसान मुआवज़े से वंचित हैं। बारां ज़िले में ख़रीफ़ सीजन में सभी किसानों की सोयाबीन व उड़द की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, देखकर नहीं बोलें, बिना देखकर बोलें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): इसके लिए बारां ज़िले के किसानों .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची पर बिना देखे बोलें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): बारां ज़िले के किसानों से केसीसी के माध्यम से, उनको केसीसी मिलती है, क्लेम के पैसे उनके खाते से काटे गए। जिन किसानों का केसीसी के माध्यम से क्लेम नहीं काटा गया उनके द्वारा व्यक्तिगत बैंक जाकर क्लेम करवाया गया। पांच माह गुजरने के बाद एक अधिकारी द्वारा भी इस ओर चिंता व्यक्त नहीं की गई। बारां के किसानों ने बीमा कम्पनी पर क्लेम किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन अधिकारियों द्वारा सर्वे करने व रिपोर्ट भेजने में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण बारां ज़िले के 50 हजार से ज्यादा किसान बीमा क्लेम से वंचित रहे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर की पिछोला व फतहसागर झील की प्रदूषण से मुक्ति

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। झीलों की सार-संभाल नहीं होगी, उनमें पानी नहीं होगा तो कौन उदयपुर आना चाहेगा। पिछोला झील में नावों व जेटियों को लेकर कोई नियम कायदे नहीं हैं। वहां होटल वालों ने नाव संचालन के लिए अलग-अलग जेटियों से एनओसी ले ली और उसे ही लाइसेंस मान बैठे। वहां पर अवैध रूप से नावों का संचालन हो रहा है। जेटियां भी अवैध बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि झील का मालिक नगर निगम है जिसकी स्वीकृति के बिना ही जेटियां बन गई। यह भी सामने

(श्री फूल सिंह मीणा)

आया है कि जयपुर से मंजूरी दे दी जाती है। होटल वालों पर बड़े आईएएस अफसरों की पूरी मेहरबानी है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि झीलों के पास एक कमरा बनाने के लिए परमीशन नहीं मिलती है। जयपुर से अफसरों ने होटल्स को मंजूरी दे दी। अभी राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया है कि बोट में शराब पार्टी हो रही है। कोई लाइसेंस नहीं था। कुछ जेटियां मनमर्जी से झीलों में खड़ी कर दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, झीलों का मामला है। पत्रिका की खबर के बाद जांच हुई तो सामने आया कि कुछ नाव व जेटियों को सीज किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): पत्रिका ने खुलासा किया तब पोल खुली। बड़ी तनख्वाह वाले अफसर इनसे मिले हुए हैं, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। अभी भी साफ लगता है कि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। सीज नाव को अभी तक बाहर नहीं निकाला।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़ा हुआ नहीं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इन झीलों के अंदर बड़ेबड़े अफसर मिले हुए हैं। जेटियों की कोई सार-संभाल नहीं है। केन्द्र की तरफ से जेटियां लगा रही है जो इस झील....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। हो गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिए प्लीज। यह बिजनस समाप्त हुआ। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे।

शासकीय वक्तव्य

कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर लाखेरी के निकट मिनी बस के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26.02.2020 को सुबह मिनी बस नम्बर RJ 20 PA 4614 गणेश तालाब बसंत बिहार, पुलिस थाना दादाबाड़ी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कोटा शहर से सवाईमाधोपुर के लिए रवाना हुई थी। इसमें मुरली पुत्र बाबूलाल जाति धोबी, निवासी बसंत विहार, कोटा का परिवार, उसकी बहिन, बहिन की बच्ची भात लेकर सवाईमाधोपुर जा रहे थे। इस बस में चालक सहित कुल 29 व्यक्ति सवार थे। सुबह 9.30 बजे से 10.00 बजे के बीच लाखेरी से 5-6 किलोमीटर पहले, कोटा की तरफ, बस के मेज नदी की पुलिया से नीचे गिर जाने व पानी में डूब जाने से बस में सवार चालक सहित 24 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं, 10 पुरुष, 2 बालक, 2 बालिकाएं हैं। सूची संलग्न है। 5 घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें कोटा रैफर किया गया। घायलों में 2 पुरुष, 1 महिला, 1 बालक, 1 बालिका है। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये व घायलों को 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जो बच्चे इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, उनके कालेज जाने तक शिक्षा का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। घटना की सूचना 10.05 AM पर प्राप्त होते ही तुरन्त एस.एच.ओ. मौके पर पहुंचे और जिला कलक्टर बूंदी व पुलिस अधीक्षक मय जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करवाया। फरियादी अमित पुत्र सुभाष उर्फ मुरली, जाति धोबी, निवासी गणेश तालाब, बसंत विहार, कोटा की रिपोर्ट पर मिनी बस नम्बर RJ 20 PA 4614 के चालक स्वर्गीय श्यामसिंह पुत्र शिवनारायण के विरुद्ध प्रकरण संख्या 39/2020 धारा 279, 337, 304-ए आई.पी.सी. में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना लाखेरी द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

दुर्घटना के सभी सम्भावित तकनीकी, मानवीय व अन्य पहलुओं पर जांच की जाकर पुनरावृत्ति रोकने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। बस चालक के अतिरिक्त उपरोक्त सभी मृतकों का पोस्टमार्टम राजकीय चिकित्सालय, लाखेरी में करवाया जा करके मृतकों की लाशों को दाह संस्कार हेतु उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बस को नदी से बाहर निकालने पर बस का एक्सल टूटा हुआ पाया गया, जो प्रथमदृष्टया दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है।

दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के क्रम में पुलिस, परिवहन, सड़क निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दिनांक 26.02.2020 को कोटा गये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और मृतकों के परिजनों से मिल करके सरकार की संवेदना प्रकट करते हुए सहयोग का पूरा विश्वास दिलाया।

अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना का जो मोटा कारण दिखता है, वह जांच का तो विषय है ही, क्योंकि अखबार में आ रहा है कि स्टेयरिंग फेल हो गया, यह हो गया, वह हो गया। एक यह भी आ रहा है कि टायर बर्स्ट हो गया। एक यह भी आ रहा है कि एक्सल टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वह गिर गई। लेकिन आपदा प्रबंधन जिला कंट्रोल रूम, बूंदी से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथमदृष्ट्या वाहन का टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और पुलिया से नदी में गिर जाने के कारण यह हादसा होना बताया गया है।

वाहन संख्या RJ 20 PA 4614 का पंजीयन 23.09.2011 का है। उपरोक्त वाहन नगरीय परमिट संख्या 637 वैधता दिनांक 19.07.2023 तक कवर्ड है। 07.08.2020 तक का इसका बीमा भी है। वाहन 25.02.2020 को कोटा से सवाई माधोपुर वाया केशोरायपाटन, लाखेरी, इंद्रगढ़ का अस्थाई परमिट क्रमांक 02804151, रिटर्न ट्रिप 26.02.2020 के लिये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा से जारी किया गया था। वाहन की फिटनैस 20.09.2020 तक वैध थी।

अब सवाल यह आता है कि इन सब दस्तावेजों की जांच परिवहन आयुक्त के द्वारा तीन अधिकारियों का दल भेजकर करवाई जा रही है कि ये दस्तावेज वाकई सही थे या नहीं थे। दुर्घटना के कारणों में तीन कारण, जो मोटे तौर पर बताये हैं, यह दल वहां जाकर यह भी जांच करेगा कि वाकई उस बस का नदी में गिरने का कारण असल में क्या रहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह घटना एक मानवीय त्रासदी है और आपने बड़े संवेदनशीलता से उन सब मृतकों के प्रति शोकाभिव्यक्ति भी की है। एक मानवीय भूल ने 24 लोगों की जिंदगी ली है।

मंत्री महोदय, आपने घटना का समय 9.20 बताया है। आपने खुद अपने उत्तर में कहा कि घटना घटित होने के लगभग एक घंटे के बाद जिला प्रशासन वहां पहुंचा। सवाल इस बात का है कि आप अपने उत्तर में खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि इसका वैध फिटनैस सर्टिफिकेट इस वाहन के पास नहीं था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि सिटी मिनी बस, जिसका काम है सिटी के अन्दर यात्रियों को लाना-ले जाना, उसको अस्थाई परमिट दिया गया। मैं यह नहीं कह रहा कि इसके पीछे, घटना के बाद क्या है, पर कुछ घटनाएं हमें सबक देती हैं। उसके बाद वह वाहन, जो चलता है, उसके बाद उस वाहन के साथ यह दुर्घटना हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि क्या यह सही है कि जिस फिटनैस सेंटर से, आदिनाथ फिटनैस सेंटर से इसका फिटनैस सर्टिफिकेट जारी किया गया था, उस फिटनैस सेंटर की 31 मार्च को वैधता समाप्त हो गई थी? उसका जाली फिटनैस सर्टिफिकेट बनाया गया था? क्या यह भी सही है कि यह जो परमिट आप कह रहे हैं, यह अस्थाई परमिट था? यह भी बाद में बनाया गया था?

मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में प्रतिदिन 28 मौतें हो रही हैं। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, राजस्थान में सुबह से शाम होती है, सड़क दुर्घटनाओं में 28 मौतें होती हैं। इन मौतों से, इन दुर्घटनाओं से सबक लेकर हम क्यों नहीं व्यापक अभियान चलाएं, ये बिना फिटनैस के, बिना इंश्योरेंस के, ये कबाड़ गाड़ियां लोगों के जीवन को लीलती हुई दौड़ती जा रही हैं। क्या कारण है कि राजस्थान का परिवहन विभाग बेलगाम हो गया और लगातार इस प्रकार के वाहन सड़कों पर यमदूत के रूप में दौड़ रहे हैं। आपने यह तो घोषणा कर दी, और यह मेरी मांग है, यह सामान्य त्रासदी नहीं है, 2-2 लाख से काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम इन परिवारों को 10-10 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे और इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर आप एक टास्क फोर्स बनाइये। हम सभी दलों के लोग मिलकर, बैठकर बात करें कि इस प्रकार की घटनाएं, जो एक नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हर वर्ष घटनाएं होती हैं। इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह काम इस लीपापोती से न हो। कितनी जिंदगियां गई हैं। राजस्थान शर्मसार हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। आपने कल ही आश्वासन दिया था कि

(श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल)

वक्तव्य मिलेगा। मेरी पर्ची भी निकली है। मुझे बोलने का मौका आपने स्थगन के माध्यम से दिया, धन्यवाद।

सम्माननीय राठौड़ साहब ने अभी सारी बात बताई। फिटनैस की भी बात उन्होंने कही। परमिट समाप्त हो गया था, अस्थाई परमिट दिया गया। जो भी कमियां थीं, कबाड़ गाड़ी थी, जो कुछ भी थी, उसकी जांच विभाग के सम्माननीय मंत्री महोदय करेंगे। मैं वहां की वासी हूं। मेरा जन्म वहां हुआ है। उस सड़क से, उस पुलिया से मैं रोज गुजरती हूं। आप देखिये कि सड़क हमने बनाई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):... पर उस सड़क में इस तरह की खामी रह जाये, जिससे लगातार डेली दो वाहन, एक इधर से चला जाये, एक उधर से आ जाये, नहीं गुजर सकते। कितनी बड़ी खामी है कि उस पुलिया को मात्र मेंटिनेंस करके छोड़ दिया गया। जो हमारा मेगा हाईवे कोटा से दौसा बना था, उसमें जगह-जगह विभाग ने पुलियाओं को अधूरा छोड़ रखा है। आज यहां पर हादसा हुआ है, कभी आप कापरेन की सुनेंगे और वहां की घटना के बारे में लोगों से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाई-पास देते समय मात्र 5 फीट की जगह में उन्होंने छोटा-सा एक डिवाइडर बना दिया और एक लाइट खड़ी कर दी। वहां भी बहुत बड़ा हादसा होने का डर है, लगातार हादसे हो रहे हैं।

साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जितने भी गांव इस हाईवे पर, मेगा हाई-वे पर पड़ते हैं, कहीं भी उन्होंने पुलियाएं नहीं दीं। किसान परेशान हैं, पानी भरता है। किसान बर्बादी की ओर जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: डाइवर्ट नहीं करें। डाइवर्ट नहीं करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहती। लगातार हादसे हो रहे हैं और केशोरायपाटन, यही सड़क हमारी जा रही है। वहां पर भी यही हालात हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा निवेदन है कि जो बच्चा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। जो तीन बच्चे अनाथ हो चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। श्री संदीप शर्मा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हैं। इश्यू क्या चल रहा है, कहां जा रहे हैं हम। माननीय संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक साथ 24 चिताओं को जलते हुए, अपनी आंखों से वह दृश्य देखा है। परिजन बिलख रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे अनाथ हो गये, परिवार बेसहारा हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो लाख रुपये की घोषणा की है। जिस प्रकार से आदरणीय राठौड़ साहब बता रहे थे, अवैध वसूलियां भी हम देख रहे हैं और सारी चीजें भी हम देख रहे हैं। साथ-साथ जो वाहन फिट नहीं हैं, उपयुक्त नहीं हैं, वे सड़कों पर दौड़ रहे हैं और ऐसे हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसी दुखांतिकाएं होती रही हैं। ऐसी दुखांतिका, हमने पहले देखा कोटा में हैंगिंग ब्रिज, 40 लोग मरे; मेहरानगढ़ में 16 और देसूरी में 27 लोग ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पाइंट पर आएं आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसलिये मेरा निवेदन है कि बहुत आवश्यक है कि हम इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दें। एक-एक व्यक्ति की जान हमारे लिये बहुत कीमती है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए उन परिवारों के लिए आर्थिक मदद को, जो दो लाख रुपये की है, उसको दस लाख रुपये करें।

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उन परिवारों को संभालें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना बेहद

(श्री संयम लोढ़ा)

दु:खद है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने सहायता कोष से दो-दो लाख रुपये की सहायता दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी ने भी ट्वीट करके इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। क्या प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी उन पीड़ितों के लिए कोई सहायता राशि प्राप्त हुई है?

और दूसरा, पूर्व मंत्री श्री बाबूलालजी वर्मा वहां पर गये थे, उनके चेहरे पर मिट्टी पोत दी, उसके क्या कारण थे?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना जिस प्रकार की घटी है और जैसा दृश्य देखा है, उससे वास्तव में दिल दहल जाता है। घटना के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं दो-तीन बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस गाड़ी का परमिट इसके पहले कौनसी ड्यू डेट थी और उसके बाद इसके परमिट को एक्सटेंड करने के लिए इसने कब अपनी तरफ से एप्लाई किया? ताकि यह सिद्ध हो सकेगा कि वास्तव में राइट टाइम पर एप्लाई किया था या केवल परमिट अवधि समाप्त होने के बाद उसने अपनी तरफ से इस प्रकार का किया। कितनी सीटर यह गाड़ी पास थी और उसमें इतनी सीटर पास होने के बाद अधिक सवारियां ले जाने के लिए क्या वह अधिकृत था? सिटी बस का अगर परमिट है तो फिर उसको रेंडम कहीं भी बाहर जाने का परमिट क्या विभाग दे सकता है या कोई देने का अधिकार है? फिर मतलब, सारी घटना हो गयी, अगर यह इंश्योर्ड नहीं है तो उस गरीब व्यक्ति को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। सामान्यत: सबसे बड़ा दु:खद विषय है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उसमें वह पहले से ही असहाय होते हैं और फिर बाद में कानून भी उनकी मदद नहीं करता है और उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। यह अपन जो कुछ भी टाइम पर दिलवा देते हैं, बस वही उनकी जिंदगी का अंतिम लाभ होता है तो मैं यह जानना चाहता था कि अगर इस व्यक्ति ने, जो इस गाड़ी का मालिक है, उसके खिलाफ आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाओ धारा 302 की, वह अपने डाकूमेंट अपने आप लेकर आएगा और उसके डाकूमेंट से यह प्रूव हो जाता है कि उसने यह सब पूर्तियां की हुई हैं तो उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी और अगर नहीं है तो निश्चित रूप से उसका मालिक पूर्णत: इन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हत्याओं का दोषी है कि उसने कानून की अवहेलना करते हुए अपनी गाड़ी के द्वारा इन लोगों को ले गया जिसके कारण से उनको मौत का शिकार होना पड़ा।

दूसरा, आर.टी.ओ. डिपार्टमेंट भी इसमें है। यदि इसकी परमिट अवधि समाप्त हो गयी तो आर.टी.ओ. ने कोई रजिस्टर्ड या कोई अन्य तरीके से इसको नोटिस भेजा है क्या कि आपकी गाड़ी का इस समय तक का परमिट था? आपका परमिट खतम हो गया है अतः आपको हिदायत दी जाती है कि आप समय पर इसका तुरंत परमिट रिन्युअल कराओ तो वह कहीं न कहीं रिकार्ड पर उपलब्ध होगा। अगर उसने राइट टाइम पर एप्लीकेशन दे दी, परमिट समाप्त होने से पहले तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, वह कानूनी रूप से सही है लेकिन अगर उसकी अवधि समाप्त हो गयी और विभाग ने एक लंबे समय तक उसको अगर नोटिस ही नहीं दिया तो इसका मतलब विभाग की भी इसमें गलती है, जिसके कारण से यह घटना घटी है।

मैं यह चाहता हूं कि उस एरिये की पुलिस भी फिर इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हमने, हमारे समय पर पालना नहीं होती इसके लिए आप और मैं दोनों दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इस बात को निकाला कि इस प्रकार की घटनाएं जिस पुलिस थाना के एरिये में होती हैं, उस पुलिस थाना की भी जिम्मेदारी होगी कि यह ओवर-क्राउडेड गाड़ी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए अगर कोई घटना घटती है तो उस क्षेत्र का थाना भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार की घटना और परिवार का परिवार नष्ट हो गया, भगवान न करे कि आप और हमारे साथ इस प्रकार की कभी कोई घटना, दुर्घटना घट जाए, नहीं तो इस कष्ट को जिंदगीभर तक नहीं भूल सकते। जो छोटे-छोटे मासूम बच्चे परीक्षा देने के कारण से, इस गाड़ी में बैठकर शादी में नहीं जा पाये, वह ही पीछे बचे हुए हैं।

ऐसी हालत में मैं यह चाहता हूं कि सरकार पूरे मन के साथ उन परिवारों को सहयोग करे। दस लाख रुपये करे या कितना करे, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं लेकिन यह बात जरूर है कि उस परिवार के उन बच्चों को जो आज भी बहुत मासूम रह गये और परिवार पूरा समाप्त हो गया, उन बच्चों का भविष्य बनाने की दृष्टि से जो-जो मदद सरकार कर सकती है, जिस तरह से भी उन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, उसके लिए सरकार को किसी न किसी प्रकार की घोषणा यहां पर करनी चाहिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि यह एक घटना हमको आगे के लिए संजीदा रहने के लिए अपने को चेताती है। मैं यह चाहता हूं कि यह दोनों ही डिपार्टमेंट के अधिकारी, वास्तव में हमारे यहां पर भी ऐसी देसूरी में ऐसी घटना घटी थी तो हमने इसको देखा था कि वास्तव में इन गाड़ियों की न तो फिटनैस होती है और कुछ नहीं होता है लेकिन गरीब आदमी यह सोचता है कि मुझे दो पैसा कम लग रहा है, इसके कारण से किराये पर ले लेता है और अपना काम निकाल लेता है। उसकी गरीबी का दुरुपयोग इतना हो जाता है कि उसकी जिंदगी उजड़ जाती है। मैं यह सोचता हूं कि इसको विवाद का विषय नहीं बनायें, प्रतिष्ठा का सवाल भी नहीं बनायें, चाहे वह आप हैं या मैं हूं, मैं यह चाहता हूं कि इसको मानवीय दृष्टि से अपनाकर जहां-जहां पर भी जिसका लेकुना रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही हो ताकि सारे प्रदेश को यह संदेश जाए कि इस प्रकार की गाड़ियां जो चल रही हैं, वह लोगों की जान लेने वाली गाड़ियां हैं, उनको जिस तरह से रोका जा सकता है, रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता महोदय ने यह बताया कि साहब, मैंने कोई सवा नौ बजे का टाइम बताया, सवा नौ नहीं, मेरे स्टेटमेंट में 9 बजकर 45 मिनट था। दूसरी बात आपने फिटनैस के बाबत कही। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस एजेंसीज ने फिटनैस जारी किया था, उसके बाद में फिर आर.टी.ओ. ने फिटनैस जारी किया है तो आर.टी.ओ. ने जो फिटनैस जारी किया है, वह फिटनैस था 20.09.2020 तक। अस्थाई परमिट के बाबत आपने यह कहा कि साहब, अस्थाई परमिट बाद में ले लिया गया। बाद में क्या लेते? कल सुबह की ही तो घटना है। क्या कल का कल परमिट बन जाता? परमिट तो उसी वक्त उसको, एस.एच.ओ. को सारे कागजात वहां पर मिल गये थे। भीगे हुए कागजात मिल गये थे तो बाद में नहीं बना, परमिट बन गया था। अब परमिट गलत बना या सही बना, जांच हो जाएगी। सवाल यह है कि श्रीमती चन्द्रकान्ताजी ने यह कहा कि पुलिया पर दो वाहन एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है, उसमें से सैकड़ों बार मैं भी निकला हूं। आप मेरी बात सुनिए। उठो मत। मेरी बात सुनिए। यह मेगा हाईवे कब बना?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 2006 में बना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसके द्वारा बनवाया गया? आप बैठिये न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज। नहीं सुनना है? नहीं सुनना है? चर्चा समाप्त हुई। आप बैठें। चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। चर्चा समाप्त हुई। यह कोई तरीका नहीं है। नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। चर्चा समाप्त हुई।

131, श्री ज्ञानचंद पारख। श्री ज्ञानचंद पारख 131, 131 श्री ज्ञानचंद पारख। नहीं, माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। यह बिलकुल तरीका नहीं है। (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली शहर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर व कस्तूरबा नगर आवासीय योजना का नगर परिषद् पाली को हस्तान्तरण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। You can’t impose. You can’t impose. यह कोई तरीका नहीं है। आपको बोलना है?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी 131 पर आप बोलिये। 131 पर बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह तो +++ लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गयी, दुर्घटना हो गयी...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठें। माननीय मंत्रीजी, नीचे बैठें। नीचे बैठें। माननीय मंत्रीजी, नीचे बैठें। माननीय मंत्रीजी, नीचे बैठें। यह गलत

(श्री अध्यक्ष)

परंपरा है। गलत परंपरा नहीं करें। आप गलत परंपरा नहीं डालें। माननीय मंत्रीजी, 131 पर, माननीय मंत्रीजी, आप सुन नहीं रहे? माननीय मंत्रीजी, सुन नहीं रहे क्या? आपको बोलना है, क्या करना है? आप बोलिए 131 पर। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा के उक्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के संबंध में तथ्यात्मक सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आप प्लीज, सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिला कलक्टर, पाली की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में स्वीकृत यातायात नगर योजना में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को माह मार्च, 1997 में प्लाट अलाटमेंट किये जाकर सभी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को शहरी आबादी क्षेत्र से यातायात नगर में जून, 1997 तक शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। इसके आधार पर नगर परिषद्, पाली द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को मार्च, 1997 में भूखंड आबंटित किये गये थे। इस योजना पर नगर परिषद् द्वारा सड़क, नाली, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराकर यातायात नगर व्यावसायिक योजना विकसित की गयी, जिस पर वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक एफ.12 (3) (6) राजस्थान 18/1671 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नंबर संख्या 629 रकबा 120.15 बीघा व खसरा नंबर 630 रकबा 128.17 बीघा कुल रकबा 249.12 बीघा गैर-मुमकिन आबादी भूमि नगर परिषद् पाली को आबंटित की गयी थी। तत्पश्चात् अध्यक्ष, नगर विकास न्यास पाली द्वारा तत्कालीन मंत्री को प्रस्तुत अभ्यावेदन, जिसमें नगर विकास न्यास पाली की नगरीय सीमा में स्थित राजकीय भूमि को नगर विकास न्यास पाली को हस्तान्तरित करने के संबंध में निवेदन किया गया था। इसके पश्चात् मंत्री द्वारा विभागीय निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास न्यास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(23)नविवि/पाली/2018 जयपुर दिनांक 11 जून, 2018 द्वारा राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नंबर 629 रकबा 120.15 बीघा व खसरा नंबर 630 रकबा 128.17 बीघा कुल रकबा 249.12 बीघा भूमि को नगर परिषद् पाली से नगर विकास न्यास पाली को हस्तान्तरित करवाये जाने हेतु जिला कलक्टर पाली को निर्देश दिये गये थे। निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक एफ.12(3)(6)राज/18/2757 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा उक्त खसरों की 249.12 बीघा आबादी भूमि को नगर परिषद् पाली के स्थान पर नगर सुधार न्यास पाली को हस्तान्तरित कर दी गयी।

चूंकि योजना नगर परिषद् द्वारा विकसित की जा चुकी है एवं नगर परिषद् पाली द्वारा उक्त खसरों में आवासीय/वाणिज्यिक पट्टों का आबंटन भी किया जा चुका है एवं समस्त संबंधित रिकार्ड नगर परिषद् पाली के पास उपलब्ध है। अत: प्रकरण का परीक्षण करते हुए उक्त क्षेत्र को नगर परिषद् पाली को पुन: हस्तान्तरित करने पर विचार किया जाएगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा और करेक्ट कर दूं आपको। जो आपने पैरा 4 में मुझे उत्तर दिया है, अध्यक्ष, नगर विकास न्यास ने तत्कालीन माननीय मंत्रीजी को जो ज्ञापन दिया, माननीय मंत्री महोदय ने कोई आदेश नहीं दिये थे। उन्होंने लिखा था विभाग के निर्देश विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण करने के, कोई भी ज्ञापन देता है न, चाहे आपको भी देता है तो आपके द्वारा टिप्पणी जरूर आगे जाती है तो उन्होंने वह टिप्पणी कर दी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास भिजवा दी। माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने भी कोई राज्यादेश जारी नहीं किये। एक अर्द्ध-शासकीय पत्र, जैसा ज्ञापन आया था, उसकी मांग के अनुरूप वह अर्द्ध-शासकीय पत्र जिला कलक्टर पाली को लिख दिया और जिला कलक्टर पाली ने उस अर्द्ध-शासकीय पत्र को आदेश मानकर जो भूमि नगर परिषद् की थी, वह विकसित थी। हां, खाली भूमि दिये जाने का तो प्रावधान है कि कोई रिक्त पड़ी हुई भूमि है वह राज्य सरकार चाहे या कलक्टर चाहे तो यू.आई.टी. को दे सकता है पर जहां पहले पट्टे जारी हो चुके हैं, वर्षों पहले जारी हो चुके हैं, उसमें यह किया जाना उचित नहीं था।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला कहां से चालू हुआ। मेन मुद्दा तो यही है अभी। 2017 में रिवाइज प्लान के लिये नगर परिषद् पाली ने नगर नियोजन को एक पत्र लिखा। तब नगर नियोजन ने लिखा कि यह आपके रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जबकि 1988 में ही साइट एण्ड सर्विस योजना के तहत एक योजना वहां बनकर 149 लोगों को भूखण्ड आबंटन किये जा चुके थे और यह प्लान भी नगर नियोजन जोधपुर ने ही मंजूर किया था। 1988 में जब यह ट्रांसपोर्ट नगर योजना बनी जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार आपका काम कर रही है न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरी पूरी जानकारी एक बार बता दूं।

श्री अध्यक्ष: सरकार पूरा काम कर रही है, अब उसको विस्तृत करने से क्या फायदा? वह करने के लिये तैयार हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह सारा एक छोटी-सी भूल की वजह से हुआ है। मेरा माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह रहेगा कि आपने परीक्षण पूरा करवा दिया कि यह नगर परिषद् की भूमि है, आप वापस नगर परिषद् को दिलवा दो। यही मांग कर रहा हूं, कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नगर विकास न्यास के अध्यक्ष द्वारा संबंधित मंत्रीजी को जो आवेदन दिया गया था, उसमें मंत्रीजी ने बाकायदा यह लिखा कि इसका परीक्षण करके यह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस पर तत्कालीन ए.सी.एस. यू.डी.एच. के द्वारा जो पत्र कलक्टर को लिखा गया, उससे यह सारी जमीन नगर विकास न्यास में ट्रांसफर हो गयी। सवाल यह आता है कि यह सारी सिवाय चक जमीन थी और सिवाय चक जमीन नगर परिषद् को अलाट नहीं हुई थी और न ही नगर विकास न्यास को अलाट हुई थी लेकिन नगर परिषद् ने वहां पर बाकायदा दोनों योजनाएं बना लीं। दोनों योजनाएं बनाकर पट्टे भी बांट दिये, सड़कें भी बना दीं, सब कुछ कर दिया। उसके बाद नगर विकास न्यास की जब स्थापना हुई तो उसके बाद में यह फिर परिवर्तन आ गया कि मंत्री ने यह इशारा कर दिया कि इसको दे दिया जाए और बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। यह सारा का सारा तो आपके वक्त में ही हुआ है, हमारे वक्त में तो कुछ हुआ नहीं। हम तो आपसे फिर भी यह निवेदन कर रहे हैं कि इस बात

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

की जांच करवा लेंगे। अगर इसमें कुछ हो सकता होगा तो निश्चित तौर पर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

शासकीय वक्तव्य

कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर लाखेरी के निकट मिनी बस के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना हो गयी, मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, जिस घटना के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, उस घटना के दो बिन्दुओं पर सरकार से अपेक्षा है। आप ध्यान दें - एक तो यह कि इस दुर्घटना की जांच कराने के संबंध में कोई निर्णय करें। दूसरा, क्योंकि छोटे बच्चे-बच्चियां हैं, उनके मां-बाप की मृत्यु हो गयी तो हमारा जो नोर्मल कंपनसेशन का दो लाख रुपये है, उससे अतिरिक्त राज्य सरकार और क्या उनके लिये वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करेगी और बच्चों को आगे पढ़ने के लिये क्या व्यवस्था करेगी, इसके संबंध में आप कुछ बात कहें तो ठीक रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब जहां तक इस जांच की बात का सवाल है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका कि सारे दस्तावेज, दुर्घटना का कारण, उस मिनी बस के जितने भी दस्तावेज थे, चाहे वह फिटनैस के थे, चाहे बीमा के थे और चाहे उसके अस्थायी परमिट के थे, इन सबकी जांच के लिये परिवहन आयुक्त के तीन अधिकारियों का दल वहां पर रवाना हो चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो परिवहन आयुक्त हैं न, अपनी गलती को छिपाने का प्रयास करेगा। आप वहां का जो भी सिटी ए.डी.एम. हो, उसको दे दो और वह 10 दिन में उसकी जांच करके रिपोर्ट दे देगा। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका सुझाव मान्य है।

श्री अध्यक्ष: बात मान ली है। आपकी बात मान ली।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जब मैं मेगा हाईवे पर बोला तो उठकर जाने की क्या जरूरत थी? उसको भी सुन लेते आप कि मेरी तकलीफ क्या है। आपकी तकलीफ को मैंने सुना। आप जिस तरीके का सोच रखते हो, मैंने माना और आप जिससे जांच करवाना चाहते हो, तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं। लेकिन कम्-से-कम मेरी बात तो सुन लेते आप कि यह मेगा-हाईवे किस तरीके का बना है। इस मेगा हाईवे को 2006 में आप लोगों ने बनाना चालू किया और 2008 में खतम किया। लेकिन पुलिया का हाल यह देखिए, मेगा हाईवे की पुलिया का हाल यह है। यह 1960 में बनी हुई पुलिया है, जिसको मेगा-हाईवे वाले ने नहीं लिया। यह गलती तो कम-से-कम अपने को मानना चाहिए कि रिडकोर कंपनी से आपने काम करवाना चाहा और उसने आपकी सरकार के साथ फ्राड किया। यह भी एक कारण रहा इसका। चन्द्रकांता जी ने जो बात उठायी कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकतीं। मैं मानता हूं इस बात को।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अपन उस मैरिट में नहीं जा रहे हैं। जिस तरह की गंभीर घटना हुई है, पूरे राजस्थान में एक मैसेज देने के लिये, कि हमने सदन में बैठकर चर्चा की और हम सब गंभीर हैं, उस स्थिति को हम छोड़ दें। अभी खाली इसी बात पर कि एक्स्ट्रा और क्या आप कंपनसेशन देना चाहते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने इसी बजट भाषण में घोषणा की थी कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रीगण भी होंगे और इस समिति का गठन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को दूसरी और सूचना देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इतने गंभीर हैं कि मैं नहीं जा सकता था, हालांकि कोटा शहर में थे, लेकिन कल मैं नहीं जा सकता था तो दो-दो बड़े-बड़े मंत्रियों को भेजा गया और कल मेरे साथ मुख्य मंत्री जी स्वयं जा रहे हैं इसको देखने के लिए।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जहां तक सवाल इस बात का है कि दो-दो लाख रुपये, तो दो-दो लाख रुपये तो इनिशियली उन्होंने घोषित किये हैं, अब उसके बाद जाकर के वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, कितनी डिमांड आती है, उन लोगों से बात करके, वो एक अलग बात है, वो करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपनी तरफ से ही घोषणा कर दो, क्या डिमांड की जरूरत है। इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सरकार इतनी कमजोर है क्या ऐसी घटना में भी? जो भी आप कर सकते हो वो कर दो घोषणा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा कटारिया जी, मैं आपके बीच में रास्ता निकालता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर भाषण देंगे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि बजट के समय में इस सम्बन्ध में और कोई घोषणा करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

एक प्रश्न जो हमारे माननीय सदस्य बलवीर सिंह लूथरा हैं, सदन चल रहा है उनके साथ कोई घटना हुई है, वो सदन के सामने अपनी बात कहना चाहते हैं।

सूचना

बलवीर सिंह लूथरा, श्री, माननीय सदस्य के साथ जयपुर में फोन छीने जाने की घटना

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल करीब पौने दस बजे सिविल लाइंस फाटक के पास खड़ा था, ओला टैक्सी का वैट कर रहा था। इतने में रेलवे स्टेशन की तरफ से जो रेलवे लाइन के पैरेलल सड़क आती है उससे एक बाइक आती है, उस पर दो जने सवार होते हैं। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरे, मेरे हाथ में जो एंड्राइड मोबाइल फोन था उसको छीन कर भाग गये। साहब, बड़े ताज्जुब की बात है, यह कानून व्यवस्था है? साहब, इस पर कार्यवाही करवाओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। एक विधायक हैं, क्योंकि सदन चल रहा है इसलिए विधायक के सम्बन्ध में हम सबकी चिंता है। कृपया आप निर्देश दें कि इस घटना की गंभीरता से जांच हो और इस तरह की घटना नहीं हो, उसके सम्बन्ध में।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिल्कुल जांच करवाएंगे साहब, लिखकर भी दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रगति विवरण व प्रतिवेदन। श्री धारीवाल साहब, ग्रामीण विकास वाला वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री वासुदेव देवनानी।

याचिका

फायसागर रोड स्थित पुलियाओं से नालों के पानी की निर्बाध निकासी हेतु पुनर्निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अजमेर शहर में फायसागर रोड स्थित पुलियाओं से नालों के पानी की निर्बाध रूप से निकासी सुनिश्चित करने के लिये उनका पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

रूट नं. 34 की बसों के रूट का रीको कांटा, मानसरोवर, जयपुर से बढ़ाकर मंगलम आनन्दा सिटी, रामपुरा रोड, जयपुर तक विस्तार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर (जयपुर) के यात्रियों के आवागमन हेतु रूट नं. 34 की बसों के रूट को रीको कांटा, मानसरोवर, जयपुर से बढ़ाकर मंगलम आनन्दा सिटी, रामपुरा रोड, जयपुर तक करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

रेवदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरोड़ी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरोड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अग्रेतर वाद-विवाद। श्री सतीश पूनियां।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं बजट 2020-21 पर अपने दल की तरफ से अपनी बात सदन के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस सदन में हम लोग बैठते हैं जो लोकतंत्र की एक ऐसी पाठशाला है जिस पर जनता की निगाह होती है। उसके द्वारा पारित कानून, उसकी मर्यादाएं, संविधान सब अक्षुण्ण रहे तो सबसे पहले मैं शहीद रतनलाल को श्रद्धांजलि देता हूं कि जिन्होंने भारत की संसद के कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से संघर्ष करते हुए शहादत पाई। साथ ही साथ मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने उस परिवार को संबल दिया।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की और उनका अंदाज अक्सर ऐसा ही होता है कि केन्द्र की सरकार, मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, यह सब उनके इशारे पर होते हैं।

(श्री सतीश पूनियां)

बजट जो रखा बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहां बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किये होंगे, मेरे बाद में कुछ बातें रखी जाएंगी लेकिन मुख्य मंत्री जी की सदन में और सदन के बाहर बोलने की आदत देखकर मुझे एक किस्सा याद आता है। एक लड़का कुंवारा था। उसके ताऊ और उसके पिताजी चर्चा कर रहे थे। लड़का जब घर में आया तो उसके कान में आवाज आई कि ताऊजी और पिताजी मेरी शादी की चर्चा कर रहे हैं। ताऊ ने लड़के को आवाज दी, बेटा, जा चिलम भर ला। लड़का पलट कर आया, बोला, ताऊ, चिलम तो भर लाऊंगा लेकिन जिक्र यह मेरी शादी का ही चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी भी शायद केन्द्र सरकार के, मोदी जी के फोबिया से ग्रस्त हैं और इसलिए उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की जी.एस.टी. से और नोटबंदी से। उन्होंने एक टूटा-फूटा शेर भी अर्ज किया कि, 'नोटबंदी पर मुंह खोलते नहीं जी.एस.टी. पर बोलते नहीं।' मैं उनको भी थोड़ा-सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि,

'देश के विभाजन की बर्बादी पर वो बोलते नहीं,
आपातकाल के झटकों पर मुंह खोलते नहीं,
राज के मजे लिए 50 साल,
महंगाई भ्रष्टाचार....
पूरा सुनो भाई, पूरा सुनो।
'राज के मजे लिए 50 साल,
महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी से देश रहा बदहाल,
फिर भी करते रहे शासन और कहते रहे हमारा शासन बेमिसाल,
यह कैसी फितरत है जादूगर, भोलीभाली जनता को ठग कर,
सब जानते हैं लेकिन जान कर भी सच बोलते क्यों नहीं,
देश के विभाजन की बर्बादी पर बोलते क्यों नहीं,
आपातकाल के झटकों पर मुंह खोलते क्यों नहीं।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस देश में दो बड़े क्रांतिकारी काम हुए, उनकी ओर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जिसका उल्लेख मुख्य मंत्री महोदय ने किया। इसमें खास तौर पर नोटबंदी और जी.एस.टी. का उल्लेख किया।

(श्री सतीश पूनियां)

(12.57 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करूंगा कि जी.एस.टी. पर 2010 में तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इसकी चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान इसको क्रांतिकारी कदम कहा गया। मैं यह मानता हूं कि जीएस.टी. और नोटबंदी के कारण इस देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हुए खासतौर पर नोटबंदी के माध्यम से नकली नोट समाप्त हुए, बैंकों में काला धन जमा हुआ और 99 लाख 49 हजार नये टैक्स पेयर बढ़े। सरकारी खजाने में इजाफा हुआ, संदिग्ध खाते बंद हुए, दो लाख 24 हजार ऐसी कंपनियां बंद हुईं और देश में 24 हजार करोड़ रुपये जमा हुआ। महात्मा गांधी जी के बारे में अक्सर, क्योंकि मुख्य मंत्री गांधीवादी हैं और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का, उनकी सब बातों का हम अमल करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि मेरी यह प्रबल कामना है कि मैं हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं, अच्छी बात है लेकिन सवा साल का इस सरकार का कार्यकाल यह अपनी बानगी कह देता है। सवा साल में अराजकता, अव्यवस्था, कमजोर वित्तीय प्रबंधन, बढ़ते अपराध, किसानों की आत्महत्याएं, युवाओं की परेशानी, रोती बिलखती माताएं-बहनें।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके मुताबिक इस बजट में सब कुछ है, मोदी जी के काम पर तोहमत है, घोषणाओं का पिटारा है, वायदों के जुमले हैं, खूब सारे सपने और सब्जबाग भी हैं, सब कुछ हैं लेकिन अर्थशास्त्री आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। मैं जितना इस बजट को समझ पाया, इस बजट में दलितों, आदिवासियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के आंसुओं का हिसाब जरूर नहीं है, बाकी सब कुछ है।

'हे जादूगर, तेरे बजट से तो स्कूल की किताबें बेहतर थीं,
देर से ही सही लेकिन समझ तो आती थीं।'

माननीय सभापति महोदय, यहां पर 7 संकल्पों पर जोर दिया गया है। मैंने 2019 के राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा सुना, 2019 के बजट को भी सुना। 2020 के अभिभाषण को भी सुना, बजट को भी सुना। बीच-बीच में जन घोषणा-पत्र को भी सुनता रहा और पढ़ता रहा। मैं सदन में प्रश्न काल से लेकर के तमाम चर्चाओं को जब सुनता हूं तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि 90 प्रतिशत ऐसे मामले जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया, या सरकार ने किसी न किसी घोषणा के बारे में बाहर भी जवाब दिया, उन पर

(श्री सतीश पूनियां)

अमल नहीं हुआ। जन घोषणा-पत्र, बजट 2019, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 2019 से लेकर पूरे सवा साल में 90 प्रतिशत घोषणाएं ऐसी थीं, जिन पर अमल नहीं हुआ। फिर भी सरकार कहती है कि बजट बेमिसाल है।

(13.00 बजे)

सभापति महोदय, 7 संकल्प लिए। इन 7 संकल्पों में से एक आपने कहा "नीरोगी राजस्थान।" मुझे लगता है कि राजस्थान में इस समय जितने रोगी हैं, उतने कहीं नहीं होंगे, तो रोगी राजस्थान। इसके बाद, आपने कहा कि सम्पन्न किसान। राजस्थान का किसान तो इस समय हलकान है। मैंने कहा, रोगी राजस्थान, किसान हलकान, महिला, बाल, वृद्ध सब हैरान। मजदूर, छात्र, युवा, जवान, सबके सब परेशान। आपने कहा शिक्षा का परिधान, मैंने कहा शिक्षा का हुआ चीरहरण, टूटे अरमान। बिजली, पानी, सड़कों का मान, यह आपका संकल्प था। सूखे नल, बिलों में करंट, टूटी सड़कें हर गली और हर गांव। आपने कहा कौशल व तकनीकी प्रधान, मैंने कहा हे जादूगर, कैसा कौशल, कैसी तकनीकी? सिर्फ छलावा और रोता राजस्थान।

सभापति महोदय, घोषणा-पत्र के वायदों से लेकर जिन 7 बातों का जिक्र मैंने किया, उसमें नीरोगी राजस्थान का जिक्र आपने किया। मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। आप अपने पिछले बजट को, पिछली सरकारों के बजट को देखें तो 12 प्रतिशत की वृद्धि से चलकर 3 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। केवल कोटा के जे के लोन की घटना इस सरकार के चिकित्सा विभाग की लापरवाही व संवेदनाओं को प्रकट कर देती है। आपने यहां पर बहुत चर्चाएं कीं। लेकिन आपने इस बजट में न तो सीएचसी के बारे में कहा, न पीएचसी के बारे में कहा और न ही सब सेंटर्स के बारे में कहा। आप उस पर मौन हैं।

आपने जनता क्लिनिक का जिक्र जरूर किया। इस बजट को मैंने देखा। दिल्ली सरकार के बजट को आपने कट, कापी, पेस्ट किया है जिसमें खास तौर पर चिकित्सा और शिक्षा में, क्योंकि उस सरकार ने उसको प्रचारित ज्यादा किया तो आपको लगा होगा कि इससे माइलेज मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि जनता क्लिनिक की जो घोषणा आपने पिछले बजट में भी की और अभी भी की, वह केवल लीपापोती की। उसमें न तो जनता थी, न ही क्लिनिक थी और न ही डाक्टर थे। यह सदन जब 10 तारीख को शुरू होना

(श्री सतीश पूनियां)

था तो आपने 8 तारीख को जयपुर में 3 जनता क्लिनिकों का दिखावे के लिए उद्‍घाटन जरूर किया।

इस पूरी दुनिया में योग को इतना महत्व मिला। आप नीरोगी राजस्थान की बात करते हैं। नीरोगी हिन्दुस्तान की बात करते हैं। इस योग को दुनिया ने अपनाया। 195 देश योग को अपनाते हैं। पूरी दुनिया योग को अपनाती है। 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। आयुर्वेद की महिमा आप मानते हो लेकिन इस बजट में न तो योग के प्रति, न आयुर्वेद के प्रति और न प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति किसी तरह का प्रावधान आपने किया।

सभापति महोदय, आपने फ्री टैस्ट का जिक्र किया। मुफ्त स्कैन और एमआरआई का आपने कहा लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल को छोड़कर इस तरह के सरकारी अस्पतालों में बेसिक जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आपने पिछले बजट में यह कहा कि नये हास्पिटल और ट्रोमा सेंटर्स खुलेंगे। 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। इनमें से किसी का भी अभी शिलान्यास नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुफ्त दवाओं के बारे में कहा कि यह दुनिया की बेहतरीन योजना है। उसमें भी केवल 14 दवाइयां उपलब्ध हैं। बाकी दवाइयां डाक्टर्स बाहर से लिख रहे हैं।

राजस्थान में आपने गुटखे और पान मसाले पर प्रतिबंध तो जरूर लगाया, लेकिन इस समय राजस्थान उड़ते पंजाब की तरह है। जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में बढ़ी है, उस पर सरकार पूरी तरह से अंकुश लगाने में नाकाम हुई है। नौजवानों को जिस तरह से नशे की लत लगी है, यह एक चिंताजनक पहलू है।

सभापति महोदय, दूसरा आपने संकल्प दिया सम्पन्न किसान। यह बात लगभग सभी सदस्य कहेंगे, सत्ताधारी दल के सदस्यों के मन में भी कदाचित जब वह अपने क्षेत्र में जाएंगे तो यह कसक जरूर रहेगी कि जिन्होंने 10 दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात की, उस बात का जवाब तो सरकार को सदन में देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, नौ नहीं, ऐसी हजारों, सैकड़ों आत्महत्याओं का अंबार इस कर्जे के कारण लगा। किसी न किसी कारण से वह किसान पिटता रहा। योजना आपकी थी, घोषणा आपकी थी, उस पर

(श्री सतीश पूनियां)

अमल नहीं हुआ। सरकार ने इस बजट में किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

सभापति महोदय, आपने भंडारण की बात की। अभी 3 लाख टन अनाज के भंडारण की आपने बात कही। उस स्कीम के लिए आपने एक हजार करोड़ का आबंटन किया लेकिन 50 प्रतिशत का भी भंडारण राजस्थान में नहीं हुआ है। आपने नई मंडियों का जिक्र जरूर किया लेकिन पिछले वर्ष में मात्र 12 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीद इस सरकार ने की है।

किसानों की इस समय जो सबसे बड़ी पीड़ा है, जिसका उल्लेख प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों ने किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली के बिलों में 833 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। उस पर सरकार मौन है।

आपने तीसरा संकल्प लिया महिला, बाल और वृद्ध कल्याण। आपने घोषणा की जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल, बच्चों के लिए पालना घर, महिलाओं के लिए आईटीआई और पोलीटेक्निक की स्थापना।

इससे बढ़कर भी राजस्थान शर्मसार हुआ कि अपराधों की दृष्टि से ढाई लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई। यह केवल इसी शासन में हुई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय, जनजाति, इसके प्रति सभी लोगों का रवैया सकारात्मक रहता है। जनजाति के लोग महफूज रहें, तरक्की करें, समाज की मुख्य धारा में रहें। यह आपकी सरकार की 2020 की प्रगति रिपोर्ट है जिसमें जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रगति रिपोर्ट कहती है कि कल्याण निधि का 55 प्रतिशत खर्चा आपने नहीं किया। विशेष केन्द्रीय सहायता जो जनजाति क्षेत्रों के लिए मिलती है, उसका 54 प्रतिशत खर्च नहीं किया। अनुच्छेद 275 (1) का 45.66 प्रतिशत खर्च नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, केन्द्र की प्रवर्तित जितनी योजनाएं हैं, उनका 73 प्रतिशत आपने जनजाति पर खर्च नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह शर्मिंदगी की बात है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से कहलवाया, 75 हजार रोजगार की बात की, 1 लाख 8 हजार पद अभी खाली हैं। अकेले 54 हजार केवल शिक्षा विभाग में

(श्री सतीश पूनियां)

खाली हैं। मैं यह समझता हूं कि आपने पिछली बार वोट बटोरने के लिए किसानों के कर्जे को एक हथियार बनाया था। बेरोजगारी भत्ता आपका दूसरा बड़ा हथियार था। सामान्य आंकड़ा आता है 27 लाख के करीब, लेकिन आपने केवल डेढ़ लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देकर इतिश्री कर ली। मजदूर कल्याण बोर्ड का आपने वादा किया था लेकिन वह पूरा नहीं किया।

सभापति महोदय, आपने पांचवां संकल्प लिया, शिक्षा का परिधान। जिस तरह से इस महकमे का राजनीतिकरण आपने किया है और आप सबसे ज्यादा परेशान हैं तो पाठ्यक्रमों से, महापुरुषों से परेशान हैं। इस महकमे में भगवा रंग अगर साइकिलों का होता है तो उससे परेशान हैं। महीनों तक वह साइकिलें पड़ी रहीं। उनका भगवा रंग था, इसलिए आपने नहीं बांटी। आपने बच्चियों को आजीवन मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। उसके बारे में आपने कहीं स्पष्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि बजट में केवल लोक लुभावने वादे करके बेटियों के साथ अन्याय किया गया है।

सभापति महोदय, छठा संकल्प आपका है, पानी, बिजली और सड़कों का मान। मुझे लगता है कि केवल मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलने से उस योजना की क्रियान्वित नहीं हो सकती जब तक कि आपकी नीति और नीयत स्पष्ट नहीं हो। आपने बिजली के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्कीम निकाली लेकिन राजस्थान के 60 लाख उपभोक्ता उस 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के बारे में आपसे जवाब जरूर मांगेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिक्र किया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का, जो आबंटन किया और जिसके प्रोग्रेस की आप बातें करते थे। आपने उसके बारे में पुख्ता तरीके से सदन को अवगत नहीं कराया।

राजस्थान की सड़कों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान फिर भी सौभाग्यशाली है कि 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। उन 18 वर्षों में लगभग पौने 2 लाख किलोमीटर सड़कें जो कुल राजस्थान की लंबाई है, उसमें से 64 हजार किलोमीटर सड़क केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रारम्भ हुई जिसका आनंद आप लोग ले रहे हैं। अभी भी जो प्रावधान हुआ है, वह पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ही हुआ है जिसके कारण सड़कों का निर्माण होगा।

(श्री सतीश पूनियां)

इसी तरह से, हमारी पिछली सरकार ने जो प्रारम्भ किए थे, मैं अपने क्षेत्र की भी बता सकता हूं कि जिन सड़कों का डामरीकरण नहीं हुआ था, हमने शिलान्यास किया, उस पर ग्रेवल सड़क बन गयी, पर डामरीकरण आज तक नहीं हुआ। हम बराबर जवाब मांगते हैं लेकिन विभाग ने आज तक जवाब नहीं दिया।

सातवां संकल्प आपने दिया, कौशल एवं तकनीकी प्रधान। केन्द्र की योजनाओं को कापी पेस्ट जरूर किया। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो एक आंकड़ा आप बताते हो, कौशल विकास के जरिये नौजवानों को पुष्ट करने का, उसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है। आपने कहीं न कहीं, किसी न किसी जिले को छोटी-मोटी रेवड़ी बांटकर इसमें आंकड़ों का मायाजाल जरूर बिछाया है, पर माइक्रो लेवल पर घोषणाओं को घोषित करके यह कहा जरूर है कि हम निश्चित रूप से इसमें कुछ काम करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे महकमे, कुछ ऐसे काम जिनका उल्लेख करना जरूरी था लेकिन उससे पहले आप केन्द्र सरकार पर तोहमत लगाते हो। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2019-20 के बजट का भार जो 46411 करोड़ था, 2020-21 में 46886 करोड़ हुआ जो 475 करोड़ रुपये अधिक है जो केन्द्र पर आप आक्षेप लगाते हो। केन्द्र की तरफ से जो सहायता आपको मिलती है, उसमें जहां पहले 100 रुपये में 11.45 रुपये मिलते थे, अबकी बार केन्द्र का योगदान 13.24 रुपये हो गया। मुख्य मंत्रीजी ने इसका उल्लेख अपने बजट भाषण में कहीं नहीं किया। प्रदेश में पूंजी निर्माण घटा है और मुझे लगता है कि विकास व्यय बढ़ रहा है।

जेण्डर बजट की बात आपने कही। यह अक्सर चर्चा होती है जब आधुनिक लोकतंत्र में समानता की, समता की बात करते हैं तो हमारी आधी आबादी है, उसके बारे में इस सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने इसी बजट में राजस्थान के 3 करोड़ किसानों को 3400 करोड़ रुपये से निपटाकर संविदा खेती का कानून थोपने की बात कही है। मैं यह मानता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, अच्छी सार्थक बहस करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मध्यम और सीमांत किसान हैं, इस संविदा खेती की आड़ में उन पर चोट नहीं हो जाए।

(श्री सतीश पूनियां)

नि:शुल्क दवाओं की संख्या तो 709 कर दी पर उसमें बजट की वृद्धि केवल 63 प्रतिशत की है, जो मामूली है। यहां पर राजस्थान की 1100 किलोमीटर सीमा लगती है और संवेदनशील भी है, विकास से महरूम भी है और कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार उनको विकास के सब्जबाग दिखाती है, लेकिन 133.33 करोड़ रुपये मात्र इसका प्रावधान करके आपने उनके सपनों पर पानी जरूर फेरा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण जो जरूरी है और आधुनिक युग में इनकी महत्ता है लेकिन आपने इनका बजट घटा दिया। उच्च शिक्षा में 322 करोड़ रुपये बताता है कि आप शिक्षा के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। मैं निवेदन कर चुका कि 75 हजार नौकरियों का वादा करके केवल 74 हजार, उसमें 30 हजार का रोलिंग और 53 हजार की नयी घोषणा, यह ट्रैक रिकार्ड बताता है कि छलावा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पूंजीगत व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और मात्र वर्तमान बजट में 9.58 इसी का उल्लेख किया गया है। पूंजीगत आय में भी घटोतरी हुई। राजस्व घाटा 28041 करोड़ 4 लाख रुपये हुआ, यह जीडीपी का केवल 3.19 परसेंट है जो एफआरबीएम एक्ट का उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन बातों का जिक्र किया मैंने लेकिन सबसे ज्यादा जो डवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी की गई है और इसके कारण काफी चीजों पर इसका इम्पैक्ट पडा है लेकिन आर्थिक तंगी का इस सरकार ने जो बार-बार रोना रोया उसका उल्लेख मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किया, लेकिन 23411 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से राशि है, जो कर वसूली की अटकी हुई है। 23411 करोड़ रुपये, माननीय सभापति महोदय, यह राशि चार विभागों के बजट के बराबर है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि एक से दस वर्ष जरूर हुए हैं पिछले एक साल में 12500 करोड़ रुपये की राशि है जिसका आपने कलेक्शन नहीं किया, 12500 करोड़ रुपये। आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों का बजट में आपने उल्लेख नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन राजस्थान के लिये महत्वपूर्ण महकमा है, आपने भी कहा लेकिन आपने उसके लिए बजट में प्रावधान कितना किया है 0.6, पर्यावरण के लिये 0.3, युवा और खेल के लिये 0.002,

(श्री सतीश पूनियां)

नगरीय निकाय के लिये 0.080, जनजाति विकास के लिये 0.330, पशुपालन राजस्थान का महत्वपूर्ण महकमा, उसमें प्रावधान आपका 0.600, उच्च शिक्षा का मैंने बताया। महिला बाल विकास 1.39, श्रमिक विकास के लिये 3.174 और पंचायती राज के लिये 4.930, आपने किसानों की कर्जा माफी का वादा पूरा नहीं किया, किसानों की बेरोजगारी दूर करने का वादा पूरा नहीं किया लेकिन कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करने का वादा किया था, बुजुर्ग किसानों को पेंशन का वादा किया था, फसल बीमा को मजबूत करने की बात कही थी। जिस तरीके से आपके मण्डी टैक्स की उम्मीद व्यापारियों को थी उसमें कोई भी किसी तरीके की रिलीफ आपने नहीं दी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 150 हास्पिटलों में 1000 बैड बढ़ाने की बात आपने की है। केवल 6 बैड प्रति हास्पिटल होता है जो न के बराबर है।

बाड़मेर की रिफाइनरी के बारे में मुझे लगता है कि केवल आपने लीपापोती की है।

बजट में जो आपने कर राहत दी है 130 करोड़ की, वह कर तो आप स्टाम्प ड्यूटी से बराबर वैसे ही वसूल कर लेंगे और 130 करोड़ रुपये की रेवेन्यू जो मिलेगी वह बिजली की दरों से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा, ऐसे अनेकों प्रावधान थे जिनके बारे में आपने वादा जरूर किया था लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरे।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह राजस्थान में जयपुर के बिलकुल पास का क्षेत्र है। पिछली सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि 1500 करोड़ से उस क्षेत्र के विकास की शुरुआत की, 350 करोड़ रुपये की सड़कें हम लोगों ने बनायीं। इतने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले, एक 'अ' श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला, आयुर्वेदिक औषधालय खोला, जालसू में सीएचसी खोली, जालसू में नयी पंचायत समिति बनी लेकिन उसके बाद पूरे सवा साल से मैं मंत्रियों के विभागों को चिट्ठी लिखता रहा हूं, अपनी बात यहां उठाता हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राजधानी की नाक के नीचे के इस क्षेत्र को आप निश्चित रूप से संरक्षण दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां तीन उप तहसीलें हैं। इनमें से एक उप तहसील को क्रमोन्नत किया जाए।

(श्री सतीश पूनियां)

हमारी सरकार ने डेढ़ करोड़ से एक सीएचसी बनायी, लगभग पांच सौ से सात सौ आउटडोर नियमित होता है। यह किराये के भवन में चल रहा है, नया भवन बनाकर हमने तैयार कर दिया, पिछले डेढ़ साल से वह उद्घाटन का इन्तजार कर रहा है। मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया कि आएं और फीता काटें और रोगियों को राहत दें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मंडियों की बात की लेकिन यह क्षेत्र पूरा आसपास का, दूध, पशुपालन और सब्जी के लिये विख्यात है। मेरे क्षेत्र में एक सब्जी मंडी की स्थापना करेंगे तो लगेगा कि निश्चित रूप से किसानों की आवाज आपने सुनी है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अभी समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आसपास के क्षेत्रों से बच्चे खास तौर पर पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए हैं जो पहले खेती का, पशुपालन का धंधा करते थे। इस बार हमारे क्षेत्र के बच्चों ने प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है इसलिये खास तौर पर दोनों पंचायत समितियों में एक-एक महाविद्यालय और एक बालिका महाविद्यालय जरूर खोलें।

सड़कें क्षतिग्रत हुई पड़ी हैं। खास तौर पर तीन सड़कें हैं, जालसू से नांगल लाडी, चौंप से राजावास, मोडी से सिरसली, बिहारीपुरा, भीलपुरा होते हुए अनोपपुरा।

माननीय सभापति महोदय, जेडीए का 56 करोड़ रुपये का एक फ्लाई ओवर हमने शुरू किया, काम चला लेकिन उसका काम अभी रुका हुआ है।

आमेर का इतना बड़ा कस्बा है वहां के अस्पताल को आप जिला अस्पताल का दर्जा दें। सेवापुरा में एक बड़ा कचरा डिपो है जिसके कारण से वहां की जनता परेशान है। बीसलपुर की परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में आप लागू करें और जो काम अभी चल रहा है उसको पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि भूगर्भ जल नीचे चला गया है, तो किसान मांग करते हैं काफी समय से कि बांडी नदी को यमुना से जोड़ा जाए। मेरे क्षेत्र में अनेकों सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें नये संकाय और विषय खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि आपने खूब

(श्री सतीश पूनियां)

घोषणाएं की हैं, हमसे भी पैसे लिये, स्वागत कक्ष के लिये 869 थानों के लिये 4 करोड़ 41 लाख रुपये विधायक कोष से लिये लेकिन इन स्वागत कक्षों में मैन पावर की जरूरत है। इसके लिए नयी भर्ती करें। आरएएस के लिये अभी बच्चे बैठे हुए हैं, व्याख्याता भर्ती के परिणाम के लिये बच्चे बैठे हुए हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपने कहा था कि यह पारदर्शी सरकार है लेकिन परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार ने और एसीबी की कार्यवाही ने इस पारदर्शी सरकार के उस पारदर्शीपन पर ताले लगा दिये। यदि जरा भी कोई इज्जत बची हो, जरा भी कोई मान-सम्मान बचा हो तो मैं समझता हूं कि यह तो बानगी है, फिल्म का ट्रेलर है। सवा साल में ऐसा हुआ तो बाकी चार साल में क्या होगा, आप देख सकते हैं। संविदाकर्मी अभी बाहर मिले। मुझे लगता है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिये जिसका उल्लेख आपने किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि:

यह ईन-मीन-तीन बजट है,

दिशाहीन है, मुद्दाहीन है,

कर्महीन है, दृष्टिहीन है, मतिहीन है,

गतिहीन है, अर्थहीन है, कर्महीन है,

सत्य विहीन है, संख्याहीन है,

परिणाम संगीन है,

इससे राजस्थान की जनता गमगीन है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 20 तारीख को हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण दिया। उस बजट में कुछ पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है। पहले मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपना जो बजट भाषण दिया था, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फिर मैं हमारे स्टेट के बजट पर आना चाहूंगा।

बीजेपी वाले यह कहते हैं- मोदी जी हैं तो मुमकिन है। GDP-lowest in eleven years, private consumption-lowest in seven years,

(श्री रोहित बौहरा)

investments-lowest in seventeen years, manufacturing-lowest in fifteen years, agriculture & production-lowest in four years तो मोदी जी हैं तो यह सब मुमकिन है, अदरवाइज जब हमारी सरकार थी तो ऐसे घाटे के सौदे कभी नहीं आते थे। आईआईपी जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडैक्स है, पिछले साल अप्रैल से दिसम्बर यह 4.29 परसेंट पर था, आज की डेट में यह 0.5 परसेंट पर है। हमारा पिछला चुनाव 2014 का जब हुआ तो मोदी जी ने बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कीं कि, साहब डालर टू रुपया कन्वर्जन 40 रुपया होना चाहिए। 2014 में जब हमारी सरकार गयी, तब डालर कन्वर्जन 59 रुपये का था, आज की डेट में 71.65 रुपये का डालर कन्वर्जन है। डालर पांच साल में सिर्फ 21 परसेंट बढ़ गया। फिर भी यदि 56 इंच का सीना चौड़ा करें तो भगवान ही जाने कि किस चीज पर सीना चौड़ा कर रहे हैं।

पिछले पचास साल में जो लोन हमारी सरकार छोड़कर गयी थी, वह था 53 लाख करोड़ रुपये का। इनकी सरकार ने पांच साल में 91 लाख करोड़ रुपये का लोन कर दिया। Per capita loan in these five years have increased by Rs. 27,200 per person throughout the country. It is shameful कि 53 लाख करोड़ रुपये से हम सीधे पहुंच गये 91 लाख करोड़ पर। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बड़ी-बड़ी बातें कीं। ढाई घंटे का बजट भाषण दिया और उसमें से निकला कुछ भी नहीं। परसों के अख़बार में मूडीज, जो कि वर्ल्ड वाइड रेटिंग एजेंसी है, उसने हमारी जीडीपी, जिसके लिए हमारी केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि हमारी जीडीपी 6.6 परसेंट से बढ़ेगी, वह आलरेडी एक-डेढ़ महीने में डाउनग्रेड हो गयी है। अब उसकी बात चल रही है कि नैक्स्ट ईयर 2020-21 में वह 5.4 परसेंट पर रहेगी।

पहली बार पचास साल में ऐसा हुआ है, जब इलेक्ट्रिक कन्जम्प्शन में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। The electric consumption throughout this country has decreased that means कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हुआ, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ, आपकी जितनी मैन्यूफैक्चरिंग थी, वह कम हो गयी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, यह किसी को पता नहीं। जीडीपी में दो सबसे बड़े पहलू होते हैं- एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। दोनों ही जब आपके इलेक्ट्रिक कन्जम्प्शन से गिर जाएंगे तो आप किस तरह से जीडीपी बढ़ाएंगे, यह भगवान जाने। केन्द्रीय मंत्री तो मेरे खयाल से जान नहीं सकेंगी।

(श्री रोहित बौहरा)

पिछली बार आपके बजट में कारपोरेट टैक्स में करीब 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का रिलीफ दिया गया था इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज को रिलीफ इसलिए दिया गया था कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लायमेंट बढ़ेगा और इसी से इस कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। मुझे बड़े दुःख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि 1.45 लाख करोड़ रुपये का आपने कारपोरेट को टैक्स तो माफ कर दिया, पर आपने बैंक से क्रेडिट फ्लो का सिस्टम खतम कर दिया। किसी को भी क्रेडिट फ्लो नहीं मिल रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को क्रेडिट नहीं मिल रहा है। सब सहमे हुए हैं। इस देश में सब सहमे हुए हैं कि कब सीबीआई आपके पीछे लग जाए, कब ईडी पीछे लग जाए।

कोई बैंक आपको लोन ही नहीं दे रहा। अब सिर्फ दो नेशनलाइज्ड बैंक्स बचे हैं जो आपको लोन दे सकते हैं- पीएनबी एवं एसबीआई और वे भी आपको लोने देने के लिए तैयार नहीं हैं तो किस तरह से यह जीडीपी बढ़ेगी, किस तरह से आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चालू होगा? ऐसा पहली बार हुआ है पचास साल में कि हमारे देश में हमारे दो टाइप के असैट्स होते हैं- एक असैट तो एनपीए हो जाता है यदि आप तीन महीने अथवा 90 दिन तक अपनी किश्त और इंट्रैस्ट का पैसा नहीं देते हैं तो आपका एनपीए हो जाता है। कई बार वह एनपीए से बच जाता है, वह कहलाता है स्ट्रैस्ड असैट। जब 2014 में हमारी गवर्नमेंट गयी थी तो पूरा जितना लोन था, वह करीब-करीब 12 परसेंट पर था। पिछले इलेक्शन से पहले यह फीगर हो गया 17 परसेंट, मतलब 17 लाख करोड़ रुपये के स्ट्रैस्ड असैट हो गये जो कभी भी एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। पहली बार हुआ है कि बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए जो एनपीए थे 11 परसेंट के, उन्हें सिर्फ 8 परसेंट रहने दिया। उनकी बैंक्स ने बैलेंस शीट में से साफ कर दिया और आज तक किसी भी आदमी का यह नहीं बताया गया, पूरे देश में यह छिपाया गया कि किन-किन इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एनपीए का पैसा माफ कर दिया गया। No banks have stated in their balance sheets कि किस तरीके से ये चुप-चाप किन इंडस्ट्रियल हाउसेज को यह केन्द्र सरकार आब्लाइज करना चाहती थी। आब्लाइज कर दिया और उनका आज तक नाम नहीं खोला। यह बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से देश चलेगा तो क्या होगा? जहां पैसा आपको देना चाहिए था, मनरेगा में आपको पैसा देना चाहिए था, जहां से कि कन्जम्प्शन बढ़ता, वह 'lower strata of society' में आप पैसा डालेंगे, वे अपनी मूलभूत

(श्री रोहित बौहरा)

चीजें खरीदेंगे, वहीं से कन्जम्प्शन बढ़ेगा, वह मनरेगा में आपने पैसा 7 परसेंट गिरा दिया। 61 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रोविजन किया जो पिछले साल 70 हजार करोड़ रुपये का था। 7 परसेंट से आपने उसका पैसा घटा दिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब-करीब 11 परसेंट, 10.9 percent to be more precise. आपने रुपया घटा दिया और फूड सब्सिडी में तो सबसे अच्छा काम किया।

जो हम किसानों की बात करते थे, एफसीआई का डेढ़ लाख करोड़ का बजट था, जिसे इस बार घटाकर 75 हजार करोड़ का कर दिया यानी 50 परसेंट बजट आपने एफसीआई का काट दिया जो 'Support Price System' आपने किसानों के लिए कहा था। आपने किसानों के लिए कहा कि हम पांच साल में उनकी इनकम दुगनी कर देंगे। ग्रोथ दो परसेंट की हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लास्ट ईयर 4 परसेंट डाउन था, पता नहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री को कौनसा सपना आ रहा है कि पांच साल में जो किसानों का 20 परसेंट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जिससे कि उनकी आय डबल होती, वह पैसा किस सपने में इकट्ठा होगा और किस तरह से किसानों के पास जाएगा।

आज रीजनल रूरल बैंक्स को आपको पैसा देना था उनकी कैपिटल बढ़ाने के लिए। पिछले साल यह 705 करोड़ रुपये का रीजनल रूरल बैंक्स जो कि किसानों की रीढ़ की हड्डी है, वही पैसा देती है, उसमें आपने 705 करोड़ से बजट कम करके 200 करोड़ रुपये कर दिया। जो एम्प्लायमेंट जनरेशन का बजट था, जहां से कि एम्प्लायमेंट जनरेट होता, स्किल डवलपमेंट वगैरह होता, वह आपने सिर्फ 1.44 परसेंट बढ़ाया है। किस तरह से आप यह करेंगे? कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का बजट केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 4.5 परसेंट से घटा दिया। हायर एजुकेशन का बजट सिर्फ 2.9 परसेंट रखा और जो सबसे बड़ा एम्प्लायमेंट जनरेशन है throughout the world i.e. textile sector. Textile sector में सबसे ज्यादा होता है यदि हम देखें तो जयपुर में टैक्स्टाइल का बहुत बड़ा सैंटर है 'madeups' हमारे यहां बनते हैं और करीब-करीब यहां पर दो से तीन लाख की लेबर आज जयपुर में लगी है।

टफ योजना चलती थी, जिसमें कि टैक्स्टाइल मिलों को पैसा सस्ती रेटों पर दिया जाता था, उसमें आपने कटौती की है सिर्फ 27 परसेंट की। टफ

(श्री रोहित बौहरा)

योजना बन्द कर दी। किसी तरह से भी जो कम इंटरेस्ट पर टैक्स्टाइल मिलों को पैसा मिलता था, वह बन्द कर दिया। अब हमारी टैक्स्टाइल मिलें किस तरह से जीएंगीं, यह टैक्सटाइल मंत्री जानें और केन्द्रीय मंत्री जानें। स्टार्ट-अप के इनोवेशन की जो पिछली बार बात की गई थी कि स्टार्ट-अप होंगे, लड़के पैसा कमाएंगे, अपनी स्टार्ट-अप करके बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बेच देंगे, किसी तरह से पैसा कमाएंगे, उसका बजट आपने 12 परसेंट कर दिया।

बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं कि हमारा हाईवे, एक ही मंत्री जी थे जो सेंटर में परफोर्म कर कर रहे थे हाईवेज एण्ड रोड्स वाले, उनका टार्गेट था 15 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का लास्ट ईयर। टोटल जो सड़कें बनीं वे 10 हजार 855 किलोमीटर की सड़कें बनीं। रेलवे की बड़ी बड़ाई हो रही है कि रेलवे में यह कर रहे हैं। आप का आपरेशनल रेशो 97.4 परसेंट हो गया और पेंशन और सैलेरी पर रेलवे सिर्फ अपने बजट का 66 परसेंट खर्च कर रहा है। फिर क्या तो डवलपमेंट होगा? यह सब राजस्थान में आएगा। (व्यवधान) जयपुर पर आ रहा हूं आप चिन्ता मत करो, आप तो बाहर जाओ। ये सुनना नहीं चाहते हैं, असली चीजें सुनना नहीं चाहते हैं।

हमारे तीन इंडैक्सेज हैं जो एक कंट्री को नापते हैं। ग्लोबल हंगर इंडैक्स, 103 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आपको जानकर बड़ा दु:ख होगा we are at 99^{th} position. We are below Bangladesh and Pakistan. It is shameful. जो डैमोक्रेटिक फील इंडैक्स था, सीएए के बाद हम दस पायदान नीचे गिर गये। ये समझेंगे नहीं। हमारी कंट्री की जो सावरिन रेटिंग थी, वह इतनी गिर गई है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि वह क्यों गिरी है। सोशल मोबेलिटी इंडैक्स, हम 82 कंट्रीज में 76 नम्बर पर हैं। इन पांच साल में हमारी इकोनोमी जितनी नष्ट हुई है वह हम सोच भी नहीं सकते उतनी हमारी इकोनोमी को नष्ट कर दिया गया।

दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि जो फिस्कल डैफिसिट था, बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं कि एफआरबीएम एक्ट के अन्दर हम उल्लंघन नहीं करेंगे, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बोला कि उल्लंघन नहीं करेंगे पर इस बार जो हमारा फिस्कल डैफिसिट था that has crossed. 3.5 की जो लिमिट थी वह क्रास कर चुके हैं और आज की डैट में 3.8 परसेंट हो गई। इस साल उन्होंने इसको कम करने की कोशिश की है 3.5 परसेंट। पहली बार ऐसा हुआ है जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में रिमार्क किया है कि इसमें पारदर्शिता लायी जाए। वह

(श्री रोहित बौहरा)

पारदर्शिता इसलिए लायी जाए क्योंकि यह ऑफलाइन बजटिंग, जो इनकी पावर फाइनेंस कारपोरेशन हैं, जो इनके फूड कारपोरेशन हैं जिनका ये पैसा बाजार से उठा लेते थे और किसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे देते। इसमें से कोई पैसा कैपिटल असैट बनाने के लिए खर्च नहीं करते थे। सीएजी ने रिमार्क किया है कि आप इसमें पारदर्शिता लाएं तो यदि इन्हीं के फाइनेंस सैक्रेटरी सुभाष गर्ग जी ने एक ब्लाग लिखा, उसमें बोला कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है i.e. more than five and a half percent और जिस तरह से यदि यह होता रहेगा तो हमारी सावरिन रेटिंग कम हो जाएगी तो हमारे शेयर बाजार में जो बाहर से पैसा आता है या जो इन्वेस्टर्स आते हैं इन कंट्री में वह इन्वेस्टमेंट आना बन्द हो जाएगा। फिर तो यह सोच लीजिएगा, जीडीपी का आप सोच ही नहीं पाओगे, निगेटिव में जीडीपी का चला जाएगा जिस तरह से यह सरकार चल रही है।

इसके अलावा, आज 3 लाख करोड़ की देनदारी केन्द्रीय सरकार की है। 3 लाख करोड़ की देनदारी किसकी है? प्राइवेट सैक्टर की है, गवर्नमेंट एम्प्लोयीज की है और करीब-करीब कारपोरेट्स पीपल, यानी पूरे कंट्री की आज 3 लाख करोड़ की है बट वह क्यों नहीं आ रहा इस बजट में? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस है कैश बेसिस। बिल्स पड़ जाते हैं साइड, कैश बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। वह 3 लाख करोड़ का आप और ले लो तो यह डेफिसिट साढ़े 5 परसेंट से बढ़कर यह डेफिसिट कम से कम 7 परसेंट पर पहुंच जाएगा। यह तो हाल है साहब, बट, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, वह मैं मानता हूं कि कुछ चीजें अच्छी की हैं। एक सावरिन फण्ड्स को लेकर आये हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर में और इन्होंने 22 हजार करोड़ रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर में दिया है। उसको हम लिवरेज करके कम से कम एक लाख करोड़ पर ले जाएंगे जो प्रधान मंत्री जी ने बोला है, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। जो चीज अच्छी की है वह भी आपको बता रहा हूं। एक लाख करोड़ का जो इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का है, 22 हजार करोड़ को लिवरेज करके यह एक लाख करोड़ पर ले जाएंगे उससे ये सावरिन फण्ड्स से कम से कम इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आपका बिल्कुल बैठ गया था वह शुरू हो जाएगा। 5 करोड़ की टर्नओवर वाली कम्पनीज थीं, जो कैश बेसिस पर काम नहीं करती थीं उनको आडिट से आपने बचा दिया। फार्मर्स को जो सोलर पम्प सैट्स दिये हैं, तीन काम बहुत ही अच्छे किये हैं केन्द्र सरकार ने, वे आपके किये हैं।

(श्री रोहित बोहरा)

एक चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि फिफ्टीन्थ फाइनेंस कमीशन को केन्द्रीय कैबिनेट ने एक दिया कि आप डिफेंस और इंटर्नल सिक्योरिटी, आप यह बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। They want that money from the Central Pool for defence और यह, जबकि केन्द्रीय कैबिनेट को कोई राइट नहीं है यह मांगने का, क्योंकि यह पहले ही हमारे कांस्टीट्यूशन में हमें बता दिया गया है कि स्टेट कहां खर्च करेंगे और सेंटर कहां खर्च करेंगे। यह पहली बार हुआ है जो उल्लंघन हो रहा है।

दूसरी चीज, जो आपके अध्यक्ष जी यहां बोलकर गये और अब निकल गये। पहली बार हुआ है कि फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट आई है, जो राजस्थान का शेयर था 42 परसेंट, that has been reduced to 41 percent. वे कहकर गये कि पैसा बढ़ गया। आज अगर 42 परसेंट होता तो हमारा पैसा कितना बढ़ता उसको वे कहना भूल गये। मेरा कहना यह है कि कहना बहुत आसान है, आज देश की हालत गम्भीर है। आपको, हमको, सबको बैठकर चिन्तन करना पड़ेगा कि किस तरह से इस देश की दशा सुधारी जाए।

अब मैं आपको स्टेट के फाइनेंसेज के बारे में बताना चाहता हूं। जब हमारी सरकार गई थी, हम साढ़े 12 हजार करोड़ का आपके पास रुपया ट्रैजरी में छोड़कर गये थे। आपकी सरकार आई, पांच साल चली, आपने जो किया वह आप जानें पर आप हमारे ऊपर 3 लाख 10 हजार करोड़ का लोन छोड़कर गये। 3 लाख 10 हजार करोड़ में आपने उदय स्कीम में इतना पैसा उठा लिया, आपने क्या किया कि हमारी बिजली कम्पनियों की तो हालत खराब थी, उसको हम ऑफलाइन बजटिंग से तैयार कर सकते थे, बट, क्योंकि यहां तो फरमान ऊपर से आता है न, स्टेट को सोचने ही नहीं दिया जाता है। आपने उदय स्कीम में शार्ट टर्म में पैसा उठा लिया। यह कहकर पैसा उठा लिया कि जितने लोसेज होंगे वे हम रिड्यूस करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी के लोसेज थे वे आपको रिड्यूस करने की बात थी तब आपको उदय स्कीम में पैसा मिला। आपने स्कीम चालू की। जब आप गये तब आप वह लोसेज रिड्यूस नहीं कर पाये। आज जो स्टेट की दशा है, जो मेरे पूजनीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा था पिछले अपने भाषणों में कि अब आप लोन क्यों ले रहे हो? लोन तो हमें इसलिए लेना पड़ेगा कि आप इतना इंटरेस्ट का बर्डन छोड़ गये हो तो उसी इंटरेस्ट की बर्डन के लिए ही तो हमें लोन लेना पड़ेगा।

(श्री रोहित बोहरा)

आज कम से कम पांच साल में आपने तेल के कुएं जिनसे हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता था और पोटाश, जो हमने नई खोज की है, उससे हम मैक्सिमम रेवेन्यू लेकर आएंगे, आपने उन दोनों की खोज की है। हमने 13 कुओं की परमिशन दे दी है एक्सप्लोरेशन के लिए, जिससे कि रिफाइनरी लग सके। इस साल बजट में 500 करोड़ रुपये हम रिफाइनरी को देंगे। आज रिफाइनरी में हमारा 26 परसेंट इंटरेस्ट है, उस डिवीडेंड से ही हमको कम से कम हजार-दो हजार करोड़ आ जाएंगे यदि हमारे डाउन स्ट्रीम पैट्रो केमिकल्स प्रोजेक्ट्स टाइम पर लग जाएंगे।

मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आज स्टेट का 71 परसेंट पैसा सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ 9.58 परसेंट पैसा खर्च कर रहे हैं। आप क्या करके गये? आप भी वही करके गये। पहली बार हुआ है कि कम से कम मुख्य मंत्री महोदय ने जो रेवेन्यू डेफिसिट है, we have got down the revenue deficit from last year from 2.7 percent to 1.1 percent. We are trying to contain it. ऐसे ही करेंगे, हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हमारे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, पोटाश प्रोडक्ट्स से, हमारी जो रेवेन्यू बढ़ेगी उससे। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था 3.17 परसेंट का, We have got it through the FRBM limit of 3 percent.

आज एम्प्लायमेंट की इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है। मुख्य मंत्री जी ने करीब-करीब 53 हजार नौकरियों का एलान किया। पिछले बजट से पहले हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक नई पालिसी दी। इस नई पालिसी से करीब-करीब 7 हजार 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेट में आ गया, 3300 नई यूनिट्स आ गईं। इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं उनका एक चीज पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। मैंने उस दिन भी बोला था एनवायर्नमेंट क्लियरेंस हमें टाइम से चाहिए। आज environment clearance- ‘Consent to Establish’ हमें नहीं मिल रही है। हमें नहीं मिलेगी तो बैंकिंग लोन भी हमें नहीं मिलेगा without ‘Consent to Operate’ तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से कहूंगा कि वे एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री से बात करें कि ‘Consent to Operate’ मिल जाए तो ये 300 जो यूनिट्स हैं, जो अभी तक बैंक लोन से वंचित हो रहे हैं, इसमें से आधे यूनिट्स, उनको बैंक लोन मिल जाएगा जिससे आपका एम्प्लायमेंट का फीगर बढ़ जाएगा।

(श्री रोहित बोहरा)

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारी सिक यूनिट्स थीं, जो बिक नहीं पा रहे थीं। लोगबाग़ उन सिक यूनिट्स को वापस नहीं करना चाह रहे थे। बजट के अंदर मुख्य मंत्री महोदय ने स्टाम्प ड्यूटी की घोषणा की कि बेचान पर कोई स्टाम्प ड्यूटी चार्ज नहीं होगा, वह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे भी आपका एम्पलायमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगा। आज दो हजार करोड़ रुपया हम अपने बिजली तंत्र पर, अपने सब स्टेशन्स को चालू करने में खर्च करेंगे, जिससे कि जो सुबह की बिजली है, लोगों को रात में अपने खेतों में पानी देना पड़ता है जीरो डिग्री पर, वन डिग्री पर, ये पूरे राजस्थान में extreme type of climate है। आप सबको पता है तो आज कम से कम यह हो जाएगा कि हमारे किसान भाई सुबह की दो पारी में ही पानी अपने खेतों में दे पाएंगे जिससे कि उनको ठण्ड महसूस नहीं होगी। वे रात में अपने घर पर सो सकेंगे।

पहली बार हुआ है भले ही जीडीपी में ग्रोथ इस साल हमारी 5.5 परसेंट रही हो but the per capita income of the person in Rajasthan has increased by 7 percent. जो हमारी per capita income है वह आज हो गई है 1 लाख 18 हजार 159 रुपये पर पर्सन। जो हमारी रिसीट्स हैं, जो आज हमारे सेन्टर और स्टेट से आती है, 56 परसेंट तो आन रिसीट्स आती हैं, 44 परसेंट हमारा शेयर सेन्टर से आता है। यह इस बार 10 हजार करोड़ से रिड्यूस, जो सेन्टर से हुई वो इसलिए हुई क्योंकि 90 परसेंट जो devolution से आता था वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया, वह 10 हजार करोड़ हमें कम मिला और 10 हजार करोड़ कम की जो हमारी बात हुई थी, जो उप नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे कि हमें wage and means में जाना पड़ेगा, हमें ओवरड्राफ्ट में जाना पड़ेगा तो यह तो समझें, क्यों जाना पड़ेगा। आज 10 हजार करोड़ एक स्टेट के काट लिए एक झटके के अंदर, उसका बेसिक रीजन ही यही है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, पांच मिनट लूंगा।

दूसरी चीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने बड़ी-बड़ी बातें कीं, पीएचसी का कोई बजट नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा बजट ही नहीं पढ़ा, यदि पूरा बजट पढ़ते तो यह नहीं कहते कि

(श्री रोहित बौहरा)

कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। This year we will be constructing 100 PHCs, 54 CHCs buildings, 103 Sub Centre buildings, 500 नये जनता क्लिनिक इस बार एस्टेब्लिश होंगे और 12 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ लैब्स चालू होंगी और शुद्ध के लिए युद्ध, जो नीरोगी राजस्थान का एक बहुत बड़ा सम्बल बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हम एक लैब सैट-अप करना चाह रहे हैं।

आज जो बच्चों के लिए किया, साढ़े पांच लाख बच्चों को आरटीई के थ्रू वजीफे मिलेंगे, 47 लाख स्टूडेंट्स को हम मिड-डे मील देंगे, 1 लाख 35 हजार गर्ल्स स्टूडेंट्स को, जो गार्गी पुरस्कार होता है, वह दिया जाएगा और जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार एक-एक लाख रुपया, तीन चार स्टूडेंट्स को पूरे जिले में मिलता है, जिससे कि हमारे बच्चों का सम्बल बढ़े, वह दिया जाएगा। 1650 गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी। 3 लाख 40 हजार लड़कियों को साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 31 हजार स्टूडेंट्स को लैप टाप की स्कीम के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जो अव्वल नम्बर से पास होंगी।

एक चीज और कही, यानी बड़े असमंजस में हैं कि किस तरह से फैक्ट्स को मरोड़ते हैं। बीजीपी अध्यक्ष महोदय ने कही, आपका सिर्फ जो पैसा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च होगा। पीडब्ल्यूडी का इस बार का बजट है 6 हजार 277 करोड़, उसमें से सिर्फ 1 हजार 50 करोड़ की मैचिंग ग्रांट जाएगी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च की जाएगी। 1215 करोड़ रुपये रूरल रोड पर खर्च किये जाएंगे, सीआरएफ पर 650 करोड़ खर्च किये जाएंगे, 1400 करोड़ एसआरएफ पर खर्च किये जाएंगे। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम फैक्ट्स को मोड़ रहे हैं। बजट पढ़ नहीं रहे हैं, बजट की सिर्फ कापी पढ़ लेते हैं, अंदर जाते नहीं हैं और फिर ऐसी-ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो लोगों को भ्रमित करने वाली हो।

पहली बार हुआ है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारी सोशल वैलफेयर स्कीम्स हैं, 182.21 Small and marginal farmers (SMF) को सम्मान पेंशन दी जा रही है। 3892.78 करोड़ चीफ मिनिस्टर ओल्ड ऐज पेंशन योजना है, 1716 करोड़ चीफ मिनिस्टर सम्मान विडो पेंशन है, पालनहार का पैसा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): ये सब पहलू दिये हुए हैं। ऐसे भ्रमित नहीं करें लोगों को, किस तरह से हम भ्रमित कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना-सा कहना था कि आप भ्रमित न करें।

आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज जो टोटल रिसीट्स हैं। इस बार ये क्यों हमारा रेवेन्यू डैफिसिट कम हो रहा है। टोटल रिसीट्स जो होंगी वे करीब 1 लाख 73 हजार करोड़ की होंगी। उसमें से 10.6 परसेंट, we will increase in SGST, वैट में करीब 5 परसेंट का इन्क्रीज लिया है, एक्साइज ड्यूटी पर 19 परसेंट का इन्क्रीज लिया और अदर ड्यूटीज पर 16 परसेंट का और लैण्ड रेवेन्यू में करीब 50 परसेंट का।

मैं मुख्य मंत्री महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि करीब-करीब उन्होंने 325 करोड़ रुपये धौलपुर लिफ्ट योजना के लिए इस बजट में दिये। 15 करोड़ रुपये मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लिए राजाखेड़ा में पूरे पाइपलाइन के लिए दिये। 500 करोड़ रुपये रिफाइनरी के लिए दिये तो मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। हमारा इस साल का जीडीपी 11 परसेंट बढ़ेगा और 5 परसेंट भी जो बढ़ा है। उसमें सबसे बड़ी ग्रोथ हुई हमारी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी का पोर्शन है, वह करीब 25 परसेंट है, मैन्यूफैक्चरिंग का 28 परसेंट है और सर्विसेज का 47 परसेंट है। The sectors over last years have grown by 5.7 percent, 2 percent and 6.9 percent respectively. तो मैं अपनी बात यही खतम करता हूं और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने पहलुओं पर जो बजट पेश किया है, बहुत ही शानदार और उम्दा बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि किस तरह से हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कम कर सकें जिससे हमारी पटरी पिछली गवर्नमेंट बिगाड़ गई थी, उस पटरी पर इस प्रदेश को ला सकें। जय हिन्द, राम-राम।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अभी राजाखेड़ा के हमारे मित्र सेन्ट्रल ही सेन्ट्रल की बात कर रहे थे। वे यह भूल गये कि यह विधान सभा है। राजस्थान की कुछ तो बात करते कि राजस्थान के बजट में क्या है।

सभापति महोदय, यह बजट आय-व्यय का केवल लेखा ही नहीं है। केवल लेखा होता तो केवल अधिकारियों का ही काम होता, आपकी और हमारी

(श्री अशोक लाहोटी)

जरूरत ही नहीं होती। यह तो एक संकल्प है और यह संकल्प इस बात का, इसका शाब्दिक अर्थ भी संकल्प है। यह संकल्प इस बात का है सभापति महोदय, कि यह जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए पाई पाई जन भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप जन कल्याण में हम लगायें, यही इस बजट का शाब्दिक अर्थ है।

सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी कहा था और आज भी मैं वे आंकड़े दुबारा बताना चाहूंगा कि ये मुख्य मंत्री जी का बारहवां बजट है और इस बारहवें बजट में आज तक मुख्य मंत्री जी ने 879 पेज, इस राजस्थान की विधान सभा में पढ़वा दिये या पढ़ लिये, 2816 इन्होंने बिन्दु पढ़े और सबसे बड़ी बात इन्होंने 2013 में जो बजट पेश किया था, वह सबसे बड़ा बजट था। सबसे ज्यादा घोषणाएं थीं, 321 घोषणाएं कीं, 113 पेज का बजट पढ़ा और अंत में कितने आए 21, मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल झूठी घोषणाओं से कोई फायदा नहीं होने वाला, ज्यादा घोषणाओं से भी नहीं होने वाला, जनता सब समझ रही है क्योंकि जितनी आपने ज्यादा घोषणा की, उतनी कम आई आपकी सीटें।

सभापति महोदय, मैं यदि इन 12 बजटों में कहूं तो कितनी ही हजार घोषणाएं कर दीं, कितनी अधूरी पड़ी हैं, कितनी तो ऐसी हैं जो उस बजट के कागजों से बाहर ही नहीं निकलीं और कितनी ही ऐसी हैं जो अगले वर्ष उसको नए नाम से दे दिया। जैसे पिछली बार महात्मा गांधी जी के 7 संकल्प दोहराए और इस बार महात्मा गांधी जी को भूल गए और एक गांधी परिवार का नाम लेकर आ गए और दूसरे 7 संकल्प दोहरा दिए।

सभापति महोदय, पिछले साल और इस साल की मैं यदि बात करूं तो मुख्य मंत्री जी ने 139 नई घोषणाएं और संकल्प इस विधान सभा में दोहरा दिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय बैठे हैं वे उनको बताएं कि यह मेहरबानी बंद कर दें। अब 21वीं सदी आ गई है, यह जादूगरी बंद करें, जनता के सौदागर बनना बंद करें और ईमानदारी से इस राजस्थान की भलाई के लिए यदि उनके मन में 1% भी कहीं है तो उस राजस्थान की भलाई पर आएं। इस पूरे बजट में आपने एक परिवार के तो दो-तीन जगह नाम बार-बार लिए पर मैं आज वास्तव में बड़ाई करना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी की, उनको तो फाइनेंस में एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं, वे तो आपके कांग्रेस के ही थे, कहीं उनका भी नाम ले लेते। कहीं पी.वी. नरसिम्हा राव साहब का भी नाम ले लेते। (व्यवधान) बाहर लिया था, यहां नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी साहब को भी याद कर लेते, उनके किए हुए 1-2 कामों को भी ध्यान में ले आते।

इतना ही नहीं, इस पूरे बजट को आप देखो तो राजस्थान में 33 जिले हैं और इस बजट में बाकी घोषणाएं हैं वह तो अलग हैं, 36 बार इस बजट में केवल और केवल जोधपुर का नाम लेकर जोधपुर को योजनाएं दी हैं अलग से। सामान्य योजनाओं से अलग से 36 योजनाएं हैं। इस बजट को देखो तो ऐसा लगता है कि यह जोधपुर नगर निगम का बजट है।

सभापति महोदय, यही नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका यह बजट जनता को गवारा नहीं है। इसमें किसानों की ऋण माफी नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, टिड्डियों से फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, विकास का कोई नया काम नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि आपका यह बजट जनता को गवारा नहीं है, चिड़ियों को घोंसला नहीं और पशुओं को चारा नहीं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की अभी बात की हमारे मित्र ने। वह बार-बार कह रहे थे केन्द्र सरकार ने यह किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के कारण ही राजस्थान सरकार का विकास का काम चल रहा है। मैं वह भी सारे बताऊंगा लेकिन आप यह देखो, इस पूरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट की मंदी की बात की मुख्य मंत्री जी ने लेकिन दिया क्या, कुछ भी नहीं। उलटा स्टांप ड्यूटी बढ़ाई है आपने। स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाकर पूरे प्रदेश में आपने उस मंदी को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। केन्द्र सरकार ने इसमें दिया है, 22000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट किया और वह लेवरेज होकर एक लाख करोड़ तक जाएगा। इतना ही नहीं, आपने तो केवल यह कहा था, यदि यह इसी तरह चलता रहा तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि यह पहली बार आप देखो बजट में, आप पिछले 13 बजट इनके भी देख लें और अब तक के सारे देख लें और आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, देखते आए हैं, आज तक कभी बजट कम नहीं आया है। पिछली बार 2,32,000 करोड़ का बजट था, इस बार आपने बजट 2,25,000 करोड़ का दिया है। हमारे यहां कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह 3.5 प्रतिशत माइनस है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आप जीडीपी की अभी बात कर रहे

(श्री अशोक लाहोटी)

थे। देश की जीडीपी 2,24,000 करोड़ है और राजस्थान की 11 लाख करोड़ लेकिन 11 लाख करोड़ में हमारी जीएसटी मात्र 5% है जबकि हम देश का सबसे बड़ा भूभाग हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा माइनिंग है। हमारे पास टूरिज्म है। हमारे पास सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसके बाद भी हम यह जीडीपी 6% पर छोड़कर गए थे, आप उसको 5% पर ले आए हो और जीडीपी की बैकबोन क्या है सभापति महोदय? एग्रीकल्चर, वह आज हमारा मात्र 25 परसेंट है। मैन्यूफैक्चरिंग, वह 28 परसेंट है, सर्विसेज 47 परसेंट है और यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यह केवल 5 परसेंट है और उद्योग, अभी बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं उद्योग के लिए, राजस्थान में उद्योग की हालत क्या है, सभापति महोदय, घटकर 2% पर आ गया है, 2 प्रतिशत पर जीएसडीपी का और 2017-18 में हमने इसको 5 परसेंट आपको दिया था। इसके बाद सर्विसेज आज 6.9 परसेंट है, हमने 8.4 परसेंट पर छोड़ी थी। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, आपने कहा पिछले वर्ष कि हमारा 28,041 करोड़ होगा। पहले आपने यह कहा कि 27,000 करोड़ का होगा, वह बढ़कर 28,041 करोड़ का हो गया। 3.8 प्रतिशत बढ़ा और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, इस बजट में एक जो चोरी की गई, इस बजट में यह कहा गया कि 12,345 करोड़ इस बार हमारा राजस्व घाटा रह जाएगा। मैं घूमकर वापस इसी बात पर आऊंगा। इस बजट में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि यह घाटा कम किससे हो रहा है। आपने लिख तो दिया, कम हो जाएगा, सदन को गुमराह भी कर दिया लेकिन यह कम किससे होगा, यह नहीं बताया। इसलिए लिखा यह है कि आपको अपना एफआरबीएम सैट करना था। एफआरबीएम सैट करने के लिए आपने लिख दिया कि हमारा घाटा कम होगा। इसमें यदि आप देखो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,85,000 करोड़ सेम है और आपके रिसीट बढ़ने की बजाय कम हो रही है तो यह घाटा कम कैसे हो सकता है सभापति महोदय? पिछले वर्ष आपने कहा कि 73,743 करोड़ रुपये हमारी रिसीट आएगी और आपके आरई में यह 4.6 परसेंट कम होकर 70,351 करोड़ हो गया, फिर घाटा कम कैसे हो सकता है, जब आपकी आय कम हो गई, खर्चा बराबर है। दूसरा आपने कहा, और इस बार हम इसको बढ़ाकर 77,030 करोड़ रुपये प्राप्त कर लेंगे। यह प्राप्त किससे कर लोगे, यह भी नहीं बताया आपने कि इस बार ऐसा क्या करोगे जिससे प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, सबसे गंभीर तो मैं आपको बजट एट ए ग्लांस के

(श्री अशोक लाहोटी)

पेज नंबर-7 पर ले जाना चाहूंगा। यह गड़बड़ी इन्होंने कहां की, आप यह देखो कि शायद पहली बार होगा बजट में और यह गंभीर अनियमितता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह बजट जिसने बनाया, सदन उनका नाम, पता मंगवाये और उनके खिलाफ यह तय करें सदन एकमत से कि वाकई यह अनियमितता है, यह सदन को गुमराह किया गया है। आप देखो 2019 के रिसीट में बजट एट ए ग्लांस के पेज नंबर-7 पर आपने लिखा, हमारी जीएसटी तो कम हो रही है क्योंकि उसका तो रिटर्न चला जाता है उसमें तो हेरफेर नहीं कर सकते, वह तो आपने एक्चुअल ले ली, 11 परसेंट कम हुई, लेकिन मुद्रांक एवं पंजीयन, आपका बीई भी 5350 करोड़ है और आपका आरई भी 5350 है। दोनों आंकड़े एक हैं। मैं तो यह कहूंगा सभापति महोदय, मैं नया हूं मुझे पता नहीं है, यह प्रिविलेज आना चाहिए इस पर।

दूसरा, आपने उत्पाद शुल्क सैल्स एंड एक्साइज में लिखा है कि 10,500 करोड़ बीई और आरई दोनों एक। सैल्स टैक्स आपने लिखा है 20,000 करोड़, पूरा 20,000 करोड़ आपने आरई में मान लिया। एक रुपये का भी फर्क नहीं है। फिर आपने लिखा कि टैक्स आन व्हीकल 5650 करोड़, फिर 5650 करोड़, यानी कापी पेस्ट तो करते पर कम से कम यह इतनी बड़ी गंभीर अनियमितता। इसके अलावा, आपने टैक्स एंड ड्यूटीज में लिखा 28,401 लाख, फिर इसमें वापस लिख दिया 28,401 लाख।

सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह कोई गंभीर चीज नहीं है इनकी नजर में लेकिन इस सदन के लिए बहुत गंभीर है कि इस तरह से आंकड़ों को केवल कापी पेस्ट करके लिख देना और बीई और आरई आज तक 50 साल में एक बार भी हुआ हो तो मुझे आप बता दें। बीई और आरई एक कैसे आ सकता है फिर तो आरई का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आपने जो बीई दिया उसको हमने पढ़ लिया।

इतना ही नहीं, यह इस जीएसटी का 36 परसेंट हिस्सा है राज्य में और उस 36 परसेंट हिस्से में राज्य की इस सरकार की अक्षमता और नोन गवर्नेंस के कारण 11% की कमी आई है फिर आपका घाटा कम कैसे हो सकता है? 28,000 करोड़ से 12,000 करोड़ कैसे हो गया?

सभापति महोदय, जीएसटी जो इस बार आप कह रहे हो कि कम होने के बावजूद भी हम इसको बढ़ाकर 28,000 करोड़ कर लेंगे। मैं दिसम्बर

(श्री अशोक लाहोटी)

तक के आंकड़े देता हूं। मैं फिर यह बता रहा हूं कि यह आंकड़े झूठे लिखकर लाए हैं जो इन्होंने कापी पेस्ट किया, उसमें भी दिसम्बर तक आपकी जीएसटी 16,000 करोड़ इकट्ठी हुई। आपने लिख दिया डेढ़ महीने में हमारी 26 हजार करोड़ हो गई। लैंड और राजस्व में 186 करोड़ इकट्ठा हुआ, आपने लिख दिया 404 करोड़ इकट्ठा हो गया। केवल डेढ़ महीने में इतना फीगर बदल जाता है। आपने लिखा कि 3,229 करोड़ होगा, अब 5350 कर दिया। दिसम्बर में आपका फीगर अलग है और इस रिसीट को आपने पूरी की पूरी झूठी रिसीट बताकर बढ़ाकर लिख दिया, ताकि आपका घाटा कम नजर आए और आप एफआरबीएम सैट कर लें।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आप यह देखो कि सरकार ने आंकड़ों में तो यह भी कहा कि 29,000 करोड़ में से 16,300 करोड़ ही ला पाए हैं और अचानक डेढ़ महीने में आपने इसको 26 हजार करोड़ कर दिया।

अभी हमारे मित्र 15वें फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे। यह 12 हजार करोड़ घाटा कम कैसे हुआ, वह मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने एक बात नहीं बताई कि 15वें फाइनेंस कमीशन में राज्य का हिस्सा 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.45 परसेंट हो गया और यह जो 6% बढ़ा है यह 6% तो केवल आंकड़ों में बढ़ा है और इससे आपको जो 36,000 करोड़ रुपये 14वें फाइनेंस कमीशन में मिले थे, वह इस बार 46,886 करोड़ रुपये मिलेंगे आपको और यह जो आपको 10,886 करोड़ ज्यादा जो मिल रहे हैं वह 30% की बढ़ोतरी केन्द्र सरकार के कारण हुई है। कम से कम इतनी तो शर्म कर लेते आप। इसकी बात तो रखते कि 15वें फाइनेंस कमीशन में हमारा हिस्सा बढ़ गया, उससे हमको फायदा मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इतनी ही नहीं, केन्द्र हमको इतनी बड़ी मदद कर रहा है। राजकोषीय घाटा आपने कम दिखाकर एफआरबीएम तो सैट कर लिया। आरई में जब आप एक्चुअल आओगे तो, सभापति महोदय, मैं आज अभी फिर कह रहा हूं कि आप मेरा भी नाम, पता और फोन नंबर लिख लें। अगले साल जब यह एक्चुअल में आएंगे तो जो इन्होंने आज इसको सैट करके दिखाया है, ईमानदारी से अगले साल वह

(श्री अशोक लाहोटी)

सामने आ जायेगा। इस साल तो इन्होंने अभी तक अपनी आडिट रिपोर्ट ही लागू नहीं की। 2017-18 की आडिट रिपोर्ट परसों आई है। 2018-19 की तो अभी तक आडिट रिपोर्ट ही नहीं आई। इसका फायदा उठाकर यह झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए इन अधिकारियों का नाम-पता जरूर लिखें।

(14.00 बजे)

इतना ही नहीं, गुजरात में जाकर कहते हैं कि यहां पर शराबबंदी है लेकिन यह हो रहा है। बिहार में शराब की टीम भेजी गई। शराबबंदी की बातें की गईं और इसी बजट में आप लिख रहे हो कि हम इससे 19 प्रतिशत राशि ज्यादा वसूल करेंगे, 12500 करोड़ रुपये वसूल करेंगे।

सभापति महोदय, पिछले बजट में 71,138 करोड़ रुपये आपको केन्द्र से मिले। 43 प्रतिशत राशि केन्द्र से मिली और आप कह रहे हो हमारा पैसा कम कर दिया। आपने जीएसटी कलेक्शन ही कम किया है तो ज्यादा कौन दे देगा आपको। आप खुद अपनी गलती मानो नहीं। आपका जीएसटी कलेक्शन तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बसों में घूम रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो परिवहन के भ्रष्टाचार में पड़ा है और आप केन्द्र से चाहो कि केन्द्र हमें पैसा देता रहे। आप घी पीते रहो और हम आपको पैसा देते रहें।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 14वें वित्त आयोग ने जो केन्द्र का पैसा दिया था, सत्ता पक्ष के सारे विधायक ईमानदारी से कह दें कि इनकी पंचायतों में कोई बिल बाकी नहीं है क्या। पंचायतों में 6-6 महीने से ट्रैजरी में बिल बाकी पड़े हैं, आज तक वह पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। उस पैसे को आपने कहां लगाया, वह भी सदन को बताओ। सदन को गुमराह कर रहे हो। टीए, डीए तक के पैसे नहीं हैं आपके पास।

सभापति महोदय, मैं अब आपको मेन बात पर लाना चाहता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। आपने बजट कितना भी दिया होगा लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या दिया उनको। हमारे विकास में कितना पैसा दिया? आपने 2 लाख 25 हजार करोड़ लिख दिया, हमारे विकास में इस बार आपने पिछले वर्ष से भी कम करके 39,981 करोड़ रुपये दिये हैं, जो बजट का 17 परसेंट है। अभी पूछ रहे थे कि आपने क्या किया, 2014 से 2019 में जब हमारी सरकार थी तो हमने 23.02 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा था, आप केवल 17 परसेंट पर इसको ले आये हैं। सभापति महोदय, आपका कुल रेवेन्यू खर्चा 1

(श्री अशोक लाहोटी)

लाख 85 हजार करोड़ है और इसमें से आपका 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये केवल सैलेरी, पेंशन और ब्याज पर जा रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, कल ही आपसे आशीर्वाद लिया था, पांच मिनट तो दो। सभापति महोदय, आप 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये सैलेरी में दे रहे हो और आपकी आय है 77 हजार करोड़ रुपये। यानी आप कर्ज लेते रहो और घी पीते रहो, इस सिद्धांत पर सरकार चलाना चाहते हो। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार को कांग्रेस पार्टी के मुखिया और सदन के नेता दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। राजस्थान में तनख्वाह देने के लिये भी पैसा आपके पास नहीं बचेगा, एफआरबीएम कितने दिनों तक सैट करोगे? अगले साल एक्चुअल आ जायेगा, बैंक आपको लोन नहीं देगी।

सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान की इन्होंने बात की। इसमें 14,700 करोड़ का बजट बताया लेकिन आपके पास कैपिटल तो मात्र 1400 करोड़ ही है। पूरे बजट का यदि आप देखो तो 0.62 परसेंट। इसमें आपने कहा कि हम 2000 करोड़ रुपये मेडिकल कालेज खोलने में देंगे। जब आपके पास कैपिटल ही 1400 करोड़ है तो 2000 करोड़ कहां से दे दोगे? उसमें भी केन्द्र ने आपको 2276 करोड़ रुपये दिये हैं।

अब आप किसानों की बात पर आ जाओ, बहुत वाहवाही लूट रहे थे। किसान और एग्रीकल्चर को-आपरेटिव दोनों में मिलाकर 11,441 करोड़ का आपने बजट दिया और इसमें आपके पास रेवेन्यू मात्र 259 करोड़ है राजस्थान की 10 हजार से ज्यादा पंचायतों के लिये, किसानों के लिये। इसमें आपकी ऋण माफी भी है और आपने पूरे बजट में 0.11 प्रतिशत किसानों की हिस्सेदारी रखी है। सभापति महोदय, इसमें भी केन्द्र का 740 करोड़ है।

मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। आपने महिला और बाल कल्याण की बहुत बात की। पूरे राजस्थान में कैपिटल में आपके पास केवल 39 करोड़ है। इससे पूरे राजस्थान की आधी आबादी का आप कल्याण करने जा रहे हैं, जो कि 0.017 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, मजदूर, छात्र, युवा, जवान की बहुत बातें हुईं। खेल और शिक्षा में पूरा मिलाकर 39 हजार करोड़ का बजट तो दिखाया लेकिन इस

(श्री अशोक लाहोटी)

बजट में आपने पिछली बार से भी कम करके 1350 करोड़, मात्र 0.62 परसेंट और इसमें भी आपको केन्द्र से 4,115 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास की बात करूंगा। यह ग्रामीण विकास तो डिप्टी सीएम साहब के पास है। इसमें आपने 13,328 करोड़ की घोषणा तो की, पर आपने कैपिटल पिछली बार से भी 2 करोड़ रुपये कम कर दी, 0.20 परसेंट है और आपको केन्द्र से 6397 करोड़ मिल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं सोच रहा था धारीवाल साहब तो बहुत पावरफुल मंत्री हैं, सरकार को वो ही बचाते रहते हैं। अब इनकी स्थिति आप देखो, घोषणा तो की 7,430 करोड़ रुपये, बजट दिया 0.54 परसेंट और बिन्दु संख्या 111, 148, 149, 153, 152, 157 और 158 पर जो घोषणा की ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह सारा पैसा स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का है और केन्द्र से 1913 करोड़ रुपये मिले हैं इनको।

सभापति महोदय, पीडब्ल्यूडी में 6,808 करोड़ की बात कर रहे थे। कैपिटल कितना है, 437 करोड़ रुपये और सबसे बड़ी बात उसमें 400 करोड़ की तो मुख्य मंत्री जी ने ही घोषणा कर दी। डिप्टी सीएम साहब के पास बचा मात्र 37 करोड़ रुपये। कौन तो विधायक जाये और कौन उनसे काम मांगे। 37 करोड़ में वह क्या काम कराएंगे। यह तो 99 करोड़ रुपये केन्द्र ने और दिये हैं उनको इसलिए थोड़ी-बहुत इज्जत बचेगी।

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं सीएम साहब के डिपार्टमेंट पर एक बात और कहना चाहूंगा। पुलिस पर कह कर मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट, अपराधों में राजस्थान नंबर वन, दलित अत्याचार में नंबर वन, साइबर क्राइम में नंबर वन। यह सारी रिपोर्ट हैं, मैं साथ में लाया हूं। महिला क्राइम में नंबर वन, भ्रष्टाचार के आंकड़ों में नंबर वन। आपने इसमें बजट को कितना बड़ा किया है, पुलिस के आधुनीकरण के लिये मात्र 8 करोड़ रुपये दिये हैं। उससे सब चीजें रुक जाएंगी? यह पूरे देश का सर्वे बता रहा है कि एससी, एसटी में सबसे ज्यादा खर्चा तेलंगाना कर रहा है और सबसे कम खर्चा 0.01 प्रतिशत केवल राजस्थान कर रहा है। यह एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी की हालत है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, अंत में मैं जयपुर शहर की सारी घोषणाओं को नहीं दोहरा कर इस बजट पर केवल दो लाइनें आपसे कहना चाहता हूं। इस बजट को मैं यह कह सकता हूं कि ''इस बजट में खुशियां कम और अरमान बहुत हैं। सदन में जिसे भी देखो बजट देखकर वह परेशान बहुत है। करीब से देखो तो यह निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की भी पहचान बहुत है।' सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। केन्द्र की जो फाइनेंशल स्थिति है, बहुत बड़ा हिस्सा हमको केन्द्र से मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान रखते हुए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मुख्य मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने रुक कर प्रतिपक्ष की ओर देखकर कहा कि कभी-कभी तो तालियां बजा दिया करो। ताली किसी ने नहीं बजाई ...(व्यवधान) आप सुनिए, आप जितना लंबा मैं बोलूंगा भी नहीं, थोड़ा-सा आप शांत होकर सुन लीजिए, मैं आंकड़ों पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे से पहले बहुत विस्तार में बहुत बड़े-बड़े आंकड़ों के साथ इस बात को सदन में रखा गया है।

इस बात का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि अगर विपक्ष कभी कोई सत्ता पक्ष की सही बात होती है उस पर थपथपी कर देता है तो वह उसी प्रकार होता है जब आप किसी दिशा में जा रहे हों और आप माइल स्टोन की तरफ देखते हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है इस प्रदेश को दिशा देने के लिये और जब हम सत्ता पक्ष के सदस्य कोई उन बातों पर ध्यान दिलाते हैं तो वह हमारी पार्टी की आलोचना की दृष्टि से नहीं दिलाते, हम ध्यान दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता को उन बातों से राहत मिले। इस बजट में जब मैं वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सारी बातें पैसे से ही सही नहीं होतीं। पैसा प्रदान करने से शफाखाना सही चलेगा, पैसा प्रदान करने से सारी व्यवस्था ठीक हो जायेगी, इस सदन में शिक्षा विभाग की एक घोषणा जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने की जिसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वित्तीय व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है मगर उस एक संदेश से,

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

प्रशासनिक व्यवस्था से क्योंकि वह बजट में कही गई है, उसका परिणाम दूर तक गया है, लोगों ने उसकी सराहना की है और उससे इस शिक्षा के माहौल में सुधार होगा। इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि जब हम स्कूल में थे, उस समय एनसीसी हुआ करती थी, उसमें भारत सरकार का पैसा लगता था और कुछ आंशिक पैसा लगता था। जब आज हमारा सारा युवा अनुशासन की दिशा से भटक रहा है तो क्या हमें एनसीसी पर ध्यान नहीं देना चाहिये। सदन में मैं इस बात को इतने तक ही रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं उन बातों के ऊपर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले दो भाषणों में उन समस्याओं के ऊपर ध्यान दिलाया है, उनको मैं केवल सामने रखूंगा ही नहीं, बल्कि सुझाव भी दूंगा। यहां विडंबना है कि आसन की जो व्यवस्था है, वह यह कहती है कि अंकित होगा या अंकित नहीं होगा। अंकित तो सब हो रहा है, अमल कौन कर रहा है? बात तो अमल की है। अगर हम इस बात से तसल्ली कर लें कि हमारे दस्तावेजों में सुरक्षित हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, 7 करोड़ में से हम दो सौ लोग यहां पर आकर अपनी बात रखते हैं। उससे आदमी को क्या मिल रहा है, उस बात को हमें देखना होगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं तीन-चार बातों के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा।

गाय को जिसे हम गोमाता बोलते हैं, मुख्य मंत्री जी ने नंदीशाला का उल्लेख किया है। आज स्थिति यह है कि शहरों में, सड़कों पर गायों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग मर रहे हैं, इसका समाधान कैसे हो? उन्होंने गोशालाओं को 500 करोड़ के अनुदान बांटने की बात की। मेरे पास सुझाव है, अंकित हो जाएगा, मगर सुनेगा कौन? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इसके ऊपर हमारी सरकार ध्यान दे। हमारा जो वन क्षेत्र है, बहुत कम क्षेत्र ऐसा है, जो जंगली पशुओं के लिए सुरक्षित है। उनमें हमारे खुले मवेशी चरते हैं, जबकि वह वन क्षेत्र है। इस वन का विभिन्न कार्यों में उपयोग करने के कारण, हमारी सरकार का 1 हजार 800 करोड़ रुपया कैम्पा का जमा है। मैंने पहले भी कहा है कि आपके जो फोरेस्ट एरिया हैं 100 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर के, अगर आपने दस-पांच क्लोजर बना दिये, जिसके ऊपर 35 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं लगते। उससे जंगल भी बचेगा और यह नंदीशाला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस पर कोई अमल करे।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

दूसरा है, भ्रष्टाचार। मैंने पहले भी सदन में इस बात का उल्लेख किया है। यह दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ था, राजस्थान में सड़कें नहीं होंगी, स्कूलें नहीं होंगी, मगर भ्रष्टाचार में और कानून व्यवस्था में स्थिति इस प्रदेश में बहुत बेहतर थी। आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से यह प्रदेश एक नंबर पर पहुंच गया है। मैं आसन के माध्यम से आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार में प्रतिदिन एक से अधिक केस भ्रष्टाचार के पकड़े जा रहे हैं। कानून लाएं। जो पकड़ा जाता है उसको तत्काल बर्खास्त करें, वह अदालत से लड़कर वापस आ जाए तो वह अलग बात है। नहीं तो यह भ्रष्टाचार की आग फैलती जाएगी और उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा।

रोजगार की बात की। मुझे खुशी है कि ये 53 हजार रोजगार प्रदान करेंगे। हमेशा स्वरोजगार योजना और कौशल विकास की बात की जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके समक्ष यह बात रख रहा हूं कि अगर युवाओं को दिशा मिलेगी, सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो वह क्राइम का क्षेत्र है। कौशल विकास उस क्षेत्र में हो रहा है। आप और हम लोग नहीं, जब रोजगार का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्राइम के प्रति, पढ़े-लिखे नवयुवक टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कोई साइबर क्राइम में लगा हुआ, कोई चोरियों में कर रहा है। जैसे आपकी पुलिस की व्यवस्था कमजोर होगी तो इसमें और ज्यादा लोग जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम इस प्रदेश के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा संभावना है।

मैं यह बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि डिमांड में फोरेस्ट पर चर्चा नहीं होगी। फोरेस्ट में व्यापक संभावना है, ट्यूरिज्म में व्यापक संभावना है रोजगार प्रदान करने की। मगर दुर्भाग्य से, जब 53 हजार भर्तियां आई हुई हैं। हमारे वन क्षेत्र को बचाने के लिए एक भर्ती नहीं हुई। शिक्षा विभाग में 40 हजार शिक्षक ले रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 70 हजार की कमी है, हम 40 हजार की भर्ती कर रहे हैं। उसमें कितना फर्क पड़ेगा, इसका मुझे पता नहीं। मगर उसमें से एक हजार की भर्ती अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट में करते तो पूरा नक्शा पलट जाता। अगर हम जंगल के साथ पर्यटन को जोड़ते हैं तो सरकार के इन्वेस्टमेंट के बिना बहुत बड़ी संभावना है, ट्यूरिज्म और वाइल्ड लाइफ में लोगों को रोजगार प्रदान करने की।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

तीसरी जो समस्या जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है। उन्होंने जिक्र किया, रेत माफिया का उल्लेख किया है। पिछले समय भी बात की, अभी भी ई-सैंड की बात कर रहे हैं। 2018 के बाद नीति बनायी, उसके कुछ परिणाम नहीं हुए। जहां तक रेत माफिया की बात है, उन्होंने पूछा कि भ्रष्टाचार की गंगा कहां से आरम्भ होती है? मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की गंगा इस विभाग में गंगोत्री से शुरू हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अंग्रेजी में एक कहावत है “You can’t fit a square peg in a round hole” माननीय मुख्य मंत्री जी जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की आग लग रही है। जब आग लगती है तो उसको फायर बिग्रेड से बुझाया जाता है। फायर बिग्रेड में पानी होता है। अगर फायर बिग्रेड से पानी की जगह कोई पैट्रोल छिड़कें तो आग नहीं बुझेगी, यह वन विभाग में हमारी स्थिति हो रही है। उसे रोकना पड़ेगा।

एक अन्य विषय, जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसके ऊपर डिमांड में चर्चा नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन कृषि है। विभिन्न योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी लेकर आये हैं। मैं कृषि के संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी सरसों की फसल नहीं आयी है। खरीफ चालू नहीं हुई है। अभी सरसों का बाजार समर्थन मूल्य से एक हजार रुपये कम है। गेहूं की बम्पर पैदावार होगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था अभी से सुचारु रूप से पूरी करनी पड़ेगी और जब सरसों का उल्लेख करता हूं। राजस्थान सरसों, मस्टर्ड का नंबर वन स्टेट है। समर्थन मूल्य पर खरीद करना उसका विकल्प नहीं है। विकल्प यह है कि राजस्थान के 25 सांसद, मैम्बर आफ पार्लियामेंट और राज्य सभा के सदस्य दिल्ली में यह करें कि आप out of proportion इस बड़ी तादाद में खाद्य तेल का इनपुट नहीं करें तो अपने आप ही सरसों का बाजार बढ़ेगा। मगर दुर्भाग्य है कि राजस्थान के सांसद कभी भी दिल्ली में इस विषय पर नहीं बोले। अगर वे बोलेंगे और इम्पोर्ट ड्यूटी बढाएंगे तो समर्थन मूल्य पर आपको खरीद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

एक अन्य विषय है पर्यावरण। जिसके ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। इस साल दो घटनाएं इस प्रदेश में घटित हुईं। एक टिड्डियों की, जिसका संबंध एन्वायर्नमेंट कंडीशंस से होता है। दूसरा, सांभर झील में जो पक्षी मरे। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद से पक्षियों की तादाद

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

80 प्रतिशत से ज्यादा कम हुई है, मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें मेरी रुचि है। बहुत सारे पक्षी तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस घटना से विचलित होकर वेटलैंड के डवलपमेंट के लिए वेटलैंड अथोरिटी बनाने की बात की, मगर बजट में इस बात के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप वेटलैंड के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये देते हैं तो उसमें काफी संभावना है। चिड़ियों को अगर संरक्षण देना है, वेटलैंड को देना है, सांभर में पक्षी मर रहे हैं, उसकी दिशा में कुछ काम करना है तो इसकी दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। आपने समय प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण सुना है उसके बाद जारी बहस सुन रहा हूं। इस बजट का रास्ता प्रगति एवं विकास की ओर नहीं जाता है। इस बजट भाषण में 2019-20 के बजट में की गयी घोषणाओं का कोई हिसाब-किताब नहीं है। नये बजट में सात संकल्प आये हैं। पिछले संकल्पों और जन घोषणाओं का क्या हुआ? जनता अभी तक इंतजार कर रही है। सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा मात्र चुनावी छलावा सिद्ध हुआ। बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को नौकरी जैसे नारों से युवाओं को छला गया है। यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस लाओ-गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी आई हैं-नई रोशनी लाई है, कांग्रेस लाओ-100 दिन में महंगाई हटाओ जैसे नारे देकर कांग्रेस ने पहले भी यह कार्य किया है। देश की एकता व अखण्डता हर भारतीय का धर्म है, परंतु इस नारे पर चुनाव लड़ा गया है। कांग्रेस के झूठे वादों व थोथे नारों से आम मतदाता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। ग्राम पंचायतों के सरपंचों के चुनाव परिणाम इसके संकेत हैं। सरकार पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव टाल रही है। जनता इंतजार कर रही है, अपनी वादाखिलाफी का परिणाम कांग्रेस को पंचायत चुनावों में भुगतना पड़ेगा। केवल भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर व केन्द्र की मोदीजी की सरकार पर दोषारोपण करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

मेरा निवेदन है कि आप केन्द्र की आलोचना बंद करें और यह बताएं कि 14 महीनों में आपने क्या किया? वाजपेयी जी की केन्द्र सरकार ने देश को फोरलेन से जोड़ा है। आज राजमार्गों पर यात्रा आसान हुई है। एक सामान्य आदमी भी जानता है लेकिन कांग्रेस के बंधुओं को दिखाई नहीं देता है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला गैस योजना में माता-बहिनों को गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना प्रधान मंत्रीजी ने बनाई है। प्रधान मंत्री आवास, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल विद्युत योजना केन्द्र सरकार की देन है। भैरोंसिंह जी शेखावत के समय बनी अंत्योदय योजना व काम के बदले अनाज योजना देश में एक आदर्श बनी है लेकिन कांग्रेस के मित्रों को केवल आलोचना करनी है। दलीय प्रतिबद्धता में हम केवल प्रतिपक्षी का दोष ही देखते हैं। यह लोकतंत्र में चिंता का विषय है।

प्रस्तुत बजट में मुख्य मंत्री जी ने डीएलसी में 10 प्रतिशत कमी करने, स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपने 6 महीने पहले आनन-फानन में डीएलसी की रेट 20 से 30 प्रतिशत बढ़ा दी थी। अब आपने 10 प्रतिशत कम कर दी। फिर भी डीएलसी की दरें 10 से 20 प्रतिशत ज्यादा है। जन-घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज मानकर लागू करने की घोषणा का क्या हुआ? जन-घोषणा पत्र में बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में क्या कहा गया था? क्या उसका पालन किया गया है? बजट में मेरे भीलवाड़ा जिले सहित पूरे मेवाड़ की उपेक्षा की गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी का जोधपुर से प्रेम अधिक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री तो पूरे राजस्थान के हैं। शासक का कर्तव्य है, वह सूर्य के समान होता है जो सभी को प्रकाश व आरोग्य देता है। शासक को भी वैसा ही रहना चाहिए। मां अपनी सभी संतानों में भेद नहीं करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मानवीय आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। माननीय शेखावत जी व वसुन्धरा जी के शासन में पूरे प्रदेश का विकास बिना भेदभाव किया गया था।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में सैंड स्टोन प्रचुर मात्रा में है परन्तु सरकार की पालिसी नहीं होने से अभी धंधा बिलकुल ठप-सा पड़ा है और सैंड स्टोन का व्यवसायी बहुत भयंकर मंदी से गुजर रहा है। माइनिंग की पालिसी नहीं है, इससे अवैध खनन बढ़ रहा है। प्रशासन अवैध खनन को बंद कराने की इच्छा नहीं रखता है।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

दूसरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी 70 किलोमीटर तक बहती है जिसमें अवैध रूप से बजरी का भारी दोहन हो रहा है। हमेशा दौ सौ, तीन सौ ट्रैक्टर, दौ सौ-तीन सौ ट्रोले, डम्पर हमेशा भरकर जा रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की भारी बढ़ोतरी हो रही है और लोकल माफिया पनप रहा है। अगर ये अवैध बजरी दोहन होती रही तो माफिया के डर से आम आदमी को जीने में भारी मुश्किल पैदा होगी।

मेरे क्षेत्र में इस साल भारी अतिवृष्टि हुई है। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में पूरी फ़सलें नष्ट हो गई थीं। सरकार ने गिरदावरी कराई, उसमें 80 परसेंट खराबा माना है परंतु अभी तक एक भी रुपया मुआवजा नहीं दिया है। पूरे क्षेत्र में अतिवृष्टि से सड़कें नष्ट हो गई हैं। पुराने समय में डीएमएफटी के फंड से रोड स्वीकृत हुए थे परंतु जैसे ही सरकार चेंज हुई रोडों पर गिट्टी डल गई थी, वह गिट्टी अभी है, डामर नहीं होने दिया, काम निरस्त कर दिए। अभी भी वह गिट्टी बिखर-बिखर कर साइड में हो गई और मोटर साइकिल पर निकलने वाले आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है।

मेरे क्षेत्र में अतिवृष्टि से जो त्रिवेणी चौराहे से सिंगोली रोड जाता है और मेरा आधा विधान सभा क्षेत्र इस नदी के उस पार है, इस बारिश में पूरी पुलिया बह गई थी। हमने क्वेश्चन भी उठाया था परंतु अभी तक कोई भी उत्तर नहीं आया है और वह पुलिया जैसी की जैसी है। चार-पांच महीने बाद वापस बारिश आ जाएगी। मेरे आधे विधान सभा क्षेत्र का कनेक्शन कट जाएगा परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने अभी जो बजट पेश किया, उसमें भी नदी की पुलिया के बजट की कोई घोषणा इन्होंने नहीं की है।

मेरे क्षेत्र में सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें 25 परसेंट भी डाक्टर नहीं हैं। मेरे यहां बीगोद कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है। जनसंख्या के हिसाब से मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। वहां पर 4 डाक्टर्स की नियुक्ति है, परंतु अभी एक भी डाक्टर वहां उपलब्ध नहीं है। अभी 10 तारीख को हमारे बीगोद में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बीगोद के पास में ही। रात को वहां ले गये मरीजों को लेकिन एक भी डाक्टर नहीं होने से, वहां पर शायद दो-चार आदमी और बच सकते थे लेकिन 11 आदमियों की डैथ हो गई और कितने ही आदमी घायल हो गए। वहां कुछ भी प्राइमरी स्टेज का भी इलाज नहीं हुआ।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारा मांडलगढ़ कस्बा नगरपालिका क्षेत्र है। वहां हास्पिटल है, उसमें 12 डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन चार डाक्टर हैं। बाकी डाक्टर और कम्पाउण्डर भी नहीं हैं। जो मंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, जब हास्पिटल में सरकारी डाक्टर ही नहीं होगा तो दवा कौन देगा? यह बहुत ही सोचने लायक बात है।

मेरे यहां बिजौलिया बहुत ही बड़ा कस्बा है। बिजौलिया में नेशनल हाईवे नंबर 28 निकलता है। आये दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। डाक्टर हास्पिटल में नहीं मिलते हैं। बिजौलिया से कोटा 80 किलोमीटर पड़ता है, भीलवाड़ा 90 किलोमीटर पड़ता है तो ऐसे मरीज को वहां ले जाने में कितना समय लगता है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर ट्रोमा सेंटर खोला जाए और वहां पर हास्पिटल में डाक्टर्स की पूर्ति की जाए जिससे आमजन को वहां सुविधा मिलेगी। वहां पर प्राइवेट हास्पिटल है। गरीब आदमी वहां इलाज नहीं करा सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो मिनट और लूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 ग्राम पंचायतों में एफएसएस है ग्राम सेवा सहकारी समिति की तरह। हमारे विधान सभा में जो मुख्य मंत्री जी या कुछ भी बजट में, लोन में छूट मिलती है, वह उनमें नहीं मिलती है। उनमें कोई सुविधा नहीं है। इन 6 पंचायतों की एफएसएस को जीएसएस में कन्वर्ट किया जाए तो उन किसानों को सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायतों में किसानों को ऋण मिलने में सुविधा होगी। अभी 24 तारीख को यहां पर घोषणा की थी कि विधायक के बिना प्रशासन लोकार्पण, शिलान्यास नहीं करेंगे परंतु 24 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र बिजौलिया में प्रशासन द्वारा स्कूल के हाल का लोकार्पण कराया गया। आपके आदेश यहां से होने के बाद भी अधिकारी उद्घाटन कर रहे हैं। अधिकारी, सरकार की बात भी मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। यह चिंता का विषय है।

सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मेरे विधान सभा मांडलगढ़ में स्टेडियम की जमीन नगरपालिका द्वारा कब की आबंटित कर दी गई है परंतु उसमें स्टेडियम बनाने के लिए बजट, इस बजट में भी आपने स्वीकृत नहीं किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

पर बहुत बड़ी जगह है, खेलों के लिए वहां पर एक स्टेडियम की घोषणा आज ही करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज की जो बसें संचालित थीं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे भीलवाड़ा से मांगरोल, मांगरोल से बडलियाज, सिंगोली, मांडलगढ़ होती हुई जोगनिया माता जाती थी। उसको बंद कर दिया है। कहने के बाद एक-दो दिन चलाई, फिर बंद कर दी। हमारे भीलवाड़ा से कोटड़ी, धनराय, महुआ, सकरगढ़ यह बस भी बंद कर दी है। रोडवेज डिपो मैनेजर को कहते हैं, कोई सुनता नहीं है। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी गांवों को जो असुविधा हो रही है, इसके लिए बसों को चालू कराया जाए। मैं अंत में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट जन विरोधी है, खोखला है व झूठ का पुलिन्दा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। Budget 2020-21 presented by the Hon’ble Finance Minister is pragmatic, prudent, visionary, inclusive, growth oriented and also wise. Hon’ble Finance Minister has tried to find a balance despite a depressed economy, rising inflation, low tax collection and environment of slow growth. With limited resources, the Finance Minister yet announced a wide array of schemes for several sectors, showing a commitment for development as a welfare state for the people of Rajasthan. "सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं।'' यह तो हमारा दूसरा बजट है। आगे-आगे आप देखिए, हमारी कर्तव्यपरायणता, संकल्पबद्ध राजस्थान के विकास के लिए है, वह आपको दिखेगी।

अभी जो अर्थव्यवस्था की हालत है, गिरती अर्थव्यवस्था, व्यापक मंदी का माहौल है acute economic slow down और सेंट्रल इसके लिए कोई corrective measures भी नहीं ले रहा। दो grave macro economic concerns हैं, demand side constraints, investment starved,12 चैलेंज हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

राज्य की अर्थव्यवस्था को सेंटर की अर्थव्यवस्था से अलग होकर नहीं देखा जाता, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। 'Four drivers of the Growth' होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, निवेश, निर्यात, उपभोग, सरकारी खर्च। निवेशकों में अनिश्चितता है। उपभोक्ताओं में असुरक्षा का माहौल है। निर्यात वृद्धि लगभग शून्य हो गई है। मांग और उपभोग की स्थिति पिछले कुछ सालों में सबसे निचले स्तर पर चली गई। भारत सरकार की योजनाओं के कारण, कार्यक्रमों के कारण खर्च कम हो रहा है, राजस्व वसूली भी गिर रही है। जीएसटी के कर संग्रहण की उम्मीद की अपेक्षा में एक से डेढ़ लाख की कमी आई है। जीडीपी भी गिरती जा रही है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है जिसका असर पूरे राज्य पर पड़ता है। इन सारे ग्रोथ स्टैग्नेशन के कारण पूरी, ओवरआल इकोनोमी स्टैग्नेशन में चली गई है, मांग ठप हो गई, उत्पादन ठप हो गए, चीजों के मूल्य बढ़ने लग गए। मुद्रा स्फीति जिसे हम महंगाई दर inflation rate कहते हैं 7.5 परसेंट पहुंच गई। बेरोजगारी भी इसी कारण बढ़ने लगती है।

सरकार के गैर कर राजस्व की भी बहुत बुरी दशा है। निवेश जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि एलआईसी वगैरह से सेंट्रल अलग तरीके से आय कर सकती हैं जैसे कि स्टेट नहीं कर सकते, उसमें भी यह कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। एलआईसी और बैंक आफ इंडिया में भारत सरकार ने शेयर खरीदे तो ओएनजीसी ने एचपीसीएल में सरकार के शेयर खरीद लिए। एक जेब से दूसरी जेब में, इससे कोई प्रभावी बदलाव तय नहीं है।

ओवरआल इकोनोमिक स्लो डाउन को जो यह ट्रांसलेट हो रहा है this is translating into job losses. बेरोजगारी के पिछले 45 साल में सबसे हाई आंकड़े आए हैं। स्टेग्नेट वेजेज हो गईं रूरल इंडिया में, कंजूमर स्पैंडिंग 40 वर्षों में, four decades के अंदर, 40 वर्षों में आपकी कंजूमर स्पैंडिंग सबसे ज्यादा गिरी लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे।

इकोनोमिक में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरी के साथ देखा जाता है। Macro economic- जितने भी पांच उसके कम्पोनैंट हैं उनके ऊपर आप बिलकुल विफल हैं। 'Virtuous Cycles' जिसे हम कहते हैं इकोनोमिक्स के अंदर increase in demand therefore consumption resulting in higher investment rate leading to higher job creation which

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

creates greater consumption drive is the need of the hour बहुत जरूरी है लेकिन भारत सरकार ने इसकी पालिसी के कारण, उनकी दमनकारी नीति के कारण यह सब कुछ साइड लाइन किया हुआ है।

विपक्ष के उप नेता ने आईएमएफ की एक नवीनतम रिपोर्ट को कोट किया था और कहा था कि कितनी बड़ी फांस को आगे करके हम गए हैं, लेकिन आपने सदन में अर्धसत्य रखा। आपने आईएमएफ की दूसरी रिपोर्ट को कोट नहीं किया। हम सात संकल्पों के साथ आए हैं। आप सात बार जीत कर आए, आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा सब मानते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं। बात रखने की आपकी जो कला है, जिस तरीके से अपने दल की बात रखते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट ने यह भी कहा and here I would like to quote, “Sharp economics slowdown in India” दूसरी बात उन्होंने कही- “they trimmed India’s growth estimate to 4.8 percent, citing stress in the non-banking financial sector and weak rural income growth.” इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया ”the re-assessment also reflects the impact of increase social unrest in these areas” आपके विभाजनकारी फ़ैसलों का असर, दूसरी रिपोर्ट और कहती है “domestic political climate affects external relations, indeed trade, indeed economy” उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहां आता है। इन सबसे क्या होता है कि हमारी जीडीपी गिरती है। आगे के फोरकास्ट में भी यह कहा गया है “the GDP is slow. Thanks to credit weakness. The key indicator or the lack of credit is slowdown of private consumption, slowdown of investment, slowdown of exports, growth and demand in the market.” Credit growth किसी भी इकोनोमिक साइकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, it’s very important for the growth आपका क्रेडिट टेकआफ नहीं हो रहा, it’s not happening in Industries. लोग क्रेडिट नहीं दे रहे slowdown in consumption हो रहा है जिसके कारण इण्डस्ट्रियल एक्टिविटीज हैपन नहीं हो रहीं। आप जब बार-बार जीएसटी के थ्री कम्पोनेंट्स को गिनाते हैं, कृषि, उद्योग और मैन्यूफैक्चरिंग, इसका असर भी उस पर पड़ता है।

आगे जीडीपी की बात आई। मुख्य मंत्री जी को जीडीपी और जीएसटी की चिंता है, राज्य सरकार की नहीं है। सभी राज्यों के योग से भारत देश की

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

जीडीपी बनती है। देश की स्वयं की कोई इंडिविजुअल जीडीपी नहीं होती है। भारत की अर्थव्यवस्था का राज्य की जीएसटी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। राजस्थान कोई अलग देश तो है नहीं। आपकी दमनकारी और इकोनोमिक क्राइसिस के कारण यह हो रहा है कि हमारे राज्य की जीएसडीपी गिरी। इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहे हैं, विकास उन्मुख परियोजनाओं के कारण इकोनोमी आगे नहीं जा रही है और परिणामस्वरूप रीयल जीडीपी आपकी गिर गई है जिसके कारण हमारी भी गिर रही है। इसका एक मुख्य कारण, यहां कहा कि नोटबंदी से बर्बादी पर बोलते नहीं, उस बर्बादी को यहां आंकड़े भी आईना दिखाते हैं जब आप कहते हैं कि तीन हजार कुछ की आपकी जीएसडीपी गिर गई। Demonetization से राज्य की जीएसडीपी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि 45 परसेंट हिस्सा भारत के अंदर अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर का है। कैश पर निर्भर रहता है फार्मर, किसान वर्ग जिससे मैं आती हूं, जिसकी आप बहुत बात कर रहे थे। एमएसएमई उद्योग, एमएसएमईज के लिए हम 19 का एक्ट लेकर आए हैं और अभी भी उसके अंदर जो चीज़ें माननीय मुख्य मंत्री जी खड़ी करने के लिए लाए हैं। लैंडलैस लेबर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आपने कमर तोड़ दी, भारी मात्रा में कारोबार बंद हुए। इकोनोमी पर असर पड़ा और राज्य की जीएसडीपी पर असर पड़ा।

इसी जीएसडीपी के अंदर आपने कहा, मैं चाहूंगी कि कोई तो इन बातों को लिखे। अंकल, सारी, प्रतिपक्ष के उप नेता, आपने कहा तो मैं तो आपकी व्यक्तिगत रूप से बहुत फरमा बरदार हूं तो मैंने खत लिख लिए। 2019-20, 10 लाख 24 हजार 304 करोड़। 2019-20 की आरई, 10 लाख 20 हजार 979 करोड़। 2020-21 में 11 लाख 33 हजार 298 करोड़, यह आंकड़े कहां से लेकर आ गए आप, कैसे इन आंकड़ों की पूर्ति करेंगे? मेरा आपके नेतृत्व पर व आपकी क्षमताओं पर अटल विश्वास है। आपको चाहे कोई भी अर्थशास्त्री जुगाड़ का कहे, लेकिन आप जब कहते हैं तो देखकर कहते हैं लेकिन आप जानबूझ कर अपने दल की बात रखने के लिए आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए आपको वह जुगाड़ के अर्थशास्त्री होने का तमगा देते हैं।

2019-20 का आंकड़ा आया, चैप्टर 14, पैज नम्बर 199, 14.66, 14वें फाइनेंस कमीशन के फार्मूले के मापदण्ड पर निर्धारित होती है, उससे निर्धारित हुई। 2019-20 की आर ई, जिसके अंदर आपने कहा 10 लाख 20 हजार 979 करोड़ का आंकड़ा आया, यह एडवांस एस्टीमेट के समायोजन होने

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

पर आया। चार प्रोजेक्शन पर जीएसडीपी आती है एडवांस, रिवाइज, रिवाइज टू और रिवाइज थ्री और चार साल में डेटा सैटल होते हैं। 2020-21 का आप बार-बार कह रहे हैं 11 हजार, आपने यह कर दिया, यह हमारी काल्पनिक नहीं है। हमने अपने मन से इसको 11 लाख 33 हजार 298 करोड़ पर नहीं टिकाया। यह फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का प्रोजेक्शन है 11 परसेंट, पेज नम्बर 77, उसके कारण यह आया है। यह वास्तविक चीज है। शीशे के महल में बैठकर पत्थर फैंकोगे, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी नीतियों के कारण यह सारा भट्टा बैठ गया और आप हमें ही कह रहे हैं।

जब सारे अर्थ पहले से तय हों तब सारे शब्द अपने अर्थ खो देते हैं। आप जान बूझकर आँख बंद कर लेते हैं। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। मैं राजस्थान की इकोनोमी पर दृष्टि डालूंगी। Total expenditure for 2020-21 is estimated to be Rs. 2,25,731 crore, 0.4 परसेंट का एक marginal इन्क्रीज हुआ। यह कह रहे थे कि asset creation होता है, यह होता है, आपने कुछ इंक्रीज नहीं किया। Total receipts estimated to be Rs. 1,80,483 crore. इसकी आप बात नहीं करेंगे।

आपने उदय को लाते ही 42 परसेंट राजस्व घाटा एक साल के अंदर बढ़ा दिया था। हमने 56 परसेंट कम कर दिया। इसकी आप तारीफ नहीं करेंगे। राजस्व घाटा, 2020-21 targeted to be Rs. 33,923 crore (2.99 percent of GSDP) below 3 percent of 14th Finance Commission. यह हमारी फिस्कल डिसीप्लीन और प्रूडेंस को दिखाता है। अब आप कहते हैं कि आपने एक्सपेंडीचर नहीं बढ़ाया। आप कोई असेट क्रिएशन नहीं करना चाहते। आप तो सिर्फ कमिटेड लायबिलिटीज पर खर्च कर रहे हैं, और कुछ करना नहीं चाहते। जब हम फिस्कल डैफिसिट को मेन्टेन कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडीचर कट कर रहे हैं, हम फिस्कल डैफिसिट मेन्टेन कर रहे हैं। हम जब एक्सपेंडीचर बढ़ाते हैं तो नेचुरली फिस्कल डैफिसिट बढ़ता है तो ये कहते हैं कि आप फिस्कल डैफिसिट मेन्टेन नहीं कर रहे। चित भी हमारा, पुट भी हमारा।

ओवरआल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की बात करें 33.12 percent of GSDP, I agree कि जो 20 प्रतिशत की लिमिट है, as suggested by

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

the FRBM Committee in 2019 for cumulative debts of states, उससे बहुत बढ़ी है लेकिन यह तो हम आपसे विरासत में लाये हैं। आप उदय से भट्टा करके चले गये। यह यकायक रातों-रात नहीं बदल सकता। यह तो आप भी जानते हैं और मेजर रीजन इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के आंकड़े का है उदय, जो आपने बिना सोचे-समझे एडाप्ट किया।

जब 15वां वित्त आयोग राजस्थान आया, तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। मैं उस दल के अन्दर थी। मैंने उन्हें कहा कि जब हमारी इकोनोमी जाम हो चुकी है और उदय के एडाप्शन से यह हो चुका है, आपने हमारे को कोई ग्रांट वगैरह, कोई फाइनेंशियल एड नहीं दी। आप इसके लिये कुछ करेंगे? उन्होंने, जब वे आंसर कर रहे थे, उसके चेयरपर्सन, एन.के. सिंह जी, He said, Divya you were not compelled to take Uday. Who asked you to take Uday? मैं उस वक्त राजस्थान को रिप्रजेंट कर रही थी। यह कह नहीं सकती थी कि प्रीवियस गवर्नमेंट की क्या कम्पलशंस हुई जो उन्होंने उसको एडोप्ट किया। This is the statement of N.K. Singh.

रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। 2020-21 के अन्दर 173404 करोड़, दस परसेंट का इन्क्रीज है, आर.ई., जिसके अन्दर से 96625, जो कि 56 परसेंट राज्य के ओन सोर्सेज से आता है और Rs. 76,779 crore (44 percent revenue receipts) which comes from central and share taxes. सेन्टर की खुद की टैक्स रिसीट्स गिर गई। आप हमें कह रहे हो, आपकी रिसीट्स लो क्यों आ रही है। कैसे बचोगे, जब आपकी जी.एस.टी., डिमोनेटाइजेशन, पूरी इकोनोमी स्लो डाउन है, आपके सारे सैक्टर्स बीमार हैं, पुअर स्टेट के अन्दर चले गये। इन्वैस्टमेंट नहीं है, पर्चेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ ठप है तो जब पूरे सेन्टर का कलेक्शन नहीं हो रहा तो राज्य उससे कैसे बचेगा, मुझे समझ में नहीं आता।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): पांच मिनट।

आफ बजटिंग आप करते हैं, वह तो दिखता नहीं है आपकी उसके अन्दर। उससे फिस्कल डैफिसिट तो आपके और भी ज्यादा हैं। और, लो जी.डी.पी., जी.एस.डी.पी. के बहुत सारे कारणों के अन्द्र, जो स्टेट पर असर पड़ा जी.एस.टी., डिमोनेटाइजेशन। वे 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे थे, लाहोटीजी हैं नहीं यहां पर। उनका आप यह नहीं बताते कि आपका पैसा बढ़

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

गया। आपने 42 से 41 परसेंट कर दिया। लेकिन जब आपने 39 से 42 परसेंट किया था, तब भी हमें आइडियली 34 पाइण्ट कुछ परसेंट मिलता था, अब लास्ट में तो 31 परसेंट मिला है, सैस, सरचार्ज काटकर, हमें मिलता नहीं है।

दूसरी बात जो आपने इस रिपोर्ट की कोट नहीं की, 15वें वित्त आयोग की इंटरिम रिपोर्ट की, जो स्वयं यह कहते हैं- The Commission highlighted some challenges with the implementation of goods and services, चैलेंजेज उन्होंने बता दिये accumulation of large integrated GST credit, high volatility in collections, glitches in invoice मतलब एक फ्लाड जी.एस.टी. आपने प्रजेंट की, इसको इंटरिम रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने भी कहा। जो आप कह रहे हैं कि इतना 15वीं रिपोर्ट, 15वें वित्त आयोग का 6 परसेंट बता दिया, उसकी आप बात नहीं कर रही हैं। यह तो इंटरिम रिपोर्ट है। आपने भी तो एक साल एक्सटेंशन किया है, ToR of डिफेंस करने के लिये, डिफेंस के बाद देखिये क्या शेयर बनता है स्टेट का कट कर। तब मानेंगे कि असली रूप के अन्दर क्या आयेगा।

I would like to cut it short, जी.एस.टी. को आपने बिना सोचे-समझे लागू किया। छोटे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज, सब इससे हैम्पर हुईं। आप कहते हैं कि एसजी.एस.टी. तो स्टेट का है, इससे आप कैसे कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, आपका जब खाने का बिल आता है, सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. साथ लगकर आते हैं। इसके तीन कम्पोनेंट्स हैं, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी यह कहने की कला, मुझे भी सीखनी पड़ेगी। यह ब्रह्मास्त्र आपको मुझे भी सिखाना पड़ेगा।

पावर जनरेशन, 50 परसेंट प्लांट लोड कैपेसिटी में चल रहे हैं। डिमाण्ड खतम हो गई। 70 percent installed capacity पर चल रहे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है। एस.जी.एस.टी. कहां से आयेगा। संदर्भ सहित आप मुझे व्याख्या करके बताइये, कैसे होगा कलेक्शन। आप कैसे बढ़ा देंगे। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान कोई आइसोलेशन में थोड़े ही रहता है। इन्कम के सोर्सेज डिप्लीट हो गये। यही कारण है कि मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज, उद्योग, सबके सब इतनी बीमारू हालत में हैं कि आपके सारे के सारे कलेक्शंस लो हो रहे हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दूसरी बात, नई चीज, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं, जो कि जी.एस.टी. एक्ट के अन्दर कहा गया था which guaranteed in 2017, a compensation for five years until 2022 for the revenue losses arising due to GST implementation. The Act guarantees a 14 percent of annual growth in their revenues which were submitted under the GST और अब आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, मैं तो किसान वर्ग से आती हूं। मेरी हस्ती का गौरव है, उगाते भी हैं, बेचते भी हैं और खाते भी हैं। इंफ्लेशन रेट आपने 7.5 पर पहुंचा दिया और मजाक उड़ाते हैं गरीब का, जो कुछ और नहीं कर सकते।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अब उन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम कम्पन्सेशन सैस फंड से ही देंगे, और वह कलेक्शंस अगर नहीं होंगे तो ठेंगा स्टेट को।

मैं एक चीज और बताना चाहती हूं, योजनागत व्यय की इन्होंने बात की कि 40 वर्षों में, 4 डिकेड्स में इतना कम हो गया, कभी कम नहीं हुआ। आपने इसको भी लहराया और कहा, इसको तो आप जानते नहीं हैं, इसको आपने देखा नहीं। आपने तो देखा भी है, पढ़ा भी है और आप जानते भी हैं लेकिन पक्ष रखने की आपकी जो कला है, उसकी मैं दाद देना चाहती हूं। आपने कहा 116735 और 2020-21 में आपने उसको 110200 कर दिया, मीन्स 6735 कटौती कर दी 40 वर्ष के अन्दर लेकिन आपने इसका यह पेज पढ़ा नहीं, मैं लेकर आई, जिसके अन्दर उदय की योजना का विवरण दिया है और आपने जो उदय का 72 हजार कुछ का लोस दिया, उसको आपको पांच साल में अदायगी करनी थी और जिसकी लास्ट किश्त ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट किश्त 2019-20 के अन्दर 14721 गई, अगर आप उसको घटा दें तो वास्तविक योजना का प्लान 102003 था, जो कि 10 प्रतिशत ज्यादा है।

इसी के सन्दर्भ में जब आप कहते हैं, किसान की बात करते हैं। उन सात संकल्पों में दूसरे नम्बर पर है, और मैं सबसे पहले उस संकल्प की बात करूंगी क्योंकि मैं किसान वर्ग से आती हूं। विषमताओं से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मैं इस सदन में किसान वर्ग की आवाज बनी। उन्हीं विषम

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

परिस्थितियों के कारण मैं अपनी खेती स्वयं भी सम्भालती हूं। मैं उनकी आशाओं, परेशानियों और पीड़ाओं को जानती हूं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण अनेकों चीजें देखने को मिलीं। खेती को जब मैंने खुद सम्भाला तो मुझे पता लगा कि क्या-क्या जोर आता है।

"सुलगता है बदन मेरा उनकी याद में ईंधन की तरह,

बरसती है मेरी आंख सावन की तरह,"

जो भी परिस्थितियां रहीं, जिस तरह की भी रहीं, मुझे जो देखने को मिला, सामने मिला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): उसके अन्दर किसान वर्ग की बात आपने बात कही कि बिजली की आपने कटौती कर दी और आप कैसे किसान को समृद्ध करेंगे तो बिजली के अन्दर भी 15142 we doubt कि वास्तविक चीज है, क्योंकि वह जो 14 हजार कुछ की लास्ट अदायगी 2019-20 में थी, 2020-21 के अन्दर नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती इन्दिराजी।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं लास्ट पाइंट पर आ जाती हूं। अपने क्षेत्र की तीन-चार समस्याओं को रखती हूं। ओसियां में बहुत टाइम से बहुत ज्यादा मांग थी, जिसकी मैंने मांग की थी, मदर एण्ड चाइल्ड सेन्टर, जो मुख्य मंत्रीजी ने ओसियां को सौगात दी, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूं।

लेकिन भेड़हलाय पानी की परियोजना थी, जो 2009 की हमारी सरकार की बजट घोषणा में थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई थी लेकिन सरकार बदलने में उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई क्योंकि ये बदले की राजनीति का प्रतीक थे। जोधपुर को तो वैसे ही ये देखना नहीं चाहते थे। मुख्य मंत्रीजी ने 2019 में लोहावट के अन्दर इसकी घोषणा की थी कि यह पुन: चालू हो। मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि विशेष रूप से इस योजना को सम्मिलित करके पानी पिलाने का, उन ढाणियों में उन लोगों को पानी पिलाने का जो हमारा संकल्प है, उसे पूरा कीजिये।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नहीं तो हमारी कथनी और करनी के ऊपर प्रश्न चिह्न लगा दिये जाएंगे।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूं कि ऐसी स्थिति के अन्दर जहां बुरी तरह से आहत है इकोनोमी, जिन परिस्थितियों के अन्दर वित्तीय परिपक्वता के साथ एक संतुलित और जनमुखी बजट वित्त मंत्रीजी ने पेश किया, और आखिर में इन चार लाइनों के साथ,

''हजार बर्फ गिरें, लाख आंधियां उठें,

वो फूल खिल कर रहेंगे, जो खिलने वाले हैं।''

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारा मेड़ता क्षेत्र है, उस मेड़ता क्षेत्र के अन्दर हास्पिटल के बारे में मैंने पहले भी मांग की और अभी भी कर रही हूं कि मेड़ता क्षेत्र में सौ बैड का हास्पिटल पहले भी कहा कि सौ बैड का हॉस्पिटल हो जाये, तो सौ बैड का हास्पिटल अभी तक नहीं हुआ। वहां सौ-सौ किलोमीटर की दूरी पर हास्पिटल नहीं है। जो सरकारी हास्पिटल है तो वहां डाक्टर्स की कमी है, डाक्टर्स नहीं हैं। जैसे मेड़ता रोड है, जसनगर है और रियां बड़ी है, गोटण है, इन गांवों के अन्दर सरकारी अस्पताल हैं पर डाक्टर्स अभी तक नहीं हैं तो मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि बराबर डाक्टर होना चाहिए। डाक्टर नहीं हैं तो जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बहुत दुख और तकलीफ होती है तो मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी सरकारी डाक्टर्स आप वहां पर लगायें।

जो हमारा क्षेत्र, वहां पर जो रोड है, अभी तक भी एक भी रोड नई नहीं बनी है तो मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं कि हमारा क्षेत्र ही ऐसा है क्या कि सरकार पैसे नहीं लगाना चाहती? आज तक एक रोड भी नई सैंक्शन नहीं हुई है।

मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं कि मेड़ता क्षेत्र के अंदर एक रोडवेज बस चलती थी, एक-दो सरकारी रोडवेज बस थी, वह भी बंद हो गयी तो सरकार को मैं यह कहना चाहती हूं कि आप लगाना तो नहीं चाहते हों पर जो लगी हुई है, आप उनको तो बंद मत करो, इतनी तो कृपा करें।

मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि मेड़ता क्षेत्र में पानी की कमी है तो मेड़ता क्षेत्र के अंदर पानी तो मीठा आ गया परंतु वहां पर जो ढाणी और

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

गांव हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो मैं हैंडपम्प की मांग करती हूं कि वहां पर हैंडपम्प जरूर होना चाहिए।

दूसरा नम्बर, हमारे मेड़ता क्षेत्र में ऐसी स्कूलें हैं, आप जो कह रहे हों कि नीरोगी राजस्थान तो नीरोगी राजस्थान, हमारे मेड़ता क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कूलें हैं तो आज आप जाकर वहां पर निरीक्षण करें, स्कूलों की ऐसी हालत हो गयी है कि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है और मैडम और सर को बाहर बैठाकर उनको पढ़ाना पड़ता है और जब बरसात का मौसम आता है तो बच्चा अंदर नहीं बैठ सकता है तो मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं कि जो भी सरकारी स्कूलें हैं, उन स्कूलों के अंदर आप मास्टर लगायें और जो भी सरकारी हास्पिटल हैं, आप वहां पर डाक्टर्स लगायें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

दूसरा नम्बर, आप सब बजट की बात कर रहे हो कि हमारे जो किसान हैं, अभी मुआवजा की बात चल रही है तो आज तक मेड़ता में, हमारे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है और पूरी फसल गल गयी और अभी जो लाइट वाले हैं, किसी का कुआ है, किसी का ट्यूबवैल है और वह भी लाइट चलाकर फसल उगाना चाहता है तो सरकार ने ऐसा कानून चलाया है कि लाइट को ही काट दिया और रात को जा-जाकर लोगों को वी.सी.आर. भर देता है कि मेरे को ऊपर से आर्डर आया हुआ है तो मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं कि जो गरीब लोग हैं, उनका आप साथ दिया करें। नया काम तो आप नहीं कर सकते हो पर जो काम चालू हैं, उनको तो सही किया करें। मैं आपसे यह निवेदन करती हूं। मैं भी उस क्षेत्र से हूं मुझे भी आज दुःख हो रहा है कि मैं जब हर गांव में जाती हूं, हर गांव में रोड ऐसी है कि आप देख नहीं सकते। आप गाड़ी लेकर एक बार चलें, आपको भी ध्यान हो जाएगा कि रोड ऐसी है।

मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि मैंने जो भी मांगें आपके सामने रखी हैं, वह मांगें आप मेरी जरूर पूरी करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस बार लगभग यह 17वां बजट मैंने सुना है, जिसमें कांग्रेस का यह 7वां बजट था। उन सबमें यह बजट पूर्णतया आंकड़ों के मकड़जाल में भ्रमित करने वाला

(श्री वासुदेव देवनानी)

साबित होता है। केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराना शायद इनकी आदत पड़ गयी है। गत एक वर्ष में 145 बार मोदी और आर.एस.एस. को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है, पूरी गिनती करके देख लो। इससे राजनीति तो की जा सकती है लेकिन राज्य के साढ़े सात करोड़ लोगों की आंखों के आंसू नहीं पोंछे जा सकते और न ही उनका कोई भला किया जा सकता है, न ही उनका कोई विकास किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह सबकी जानकारी में है कि अपने यहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42 परसेंट हिस्सा राज्यों को प्रदान करने की अनुशंसा की गयी, उसके अनुसार राशि मिल रही है।

(14.54 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

जी.एस.टी. की बार-बार बात होती है। जी.एस.टी. में यह प्रावधान है कि यदि किसी कारण से कम आय हुई तो आपको, उसका डिफरेंस राज्यों को मिलेगा और वह लगातार मिल रहा है 14 परसेंट। उसके बाद इस तरह की चर्चा करना मैं समझता हूं कि व्यावहारिक नहीं है।

आज जब विकास की बात चलती है तो पूरी वैश्विक विकास दर 2.7 से 2.8 परसेंट है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका और चीन की विकास दर लगातार कम हो रही है, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 5 परसेंट से ऊपर बनी हुई है, यह हमारी केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण है।

आज अमेरिका सहित सारा विश्व यह स्वीकार कर चुका है कि भारत अब विश्व की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। केन्द्र सरकार भारत को पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने में, किसानों की आय को दुगुनी करने में, मेक इन इंडिया को प्रभावी बनाने में, गांधीजी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंतिम व्यक्ति के विकास से ही गरीब के आंखों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, वक्तव्यों से नहीं पोंछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी का नाम लेकर केवल सत्ता तो हथियाई जा सकती है लेकिन इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गांधीजी के, अगर वास्तव में आप गांधीवादी हों तो क्या गांधीजी ने कहा था कि शराब से आय बढ़ाओ? आज हरेक जगह पर दबाव

(श्री वासुदेव देवनानी)

डाला जाता है कि आप राजस्व 10 परसेंट बढ़ाओ और 19 परसेंट उसकी आय बढ़ाने के लिए आप लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। यह क्या गांधीवादी दृष्टिकोण है?

इस सरकार ने बहुत कहा, मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि मैं यह कामना करता हूं कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं। यह कहना सरल है लेकिन किया क्या? आपने आंसू पोंछने की जगह भोली-भाली जनता को आंखों में आंसू देने का काम किया है। किसानों के प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 1430 करोड़ रुपये में से केवल 53 करोड़ रुपये ही जमा करवाकर, आयुष्मान योजना को लागू न कर, 55.5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता से महरूम रखकर और पैट्रोल और डीजल पर 4 परसेंट वैट पुन: बढ़ाकर, बिजली के बिलों में वृद्धि कर, यह आंखों के आंसू ला दिये हैं और फिर कहते हैं कि हम आंखों के आंसू पोंछेंगे।

आप महिला उत्थान की बात करते हैं तो महिला उत्थान में महिला और बच्चों के दुष्कर्म की घटनाएं, मां-बहन के एक के आंसू एक बार पोंछते हैं तो दूसरे दिन दूसरी मां-बहन के आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अखबारों की स्याही एक दिन आती है और अगले दिन जब तक सूखती नहीं, तब तक दूसरी कहीं दुष्कर्म की घटना सामने आ जाती है। आज दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में रिकार्ड तोड़, 5500 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं केवल इन 14 महीनों में हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं प्रदेश को मेरे एक परिवार की तरह मानता हूं। इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है कि आप इस बजट के आंकड़े उठाकर देख लें कि केवल जोधपुर और उस पर ही दिखाई देता है। सारी योजनाएं जोधपुर केंद्रित हैं। उसके अलावा क्या अजमेर दिखाई नहीं देता, भीलवाड़ा दिखाई नहीं देता, प्रतापगढ़ दिखाई नहीं देता, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की जनता, क्या उनकी नजरों में यह राजस्थान की जनता नहीं है? यह राजस्थान की जनता को अपना परिवार केवल अपने शब्दों में मान रहे हैं। केवल गृह जिला जोधपुर में घोषणाओं का पिटारा खोलना और दूसरे जिलों की उपेक्षा करना, यह उनकी संकीर्ण सोच दर्शाती है कि वह बोलते क्या हैं और करते क्या हैं।

अब मैं उनके सात संकल्पों में से केवल दो-तीन संकल्पों की ही चर्चा

(श्री वासुदेव देवनानी)

करूंगा। आप बहुत घोषणाएं करते हैं। मैं शिक्षा के यह आंकड़े जो आपके बजट के हैं, उनको केवल पढ़कर सुनाऊंगा कि जब-जब भी भाजपा की सरकार आयी है तभी इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और जल आपूर्ति और सफाई में खर्च किया है। सामान्य शिक्षा में जब हमारा 2004 से 2009 तक शासन था, हमने 3869.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7522.59 करोड़ रुपये अर्थात् 94 परसेंट बढ़ाये। आपका शासन आया वर्ष 2010 से 2014 के बीच में तो आपने 9091 से 12730 अर्थात् केवल 40 परसेंट ही बढ़ाया। फिर हमारा शासन आया, हमने 19076 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 34158 करोड़ रुपया किया अर्थात् 79 परसेंट बढ़ाया और आज आपके पिछले दो बजट में 2019-20 के बजट में था 38712 करोड़ रुपये और इस बार क्या रखा है 38093 करोड़ रुपये अर्थात् माइनस वन पाइंट सिक्स परसेंट अर्थात् शिक्षा की ओर आप कोई ध्यान ही नहीं देते। इतनी शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती और आप फिर कहते हैं कि हमने बजट बढ़ाया है तो यह बजट के आंकड़े मेरे नहीं हैं। यह आपके सारे बजटों में यह आंकड़े कह रहे हैं।

चिकित्सा के लिए यह कहते हैं कि हम नीरोगी राजस्थान बनाएंगे। नीरोगी में, जब हमारा शासन था, 2004 से 2009 में तब हमने 88 परसेंट बजट बढ़ाया, उसके बाद आपका शासन आया, आप 88 परसेंट से घटाकर 53 परसेंट की ओर गये। फिर हमारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 का बजट आया तो 116 परसेंट हमने बजट बढ़ाया और आपने क्या किया, आप नीरोगी राजस्थान की बात करते हैं, आपका बजट है 9066 करोड़ रुपये से केवल 10561 करोड़ रुपये अर्थात् 16 परसेंट, जो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे नीरोगी काया तो नहीं बन सकती।

(15.00 बजे)

जल मंत्री बैठे हैं। जलापूर्ति पर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। हमने 2004 से 2009 के बीच में 51 प्रतिशत बढ़ाया, आपने आकर 2009 से 2014 के बीच में केवल 12 प्रतिशत बढ़ाया। और फिर हम आये, 2014 से 2018-19 के बीच में, हमने 65 प्रतिशत बजट बढ़ाया और आपने आकर आप केवल 8 प्रतिशत तक सीमित रहे जिसमें विकास के काम तो कोई हो नहीं सकते। इस प्रकार की दुर्गति आपने की है। मैं समझता हूं कि यह हमारी आंखें खोलने वाला है। हम चाहे पक्ष-विपक्ष के हों, आपको सराहना करनी है, हमें आलोचना करनी है, लेकिन आंकड़े तो सामने पड़े हैं। आंकड़ों की ओर जब देखेंगे तो मैं समझता हूं सच्चाई सामने होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सभापति महोदय, नीरोगी काया की चर्चा की गयी। आपने नीरोगी काया के लिये बजट कितना रखा? इसके अंदर 100 करोड़ का बजट रखा। राजस्थान की जनता कितनी है, साढ़े सात करोड़। अब एक व्यक्ति पर कितना खर्च होगा? साढ़े तेरह रुपये, साढ़े तेरह रुपये में क्या नीरोगी काया बनेगी। जब भी मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तब इसका जवाब तो दें।

आपने दूसरी घोषणा की थी कि जनता क्लिनिक खोलेंगे। पूरा वर्ष बीत गया, केवल 12 जनता क्लिनिक, वह भी जयपुर में खोली। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, क्यों उनको भ्रमित कर रहे हो? इससे एक भी व्यक्ति ठीक नहीं होने वाला। फिर कहते हैं केन्द्र सरकार पैसे नहीं दे रही। केन्द्र ने आपको कहा है कि हर पी एच सी में अवेयरनैस सेंटर खोलें। यह आपको मार्च, 2020 तक खोलने थे, आपने एक भी नहीं खोला। उसमें स्पष्ट प्रावधान है, यदि आप मार्च, 2020 तक खोलोगे तो आपको 20 प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा और यदि नहीं खोलोगे तो 20 प्रतिशत आप पर पैनल्टी लागू होगी। आप तो पैनल्टी देने जा रहे हो। केन्द्र से पैसा आ रहा है और आप खोल नहीं रहे हो। इस प्रकार की दुर्दशा मैं समझता हूं कि नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेडिकल कालेज की चर्चा की, 15 मेडिकल कालेज खोलेंगे। स्टेट शेयर का कहीं कोई पता नहीं। डाक्टरों के पद खाली हैं। चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि हम चिकित्सा में पद भर रहे हैं। 3,902 पद खाली हैं, उसमें से आपने अर्थना कितनी भेजी है 753 की, अर्थात् उसके बावजूद भी 3,200 पद खाली रहेंगे, उससे क्या नीरोगी काया बनेगा राजस्थान? यह केवल सपना दिखाने का छोड़ो और वास्तविकता पर जरा आगे बढ़ो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया कि अजमेर मेडिकल कालेज शिफ्ट करेंगे। बजट में कोई प्रावधान नहीं, केवल अजमेर की जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पानी देने की बात कही। यह मेरे पास कागजात और आर्डर पड़े हैं। उस आर्डर में साफ लिखा है केन्द्र ने आपको पैसे दिये हैं, लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो। केन्द्रीय जल शक्ति विभाग ने आपको यूपीए की सरकार में 2009 से लेकर 2013-14 तक 72,841.99 करोड़ दिये, जबकि 2014-15 से लेकर 2018-19 तक एक लाख

(श्री वासुदेव देवनानी)

60 हजार 196 करोड़ मिले। आप कह दोगे कि आपकी सरकार थी, लेकिन पिछले दो वर्षों में जबकि केन्द्र में बीजेपी की सरकार है, इन दो वर्षों में आपको 82,935 करोड़ मिल चुके हैं और आप कहते हो कि केन्द्र से पैसा नहीं मिल रहा। आपकी यूपीए सरकार ने तो आपको दिये केवल 72 हजार करोड़ और दो सालों के अंदर ही आपको 82 हजार करोड़ रुपये मिल चुके हैं और आपने खर्चा कितना किया? इस बार तो राजस्थान बी.ई. में 2,424 करोड़ इन्क्रीज भी किये। आपको यह पैसा इसलिए दिया कि आप राजस्थान के गांवों के अंदर घर-घर कनेक्शन दो। आपको कनेक्शन देने थे 81.19 लाख ग्रामीण घरों में और आपने कितने जोड़े? केवल 16 हजार घरों को कनेक्शन दिये। फिर केन्द्र का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक हजार करोड़ आये और उसमें से आपने केवल 16 लाख खर्च किये, यानी केन्द्र का पैसा आ रहा है और आप खर्च नहीं कर पा रहे हो और केन्द्र पर आरोप लगाते जा रहे हो कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के झूठे आरोपों से जनता आपके चक्कर में नहीं आने वाली। इस बार भी आपको 1301.70 करोड़ खर्च करने के लिये दिये हैं, पर आप कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हो। आखिर पैसा जा कहां रहा है?

माननीय सभापति महोदय, जब भी कांग्रेस सरकार आती है, अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री बनते हैं। पैसे का अकाल, कहां जाता है पैसा? विधायक कोष तक पर भी आपने कैंची चला दी। विधायक कोष 2 करोड़ 25 लाख हमारा अधिकार है। आज तक कितना दिया है? इस वर्ष पहली बार है, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, केवल आधा पैसा ही दिया है। विधायक कोष नहीं है तो विकास कैसे होगा? इससे ज्यादा और क्या दुर्गति हो सकती है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा आर्थिक दिवालियेपन की ओर राजस्थान बढ़ रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मुझे 15 मिनट का समय दे रखा है। अभी मुझे 9 मिनट हुए हैं, मैंने घड़ी देखी है। मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आपका समय पूरा हो रहा है। प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने भ्रष्टाचार की बात कही। आज राजस्व इकट्ठा क्यों नहीं होता? अभी हमने परिवहन विभाग को देख

(श्री वासुदेव देवनानी)

लिया कि इतने अफसर, इतने दलाल। निजी बसें बिना परमिट के चल रही हैं। यदि मैं कहता हूं कि अन्य डिपो में भी यह हालत है। एसी.बी. क्या, कोई भी जांच करा लें, इसमें मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सारे जितने अफसर हैं उनकी सम्पत्ति की जांच हो। यदि किसी की आय से ज्यादा सम्पत्ति हो तो सभी उसके घेरे में आ जाएंगे। ऐसे भ्रष्ट अफसरों द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, आप उदयपुर के, मेवाड़ के हैं। फैल्सपार अन्य राज्यों में ले जाने में प्रतिबन्ध है, लेकिन लगातार गुजरात की ओर सीमा से जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है। 49 करोड़ के राजस्व की हानि इस वर्ष हुई है। माननीय सभापति महोदय, सारे राजस्थान में विकास का काम ठप पड़ा है। प्रदेश में सड़कों के नाम से जितनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी हैं, उन ट्रेजरियों में बिलों का भंडार पड़ा है, अथाह बिल पड़े हुए हैं। किसी ठेकेदार का काम नहीं हो रहा है तो दूसरा ठेकेदार काम करेगा कैसे? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर सरकार ध्यान दे। केवल सरकारी कर्मचारियों को वेतन बांटने के अलावा कुछ कुछ नहीं किया।

दूसरा, अपराधों के बारे में केवल एकाध बात कहूंगा कि आज पत्रकारों पर आक्रमण, जो सच्चा लिखते हैं, अभी पत्रिका का तो सदन में आया कि केकड़ी के अंदर पत्रकार पर हमला हुआ। मैं मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए जिसके कारण से हमारे पत्रकार बिलकुल नि:संकोच होकर लिखने का कार्य कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात चली। हालांकि मैं इसमें डिमांड्स पर बोलूंगा ज्यादा, लेकिन एक बात कहूंगा कि विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत खाली पद पड़े हैं। प्रदेश की जनता देख रही है। सड़क के ठेकेदार का पेमेंट नहीं। पानी-बिजली की बात करें तो करंट आ रहा है और सफाई मजदूर की बात करें तो युवा लोग इंतजार कर रहे हैं। यह नीरोगी नहीं, रोगी राजस्थान बनाने के लिये 18 हजार बच्चों की मृत्यु हुई है। आयुष्मान योजना लागू नहीं करेंगे, सम्पन्न किसान आज कराहता किसान है।

माननीय सभापति महोदय, कौशल विकास की बात करते हैं। सारे इंजीनियरिंग कालेज, पोलीटैक्निक कालेज बंद हो रहे हैं। वहां पर कोई संभालने वाला नहीं। क्या टैक्निकल विकास करेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापतिजी, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। एक बात आपसे इस संबंध में कहूंगा कि आज आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। आर्थिक अपराधों में राजस्थान पहला, भ्रष्टाचार में पहला, दलित अत्याचार में पहला, बाल तस्करी में चौथे नंबर पर है, पुलिस के हिसाब से कुछ नहीं और अजमेर के जो मंत्री बैठे हैं पानी के, अजमेर की ब्राह्मणी नदी के लिये 6 हजार करोड़ की योजना हमारी सरकार ने लागू की थी, उसका बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आज अजमेर के व्याख्याता आमरण अनशन पर है लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करता हुआ अपनी बात को यही कहते हुए समाप्त कर रहा हूं कि आज इस समय प्रदेश की पूरी जनता देख रही है, राजस्थान दिवालियेपन की ओर जा रहा है, कांग्रेस के नुमाइंदों को कहीं भी देखने का नहीं, केवल वाहवाही लूटकर मुख्य मंत्री के सामने केवल अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। प्रदेश देख रहा है इनसे जनता अपना हिसाब समय पर पूरा करेगी। मैं इस बजट का पूर्णतया विरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करती हूं। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो इस राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता के लिये सात संकल्पों के साथ किया गया और यह इनका सातवां बजट है। मुझे लगता है कि सात का आंकड़ा हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिये बड़ा लकी है और इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में हो तब भी अगर मुख्य मंत्री चाहें तो ही ऐसा बजट पेश कर सकते हैं जिसमें जनता की तरफ से कहीं कोई नाराजगी ही न प्रकट हो और जनता खुश हो कि कम-से-कम कुछ महंगा तो नहीं हुआ। मुझे ध्यान है बचपन में हम रेडियो पर सुना करते थे जब बजट आता था कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तब बजट में इस तरह बोलते थे कि साबुन सस्ता होगा, तेल सस्ता हो गया, बहुत-सी चीजें सस्ती हो गयीं लेकिन इस मंदी में मुझे लगता है जनता सस्ती होने की तो कोई अपेक्षा कर नहीं रही, महंगाई न बढ़े, इसकी अपेक्षा जरूर सरकार से

(श्रीमती सफिया जुबेर)

कर रही है। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा बजट दिया है बल्कि यह बजट मैं कहूंगी शिक्षा और स्वास्थ्य को समर्पित है और वह भी ऐसे समय में समर्पित किया है जो हमारा शेयर है सैंट्रल एक्साइज टैक्सेज में, उसमें हमारे राजस्थान के लगभग 10,362 करोड़ की कटौती की गयी है। मैं पूछना चाहूंगी, विपक्ष में बैठे हमारे बहुत-से साथी विधायक हैं, चार-पांच दिन से इस पर बहस चल रही है और बहुत कमियां निकाल रहे हैं और आप लोग रोज किसी-न-किसी बात पर वाक-आउट करते हो तो कभी वॉक-आउट करके दिल्ली जाइए और मोदीजी से चाय पर चर्चा करके मन की बात तो करिए। यह 11 हजार करोड़ क्यों नहीं हमारा पैसा लेकर आते हैं। यह राजस्थान की जनता ने उनको जिताकर इसलिए भेजा था कि राजस्थान के बजट पर ही कैंची चलाएंगे। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना तो यह लोग जानते ही नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि तो नीरोगी राजस्थान है, जिसकी बेसिक पालिसी यह है prevention is better then cure यानी हम पहले से बीमारियों को दूर रखने की सोचें और इसके लिये 100 करोड़ का बजट मुख्य मंत्रीजी ने दिया है और इस बजट का उपयोग प्रचार-प्रसार, गोष्ठियों का आयोजन करने के लिए किया जाएगा क्योंकि मुझे लगता है यह किसी भी योजना का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। हमारे यहां इतनी अशिक्षा है, लोगों में जागृति नहीं है, बीमारियों के बारे में नहीं पता, दवाइयां कैसे खानी हैं नहीं पता। गरीब महिलाएं जाती हैं दवाइयां ले आती हैं, दवाई तो उनको कांग्रेस की सरकार फ्री में देती है निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना कांग्रेस ने, मुख्य मंत्री जी ने शुरू की थी लेकिन वो एक दिन दवाई खाकर भूल जाती है, सोचती है कि मैं ठीक हो गई हूं तो उनको यह समझाने की जरूरत है कि आपको यह दवाई पांच दिन तक खानी है ताकि आपकी बीमारी पूर्ण रूप से जड़ से खतम हो जाए। इसका प्रावधान इस नीरोगी राजस्थान में किया गया है। उसकी कमी थी जिसकी वजह से, जैसे कि सब जानते हैं कि जो सिलिकोसिस बीमारी थी, उसको टीबी समझकर टीबी की दवाइयां दी जाती थीं, बहुत से पेशेंट्स मर जाते थे इसलिए पिछले बजट में इसके बारे में भी मुख्य मंत्री ने अलग से बजट दिया है, ऐसे रोगियों को आर्थिक मदद भी की है लेकिन यह योजना नीरोगी राजस्थान मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सार्थक हो पाएगी। इसमें पोल्यूशन

(श्रीमती सफिया जुबेर)

डिपार्टमेंट को भी अपना पूरा सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि आज की ज्यादातर बीमारियां पोल्यूशन से संबंधित हो रही हैं। बहुत अधिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे संदीप यादव जी ने फर्माया था कि भिवाड़ी में बहुत पोल्यूशन है। बच्चा अगर पैदा होते ही गंदी सांस लेगा तो उसको तो बीमारियां लगना तय है और गांवों में रहने वाली माताएं तो पहले ही बीमार हैं उनका हीमोग्लोबिन सात या आठ होता है। स्थिति वाकई बहुत खराब है। महिलाओं में विटामिन डी की डेफिशियंसी इतनी है जिसका उनको ज्ञान नहीं है। कहती हैं कि चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा तो इन सब बातों के लिए जो यह नीरोगी राजस्थान किया गया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता स्वस्थ होने के रास्ते पर चलने वाली है।

हमारे एक साथी विधायक हैं कासनियां जी, जो कह रहे थे कि मेरी तो शुगर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है ये सरकारी दवाई खा-खा करके। वो सरकारी दवाई की वजह से नहीं, सरकारी दवाई तो असर कर रही है लेकिन जब आप विपक्ष में बैठे होते हो तो मुझे लगता है कि वहां बीपी और शुगर थोड़ा वैसे ही बढ़ जाता है और जिस तरह के कारनामे केन्द्र सरकार कर रही है, प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं, उससे लगता है कि आपका वहां दस-बीस साल बैठना तय है और कांग्रेस सरकार का, हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी का यहां बैठना तय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): तो डबल डोज करवा दीजिए क्योंकि सेहत का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

इसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहां बहुत अच्छा अभियान चल रहा है कि खाने-पीने की नकली चीजों पर लगाम कसी जा रही है। इसके लिए सब जिलों में लैब खोलने का भी प्रावधान किया गया है। नकली मावा, नकली दूध, नकली मिठाइयां, हर चीज में कहीं न कहीं मिलावट है तो इसको रोकने के लिए सरकार ने सोचा है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति जी, आधा घंटा दीजिए न।

श्री सभापति: मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब समय.. .

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है।

इसके लिए अभी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है यह बहुत बड़ा काम है जो सरकार के द्वारा करा गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले लिये गये हैं। हमने एक माडल के रूप में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाये थे, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और अब दोबारा से 167 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ब्लाक्स में चलाए जाएंगे। कम्प्यूटर शिक्षा कैडर का प्रावधान किया गया है। देखिए आपका मोबाइल भी, एक छोटा-सा कम्प्यूटर होता है स्मार्ट फोन, ये सबको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तभी आप कहते हैं न कि टैक्नोलोजी के साथ-साथ चलेंगे। यह राजीव जी की देन थी कि आज देखिये मोदी जी सैल्फी खींचते रहते हैं और फिर यह लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। खुद घर में बैठे सैल्फी खींच रहे हो, इससे बड़ा और क्या करेंगे, आप लोग बताइए।

कस्तूरबा गांधी स्कूल्स खोले जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आप जो नये कस्तूरबा गांधी स्कूल्स खोल रहे हैं, जो आलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनमें से कुछ स्कूलों को दसवीं करनी चाहिए और अलवर जिले में मेवात आवासीय स्कूल हैं, जो आठवीं तक हैं, इनको भी दसवीं करना चाहिए तो मुझे लगता है बच्चियों की शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): और यह दो स्कूल खोलने की बात कर रहे थे कि आपने तो दो स्कूल खोले, आपने तो डबल दो, यानी कि 22 हजार स्कूल बंद कर दिए गये थे, आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं क्या? वो भी स्कूल वहां बंद किए जहां एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक लोग रहते थे। यह आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आप खुद देखिए आपने कहां-कहां स्कूल बंद किये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): नो बैग डे, सबसे अच्छा काम यह रहा कि नो बैग डे। अभी एनुअल फंक्शन में गई थी तो मैंने पूछा कि कब छुट्टी करोगे तो बच्चे कह रहे थे कि, मैडम, हम सैटरडे को तो छुट्टी नहीं

(श्रीमती सफिया जुबेर)

करेंगे, मतलब बच्चे जो स्कूल से छुट्टी करते थे, इस योजना से, नो बैग डे की वजह से वो अब स्कूल जाना पसंद करेंगे और छुट्टी नहीं करेंगे।

मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे रामगढ़ में मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री शान्ती धारीवाल जी ने एक नगरपालिका भी दी है, दो कृषि उपज मंडिया भी दी हैं। बहुत कुछ दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। एकदो कालेज की जरूरत और भी है अगर रामगढ़ में एक कालेज खुल जाएगा क्योंकि एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है और फिर भी मेरे पास कालेज नहीं है तो मुझे लगता है कि एक कालेज और आ जाएगा तो यह सोने पे सुहागा हो जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। समय हो गया, मैडम, प्लीज समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति जी, आप महिलाओं को तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): इसके अलावा पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, पंचायत समितियां बनी हैं, डीसैंट्रलाइजेशन आफ पावर हुआ है पंचायती राज में जिसको कांग्रेस हमेशा सपोर्ट करती है।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीक प्रधान, इसमें है जनता का सम्मान, यह है कांग्रेस की दास्तान।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संदीप जी शर्मा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मैं पुरजोर तरीके से इस बजट को समर्थन देती हूं। धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संदीप जी, 3 बज कर 15 मिनट हुए हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, 10 मिनट तो बोलने दोगे न?

श्री सभापति: हां, बिलकुल बोलने देंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिए गए बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

मुख्य मंत्री जी ने 20 फरवरी को अपना बजट का उद्बोधन दिया और हमने भी सुना और पूरे प्रदेश ने भी सुना और बड़ी निराशा हाथ लगी इस सारहीन, तथ्यहीन और आधारहीन बजट को सुनकर। किसी भी प्रदेश के लिए उसके बजट की बड़ी महत्वपूर्णता होती है, बहुत प्रमाणिकता होती है, विश्वसनीयता होती है क्योंकि यह बजट प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धता के लिए होता है और इस बजट के द्वारा ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इस बजट में कहा गया एक-एक कथन, एक-एक वाक्य, एक-एक घोषणाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं परंतु जब सरकार द्वारा पढ़े गये इस बजट को सुना तो निश्चित रूप से ये झूठ और खोखले वादों का पुलिंदा निकला। इसमें से अधिकांश घोषणाएं तो धरातल पर ही नहीं आ पायीं, बजट के कागजों में सिमट कर रह गईं।

चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि राजस्थान को नीरोगी राजस्थान बनाएंगे, स्वस्थ राजस्थान बनाएंगे परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो शुरू का वादा आपने किया था, प्रारंभिक तौर पर आप सौ जनता चिकित्सालय खुलवाओगे, जनता क्लिनिक खुलवाओगे, मेरा कहना है कि इन सौ में से पांच के अलावा छठा चिकित्सालय भी कहीं दिखाई दे जाए तो हम मान जाएंगे कि आप राजस्थान को नीरोगी बनाना चाहते हो, राजस्थान को स्वस्थ रखना चाहते हो। आपके मौहल्ला क्लिनिक तो कहीं नजर ही नहीं आते। आपके नीरोगी राजस्थान की हालत तो पूरे देश ने अभी कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में देखी है माननीय सभापति महोदय।

पिछले बजट में आपने वादा किया था कि 75 हजार सरकारी भर्तियां दोगे, वो सारी भर्तियों के परिणाम अटके पड़े हैं, अभी तक विज्ञापन भी नहीं निकले और आपने फिर 53 हजार की भर्तियों की घोषणा की है। क्यों आप मखौल करना चाहते हैं? जिन-जिन परीक्षाओं को लंबा समय हो गया, आर.ए.एस. की, आर.पी.एस.सी. की, उनके आपने अभी तक परिणाम घोषित नहीं करे।

आपने नंदी गौशालाएं स्थापित करने के लिए कहा था कि आप ग्राम

(श्री संदीप शर्मा)

पंचायतों में नंदी गौशालाएं बनाएंगे, एक भी ग्राम पंचायत में कोई नंदी गौशाला नहीं खुली।

संविदाकर्मियों के साथ आपने कहा कि उनको नियमित कर देंगे और यह ऐसे संविदाकर्मी हैं जो चार या पांच हजार रुपये महीने में अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं और इनसे एक हजार रुपये पहले एजेंसी के द्वारा ठेकेदार और अधिकारी मिलीभगत करके ले लेते हैं, फिर इनको पांच हजार रुपये का चैक दिया जाता है। अभी मेरे को हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने बताया कि मात्र चिकित्सा विभाग में 24 हजार ऐसे संविदाकर्मी हैं, तीन-तीन मंत्रिमंडलीय बैठकें हो गईं, उन मंत्रिमंडलीय बैठकों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और कम्प्यूटर पर, सफाईकर्मी, अन्य कर्मी, यह तो लाखों की संख्या में ऐसे संविदाकर्मी हैं जिनको नियुक्त करने के लिए हमने उनको सब्जबाग दिखाये, सुनहरे सपने दिखाये और अब सरकार पीछे हट रही है।

मैं सीधे-सीधे मेरे कोटा शहर की बात करता हूं। कोटा शहर जो शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है इस बजट में पूरे तरीके से उसकी घोर उपेक्षा की गई है। आई.आई.टी. इसका अधिकार था, दो लाख बच्चे इस कोटा शहर में पूरे देश भर से अध्ययन करने आते हैं लेकिन आई.आई.टी. जोधपुर चली गई। आईआईआईटी 9 साल से प्राइवेट कमरों में चल रही है। यह बड़ी ही निराशा की बात है। आपने 2020 में फिर कोटा के अधिकार को छीना। आपने कोटा शहर को कोचिंग हब देने के बजाय जयपुर को कोचिंग हब दिया। कोटावासियों के हितों पर आपने पुन: कुठाराघात किया। कोटावासी आपसे जवाब पूछ रहे हैं। आपने 650 करोड़ रुपये की विभिन्न घोषणाएं बजट में कीं जिनके कि टेंडर पहले हो चुके हैं। यह स्मार्ट शहर में कराए जा रहे हैं या सरकार इसका बजट प्रदत्त करेगी, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को बताएं कि यह कौनसा पैसा है?

सभापति महोदय, आपकी यूआईटी खस्ता हाल पड़ी हुई है। यूआईटी के पास पैसा नहीं है। आपने आईएल की कालोनी बेची। उसमें आपने फर्जीवाड़े से प्लाट बेच दिए। लोग उन प्लाटों को खरीदना नहीं चाहते। जो वर्तमान के हालात हैं, जो टेंडर कराते जा रहे हैं और आप उनको सरकारी बजट में भी

(श्री संदीप शर्मा)

दिखाते जा रहे हैं। राज्य सरकार के बजट में भी आपने घोषणा करवा दी। इसको स्पष्ट किया जाए।

सभापति महोदय, कोटा के सुपर स्पेशलिटी ब्लाक के लिए 150 करोड़ रुपये के जो प्रस्ताव थे, उसमें से 135 करोड़ रुपए लग चुके हैं। जनता जनार्दन के 135 करोड़ लगने के बाद, इसमें इक्विपमेंट लग गए, उसके बाद भी यह ब्लाक काम में नहीं आ रहा है। जनता जनार्दन का इलाज नहीं हो पा रहा है। हम बात करते हैं नीरोगी राजस्थान की। मात्र 29 लाख रुपये नगर निगम को, सरकार को माफ करके फायर एनओसी देनी है लेकिन वह फायर एनओसी भी राजस्थान की सरकार नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यह बड़े ही दु:ख की बात है। यह क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। जो सुपर स्पेशलिटी चीज है, जहां परम विशेषज्ञ बैठकर लोगों का इलाज कर सकते हैं। वह मात्र 29 लाख रुपये की वजह से बंद पड़ी हुई है। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

सभापति महोदय, कोटा में मथुराधीश जी का मंदिर है। वह वल्लभ कुल की प्रथम पीठ है। मथुराधीश जी का मंदिर एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो सकता है लोग यहां भारी संख्या में तीर्थ यात्रा करने के लिए आ सकते हैं लेकिन पर्यटन की दृष्टि से उसका कोई ध्यान नहीं है। उसके रास्ते संकड़े हो रहे हैं। लोग वहां घुस नहीं सकते हैं जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लोग यहां आने को तैयार हैं। इससे कोटा का रेवेन्यू बढ़ेगा। कोटा में लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इस मथुराधीश जी मंदिर का उद्धार कर दें तो यह लोगों की श्रद्धा का केन्द्र बन सकता है।

सभापति महोदय, कोटा चंबल नदी के किनारे भी प्यासा है। कोटा में स्थिति यह है कि 30-30, 40-40 साल से कोटा की पाइप लाइनें जीर्ण-शीर्ण पड़ी हैं। उनसे 40 परसेंट लीकेज है। मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया तो मंत्री जी ने बताया कि 40 प्रतिशत लीकेज है। स्मार्ट शहर के प्रस्ताव में 153 करोड़ के कार्य हमने करवाए थे लेकिन स्मार्ट शहर के प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। नए सिरे से अब प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। इसकी कोटा में भारी आवश्यकता थी। 2 लाख बच्चे वहां पर हैं, उनको जल पिलाना पड़ता है। आपने हमारे प्रस्तावों को खतम कर दिया।

सभापति महोदय, आपने 400 करोड़ रुपये से रिवर फ्रंट दिया। वह तो आप दे रहे हो लेकिन उस चंबल नदी में जो 22 गंदे नाले गिर रहे हैं, उनको

(श्री संदीप शर्मा)

रोकने का प्रयास करते। 222 करोड़ के 3-3 ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद भी बंद पड़े हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उनका गंदा पानी उस चंबल नदी में आ रहा है। उसको जहरीला बना रहा है। उसको लोग पी रहे हैं।

सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में आप कोटा को बिलकुल नजरंदाज कर गए जबकि कोटा कभी उद्योगों का गढ़ माना जाता था, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। वहां चंबल नदी का पानी है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में बिजली है। वहां पर दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा के औद्योगिक क्षेत्र को आपने कुछ नहीं दिया।

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार ने काम किए। इस सरकार ने हमारी आयुष्मान योजना को बंद किया। उन मीसा बंदियों की पेंशन को बंद किया जिनको इंदिरा गांधी ने आपातकाल ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उनके तानाशाही रवैये के चलते उनके परिवार बिखर गए थे।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हो गया। कृपया समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उनके बच्चे भूखे रहते थे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री किसनाराम जी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री किसनाराम जी।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने आज मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने दूसरा बजट पेश किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

हमारी पार्टी के जन घोषणा-पत्र की अवधारणा को लेकर, 7 संकल्पों की थीम को लेकर सरकार ने जनता जनार्दन की सेवा के लिए बजट पेश किया है। पिछले साल, सवा साल से प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आई है। सरकार ने काम संभाला है। पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी, वे घोषणाएं जमीन पर उतरी। उस सबके कारण आज प्रदेश की जनता, आम अवाम इस सरकार से खुश है। इस सरकार से संतुष्ट है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का और पूरी सरकार का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जन घोषणापत्र की करीब 30 प्रतिशत घोषणाएं साल, सवा साल के अंदर पूरी हो चुकी हैं।

सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान की थीम लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने 100 करोड़ का नीरोगी राजस्थान कोष का गठन भी किया है जिसका फायदा इस राजस्थान की आम अवाम को मिलेगा, राजस्थान की 36 कौमों को मिलेगा। गरीब लोगों, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनको मिलेगा। अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और वृक्ष लगाओ जैसे संकल्प लेकर इस प्रदेश की सेवा की थी। उसी तरह से यह 7 संकल्प लेकर हम आज आए हैं।

सभापति महोदय, पिछले बजट में सरकार ने कई पीएचसी प्रदेश के अंदर खोली हैं। कई सीएचसी भी खोली हैं। नए डाक्टर्स की भर्ती भी हो रही है। नर्सिंगकर्मियों की भर्ती भी हो रही है। हर परिवार की चौखट पर ही इलाज करने के लिए जनता क्लिनिक की भी शुरूआत सरकार करने जा रही है। पिछली सरकार ने नि:शुल्क दवाइयों को कम करके, उस व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। उनमें 709 दवाइयां करके जनता को सुविधा दी है। मरीजों को सुविधा देने के लिए सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, आप सबको मालूम है कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं किसान हैं। किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी कई योजनाएं लाए हैं। किसान के लिए पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने बिना ब्याज का डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण दिया था जो कि आज भी चालू है। साथ ही सरकार के आते ही किसानों के लिए एक हजार करोड़ के किसान कल्याण

(श्री किसनाराम विश्नोई)

कोष की घोषणा कर दी। वह भी अभी चालू हो रहा है। जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने फार्म पौण्डों की भी घोषणा की है। ड्रिप इर्रिगेशन में भी सरकार काम करने जा रही है।

राजस्थान की जनता 80 प्रतिशत जो गांव और ढाणियों में रहती है, वह कृषि पर निर्भर है। जमीन में जल स्तर नीचे जा रहा है। उनके जीविकोपार्जन के लिए फार्म पौण्ड्स बनाकर जल स्तर बढ़ाने का सरकार काम कर रही है। करीब 12 हजार फार्म पौण्ड बनाने की मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। इसका मैं स्वागत करता हूं। ड्रिप इर्रिगेशन के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। उसके साथ ही 25 हजार सोलर पम्प लगाने की भी मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए घोषणा की है। इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

किसानों के लिये घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं, विशेषकर पिछले एक साल से, सवा साल से सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी यूरिया की, डीएपी की कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यूरिया और डीएपी के भण्डारण के लिए भी व्यवस्था की है इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं।

पूरे प्रदेश में किसान उचित मूल्य पर अपनी जिंस बेच सके, नजदीक बेच सके, अपनी खेती की फसल नजदीक बेच सके, इसके लिए 44 स्वतंत्र मंडियों की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। मैं स्वयं एक साधारण खेतिहर किसान परिवार से हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए विशेषकर भले के लिए सोचा, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं।

सहकारी ऋण देने में जो लीकेज था उस लीकेज को मिटाने के लिए ऑनलाइन सहकारी फसली ऋण देने की जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करता हूं। हमारी सरकार ने पशुओं की जो दवाइयां पहले से चल रही थीं, उनकी संख्या को बढ़ाया है। पशु उप केन्द्र पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में खोलेंगे। लम्बे समय से पशुधन सहायक पदों की भर्ती अटकी पड़ी थी उनको नियुक्ति दी है जिससे आज गांवों में, ढाणियों में पशुओं को इलाज मिल रहा है। लोगों को उनके इलाज के लिये दूर नहीं जाना पड़ रहा है। भाजपा वाले हमेशा गायों की बात करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। पिछली बार पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदीशाला

(श्री किसनाराम विश्नोई)

की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी। आवारा पशुओं की हालत खराब है। आज सड़कों पर पशुओं का एक्सीडेंट होता है, वे एक्सीडेंटों में मरे जा रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था नहीं थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नंदीशाला खोलने की घोषणा की, उसका मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से वह भी धरातल पर आयेगी और आवारा पशुओं के लिए भी उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ये लोग गायों की बात करते हैं, ये बात तो गायों की करते हैं और इन्होंने ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया। आज एक ऊंट जिससे एक गरीब किसान अपनी जोत जोतता था, खेती करता था, ऊंट गाड़े से वह अपना रोजगार कमाता था और ऊंटों का इससे पालन पोषण भी सही ढंग से हो रहा था। आज ऊंट आवारा घूम रहे हैं, आवारा ऊंटों के कारण आज सड़कों पर जगह-जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, नेशनल हाईवे पर ऊंटों की जगह-जगह मृत्यु हो रही है, ट्रेनों से ऊंट कट रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऊंट की दुर्दशा हो रही है राज्य पशु घोषित करने से इसलिये ऊंट को वापस राज्य पशु से हटाया जाये ताकि ऊंट का पालन पोषण सही ढंग से हो और किसान अपनी खेती की जोत जोत सके और अपने अन्य काम कर सके, रोजगार कर सके, साथ ही ऊंट का पालन भी हो सके। यह भी मैं आपसे मांग कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, ईडब्ल्यूएस के अंदर केन्द्र सरकार ने आरक्षण दिया उसका राज्य सरकार ने सरलीकरण किया है, उसके लिए भी कई जातियों को विशेषकर प्रदेश में फायदा मिलेगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, हम लोग भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को इससे फायदा मिलेगा।

इसी तरीके से पंचायती राज में पिछली सरकार ने 2014 में पुनर्गठन किया, जहां पंचायत समिति बननी चाहिए थी वहां नहीं बनायी गयी। जहां ग्राम पंचायतें बननी थी वहां नहीं बनायी गयी। उनका पुनर्गठन, नवसृजन करके हमारी सरकार ने 1456 नयी पंचायतें बनायीं, 57 पंचायत समितियां बनायीं। इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मनरेगा में भी लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया गया था और पिछली सरकार ने 15 लाख रोजगार देने की बात की थी। वह मनरेगा के लोगों को रोजगार में, नौकरी में शामिल माना गया। इस तरीके से फर्जी आंकड़े पिछली सरकार ने पेश किये। मनरेगा में हमारी सरकार 53 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार नये-नये आयाम स्थापित कर रही है। सरकार द्वारा करीब 50 कालेज खोले जा रहे हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला स्तर पर खोले जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। दो मिनट, दो मिनट माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समय आपका पूरा हो गया, समाप्त करें प्लीज।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभी ब्लाकों में इंग्लिश स्कूल खोले जा रहे हैं। कम्प्यूटर शिक्षा और पानी के साथ ही जल जीवन मिशन जो घर-घर पानी देने की योजना है जिस पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है। उसमें भी मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अपना हिस्सा बढ़ाये ताकि गांव और ढाणी में लोगों को पेयजल मिल सके। सोलर नलकूप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत किये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): दो मिनट, दो मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं, आपका तो पूरा टाइम ही पांच मिनट का था। प्लीज, नहीं, एडवांस में, पहले ही ज्यादा समय ले लिया। घड़ी सबके सामने है। आपका समय समाप्त हो गया प्लीज।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मैं धोरां धरती से आता हूं। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे जोधपुर के लिए ही घोषणाएं की जा रही हैं। पिछले 2013 में आपको 34 में से 31 सीटें मारवाड़ ने दी थी लेकिन जोधपुर संभाग की भारी उपेक्षा हुई, एक भी धेले का काम नहीं हुआ, ...(व्यवधान) जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में जो सुविधाएं दी हैं, चाहे कैथ लैब की हो, चाहे वार्ड की हो, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करता हूं क्योंकि पूरे मारवाड़ में...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री गणेश घोघरा।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान) आपका अंकित वैसे ही नहीं हो रहा है। गणेशजी घोघरा।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सभापति: आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। श्री गणेश घोघरा।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, टीएसपी क्षेत्र से आता हूं। मुझे समय कम से कम दस मिनट का तो दें।

श्री सभापति: आप भूमिका नहीं बनाएं, अपनी बात कह दें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, गरीबों के मसीहा, जन-जन के लाडले, इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे शानदार और जानदार बजट की घोषणा की। सबसे पहले मैं नीरोगी राजस्थान के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान को स्वस्थ रखने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सौ करोड़ रुपये की घोषणा की है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीरोगी काया बहुत ही जरूरी है, भले ही हम कितना ही सोना-चांदी, पैसा कमा लें लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि कई योजनाओं के माध्यम से कई बीमारियों पर फोकस किया गया है। इसमें किडनी, लीवर और कैंसर जैसी भारी बीमारियों के लिए नि:शुल्क दवाओं का प्रस्ताव रखा है। हमारे आदिवासियों के लिये सौ रुपये की दवाई भी वहां फ्री मिल जाए तो वह हमारे लिये संजीवनी मानी जाती है इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच योजना का जो प्रावधान रखा है, 14 हजार करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान रखा है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मिलावटखोर मावा, स्कूलों में दूध जहर के माफिक, मिलावटी मिठाइयां बेच रहे हैं, उनके खिलाफ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक्शन लिया है उनके लिये प्रत्येक जिले में लैब लगायी जायेगी, जांच

(श्री गणेश घोघरा)

करायी जायेगी। ऑनलाइन किया जायेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी बहुत सराहनीय कदम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों के आवासियों को देय मैस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी दो हजार से बढ़ाकर ढाई हजार कर दी गई है, प्रति माह किया गया है।

राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25 हजार युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा, यह भी उनके लिये बहुत बड़ा काम है।

हमारे वहां उबड़-खाबड़ जमीन है, एक बीघा, दो बीघा जमीन है तो वहां किसानों के लिए फार्म पौण्ड की व्यवस्था की है जिससे वहां जल रुक सके और जल स्तर बढ़ सके।

किसानों के लिये सबसे बड़ी बात, वहां पर जो पहाड़ी एरिया है, टीएसपी एरिया, वहां पर उनको दिन में बिजली दी जायेगी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रथम फेज में डूंगरपुर को लिया गया है, इसके लिए सीएम साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसानों का 1800 करोड़ रुपये कर्ज माफ हुआ है सहकारिता विभाग से, बहुत-बहुत सराहनीय काम है। शिक्षा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुख्यालय पर खोली गयी हैं। आदिवासियों के लिए यह वरदान साबित हुई है और अगर यह हर ब्लॉक में खोली जाएगी तो गरीब आदिवासी जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता है, वह अब इसके माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख सकेगा। यह बहुत ही सराहनीय काम है।

टीएसपी एरिया में जो वनाधिकार के पट्टे दिये हैं, वह भी सराहनीय काम है। कई वर्षों से आदिवासी लोगों की मांग थी बिलानाम जमीन पर पट्टे दिये जाएं। जो वर्षों से बैठे हुए हैं, उन्हें पट्टे दिये जाएं। इसमें भी मैं सरकार से और सीएम साहब से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी वनाधिकार के पट्टे बाकी हैं, नहीं मिले हैं। बिलानाम भूमि पर जो भी आदिवासी वर्षों से बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि विशेष शिविर लगाकर टीएसपी एरिया में आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिलाये जाएं।

(श्री गणेश घोघरा)

इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां पर अगले बजट सत्र में सीएम साहब ने विधि कालेज के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति जारी हो चुकी है। मैं सीएम साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां आदिवासी बैल्ट में एक विधि कालेज खोलकर बहुत बड़ा काम किया है और नीति घोषणा जारी कर दी है। यह हमारे आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा काम है।

सीएम साहब सीमलवाड़ा आये थे। वहां उन्होंने मांडली वाली रोड की घोषणा की थी। इन्होंने उसके लिए बजट में 19 करोड़ 26 लाख की घोषणा की है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे विपक्षी साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने हर बात पर मोदी-मोदी की बात कही। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इनके अच्छे दिन कहां गये, काला धन कहां गया, पंद्रह लाख रुपये कहां तक पहुंचे, यह मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। पांच साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र को अटल सेवा केन्द्र कर दिया। राजीव गांधी विद्युतीकरण नाम को इन्होंने पं. दीनदयाल ज्योति में बदलने का काम किया है। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है, और कोई काम नहीं किया। यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा पट्टे दिये जा रहे हैं, लेकिन केन्द्र में मोदी सरकार जो बैठी हुई है, उसने लाखों आदिवासियों को बेघर कर दिया है। आप उनसे कहें कि आदिवासियों और एससी-एसटी के आप हितैषी नहीं हैं। आज एससी-एसटी को कहीं भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आज हर विभाग में गुरु द्रौणाचार्य बैठा हुआ है जो एकलव्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मैं एससी-एसटी की यह तकलीफ आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

आज डूंगरपुर नगर परिषद् पूरे भारत में स्वच्छता के मामले में नम्बर वन बन रही है, लेकिन वहां पर आदिवासियों के कितने झोंपड़े गिराये गये, कितनी जमीनों की नीलामी कर दी, यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं। डूंगरपुर नगर परिषद् ने कितना भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? इसकी जांच होनी चाहिए और गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जांच कब होगी?

(श्री गणेश घोघरा)

जो जमीन तालाब की थी, उसे भी भू-माफियाओं के साथ मिलकर प्लाट काटकर बेच दी। यह क्या हो रहा है? यह आदिवासियों के साथ बिलकुल अन्याय हो रहा है।

हर विभाग में गुरू द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। प्राचीन काल में उस एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, क्योंकि अर्जुन को गुरू द्रौणाचार्य आगे संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। आज भी हर विभाग में गुरू द्रौणाचार्य बैठे हुए हैं, हर विभाग में एकलव्य आगे बढ़ना चाहता है और उसमें योग्यता भी है, फिर भी एससी-एसटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अभी भी कई मांगें हैं। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक हमें आरक्षण का फायदा नहीं मिला। प्रशासनिक सेवाओं में साढ़े बारह में से साढ़े पांच प्रतिशत आरक्षण हम आदिवासियों को मिलना चाहिए। आदिवासियों में मालामाथा से कालापानी तक देश आजाद हुआ, आज भी वहां पर कोई गया नहीं है, वहां पर रोड नहीं बनी है। जंगल में आदिवासी बसते हैं। आज भी स्कूलों की हालत खराब है, वहां पानी टपक रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं। मैं सीएम साहब से मांग करना चाहूंगा कि हमारे यहां डूंगरपुर में एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए। यह मेरा मुख्य पाइंट है। कृषि महाविद्यालय खुलने से हमारे बच्चों को उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जो कृषि का सब्जैक्ट है, वे उसे छोड़ देते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाए, जिससे आदिवासियों का भला होगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस बजट में वित्तीय प्रबंधन, प्रशासकीय कौशल दर्शाने के बजाय केन्द्र सरकार और पूर्ववर्ती राज्य सरकार को कोसने पर ही ऊर्जा व्यय की गयी

(श्रीमती संतोष)

है। वित्तीय संसाधनों के बिना बजट घोषणाओं का अम्बार लगा दिया गया है। वार्षिक बजट विजन डाकूमेंट होता है। ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी अपना विजन तय कर पाने में असफल रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जिस पर 245 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, इन्दिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग के लिए बजट में प्रावधान तो रखा है, लेकिन पूर्व का रीलाइनिंग कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पहले उसे पूर्ण करवाया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। बजट में सीपेज के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रस्तावित नहरबंदी से किसान भाइयों को मात्र एक सिंचाई पानी की बारी मिलने से खेतों में तैयार खड़ी फसलें बच सकती हैं, लेकिन एक सिंचाई पानी न मिलने के कारण वे फसलें नष्ट हो जाएंगी। वह एक बारी अगर दे दी जाए तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

बार-बार नहरबंदी की बात की जाती है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहरबंदी 70 की बजाय 40 दिन की जाए। मैं इसके लिए पहले भी सरकार से आग्रह कर चुकी हूं। प्रस्तावित नहरबंदी को पंद्रह-बीस दिन आगे बढ़ाकर किसानों को एक अतिरिक्त सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, जिससे कि उनके खेतों में खड़ी फसल तैयार हो सके, क्योंकि अभी रबी की जो गेहूं की फसल है, वह मात्र एक सिंचाई पानी न मिल पाने के कारण नष्ट हो जाएगी।

सभापति महोदय, भूमि के जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संरक्षण एवं नहरी पानी को डिग्गियों में सिंचित किया जाता है, लेकिन गंगानगर जिले के काश्तकारों ने डिग्गियां कर्ज लेकर बना ली हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा तय की गयी अनुदान राशि नहीं दी जा रही है। इसके लिए बजट में भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिग्गियों की अनुदान राशि शीघ्र दिलवायी जाए।

बजट में उल्लेख किया गया है कि राज्य में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को चिह्नित किया गया है, लेकिन इसमें मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ की उपेक्षा की गयी है। अनूपगढ़ से नारावाली रोड, जिसकी मांग मैंने पहले भी की थी, इस सड़क की हालत बहुत खराब है, ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी के साथ पुरानी मण्डी घड़साना से रावला रोड, रामसिंहपुर से

(श्रीमती संतोष)

गोमावाली पूपली, माइलेटी की रोड व क्षेत्र में अन्य कई ऐसी सड़कें हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिनके बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

बजट में नीरोगी राजस्थान की बात की गयी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, पद खाली हैं। ऐसे में राजस्थान कैसे नीरोगी होगा, जब अस्पताल में दवाई देने वाले या जांच करने वाले डाक्टर ही नहीं होंगे? इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अस्पतालों में डाक्टरों के पद काफी लम्बे समय से खाली पड़े हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भारत माला रोड गुजर रही है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इस मार्ग पर गंगानगर से सत्तासर के मध्य कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। बजट में जो सरकार द्वारा ट्रोमा सेंटर्स की घोषणा की गयी है, उसमें अनूपगढ़ को वंचित रखा गया है। अनूपगढ़ में ट्रोमा सेंटर स्थापित हो जाए तो दुर्घटनाओं से काल कवलित होने से लोगों को बचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती सम्बन्धी उपकरण किराये पर उपलब्ध करवाने के लिए सौ कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गयी है, लेकिन दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में सौ कस्टम हायरिंग केन्द्र खुलवाया जाना बहुत ही कम है। किसानों को खजूर की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरे गंगानगर जिले के किन्नू पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। काश्तकारों को किन्नू उत्पादन पर फसल के समय जो मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है और काश्तकार अपनी फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राज्य में कराधान वसूली के लिए दोहरी नीति अपनायी जा रही है। व्यापारी अपना व्यापार करें या सरकार को अलग-अलग करों की विवरणियां दाखिल करे। हमारे उद्योगपति, व्यापारी चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार कर प्रणाली को संतुलित बनाये ताकि व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत मिल सके।

ऐसा लगता है कि राज्य सरकार शिक्षा के प्रति भी गंभीर नहीं है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है। मेरे क्षेत्र

(श्रीमती संतोष)

में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां एक ही संकाय पढ़ाया जा रहा है, वहां नवीन संकाय खोले जाएं व खाली पदों को भरा जाए ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगता है जहां आज भी ऐसे कई गांव और ढाणियां हैं जहां पेयजल की भारी किल्लत है। ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके इसके लिए सरकार कोई प्रावधान लेकर आये।

इस बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं लेकिन किसान आज भी प्रताड़ित है, किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखे गये हैं। कुछ समय पहले राजस्थान में टिड्डी दल का हमला हुआ था और ओलावृष्टि भी हुई थी जिसका मुआवजा नाममात्र का घोषित कर दिया गया है तथा किसानों को अभी तक उससे कोई राहत नहीं मिली है जिसका बजट में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, इस बजट में सरकार ने जनता को किसी प्रकार की आर्थिक राहत नहीं दी है। यह बजट नकारात्मक मानसिकता से भरा है जिसमें विकास का कोई नया आयाम नहीं दिया गया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे बजट 2020-21 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मुझे कुशलगढ़ क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी दी। इसी तरह से मैं सभापति जी से निवेदन करती हूं कि हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में एक हास्पिटल है वह जर्जर अवस्था में है। कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ का हास्पिटल बहुत पुराना है और मैं पिछली बार भी सदन में बोल चुकी हूं। मैं इस सदन में मांग करती हूं कि कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ का भवन मुझे दिया जाए क्यों हमारी कुशलगढ़ की जनता गुजरात में इलाज कराने के लिए जाती है, बांसवाड़ा जाती है, उदयपुर जाती है जिससे उनको भटकना नहीं पड़े।

इसी तरह मैं सभापति महोदय से कहना चाहती हूं, पिछली सरकार में मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे पिपलोन कुंडिया 25 करोड़ की लागत से बनाया था जो अच्छा है। उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया और

(श्रीमती रमीला खड़िया)

जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने उसको ढंग से नहीं बनाया और उसमें सीपेज है। मैं मांग करती हूं कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो पिपलोन कुंडिया है उसमें जो सीपेज है और नीचे की ओर पानी जा रहा है उसको एनीकट के रूप में बनाएं। हमारा घाटा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि बिलकुल पिछड़ा हुआ है। बिजली, पानी से वंचित है इसलिए इसमें एनीकट बनवाकर लिफ्ट द्वारा पाटन, छोटी सरवा, बड़ी सरवा, इन सबको पानी दिया जा सके। इसी तरह से मैं मांग करती हूं कि पिपलोन कुंडिया की जो नहर जा रही है वह बिलकुल कच्ची है और काश्तकारों को पानी मिलना तो दूर की बात है, इनके घरों में पानी घुस रहा है, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है और बिलकुल हालत खराब है। मैंने पिछली बार उसका सर्वे किया था तो काश्तकारों के घरों में पानी घुस रहा है। खेतों में गेहूं नहीं पक रहे हैं क्योंकि पानी ऊपर आ गया है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं और मांग करती हूं कि इस नहर का बजट दिया जाए और इस नहर को पक्का किया जाए ताकि आगे वाले काश्तकारों का भला हो सके।

सभापति महोदय, मैं घाटा क्षेत्र की बात आपको कहना चाहती हूं। मैंने पाटन पोटलिया में पिछले शनिवार को एक विजिट की थी। पाटन पोटलिया में एक स्कूल है वहां मात्र दो टीचर हैं जबकि पांच पोस्ट है। उसमें बड़े दु:ख की बात है जो मैंने देखी कि बहुत पुराना भवन है और मात्र दो कमरे उसमें हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पाटन पोटलिया में आज की तारीख में 175 बच्चे हैं तथा दो कमरे हैं और वे दो कमरे भी जर्जर अवस्था में हैं। वहां पानी के मौसम में बच्चे अन्दर नहीं बैठ सकते हैं और आज भी वहां हालत बहुत खराब है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखती हूं कि ये दो कमरे जो हैं उनकी जगह वहां कम से कम 5 कमरे बनाये जाएं और दो टीचर की जगह 5 टीचर लगाने की भी मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूं।

इसी तरह से कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़क, बिजली से कुशलगढ़ की जनता बहुत दु:खी है और यह मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं।

इसी तरह से एक कृषि मण्डी अभी मुख्य मंत्री जी ने दी है उसके लिए दुबारा धन्यवाद देना चाहती हूं और जल्दी से जल्दी उस मण्डी को चालू

(श्रीमती रमीला खड़िया)

किया जाए ताकि हमारे काश्तकार को मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चने पकते हैं तो मण्डी खुल जाती है तो उसका फायदा उनको मिल सकता है।

इसी तरह से पिछले बजट में जो सज्जनगढ़ में महाविद्यालय दिया था उसमें आज की तारीख 500 बालक-बालिकाएं पढ़ रहे हैं। वे एक कुण्डा स्कूल में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी उसके लिए बजट दिया जाए ताकि भवन बन सके और बच्चों को सुविधा हो सके। अभी दो-तीन कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, ओनली वन मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट। हमारे ध्यान में है। आप विराजें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने को मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। 2020-21 का बजट सरकार का जनता को आईना होता है। हमारे मुख्य मंत्री ने 7 संकल्प लिये, मैं एक संकल्प पर ही विशेषकर ध्यान दूंगा, वह है सम्पन्न किसान। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किसान आज बदहाली में है। विशेषकर जो ट्यूबवैल से खेती करता है, उनकी समय पर न तो खरीद की इस घोषणा पत्र में है और फसल खरीद की कहीं बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर विशेषकर मेरे इलाके बीकानेर में ट्यूबवैल से खेती होती है, सैकड़ों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। आज फसल पकाव पर है, सरकार का मैं स्वागत करता हूं कि जो नहर पर अलाटमेंट हैं उनमें छूट दी गई है जो किसान समय पर किश्त नहीं चुका पाये। बीकानेर जिले के अन्दर ट्यूबवैल से जो खेती करता है, हर बार, हर सरकार द्वारा जब समय पर बिजली का बिल नहीं चुका पाते, उस समय ब्याज और पैनल्टी माफ की जाती है तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अभी ये जो किसान दुविधा में हैं और समय पर बिल नहीं चुका पाते, उनको भी राहत प्रदान करें।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान के लिए जहां कई जगह ट्रोमा सेंटर खोले गये हैं विशेषकर जोधपुर जिले में, मैं उसका स्वागत करता हूं और साथ-साथ मैं भी मांग करता हूं कि रतनगढ़ से बीकानेर के बीच सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और लम्बे समय से वहां की जनता द्वारा, जन

(श्री गिरधारीलाल)

प्रतिनिधियों द्वारा ट्रोमा सेंटर डूंगरगढ़ में खोलने की मांग की जा रही है। वहां से 70 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, 70 किलोमीटर रतनगढ़ पड़ता है और बीच में कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं होने की वजह से, दुर्घटना होने पर समय पर मरीज को हास्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता। ट्रोमा सेंटर की लम्बे समय से मांग की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा के राज में जो स्कूल समायोजित कर दिये गये थे उनमें अभी सरकार द्वारा समायोजित किये गये विद्यालयों को खोला गया है उनका स्वागत करते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में जहां शैक्षणिक व्यवस्था कम है विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में, कीतासर के अंदर वहां क्रमोन्नत करने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है। पिछले लोक सभा चुनाव में वहां की जनता ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया था। यही कहते हुए मैं यह भी मांग करूंगा कि बजट के अंदर, माननीय कल्ला साहब बैठे हैं, राजस्थान मायड़ भाषा के प्रोत्साहन की बात इसमें नहीं लिखी गई तो माननीय कल्ला साहब, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मायड़ भाषा को दोयम दर्जे के रूप में, जहां हमने 12वीं विधान सभा में संकल्प पारित करके, विधान सभा के अध्यक्ष परसराम जी थे, कल्ला साहब भी थे, गहलोत साहब के द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प भेजा था।

इसी प्रकार हमारे बजट के अंदर निश्चित रूप से जनता आस लगाए होती है चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, बजट का एक संदेश ऐसा जाए कि जब सत्ता पक्ष उसकी सराहना करता है, विपक्ष उसकी आलोचना करता है, ऐसा न होकर निश्चित रूप से जनता को नौजवान को, दलित को फायदा मिले, मैं यही कहते हुए स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण जी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह आंकड़ों के मकड़जाल जैसा प्रतीत होता है। यह थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है। सभापति महोदय, हम लोगों ने पिछले बजट 2019-20 को बहुत बारीकी से देखा, चश्मा लगाकर भी देखा, परन्तु जालौर जिले का कहीं नाम नहीं था और अब की बार जो यह बजट पेश किया, मात्र सांचौर में

(श्री नारायण सिंह देवल)

एक ट्रोमा सेंटर खोलकर मंत्री जी को खुश करने के लिए इतिश्री कर दी। चलो कोई बात नहीं, पिछले बजट में जालौर जिले की याद नहीं आई। इस बार तो बजट में आपको याद आया। मैं तो कहना चाहूंगा कफस में रहकर इंसाफ मांगने वालों, यही बहुत है कि फरियाद की इजाजत है। उसका कारण मुझे मोटा-मोटा यह नजर आता है कि जालौर जिले में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। एक मात्र विधायक जीता, लोक सभा में भी इनकी बुरी तरह से हार हुई। उसी का नतीजा है कि हम ये सब झेल रहे हैं। इसके लिए मैं कहने जा रहा हूं "न तो तड़पने की इजाजत है, "न फरियाद करने की इजाजत है, घुटके मर जाऊं, यह मर्जी मेरे सय्याद की है।"

सभापति महोदय, हमारे जालौर जिले की जीवनदायिनी नर्मदा नहर है, तीन प्रोजेक्ट हैं। न तो पिछले बजट में एक रुपया दिया और न ही इस बजट के अन्दर एक रुपया दिया। जालौर जिले में पिछली बार भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई और इस बार भी नहीं हुई। जालौर जिले के किसान लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि नर्मदा का जो एक्सेस वाटर है, जो नदियों में जा रहा है। सांचौर के नहर क्षेत्र में जलमग्न हुआ है तो किसान मांग कर रहे हैं कि सिंचाई के लिए यह पानी मिले और इसका विस्तार किया जाए। इसके बारे में भी बजट में बात नहीं कही गई। मेरे रानीवाड़ा विधान सभा में डीआर प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 138 गांवों को पीने के पानी का फायदा मिलने वाला है। दिसम्बर में यह काम पूरा होना था और अब तक मात्र 39 गांव ही जुड़े हैं और इस डीआर प्रोजेक्ट में भी एक रुपया भी नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, रानीवाड़ा उपखण्ड कार्यालय है। दोनों साइड बस्ती है, बीच में रेलवे ट्रैक है। दिन भर में 35 गुड्स और ट्रेन चलती हैं। जनता की लम्बे समय से मांग है कि यहां आरओबी बनाया जाए, उसका सर्वे भी हो गया है परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण ये आरओबी भी नहीं बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सीएजी की रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें तो 31 दिसम्बर, 2019 को एक रिपोर्ट में सीएजी ने बताया है कि लगभग 56-57 परसेंट ही पैसा खर्च हुआ है। आधा दिसम्बर निकल गया और तीन महीने बाकी है। मुझे तो नहीं लगता कि आप कौनसा तीर मारकर, यह सारा पैसा आप खर्च कर दोगे।

(श्री नारायण सिंह देवल)

सभापति महोदय, इस सरकार ने सब्सिडी देने में तो कमाल ही कर दिया। मात्र 25 प्रतिशत ही पैसा सब्सिडी का ये लोग खर्च कर पाये हैं। जो पिछली सरकार ने किसानों को 833 रुपये एक बिल में सब्सिडी देने का वादा किया था, वह सब्सिडी भी इन्होंने बंद कर दी और इसके अलावा न जाने कौन-कौनसी इस सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 के बजट में एक किसान कल्याण कोष के गठन का सरकार ने निर्णय किया था। उसका भी नाम बदलकर कृषक कल्याण कोष कर दिया गया। एक हजार करोड़ का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। मैं कहना चाहूंगा अभी मंत्री जी के रिप्लाई में आया, इस एक हजार करोड़ में से 6 सौ करोड़ तो प्रधान मंत्री फसल बीमा के प्रीमियम के दे दिये और इसके अलावा कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि किसानों के फसल के मूल्य में एमएसपी के कहां-कहां आपने पैसे दिये हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पैसा दिया गया है। इस बजट के अंदर कहा गया है कि ग्राम सेवा सहकारी सोसायटी के अंदर 700 से ज्यादा जीएसएस बना दिये जाएंगे, गोदाम बना दिये जाएंगे। बना दिये क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये केवल और केवल थोथी घोषणा है। किसानों के सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कही। मुख्य मंत्री जी ने टोंक जिले के दो किसानों का उदाहरण दिया, किसान लड्डू लाल का 7 लाख 58 हजार, देवकरण का 5 लाख 61 हजार।

माननीय सभापति महोदय, मेरे रानीवाड़ा विधान सभा के अंदर दहीपुर गांव में काश्तकारों की जमीन पैसा नहीं भरने के कारण कुर्क कर दी और पूरे राजस्थान में ऐसे हजारों की संख्या में आंकड़े हैं। अल्पकालीन फसली ऋण में इन्होंने 2019-20 में 16 हजार करोड़ का बजट का प्रावधान किया था और अभी तक दिया मात्र है 8 हजार 4 सौ 97 करोड़, मतलब आधा और इसमें भी आपने एक राइडर लगा दिया है, साख सीमा, काश्तकारों को एकमुश्त पैसा नहीं दिया जा रहा है और सरकार अपने आपको किसान की हमदर्द समझ रही है।

अभी एक नया फंडा लेकर आई है नीरोगी राजस्थान। मैं बजट का मेन पृष्ठ देख रहा था। इसमें जो राजस्थान का मैप है, उसके अंदर तो आपने कहीं नीरोगी राजस्थान का उल्लेख नहीं किया और इसके चारों ओर आपने

(श्री नारायण सिंह देवल)

राजस्थान के नीरोगी का उल्लेख कर दिया है तो ये जो आपकी मंशा है, इस बजट के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। इसमें आपने 1291 करोड़ का प्रावधान किया है और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें आपने 28 करोड़ की कमी कर दी है। माननीय सभापति महोदय, पूरे साल के अंदर इस सरकार ने 5 पीएचसी को अपग्रेड किया है और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014-15 में 5 पीएचसी से सीएचसी को अपग्रेड किया और 12 नई पीएचसी खोलीं और 3 नये सब सेन्टर खोले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जसवतंपुरा के अंदर एक हास्पिटल है, पूरा एक डाक्टर के भरोसे चल रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग हैं, वह मैं निवेदन कर दूं। कहना तो बहुत था मगर आप समय नहीं दे रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग करता हूं। जालौर जिले के जो तीनों प्रोजेक्ट नर्मदा के हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करें। ईआर प्रोजेक्ट में क्लस्टर में स्वीकृति दिलाएं। नर्मदा का जो सरप्लस वाटर है, वह खेती के लिए दिया जाए। रानीवाड़ा में कालेज स्वीकृत हुए दो साल हो गये हैं। भवन के अभाव में आज भी बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): जसवंतपुरा के अंदर आईटीआई बिल्डिंग बन चुकी है, तुरन्त चालू की जाए और बड़गांव के अंदर एक फल-सब्जी मण्डी की घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि रानीवाड़ा तहसील के अंदर जलदाय विभाग के दोनों ए.ईएन. के पद खाली हैं, सारे जे.ईएन. के पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी काम करने वाला नहीं है, उनको भरा जाए। आपने मुझे बोलने दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) आसन इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है?

श्री सभापति: आप इनका खतम होने दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिर्फ एक मिनट लूंगा मैं।

श्री सभापति: दे रहा हूं, फर्क कौनसा पड़ रहा है। विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संवेदनशील मुद्दा है।

श्री सभापति: दे रहे हैं। आप विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपके होने के बाद भी यह हालत है।

श्री सभापति: विराजिये। दे रहे हैं। श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, 7 संकल्पों को प्राथमिकता से बनाया है। पहला सुख नीरोगी राजस्थान जिसके तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय, जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारम्भ करने के लिए गैस्ट्रो सर्जरी वार्ड की स्थापना किया जाना बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से रोगी यहां आते हैं, सबको फायदा मिलेगा। एसएमएस हास्पिटल, जयपुर में वर्तमान काटेज वार्ड के स्थान पर 8 मंजिला नया आईपीडी भवन बनवाने एवं जिसमें कोटेज वार्ड के साथ-साथ सामान्य वार्ड की सुविधा विकसित करने के लिए 28 करोड़ रुपये प्रस्तावित करना बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे भी आने वाले मरीजों को सुविधा होगी। जयपुर में कैंसर के उपचार के लिए उच्च श्रेणी के अस्पताल राज्य कैंसर संस्थान में ओपीडी प्रारम्भ कर इसे अगले वित्त वर्ष में संपूर्ण आधुनिक उपकरणों द्वारा यथा लीनियर एक्सीलरेटर, माड्यूलर आपरेशन थिएटर के साथ सुचारु रूप से चलाए जाने से इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों को राहत मिलेगी।

सीकर जिला मुख्यालय पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 50 शय्याओं के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना करने का जो संकल्प लिया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

दूसरा संकल्प-सम्पन्न किसान। महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसान को सम्पन्न बनाने के लिए पहले बजट में 1000 करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की थी, जिसके तहत कृषक कल्याण कोष स्थापित किया जा चुका है जो सराहनीय कदम है।

हमारा प्रदेश कृषि क्षेत्र में सोलर पम्पों की स्थापना में देश के प्रथम स्थान पर है, यह हमारे लिए खुशी की बात है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए

(श्री हाकम अली खां)

कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 25000 सोलर पम्प लगाने के लिए 267 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना किसानों के हित का काम है।

तीसरा संकल्प-महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण में पांच करोड़ रुपये की लागत से जिला मुख्यालय जयपुर में सौ शय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण करवाये जाने तथा वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये ग्रांट उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

चौथा संकल्प-सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान। महोदय, यह संकल्प हमारी सरकार द्वारा ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं को खोजकर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लाक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करने हेतु राशि 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम साबित होगा तथा वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल अधिक सफल हो सकेंगे, जिसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

पांचवां संकल्प-शिक्षा का परिधान। महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो और संस्कारित हो, इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में 39 हजार 524 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महोदय, राइट टू एजुकेशन के तहत राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिक से लेकर सीनियर सैकंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर सैकंडरी विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलना सुनिश्चित है तथा प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त संकाय, 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले जाने का प्रावधान सराहनीय कदम है।

महोदय, यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की कमी है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां उर्दू पढ़ने के इच्छुक छात्रों की पर्याप्त संख्या है परंतु अध्यापक नहीं हैं। जहां-जहां, जिन-जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने के लिए इच्छुक छात्र पर्याप्त संख्या में अध्ययनरत हैं, उन सभी विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएं तथा जहां

(श्री हाकम अली खां)

पद स्वीकृत हैं वहां अध्यापक लगाए जाएं और आगामी शिक्षक भर्ती में उर्दू अध्यापकों की पर्याप्त भर्ती की जाकर उर्दू के पदों को भरा जाए।

छठा संकल्प - पानी, बिजली व सड़कों का मान। महोदय, प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जलदाय विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8,794 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में किसान भाइयों को खेती के लिए रात्रि में बिजली उपलब्ध कराए जाने से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ता था। हमारी सरकार ने किसानों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दिन में 2 ब्लाकों में कृषि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है जो सराहनीय कदम है। इससे किसान भाइयों की परेशानी कम होगी।

महोदय, प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में घायल होने पर नजदीकी निजी अस्पताल में लाए जाने पर निजी अस्पताल द्वारा उसका उपचार करना अनिवार्य किया जाना बहुत ही अच्छा विचार है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में आने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी तथा दुर्घटना में घायल हुए लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

महोदय, वित्त वर्ष 2020-21 में आरयूआईडीपी-चतुर्थ चरण के अंतर्गत कराए जाने वाले सीवरेज कार्य में मेरे फतेहपुर को शामिल करने के लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): देश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 22 स्मारकों का पुनरुद्धार किए जाने हेतु राशि 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना सराहनीय कदम है। इससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण का काम किया जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): महोदय जी, हम नीरोगी राजस्थान का संकल्प लेना चाहते हैं कि राजस्थान स्वस्थ नीरोगी बने और इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुबह-सवेरे भ्रमण करने के लिए किसी प्रकार का पार्क

(श्री हाकम अली खां)

नहीं है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार का, मंत्री जी का ध्यान दिलाकर मेरे फतेहपुर में एक पार्क निर्माण किये जाने का निवेदन करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं। मदरसा पैरा टीचर जो 6000 रुपये में लगे हुए हैं। 6000 रुपये में कुछ नहीं होता है, उन-उन मदरसा पैराटीचर्स पर ध्यान दिया जाए। उनको या तो नियमित किया जाए और नियमित नहीं किया जाए तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए।

महोदय, नीरोगी राजस्थान के तहत आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के राजकीय धानुका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक लाख से अधिक सालाना मरीज आते हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल के बैड्स की संख्या बढ़ाकर 50 से 100 की जाए जिससे सभी वर्गों के लोगों का इलाज समय पर किया जा सके।

महोदय, फतेहपुर एक हैरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है। यहां देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन काफी संख्या में होता है। अतः महोदय, मैं चाहता हूं कि फतेहपुर शहर को एक अच्छा हैरिटेज शहर बनाने के लिए अलग से बजट देकर सभी टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए। अंत में, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर का रतनलाल जो कल परसों दिल्ली में घटना हुई थी उसमें शहीद हो गया और उसको शहीद का दर्जा दिया जा चुका है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको एक अच्छा पैकेज देकर सरकार एक अच्छा मैसेज दे। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मुझे 2020-21 के बजट पर बोलने का आपने जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। परिस्थितियों के अनुसार हमारे नेता जी ने हमें 10 मिनट दिए हैं। आपसे पहले ही मेरी तो मांग यही रहेगी कि मुझे 5 मिनट और दे दो तो थोड़ा फायदा रहेगा।

श्री सभापति: आप भूमिका मत बनाओ तो आपको समय मिलेगा। भूमिका मत बनाओ। आप तो बहुत अच्छा बोलते हो।

श्री रूपा राम (मकराना): वैसे पगड़ी से पगड़ी मिले, कर-कर लंबे हाथ। 5 मिनट मांग रहा हूं, दे देना सात।

माननीय सभापति महोदय, बजट पर सभी माननीय विद्वान सदस्यों ने, मैं पिछली बार जब विधान सभा में बोल रहा था तो एक ऐसा समय आया कि मैं बोल रहा था और माननीय सभी पक्ष और विपक्ष के विद्वान सदस्यों ने मेरे लिए टेबलें थपथपाई, धन्यवाद। आपके प्रेम से, आपके सम्मान से मैं कोशिश करूंगा, मैं विपक्ष की मेरी जिम्मेदारी पर खरा उतरूं चाहे आप प्रेम करें, चाहे टेबलें बजें, चाहे न बजें। मैं आज बजट पर चर्चा के समय इतना ही कहना चाहूंगा कि..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप तो एक गीत सुना दो, समय पूरा हो जाएगा। काहे के लिए बजट-बजट, जो चाहिए मिल जाएगा, कहां चिंता करते हो।

श्री रूपा राम (मकराना): मैं वादा करता हूं माननीय सभापति महोदय, एक शाम विधायकों के नाम रखकर देख लीजिए, उसमें मैं खरा उतरूंगा। अभी मुझे मेरे क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर, समस्या और समाधान को लेकर कुछ बोलने दीजिए। लाया तो बहुत हूं माननीय मंत्री जी, कुछ तो बोलने दीजिए। माननीय विद्वान सदस्यों के जो कहने के तरीके से मैंने सुना है, कोई वीर रस में बोल रहे हैं, कोई चापलूसी रस में बोल रहे हैं, कोई खीझ रस में बोल रहे हैं, कोई हास्य रस में बोल रहे हैं और अलग-अलग बोल रहे हैं। कुछ को बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। कुछ प्रेम से और मधुर भाषा से बोल रहे हैं और कुछ हर शब्द में जहर घोल रहे हैं, यह मैंने देखा है। कुछ बोलने के लिये बोल रहे हैं। मैं किसी भी सरकारी योजना के बजट का समर्थन तब तक नहीं करता जब तक उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई गई हो। आज हम सब देख रहे हैं, बजट हो या विकास की कोई भी सरकारी योजना हो, जनता तक पहुंचने से पहले आधी से ज्यादा तो कुछ लोग जो राजनीति में बैठे हैं, अधिकारी हैं, वही चाट जाते हैं। आपकी पार्टी के प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी हुए थे। वैसे आप लोगों को धन्यवाद कि आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का अनुसरण करते हैं, उनकी बात आराम से मानते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम योजना में 100 रुपये भेजते हैं वह मुश्किल से 20 रुपये पहुंचते हैं। मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि कम से कम राजीव जी की बात को इतना तो तवज्जोह दीजिए कि उन्होंने जो कहा वह सच है।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद में आजादी के रखवालों ने, आजादी के दीवानों ने हमें कुछ नई-नई बातें बताई थीं। वैसे बोलने वाले अपने-अपने तरीके से बोलते हैं, वह मैंने बता दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूं यहां जीने के ढंग सबके अलग-अलग होते हैं। ईश्वर की लीला देखो, 9x6 इंच हमारा चेहरा है, फिर भी दो शक्लें दो करोड़ में नहीं मिलती तो बुद्धि तो हवा से भी पतली है, इसलिए अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सोच से बोल रहे हैं। इस पर मैंने लिखा है। जीने का ढंग जग में न्यारा-न्यारा सा, कोई न लागे सांच मीठो, कोई न खारा-सा। जग में जीने का ढंग अलग-अलग है। राजनीति में होते हुए भी सेवा की बजाय अपना फायदा कर रहे हैं, उनके लिये मैंने कहा है, वे इतने नादान निकले कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं, हमें देखो उनके गुनाह से अपने आप में शर्माते हैं। मैं आपको एक साधारण सा सुझाव दे रहा हूं, भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है, जनता की सेवा की बजाय अपनी सेवा कर रहा है तो उनको कहा है, भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ, न आ सको वापस कोई बात नहीं, तनिक ठहर तो जाओ, वर्ना अनचाही राहों में बहुत दूर चले जाओगे, लाख चाहकर भी वक्त वापस आने का निकाल न पाओगे। कोई भी जन प्रतिनिधि क्या यह पसंद करता है कि उसके परिवार के लोगों को कहे कि तेरा बाप चोर है, तेरा बाप भ्रष्ट है, यह मान सकते हैं क्या हम? यह कोई पसंद नहीं करेगा लेकिन काम जरूर करेगा। यह मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है राजनीति से कठोर कोई तपस्या, साधना, यज्ञ और स्वर्ग का मार्ग नहीं हो सकता लेकिन हम भटक रहे हैं। इसीलिए कहा है कि भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ।

मेरे पास में शायद समय कम रहेगा इसलिए मैं पहले मेरी मुख्य बात बोल देता हूं। उसके बाद आप मना करोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा कोई ज्यादा लंबा खड़े रहने का मतलब नहीं है। नीरोगी राजस्थान पर मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं, मकराना में जहां लगभग डेढ़ लाख की आबादी है और 78 का स्टाफ है और मात्र 19 कार्यरत हैं, मात्र चार डाक्टर हैं। मेरे क्षेत्र मकराना, बोरावड़, गच्छीपुरा, बेसुरोली, मोरेड, बीलू, यहां सब जगह सरकारी अस्पताल हैं इनमें डाक्टर कम हैं। कल मकराना में इस बात को लेकर धरना दिया जायेगा, ज्ञापन दिया जायेगा कि जहां 78 का स्टाफ है, वहां सिर्फ 19 कार्यरत हैं।

(श्री रूपा राम)

दूसरा, बिजली विभाग व पानी विभाग के मंत्री जी नहीं हैं। मैं जब किसानों के मुद्दे पर बोला, सबने तालियां बजाईं। माननीय सभापति महोदय, किसान की समस्या को लेकर आज तक सरकार गंभीर नहीं है। मैंने यहां तक कहा था सभी कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को इस बात का भली भांति पता है कि किसान की समस्या क्या है। आज किसान को रात को बिजली देते हो और उसमें भी बीच में पावर कम देते हो, जब चाहे तब काट लेते हो। किसान पैसे देकर भी बिजली नहीं ले पा रहा है। शायद दुनिया में मां-बाप के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है लेकिन किसान को तो बिजली के पैसे देने के बाद भी बिजली नहीं दी जा रही है। मैं जोर से बोला, टेबलें थपथपाईं, मैंने देखा कल से बिजली आ जायेगी। कहा, यह तो बीजेपी का है। जो आ रही थी वह भी काट ली। इसलिए यहां पक्षपात की बात न हो।

आजादी के बाद हमारे आजादी के वीर सिपाहियों ने हमें कुछ हिदायत दीं, कोई चेतावनी दी, कुछ जिम्मेदारी दी, उस पर गीतों के द्वारा लिखा गया था और मैं गीतों के द्वारा लिखी हुई बात को ही कह रहा हूं कितनी जिम्मेदारी से हमको समझाया था। हम लाये हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। (व्यवधान) माननीय विधायक महोदय, यह गाना नहीं है, किसी अच्छे गीतकार, संगीतकार और कवि की बात को मैं यहां कह रहा हूं कि आजादी के बाद हमें जो जिम्मेदारी दी है, जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। हिमालय की बुलंदियों से सुनो आवाज है आई, कहो माता से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। अच्छी कही हुई चीज का यहां बखान करना या उदाहरण देना मेरे लिये जरूरी हो जाता है। मैं सबको कह रहा हूं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी हम जिम्मेदार हैं क्या? एक वक्त था जब आजादी के लिये मर मिटने को तैयार थे। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। मैं जल्दबाजी में हूं। बजट राजस्थान में है और चर्चा कुछ माननीय सदस्य दिल्ली में कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका भी समय खतम हो रहा है।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट और बोल दूं मैं। मैं 15 दिन में तो आज बोला हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने वैसे यह भी देख लिया कि

(श्री रूपा राम)

बोलने से कुछ नहीं होता, थोड़े कंठ ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने तो देखा है कुछ होने वाला तो है नहीं। माननीय सदस्य लगातार बोल रहे हैं, वह अभी तक वैसे ही चिल्ला रहे हैं।

मैं बिजली मंत्री जी से यही कहूंगा कि हमारे मकराना में कुछ ऐसी समस्या है ...(व्यवधान) आ गये, बहुत अच्छा किया आ गये आप। सर, बिजली विभाग आपका है और पानी का भी आपका है। जेजेवाई की कुछ योजना है, सरपंच को पैसे भरने चाहिये, नहीं भरता है। बिजली डिपार्टमेंट में, पानी के डिपार्टमेंट के पैसे सरपंच को ही भरने चाहिये। जेजेवाई में नहीं भरता है तो बिजली विभाग वाले कनेक्शन काट देते हैं और वह ट्रांसफार्मर उठाकर ले जाते हैं, कोई रोने-धोने वाला नहीं है। एक मिनट और बोलने दो मुझे।

श्री सभापति: एक मिनट बोलने देंगे।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय विधायक महोदय, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यह जिम्मेदारी दी थी आपको और हमको, हम कर क्या रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं उनको जवाब जरूर देता जो कह रहे हैं कि दिल्ली जल रही है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप सुनो। हम लाये हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): यही तो मैं बोल रहा हूं। एक मिनट साहब।

श्री सभापति: नहीं, अब समाप्त करें आप।

श्री रूपा राम (मकराना): यह अधूरा रह जाएगा तो लिखने वाले किसी कवि का दिल टूट जाएगा। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, आप समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना। सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर। विराजिए, विराजिए। (अनुपस्थित)। श्री प्रशान्त बैरवा जी।

श्री रूपा राम (मकराना): अच्छी लाइन आ रही है। एक मिनट, मिनट।

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए। प्रशान्त बैरवा जी। अंकित नहीं होगा।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: विराजो आप। रास्ते तो बहुत कठिन हैं। विराजो आप।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य दिल्ली की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जहर घोलते हो तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ बात कहना चाहूंगा। कुछ पंक्तियां हैं-

"क्यों देश के सिपाहियों पर पत्थर चलाते हो,
कैसी है ये आग, क्यूं देश को जलाते हो,
सरकारें पहले भी थीं, अब क्यूं इन्हें हकलाते हो,
पैरों पर खड़ा न हों जो, उन्हें क्यूं बहकाते हो,
अमन-चैन का देश मेरा, क्यूं इसे जलाते हो,
बने दो पुल दिलों में, क्यूं दीवारें बनाते हो,
अपने देश नियम कहीं कैसे आजमाते हो,
ठोककर छाती तुम आरएसएस का कानून बनाते हो,
पूछना है तो मुझे बीजेपी नेताओं से,
कुर्सी पर सब भूल बैठे, क्यूं ईमान लुटाते हो,
बीजेपी/आरएसएस वालों। सच देखो, क्यूं दशकों से आंख चुराते हो।
लहू बहता है हिन्दुस्तान के बेटे का और कैसे आंख लड़ाते हो।"

तो यह हकीकत है। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पूरा माहौल खराब हो रहा है। हमारे गहलोत साहब ने जब बजट पेश किया तो आर्थिक मंदी थी। केन्द्र सरकार के द्वारा हमारे साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि पहले जब वसुंधरा जी थीं तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने राजस्थान को सपोर्ट नहीं किया। अब हमारी कांग्रेस की सरकार है तो अब कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा ही सौतेला व्यवहार हमारे साथ

(श्री प्रशान्त बैरवा)

किया जा रहा है। कह रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं तो एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा कि अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया तो आरबीआई का इतना सारा फंड कैसे आया। आपने क्यों 1 लाख 75 करोड़ को विदड्रा किया। हमने कुछ किया है, कुछ बनाया है तभी तो आपने उसका यूज किया है। अब आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जो रेलवे, इंश्योरेंस BSNL को प्राइवेट में बेच रहे हैं, उसको मत दीजिए।

राजस्थान से 25 माननीय सांसद हैं। आप एक भी कोई बता दीजिए कि प्रधान मंत्री के पास जाकर इन 25 लोगों ने राजस्थान के लिए कोई डिमांड की हो, कोई पेयजल के लिए पूछा हो, कुछ फाइनेंस देने के लिए बात की है। यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि जो 25 के 25 सांसद हैं, उनको राजस्थान के लिए जाना चाहिए। कल हमारे विधायक साहब महर्षि जी बोल रहे थे कि विपक्ष से भी सलाह लेनी चाहिए। अब मैं दिल्ली की बात करूं। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, गलती से, हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इकोनोमिस्ट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। हिन्दुस्तान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मनमोहन सिंह जी के पास वे गयी थीं। उनका मकसद शायद यही होगा कि किस तरह से ग्रोथ को ठीक किया जाए। वे गयीं उसके बाद जो हालात हैं, वे आपके सामने ही हैं। जितनी भी फाइनेंस की मीटिंग हुई, उनको नहीं बुलाया गया। यह शेमफुल है। बुलाया ही नहीं गया तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी दादागीरी कर रखी है। ये बड़े लोग हैं। हकीकत को छिपाना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे, यह मुझे नहीं लगता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी साहब ने हमें सात संकल्प दिये हैं। जिस तरह पिछली बार गांधी जी की तर्ज पर सात संकल्प थे, उसी तरह से पूरे बजट को उन्होंने सात भागों में बांटा है। गांधी जी याद हैं और उनकी जो अच्छाइयां हैं, वे अभी भी प्रासंगिक हैं। उसको यह बजट रिफ्लैक्ट करता है।

सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं देख रहा था कि नीरोगी राजस्थान के अंदर सारे के सारे विपक्ष वाले बहुत नेगेटिव बोल रहे थे। ऐसा नहीं है। आप अगर सीएम साहब को अपनी रिक्वैस्ट भी देते तो वे मना नहीं करते। मैं सोचता हूं कि आप सब इस हाउस के अभिन्न अंग हैं। अगर आप भी कुछ मदद करना चाहेंगे तो साहब करेंगे। नीरोगी काया के अंदर जो सबसे बढ़िया काम किया है, एक तो कैंसर और लीवर ट्रांसप्लांट का जो काम किया है, वह

(श्री प्रशान्त बैरवा)

बहुत ही बेहतरीन है। मैं एक डिमांड रखना चाहूंगा, मैंने मेरे यहां के लिए ट्रोमा हास्पिटल के लिए कहा था कि मेरे यहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि हाईवे पड़ता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी नेशनल हाईवे पर रहती है तो वहां पर ढंग से इलाज नहीं हो पाता। मैं माननीय सीएम साहब से और माननीय रघु शर्मा जी, मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ट्रोमा हास्पिटल बनाया जाए क्योंकि वहां पर इमरजेंसी भी बहुत ज्यादा है, वहां पर पोस्टमार्टम भी बहुत होते हैं। इससे मेरे इलाके को फायदे होगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां फागी से टोंक मेरा क्षेत्र पड़ता है। फागी से अगर आपको टोंक जाना हो तो चाकसू से होते हुए जाना पड़ता है। करीबन सवा सौ किलोमीटर पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फागी से पीपलू होते हुए अगर आप स्टेट हाईवे घोषित कर देंगे तो कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता शोर्ट पड़ेगा और इससे डीजल व पैट्रोल की बचत होगी और आम जनता को सुविधा भी होगी।

मेरे क्षेत्र में पहले पानी की बहुत मांग थी। पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो उसने बीसलपुर का पानी दिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाये थे। यह सरकार बहुत संवेदनशील है। इस सरकार में साढ़े चार करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसमें घर-घर कनेक्शन मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि इस गर्मी के अंदर बहुत राहत मिलने वाली है।

मेरे विधान सभा का एक और मैटर है। मैं यह चाहता हूं कि आप हास्पिटल में 50 से 100 बैड दे दीजिए। जिस तरह से मेरे यहां पर 2 लाख 35 हजार मरीज एक साल में आए हैं, एक लाख से ऊपर जांचें हुई हैं। आउटडोर बहुत ज्यादा है तो मैं समझता हूं कि थोड़े बैड और मिल जाएंगे तो बहुत फायदा होगा।

हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अभी राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा इवेंट रखा था, बहुत सारे खिलाड़ी यहां पर आये थे, पार्टिसिपेट किये थे। बहुत लोगों ने मैडल भी लिए। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह उसी सोच को दर्शाता है कि जब तक यहां का युवा, आपने जो मैडल दिये हैं और जो 3 करोड़ रुपये तक बढ़ाए हैं ओलिम्पिक के गोल्ड मैडल के लिए, सिल्वर मैडल के लिए। मैं सोचता हूं यह बहुत अच्छा है। यह हरियाणा की तर्ज पर किया गया है। यहां से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलने वाले हैं।

(श्री प्रशान्त बैरवा)

जो 'नो बैग डे' का बजट में दिया है, मैं भी मेरे एरिये में था। मैं दो-तीन स्कूलों में गया था तो हर जगह पर इसकी वाहवाही हो रही है। बच्चे वाकई चाहते हैं कि नो बैग डे हो और खुश रहें। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, जितनी भी वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसमें मैं समझता हूं कि इससे उन्हें राजस्थान की संस्कृति को प्रजेंट करने का मौका मिलेगा, युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी। 'हिट राजस्थान, फिट राजस्थान' का जो संदेश दिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। स्कूलों के बारे में अभी लिखा कि हर ब्लाक पर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे, मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): मैं बस चंद लाइनों से समाप्त करना चाहूंगा-

"शब्द ही तीर हैं, शब्द ही तलवार हैं,
मेरी जान से प्रिय मेरा राजस्थान है।
चिंता नहीं, जितना चाहे जोर लगा ले,
हमने तेज कर ली अपनी धार है।
जन-जन का हमने प्रेम ले लिया है,
अशोक गहलोत ही जनता की पुकार है।
मेरी जान से प्रिय मेरा राजस्थान है।"

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी को बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ बजट को रखा गया। चुनाव जीतकर आने के बाद लगातार दूसरा बजट इस बार देखा है। जनता बड़ी आस लगाकर बैठी थी कि गत वर्ष केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का नाम बजट में नहीं आया तो कम से कम इस बार तो आएगा ही आएगा लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही बजट की बुक्स में कहीं पर भी केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे थे, किसानों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किसान कल्याण कोष बनाकर हमने चिंता जाहिर की है, उसके बावजूद भी हम किसानों की दशा और दिशा देखेंगे तो किसानों का दर्द किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी किसान इस बात का इंतजार कर रहा है। उसकी फसल चाहे अनावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओले पड़ें और उससे जब उसका नुकसान हो जाए और फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी काटी गयी राशि भी अगर उसको नहीं मिलती है तो हम मान सकते हैं कि उस किसान के मन की पीड़ा क्या होगी? उसके दिल से हमारे लिए क्या बद्दुआएं निकलेंगी? यही हाल राजस्थान के किसानों का हो रहा है। मैं बात करना चाहूंगी कि किसानों से बहुत सारे वादे किये गये थे, कर्ज माफी की बात भी की थी, लेकिन पूरी नहीं हो पायी। किसानों के इंश्योरेंस का डिटेल रखने की बात थी। इसी के साथ-साथ किसान लगातार राजस्थान के अंदर जूझते हुए आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों को बिजली, पानी देने के लिए हमने जो पिछली बार भी वादा किया था कि हम दिन को थ्री फेज बिजली देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में किसानों को रात में ही बिजली मिल रही है। कम से कम हम इस बात की ओर ध्यान दें। यह घोषणा पिछली बार की, फिर अभी हम कर रहे हैं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हम बिजली की बात करें। सरकार आई थी, सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बिजली के दाम बढ़ाने से सीधा-सीधा सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वह किसान का हुआ है। अगर डीजल के दाम बढ़ने से सीधासीधा नुकसान हुआ है तो वह किसान का हुआ है क्योंकि हम मान सकते हैं कि किसान कितना डीजल फसल को पानी पिलाने के लिए खर्च करता है और इसका सीधा-सीधा प्रभाव किसान के ऊपर पड़ता है, जो हमेशा गरीबी से जूझता है। मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि सात संकल्प के साथ सरकार ने इस प्रस्ताव को, इस बजट को पेश किया है लेकिन साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थीं, सम्माननीय मंत्री महोदय चांदना जी यहां बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था कि कम से कम वे तो मेरा इस बात के लिए पक्ष लेंगे कि हां, इनकी विधान सभा में इन-इन चीजों की अति आवश्यकता थी।

मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत जाए तो उसके क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध न

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हो? इसका जीता-जागता उदाहरण जो हमारी चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना थी, जो 285 गांवों की योजना थी, हमारी ढाणियां भी उसमें जुड़नी थीं 200 से ज्यादा। लेकिन आप देखिए उस योजना में, मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक हूं, इसलिए मेरी 14 पंचायतें जो नैनवां पंचायत समिति की पड़ती हैं, उनको काट दिया गया। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब बजट भाषण को पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा दु:ख हुआ। कम से कम जनता के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी जनता के लिए मैं पीने के पानी की मांग करती हूं। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब जवाब दें तो मुझे यह भी बताएं कि आखिर में मेरी 14 पंचायतों को क्यों काटा गया?

साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूं कि ट्रोमा हास्पिटल जो कई वर्षों से बना हुआ है लेकिन लाखेरी के ट्रोमा हास्पिटल में इतना बुरा हाल है कि कम्पाउंडर के भरोसे चल रहा है तो उसका भी कुछ होगा।

सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेडिकल कालेजों की बात की लेकिन 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी मेडिकल कालेज, कोटा का ये ही हाल हो, हम कैथलैब शुरू करने की बात कर रहे थे। मात्र एक छोटे-से कारण की वजह से, 30 लाख रुपये की वजह से मेडिकल कालेज में, कैथलैब में हमारी जो सुपर स्पेशलिटी विंग बननी है, उसके अंदर जनता को अगर सुविधा नहीं मिलती है तो यह जनता का दुर्भाग्य है। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले समय एक फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ और बड़े दु:ख के साथ मैं इस बात को यहां बताना चाहती हूं कि उस फ्लाईओवर के अंदर आप देखिए, पीडब्ल्यूडी हो चाहे हमारा रेलवे विभाग हो, टैक्निकल डिपार्टमेंट होता है। हमारे इंजीनियर बड़े सोच-समझकर डिजाइन तैयार करते हैं लेकिन कोटा से हमारा माधोपुर की तरफ रोड जा रहा है, उसी रोड पर जो हमारा ओवरब्रिज बनेगा, उस ओवरब्रिज की डिजाइन में लगातार तीन-तीन, चार-चार बार परिवर्तन हो रहा है। उसकी डिजाइन चेंज हो रही है। इससे सीधे-सीधे हमारे वहां के जो गरीब बंधु हैं, कम से कम 300 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनको कहीं न कहीं उजाड़ने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस सड़क से कोटा की तरफ से 2500 गाड़ियां निकल रही हैं, जिस बात के लिए हमने ओवरब्रिज बनाया, मात्र 5 गाड़ियां जिधर निकलें, जो हमारा ओवरब्रिज फोरलेन था,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उसको मात्र तीन लेन में परिवर्तन कर दिया। मुझे लगता है कि ढ़ाई हजार गाड़ियां जहां से निकल रही हों, वहां पर हम ध्यान नहीं देंगे तो इससे बहुत बड़े हादसे आने वाले समय में हो सकते हैं। इसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए। हमारी 80 लाख रुपये की जो सेविंग है, सरकार की तरफ किसी तरह का कोई लोड पड़ने वाला नहीं है। जो हमारी सेविंग है उसी में ये काम पूरा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस काम को करने का प्रयास करेंगे तो जनता को बहुत लाभ मिल सकता है।

मैं आज के दिन बात करना चाहूंगी डीएमएफटी योजना की। हम बात कर रहे थे भीलवाड़ा की जहां पर 200 करोड़ रुपये, हम बात कर रहे थे उदयपुर की, राजसमंद की जहां 800 करोड़, इतने करोड़ों रुपये हमारे पास बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जनता का पैसा, डीएमएफटी का पैसा, जहां कहीं माइनिंग एरिया होता है, जहां खनन होता हैं, जहां धूल-मिट्टी उड़ती है, उन किसानों से पूछिए जिनकी फ़सलें चौपट हो जाती हैं और धूल की वजह से पूरे खेत के खेत, हजारों बीघा जमीन पड़त रह जाती है लेकिन डीएमएफटी को हम लोग खर्च नहीं कर पाते। इतना पैसा पड़ा होने के बावजूद, मुझे मालूम है, पिछली बार मैं विधायक थी, हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर भेजे। सम्माननीय कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग की। हमें पता लगा कि टेंडर होने वाले हैं लेकिन उन सारे कामों को रोक दिया गया है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगी कि उन कामों को तुरंत पूरा करें।

साथ ही साथ मांग करना चाहूंगी कि मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र जो 150 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मैंने इसका प्रश्न भी लगाया था। अगर इस महाविद्यालय की सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे वहां की बालिकाओं को, बच्चियों को जो 100-100 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए कोटा आती हैं या बूंदी आती हैं, कहीं न कहीं वे आपको दिल से दुआएं देंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मेरे क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए, यही मैं निवेदन करना चाहूंगी।

साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि पशु चिकित्सालय जितने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, एक भी जगह हमें पशु चिकित्सक देखने को नहीं मिलता।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मुझको आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट पर जवाब पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया।

आय व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरे पंचायत समिति की घोषणा भी करेंगे मुख्य मंत्री महोदय तो अच्छा लगेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, बजट 2020-21 पर मैं अपने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा बताया, कुछ ने इसको बहुत खराब बताया। मैं कोशिश करूंगा और निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि मेरी बात बोलने के बाद आप तय कर लें कि वास्तव में हम कहां खड़े हैं? क्या हमारे राजस्थान की स्थिति है? आप हमें कितना ही कोस लो, चाहे केन्द्र की सरकार को कोसो, चाहे हमको कोसो, केवल कोसने के लिए कोसना चाहें तो आपको इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो धरातलीय हकीकत है, वह मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मैं सोचता हूं कि मेरी बात का कोई जवाब देता नहीं है। सामान्यत इस बात के लिए मैं बहुत दु:खी हूं। पिछली बार भी राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं एक घंटे तक बोला। मैंने जिन विषयों को उठाया, मुझे दु:ख है इस बात का कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता है। आज बजट की रिप्लाई है। मैं सदन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के नेता से प्रार्थना जरूर करूंगा कि अगर मेरे कोई तथ्य गलत हों तो उसको आप सुधार कर मुझे बताएं कि मैं यहां गलत हूं, मैं उसको सुधारने का प्रयत्न करूंगा।

मैं सोचता हूं किसी भी प्रकार की उपलब्धि का आधार उसका राजस्व प्राप्ति का है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 2013-14 में जब आपने सरकार छोड़ी थी, तब इस राजस्थान की राजस्व प्राप्ति 74 हजार 470 करोड़ थी। पहले ही साल में जब हमने 2014-15 का बजट रखा तो हम सीधा ही इस 74 को 91 हजार 326 करोड़ पर ले गये और लगभग 23 परसेंट की बढ़ोतरी की। लगातार जो हमारी सरकार रही, हमने अंतिम बजट जो छोड़ा था, जिसमें रेवेन्यू छोड़ी थी हमने, वह 1 लाख 37 हजार 873 करोड़ पर छोड़ी थी। यह जो सारी वृद्धि थी, 23 परसेंट तो पहले राउंड में थी और उसके बाद लगातार पांच साल तक 51 परसेंट की रेवेन्यू की बढ़ोतरी हम लोगों ने की। इसका मतलब हमने राजस्थान के विकास के लिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

आपने अभी दो बजट रख लिए। पहला बजट रखा आपने 2019-20 का, उस समय आपकी रेवेन्यू रिसीट थी 1 लाख 64 हजार 4 करोड़। इस समय आपकी रेवेन्यू रिसीट है 2020-21 की, वह 1 लाख 73 हजार, आपकी जो वृद्धि है यह केवल 5.7 परसेंट है। हमने वृद्धि को, अगर आप सही ढंग से देखें तो हमने 74 से 137 पर जब छोड़ा तो हमारी यह बढ़ोतरी लगभग 60 परसेंट से अधिक थी। मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर प्रदेश के विकास का आधार बनेगा तो ये ही बनेगा। केवल भाषण आधार नहीं बन सकता है। हमारी जेब में कितना पैसा है, वही विकास का आधार बनेगा। इसमें जो राजस्व व्यय है, आपने जब सरकार छोड़ी तब राजस्व व्यय था 75 हजार 509 करोड़। हमने जब पहला बजट रखा तो हमने रखा 94 हजार 541 करोड़, लगभग 25 परसेंट की पहले साल में बढ़ोतरी की। जब हमने अंतिम छोड़ा था तब 1 लाख 66 हजार 773 करोड़ पर हमने आपका राजस्व व्यय छोड़ा था। अभी मैं आगे बताऊंगा, आपने पहला बजट जो रखा, वह 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ का आपने व्यय बताया और इस बार दुर्भाग्य से, बहुत चतुराई से यह जो आप कह रहे हैं कि हमको घाटा कम हुआ और 12 हजार करोड़ रहा, यह कलाकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, कितनी कलाकारी से आपने अपने बजट को घुमाया है, इसको समझने का प्रयास करिए। केवल बातों के आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर नहीं। आपने इस साल अपना राजस्व व्यय घटाया है, 1 लाख 85 हजार 750 करोड़ कुल खर्च हुआ है। इसका मतलब आपने पिछली बार राजस्व व्यय का बजट पेश किया उससे आपने 2.8 प्रतिशत बजट घटाया है।

पूंजीगत व्यय की स्थिति- आपको जब तक मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा तो आप हमको ही हमको ठोकते रहोगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब आपने ही दो वर्षों में कर डाला। पूंजीगत व्यय 2013-14 में 13664 करोड़ था, हमने पहली साल में इसको 16102 करोड़ बनाया, 2018-19 में जब छोड़ा, तो हमने 19638 करोड़ पर छोड़ा। अभी आपने इस साल बजट किया 2019-20 में 19472 करोड़ पर लिया जो हमने 19638 करोड़ पर छोड़ा था। अब जो बजट पेश कर रहे हैं 21677 करोड़, यानी 11 परसेंट की बढ़ोतरी पूंजीगत व्यय में है। आपने घाटा कम बताया उसको मैं आगे बताऊंगा। विकास व्यय की दृष्टि से अगर आंकड़ा देखें तो, यह थोड़ा नीरस जरूर लगता है, बजट का डिस्कशन और आंकड़ों के जाल में रुचि नहीं हो सकती लेकिन इसको हकीकत तक ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

विकास व्यय- जब आपने 2013-14 में सरकार छोड़ी थी तब 65251 करोड़ रुपये था। हम पहले ही साल इस 65 को बढ़ाकर 82242 करोड़ पर ले गए। जब हमने सरकार छोड़ी थी तब 1 लाख 31 हजार 458 करोड़ रुपये, हमने पहले साल में लगभग 26 परसेंट की बढ़ोतरी की। टोटल पांच साल में 60 परसेंट की बढ़ोतरी हमने विकास व्यय में की। आपने 2019-20 का बजट रखा तब 1 लाख 51 हजार 418 करोड़, उसके बाद आपने जो छोड़ा, आपने यहां बजट घटाया है। आपका विकास व्यय का बजट घटा है, वह

(16.52 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

1 लाख 44 हजार 684 रुपये, इसका मतलब आपने विकास दर में 4.4 प्रतिशत कम किया है। आप अगर इस आंकड़े को गलत बताएं, लेकिन आपकी आर्थिक समीक्षा से लेकर, जो किताबें आपने मुझे दी हैं उसके आधार पर मैंने निकाला है।

आर्थिक सेवाएं- आर्थिक सेवा में कृषि, पशुपालन, सिंचाई सब आ गए। इसमें आपकी क्या स्थिति है। जब आपने 2013-14 में छोड़ा था तब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान का आर्थिक सेवाओं पर खर्च होता था, वह 20 हजार 435 करोड़ रुपया होता था। हमने पहले ही साल 20 को बढ़ाकर 28920, अर्थात् 29 हजार करोड़ किया। उसके बाद जब अंतिम छोडा, तब 31 हजार 458 पहले साल में लगभग 42 परसेंट की बढ़ोतरी थी, पाँच साल के अंत में हमारी बढ़ोतरी 62 परसेंट थी। अभी आपकी बढ़ोतरी का क्या है, 56112 करोड़ पर आपने लिया है, अभी 43305 करोड़ पर छोड़ा है आर्थिक विकास को। आगे और बताऊंगा। इसी तरह कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा, ग्राम विकास किसी विकास का मापदण्ड होता है, उस विकास के मापदण्ड में आपने अपना खर्चा काटकर, 15.7 प्रतिशत आपका बजट घटा है। थोड़ा-सा इसकी ओर ध्यान कीजिए।

सामाजिक सेवाएं- जिसमें शिक्षा, चिकित्सा सारी चीज़ें आती हैं। इसको आपने हमें दिया था तब आपका बजट 31 हजार 486 करोड़ था, हमने पहले साल में इस 31 को 37 पर और अंतिम 65 हजार 686, अर्थात् पहली बार का विकास 20 परसेंट और पूरे पांच साल का विकास 74 परसेंट था। अब आपकी स्थिति क्या है, आपका 2019-20 का पहला बजट 76627 करोड़ रुपया, अभी आपने किया 76423 करोड़ रुपये, इसका मतलब आपका 0.3 परसेंट शिक्षा, चिकित्सा, नीरोगी राजस्थान भी जिसमें हैं, उसमें कम हुआ है।

कर्ज़ की स्थिति के बारे में आप चाहे जो रोज इधर से उधर लगा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि हकीकत क्या है। आपने कहा कि हमने 2018-19 में कर्जा छोड़ा तब 3 लाख 11 हजार 373 करोड़ था, यह बिलकुल सच है। लेकिन आप उस बात में जाओ जब आपने हमको सुपुर्द किया तब 1 लाख 29 हजार करोड़ क्यों था? 1 लाख 29 हजार करोड़ का सुपुर्द किया था। उस समय राजस्थान की जितनी भी बिजली कम्पनियां थीं वह 88 हजार करोड़ रुपये के घाटे में थीं या नहीं थीं? वह भी कर्जा ही था। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 लाख 17 हजार करोड़ पर हमने उसकी देनदारियां चुकाईं। आप इसको 2 लाख 17 हजार करोड़ पर छोड़कर गए हो। अभी आपके पास जो कर्जा है, जो हमने आपको सुपुर्द किया है, उसके बाद आपने 64 हजार करोड़ रुपया केवल दो साल में कर्जा लिया है। हमने पांच साल में 90 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया, आपने दो साल में 64 हजार करोड़ का कर्जा लिया। अब की बार आपका अनुमान है वह है 3 लाख 75 हजार 353 करोड़ रुपये। कर्जा हमने बढ़ाया या आपने बढ़ाया, आप इसका हिसाब लगाना।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सामान्य शिक्षा पर जो व्यय होता था उसको आपने पहली बार घटाया है। सामान्य शिक्षा पर आपका इस साल का बजट घटा है। कांग्रेस ने जब हमको 2013 में सुपुर्द किया था तब 12730 करोड़ रुपये थे, हमने पहले साल में 29 हजार करोड़ किया, फिर जब छोड़ा तब 34 हजार करोड़ किया। उसके बाद आपने पिछला बजट पेश किया उसमें सामान्य शिक्षा पर 38712 करोड़ रुपये का आपका बजट था, जो अभी आपने 38 हजार 93 करोड़ किया, इसका मतलब इसमें 1.6 परसेंट की कमी आई है। सामान्य शिक्षा में इस बार आपके बजट में कमी आई है।

ग्रामीण विकास- ग्रामीण विकास राजस्थान का आधार है। उस ग्राम विकास में भी आपकी क्या स्थिति बनी है, 2013-14 में 4 हजार 990 करोड़ रुपये ग्राम विकास पर छोड़ा था। हमने पहले ही साल में 4 को बढ़ाकर 10 हजार 404 करोड़ रुपये, यानी 108 परसेंट का ग्रामीण विकास में पहली बार जम्प दिया 108, उसके बाद पांच साल तक हम इसको लगातार बढ़ाकर 11 हजार 373 करोड़ पर ले गए। सारा विकास है तो 9 परसेंट है। 13 हजार 948 आपका पिछले बजट में था, इस बजट में आपका 12 हजार 864 करोड़ रुपये आ गए हैं, इसका मतलब 7.8 परसेंट ग्रामीण विकास में आपका कम हुआ है।

एससी, एसटी, ओबीसी, आप सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा बजट है। भले आदमी, आप इसको देखने की कोशिश करो। आंकड़ों के आधार पर चलना पड़ेगा। यह बजट न मैं बनाता हूं, न आप बनाते हो, जो कुछ बनता है वह इन किताबों में आप और हम सब बंद करते हैं और उसको देखते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के कल्याण पर खर्च हो रहा था वह 2013-14 में 809 करोड़ था, हमने इसको 965 करोड़ किया। जब छोड़ा था तब 1501 था। पिछली बार जब आपने टेकओवर किया उस समय आपका पहला बजट 1670 करोड़ रुपये का था, आपका अब की बार का बजट 1667 करोड़ रुपये हैं। 1670 से 1667 यानी 3 करोड़ कम हुआ।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- इसमें बालिकाओं-बालकों के छात्रावास, छात्रवृत्ति, पेंशन आ गई, सब कुछ इसमें है। सामाजिक सुरक्षा में 1186 करोड़ था, उसको हमने पहले साल में ही 4 हजार 64 करोड़ रुपये बनाया। लास्ट में छोड़ा तब 5 हजार 993, अर्थात लगभग 6 हजार करोड़ रुपये। पहली बार में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारा विकास था 243 परसेंट, 1100 से सीधा हम 4 हजार पर ले गए। उसके बाद आपका 2019-20 में 881 करोड़ का बजट था। अभी आपका 7 हजार 710 आया है, लगभग 5.2 परसेंट सामाजिक सुरक्षा, बच्चों, विधवाओं, महिलाओं की पेंशन है, उसमें आपने इतनी कटौती की है। इन-आल मिलाकर जो कुछ भी आप कह रहे हो, आप कह रहे हो टोटल मिलाकर 2019-20 में बजट था वह 2 लाख 33 हजार 6 करोड़ का था। अभी आपका टोटल बजट 2 लाख 25 हजार का है। इसका मतलब आपने माइनस 3 परसेंट की, हमारा टोटल बजट है उसमें कमी की है।

आप बार-बार एक ही बात कहते हैं कि हमें केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती। आप अपने इन आंकड़ों से सिद्ध करो कि केन्द्र सरकार से आपको पैसा कम मिला या ज्यादा मिला? यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह किताब बता रही है कि केन्द्र सरकार का पैसा पहले से इस बार ज्यादा मिला है, लगातार ज्यादा मिला है।

(17.00 बजे)

केन्द्रीय करों का अंश, मैं बता रहा हूं आपको, केन्द्रीय करों का अंश जो हमें मिलता था 2013-14 में, जो आपको मिलता था वह 18676 करोड़ था। हमने उसको बढ़ा करके, जब 2018-19 में आपको दिया था तो 18000 को हमने 41852 करोड़ रुपये पर किया जो केन्द्र से हमें सहयोग मिला था और आपको पिछली बार मिला है 44461 करोड़, और इस बार आपको मिल रहा है 46886 करोड़, अब इसमें आप बताओगे कि हम आर.ई. में जब गये तो यह हमारा 44000 करोड़ रुपया 36000 करोड़ रुपया कैसे हो गया। यह वास्तव में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, यह केवल एक स्टेट का नहीं होता है। अगर वास्तव में केन्द्र से सहायता मिलती है तो जिन हैड्स में मिलती है और जिस तरीके से मिलती है, उसकी आपको पूर्ति करनी पड़ती है। उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी लेकिन आपको मिला है, जो आपने एस्टीमेटेड किया है।

अब यह केन्द्र सरकार से सहायता, यह जो आपको मिली न, जिसको आप बार-बार कहते हैं कि जी.एस.टी.। इस जी.एस.टी. के कारण से हमको कम पैसा मिला, यह आपका कागज नहीं बता रहा है, कम मिला। यह आपका बता रहा है, पहले साल में आपने देखा होगा कि हमको उस समय 2018-19 में 20037 करोड़ रुपया मिला। उसके बाद आपको 2019-20 में 26676 करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपया मिला। बीस से एकदम छब्बीस बढ़ा और इस साल आपको 29893 करोड़ मिल रहा है, तो अभी तो आपने एस्टीमेटेड किया है जबकि एस्टीमेटेड से भी जब आप आगे बढ़ेंगे न, सबने भाषण ठोकने के लिये ठोक दिया। चौदहवें वित्त आयोग से यह हो गया, पन्द्रहवें से हमारा कम किया। यह चौदहवें वित्त आयोग का कागज है। 42 प्रतिशत के हिसाब से जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उस समय अपने राजस्थान का जो शेयर था, 42 पैसे में से 2.31, चौदहवें वित्त आयोग में अपने को मिलता था 2.31, इसका मतलब सौ रुपये में से हमको 5.5 रुपया मिलता था। आज इस 41, एक परसेंट तो जरूर गिरा है लेकिन एक परसेंट के बाद राजस्थान को 2.45 मिलता है। पहले मिलता था 2.31 और अब मिलता है 2.45, इसका मतलब लगभग 6 प्रतिशत, जो पहले हमारा 5.5 प्रतिशत था। टोटल सौ रुपये में से जितना टैक्स वसूल होता था, उसके अगेंस्ट में आज आपको 6 परसेंट मिलता है। आप इसमें 46 हजार करोड़ को लाये हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह आंकड़ा यह बता रहा है कि राजस्थान को इसके तहत 51131 करोड़ रुपया मिलेगा। 51000, अर्थात् जब आप आर.ई. में जाओगे न, तब भी आपको यह जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसके कारण से आपका बजट पड़ेगा, यह 855176 करोड़ रुपया जो उनकी आमदनी है, उस आमदनी का जब आपको पैसा मिलेगा तो आपका शेयर 51131 करोड़ रुपया बन रहा है। इसका मतलब कहीं भी केन्द्र से पैसा कम नहीं हुआ है। केवल केन्द्र के माथे ढोल करके अपनी कमजोरियों को दिखाने के लिये काम करेंगे न, तो मैं सोचता हूं, राजस्थान का भला नहीं कर सकते हैं।

राजस्व घाटे की जो कमी हुई अब आपने बहुत तरीके से निकाला। यह जो आपने बताया न, 12912 करोड़ रुपये का रेवेन्यू में आपने जो घाटा दिखाया है, वह वास्तव में नहीं है। आपने घाटा दिखाने के लिये इसमें कटौतियां की हैं। ग्राम विकास में किया है 1083 करोड़ रुपया; ऊर्जा में किया है 9767 करोड़ रुपया; उद्योग में किया है 142, माइनस बताया है, कम किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण में माइनस 6.43 और उसके बाद शिक्षा पर माइनस 618; फिर परिवार कल्याण पर माइनस 444; फिर एस.सी., एस.टी. में माइनस 53; समाज कल्याण में माइनस 419; पोषण में किया 376, यह मिला करके आपने 12912 करोड़ का घाटा दिखाया है जबकि वास्तविकता में, जैसे आपने इन सब में कटौतियां करके और आपने अपना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खर्चा कम दिखा करके आप इस घाटे को दिखा रहे हो, इससे राजस्थान का विकास होगा? इससे राजस्थान का विकास सम्भव है? हम केवल और केवल, हमारे टाइम पर 28000 करोड़ का घाटा था। आपने उस घाटे को कम करने के लिये सभी हैड्स में अपनी राशि को घटा करके, अपना खर्चा कम बता करके राजस्थान को यह दिखा रहे हो कि 12000 करोड़ रुपया हमको एक्चुअल में घाटा है। ऐसा नहीं है। आप इसको ठीक तरह से देखिये और आपके अधिकारियों को बताइये।

यह 2019-20 की तुलना में 2021-22 में, यानी जो मैं टोटल आपको बता रहा हूं, जो मैंने पहले भी पढ़ा है, शिक्षा में कम हुआ, केवल चिकित्सा में आपका 16 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह से जलापूर्ति में 8 परसेंट बढ़ा है। बाकी परिवार कल्याण में माइनस 14 हो गया, एस.सी., एस.टी. में माइनस 3 हो गया, समाज कल्याण में माइनस, पोषण में माइनस, कृषि में माइनस 24 परसेंट, कितना? कृषि पर आपका जो खर्च है वह माइनस 24 परसेंट हो रहा है ग्राम विकास पर माइनस 0.5 और विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम में माइनस 11.5, और उसके बाद ऊर्जा में आपका 0.2 प्लस हो रहा है। सिंचाई और इस पर, जरूर आपका 0.21 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह से उद्योग में माइनस 31 परसेंट है। आप कह रहे हैं एम्प्लायमेंट मिलेगा, कहां से एम्प्लायमेंट मिलेगा? माइनस 31 परसेंट आप उद्योग में कटौती कर रहे हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में माइनस 60 परसेंट। आप खर्चा घटा करके बातें कर रहे हो। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, और मेरी बात गलत निकल जाये, यह जो कुछ भी आपने दिसम्बर तक का आंकड़ा जाल किया है न, ये आंकड़े केवल आपने पैसों को बुक करके दूसरी बुक में डाल दिया। ईमानदारी से अगर कोई मुझे साबित कर दे कि धरातल पर अगर वह काम हो गया तो मैं यह सदन छोड़ कर चला जाऊंगा। आज यहां कह रहा हूं, यह आज कह रहा हूं। यह केवल और केवल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, नीचे बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बता रहा हूं कि केवल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मंत्री रहे हैं। (व्यवधान) आप मंत्री रहे हैं। आप मंत्री रहे हैं। बैठें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान) अकाउण्ट वालों ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बैठें, मंत्रीजी बैठें। माननीय मंत्रीजी, बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेहरबानी करके सदन छोड़ने की बात मत किया करो वरना मैं कागज पेश कर दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): शांती कुमार जी धारीवाल साहब, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कटारियाजी। कटारियाजी, एक मिनट आप बैठें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, अलाउ नहीं है। Not to be recorded. प्लीज, माननीय मंत्रीजी संसदीय मंत्री हैं, प्लीज सुन लें। प्रतिपक्ष नेता ने यील्ड नहीं किया। Don’t disturb to प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) प्लीज, नहीं, बैठें आप। प्लीज बैठें आप। अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। अंकित नहीं होगा। आप बैठें। यह गलत परम्परा है। संसदीय मंत्री यदि इंटरप्ट करेंगे तो बाकी क्या बचा। प्रतिपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया। प्लीज। प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जो आंकड़े की तुलना कर रहा हूं, वह वर्ष बीत चुका है अर्थात् उसमें एक्चुअल खर्चा जो आया है, वह दिसम्बर तक का है। अगर हम 2018-19 का दिसम्बर तक का खर्चा और इस साल का आपका 2019-20 का दिसम्बर तक का खर्चा, आपने पैसे को पी.डी. खाते में डाल करके एक बार उसको आपने पूर्ति दिखा दी कि हमारे खाते से पैसा निकल गया और उस खाते में जाकर जमा हो गया, अगर सब विभागों का यह पी.डी. खाता निकाल करके देखा जाये तो ईमानदारी से आपको वह खाते में मिलेगा, जमीन पर हुए काम के लिये नहीं मिलेगा। यह जो सारे विधायक, चाहे इधर के हों, चाहें उधर के हों, ईमानदारी से कह दें कि इस एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल में जमीन पर अगर दिखता हुआ कोई काम आपको दिखाई दिया हो तो ईमानदारी से कह दो, वह पैसा वहां बुक हुआ। पैसा बुक नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा-सा अब बताना चाहता हूं क्योंकि 2018-19 में कोई छुपाना चाहे तो नहीं छुपा सकता। हमने रेवेन्यू रिसीट में, हमने दिसम्बर तक जो पैसा बुक कर लिया, वह 63.25 परसेंट था। आपने रेवेन्यू रिसीट में जो अभी तक बुक किया वह 61 परसेंट किया, फिर भी 2 परसेंट कम है। टैक्स रेवेन्यू में हमने 66 परसेंट दिसम्बर तक कवर कर लिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह गलत परम्परा है। नहीं सुनना है तो बाहर चले जायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने किया 58 परसेंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बाहर निकालो साहब इनको।

श्री अध्यक्ष: आप भी सम्मिलित हैं उसमें, आप भी सम्मिलित हैं। गलत बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): टैक्स रेवेन्यू में जो कुछ भी आपने किया वह 58 प्रतिशत दिसम्बर तक आया। जी.एस.टी. पर हमारे टाइम पर 80.9 परसेंट आ गया, आपका 56 परसेंट है। यह जो स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें हमने 66 प्रतिशत पूर्ति कर ली थी। आपका अभी 60 प्रतिशत पर है। केवल एक लैण्ड रेवेन्यू में आपने हमसे ज्यादा उपलब्धि की। हम केवल 25 प्रतिशत तक रेवेन्यू अर्जित कर सके और आपने 43.7 प्रतिशत किया है।

उसके बाद आप नीचे आयें, सेल्स टैक्स में हमने 73 प्रतिशत दिसम्बर तक पूर्ति कर ली थी, आपका 59 परसेंट हुआ। स्टेट एक्साइज ड्यूटी में हमने 52 परसेंट किया, आपने 57 परसेंट किया, इसमें आपका अधिक है। यह जो स्टेट शेयर आफ यूनियन टैक्स में हम लोगों ने 61 परसेंट किया, आपने 59 परसेंट किया। यह सारा मिला करके आपको बताता हूं कि आपने सभी में, जो आपके फीगर्स आये हैं, वे लगभग-लगभग एक-दो को छोड़ दीजिये, जिसमें आपने अधिक वसूली की, बाकी जो हमारी 2018 में थी, उससे आपका आंकड़ा कम है।

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक को अगर देखें और इस सूचकांक के आधार पर अगर राजस्थान की प्रगति को नापने के प्रयास करें तो इसके तीन सूचकांक हैं। विनिर्माण आपने कितना किया, खनन में कितना आया और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विद्‌युत में कितना आया। अगर अपन ने बेस ईयर 2011-12 को मानकर किया है तो इस वर्ष 2011-12 में, हमने 2015-16 में 102 परसेंट विनिर्माण में, 2016-17 में 115, फिर 2017-18 में 134, फिर 2018-19 में 143 और आप घटकर आ गये 126 परसेंट। इसी तरह से खनन पर हमने पहले साल में 2015-16 में 134, फिर उसके बाद 135, फिर 132, फिर 134 और आपका वह भी घटकर आया 126 परसेंट, फिर विद्‌युत में 130, 125, 124, 137 था हमारा पिछली बार, आपका घटकर 136 परसेंट पर आया। इसमें भी आप कहां हैं?

अब प्रति व्यक्ति की आय के बारे में आपने यह कहा कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, पर यह आंकड़े यह बोल रहे हैं कि वास्तव में प्रति व्यक्ति आय में, वर्ष 2014-15 से मैंने लिया, 2014-15 में राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आमदनी थी 64496 रुपया, उसके बाद 2015-16 में हुआ यह 68565 अर्थात्, 6.3 परसेंट बढ़ा। उसके बाद 2016-17 में 71394 हुआ, 4 परसेंट बढ़ा। उसके बाद 2017-18 में 74441 हुआ, 4.2 बढ़ा। उसके बाद 2018-19 में 78570, 5.5 बढ़ा। उसके बाद 2019-20 में आपका जो बढ़ा है वह 81355, परसेंटेज के हिसाब से विचार करें प्रति व्यक्ति आय तो आपका 3.5 हुआ है, जो हमारा 5.5 था अर्थात् 2 परसेंट आपकी प्रति व्यक्ति आय, आमदनी की दृष्टि से यह कम हुआ है।

अब आपको मैं कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं कि हमारी विकास की गति अवरुद्ध जा रही है, उलटी जा रही है और पर्यटन मंत्रीजी, मैं आपको हकीकत कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी पिछली सरकार ने, श्रीमती वसुन्धराजी ने पर्यटन को महत्व देकर, जब आपने हमको सुपुर्द किया था, उस समय पर्यटन का खर्चा, पहला बजट हमने रखा तो 61 करोड़ रुपये का रखा और उसके बाद दूसरा रखा तो 139 करोड़ रुपये का रखा, फिर उसके बाद रखा तो 133, फिर 163, फिर 127, आपने पिछली बार रखा 114 करोड़ रुपये कुल और इस बार बजट में है 100 करोड़ रुपया और उसमें से भी अगर खर्च का परसेंटेज निकालो न, तो यह आपका जो दिसम्बर तक का खर्चा आया, वह केवल 31 परसेंट, 114 करोड़ में भी 31 परसेंट ही पर्यटन पर खर्चा हुआ है जबकि हमारे हर टाइम में 90, 85, 95 परसेंट के आसपास हमने इसको खर्च किया है। इसका मतलब, पर्यटन की दृष्टि से भी हमारी यह हालत है।

फिर नीरोगी राजस्थान, बहुत अच्छी बात है। नीरोगी राजस्थान बने,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसको कौन ना करेगा? आप एक अच्छी स्कीम लाये थे। उस समय भी मैंने यह कहा था कि नि:शुल्क दवा के कारण से गरीब आदमी को बहुत बड़ी मदद मिलती है। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है लेकिन हकीकत में अगर इसको आप देखने की कोशिश करोगे तो आप भले ही हम पर पत्थर फेंकने का काम करो लेकिन श्रीमती वसुन्धराजी ने यह सब भामाशाह योजना के तहत उन गरीब आदमियों को जाकर ईमानदारी से, कुछ जगह पर बेईमानी हुई होगी, कुछ कमी रही होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जो कमी रही, जिसने गलत किया, उसको सज़ा दो लेकिन एक अच्छी योजना को यह कहकर पत्थर फेंकने का काम करने से कोई भला होने वाला नहीं है।

आपने उसको नीरोगी राजस्थान कर दिया लेकिन नीरोगी राजस्थान में मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2016-17 में हमने कितना बजट रखा था। राजस्थान में इस भामाशाह में 400 करोड़ रुपये, उसमें से हमने खर्च कर दिया 382 करोड़, 95.5 परसेंट। उसके बाद दूसरे साल में हमने 760 करोड़ रुपये रखा और हमने खर्च किया 744 करोड़, 97.5 परसेंट। उसके बाद वर्ष 2018-19 में हमने रखा, जो खर्च किया है, वह 1183 करोड़ रुपया, इस भामाशाह योजना के तहत उस गरीब को मदद करने का पैसा और उसमें भी हमने 97.4 परसेंट की पूर्ति की और उसके बाद यह 2019 में आपका यह जो 31.8.2019 का आंकड़ा है, उसमें आपने दिया था 309 करोड़ रुपया, कितना? 1100 करोड़ की जगह 309 करोड़ रुपया और उसमें से खर्च कितना हुआ? 285 करोड़ रुपया। जो हम हजार तक ले गये थे, गरीब आदमी को उसमें आपने कम किया और अब की बार आपने नीरोगी राजस्थान में 100 करोड़ रुपये का एक फंड रख लिया ताकि प्रचार-प्रसार में और लोगों को जाग्रत करने में यह काम में आएगा, उसके कारण से अगर नीरोगी हो जाता है राजस्थान तो बाकी सब पुराने लोगों को ध्यान में क्यों नहीं आया कि इतना बढ़िया काम, बिना पैसे के भी हो रहा है तो वह कर लेना चाहिए था? सच्चाई यह है कि इसको केवल प्रचार का माध्यम बनाकर आप कहना चाहो, आपने मुफ्त दवा योजना जब निकाली थी तो हमने उसकी तारीफ की थी क्योंकि उससे हमें लगा था कि वास्तव में इस प्रदेश के उन गरीब आदमियों को मदद मिलेगी।

अब आपने यह देखा है, यह श्रमिकों का है। श्रमिकों के आंकड़ों को भी विभाग थोड़ा-सा गहराई से देखें कि वास्तव में हम श्रमिकों को जितना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लाभ दे रहे हैं, उसमें कमी हो रही है। आपके एकदम घाटा आया है। हमने पहले साल में यानी वर्ष 2016-17 में 71111 लोगों को सहायता दी थी, जिसमें अलग-अलग है। निर्माण श्रमिक के औजार के हैं, जीवन की भविष्य सुरक्षा योजना है, शिक्षा कौशल पर है, श्रमिक सुलभ आवास योजना है, शुभ शक्ति योजना है। सारे जो हैड हैं जिसमें श्रमिक को राज्य सरकार की तरफ से पैसा मिलता है और केन्द्र सरकार का भी सहयोग मिलता है। उस समय हमने पहले साल में जो किया था वह केवल 23 करोड़ रुपया किया। दूसरे साल में 159 करोड़, फिर उसके बाद में 361 करोड़, फिर उसके बाद 439 करोड़ और अब की बार जो आपने किया है वह केवल और केवल 303, हम 400 तक ले गये थे, उसको आपने घटाकर मजदूरों को इन योजनाओं में जो मदद की वह 303 करोड़ रुपये की की है अर्थात् आपने इसमें भी पैसा घटाया है।

अब आप सच में कहना, मैं जो बात कह रहा हूं न दिसम्बर तक जो आप पैसा बुक कर रहे हो कि 60 परसेंट, 61 परसेंट, वह हुआ नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस विधान सभा के एक-एक प्रश्न के जवाब में जो कुछ भी आया है न, वह आपको और मेरे को इस बारे में सच्चाई बता देगा कि क्या वास्तव में सच है और क्या गलत है।

पहला विधान सभा का प्रश्न आया था कि हम नंदीशाला खोलेंगे। उसके लिए आपने तालियां पिटवाई थीं कि नंदीशाला हर पंचायत समिति में खोलेंगे। प्रश्न का जवाब क्या आया? अभी तक किसी भी पंचायत समिति में नंदीशाला स्थापित नहीं की गयी है। यह आपका उत्तर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके इस विधान सभा में लगे हुए प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूं।

फिर आपने कहा कि गत बजट में कृषक कल्याण कोष की स्थापना की। बहुत अच्छा काम किया आपने। 100 करोड़ रुपया आपने कृषक कल्याण के लिए किया। इसका जो हेतु था, वह यह था कि उसकी सपोर्ट प्राइस जब गिरती है तब हमको खरीदने में, उस किसान को मदद करने की दृष्टि से हम इस फंड का उपयोग करेंगे लेकिन आपने उपयोग कहां किया? प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि 500 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश प्रीमियम के लिए रखा है। मतलब, राज्यांश प्रीमियम आप किससे जमा करा रहे हो? इस कृषक कल्याण कोष से। क्या इसका हेतु यही था, इसके कारण से इसको किया था?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने यह देखा कि फसल बीमा नहीं होना। मैंने बार-बार उस समय भी पूछा था। मैंने यह कहा कि राजस्थान का किसान बहुत भुगत रहा है, समय पर उसका जो कर्जा है, वह फाइल पर न तो उसके खाते में जमा हुआ और न उसके कारण से रीलोनिंग हुई। रीलोनिंग नहीं होने के कारण से उसको इंश्योरेंस जो होना है, वह पैसा जमा नहीं हो पाया। आपने स्वयं ने यहां विधान सभा के फ्लोर पर खड़े होकर यह कहा था कि 31 जुलाई तक अगर आपका पैसा जमा नहीं होगा तो इंश्योरेंस कम्पनी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, आपका इंश्योरेंस नहीं होगा और इस प्रश्न के उत्तर ने इस बात को बहुत सच्चाई से प्रमाणित कर दिया। कृषि मंत्रीजी, आपके जवाब में, खरीफ, 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा जो 4 परसेंट आता है वह 1430 करोड़ रुपये जमा करा दिये, राज्य सरकार द्वारा 1430 करोड़ रुपये अभी तक भी जमा नहीं करवाये हैं। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

इसी तरह से रबी, रबी की फसल वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश प्रीमियम राशि 685 करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं, राज्य सरकार द्वारा अभी तक जमा नहीं कराई गई। फसल बीमा की दृष्टि से किसानों को एक रुपया भी नहीं मिला। यह आपका उत्तर है, मैं नहीं कह रहा हूं।

आपके प्रश्नों के उत्तर के आधार पर आपको और मेरे को यह समझ में आ जाता है कि गलती कहीं पर भी हुई हो लेकिन उसको भुगत कौन रहा है? राजस्थान का किसान भुगत रहा है।

आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि 50 नये सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। कितने? ओहो, पचास। उसमें से खोले कितने? प्रश्न का जवाब आया कि वर्ष 2019-20 में मात्र दो सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। यह बजट का उपयोग है। यह बजट का उपयोग हुआ न जो आप 61 परसेंट बता रहे हो हरेक में, वह 61 परसेंट ऐसे ही जमा हुआ है।

फिर आपने एक और अलग प्रश्न में दिया है, पशुपालन में। आपने यह कहा कि 400 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे। यह आपके बजट की घोषणा है, सबने तालियां पीटीं और आपने यह कहा कि हमने हां, एक लिस्ट बनाकर फेहरिस्त जारी कर दी, 226 पशु चिकित्सालय केन्द्र स्वीकृत किये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवसृजित पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अक्रियाशील होने के कारण बजट आबंटन व्यय नहीं हुआ। बजट आबंटन नहीं हुआ। यह 400 करोड़ का बजट यूं का यूं मैंने कहा न, अभी कहीं न कहीं फाइलों में पड़ा है बजट का पैसा, जिसको आप खर्चा बता रहे हो।

फिर आपने कहा रबी फसल का, 2019 में छह जिलों में टिड्डी के कारण से फसल को जो नुकसान हुआ, उसके बारे में प्रश्न पूछा तो आपने कहा 23,761 किसान आज भी आर्थिक सहायता से वंचित हैं। यह आपका ही दिया हुआ उत्तर है।

बजट घोषणानुसार 2019-20 का जो बजट था, उसमें आपने लिखा था 600 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय, 500 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय, लगाओ ताली, सबने बजायी पर जब प्रश्न का उत्तर आया तो यह सब चौपट हो गया। स्थानीय मांग एवं निर्धारित मापदण्ड तथा समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन करने के पश्चात्, सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात्, सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कब? फरवरी, 2020 में। फरवरी, 2020 में यह विचार किया जाएगा, इसका मतलब आपका बजट कागजों में बुक है, पर ईमानदारी से धरती पर नहीं आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता क्लिनिक के बारे में, बहुत अच्छी बात है। इस बार भी घोषित किया और पिछली बार भी आपने घोषित किया अपने बजट में। अब की बार भी लिखा है। जनता क्लिनिक जयपुर में, आपने देखा जयपुर में कब खुला है 15.02.2020 को पांच जनता क्लिनिक, अचानक एकदम से नींद उड़ी कि ये क्या हुआ, जनता क्लिनिक के नाम से तो अपन ने बहुत कमाई की, यह तो बिलकुल ही गड़बड़ हो गया तो प्रश्न के उत्तर में यह 5 जनता क्लिनिक खोलकर, उस दिन प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि हमने पांच जनता क्लिनिक खोल दिये। यह इसीलिए था कि सम्पूर्ण राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं में लोगों को सुलभ इलाज मिले, इसके लिये जनता क्लिनिक थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण परिवहन सेवा चालू करेंगे। यह बजट में आपकी घोषणा थी। आपने उत्तर में क्या लिखा है? ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संसाधन हेतु कार्यवाही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रक्रियाधीन है। फरवरी, 2020 में प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब जमीन पर आ गयी न?

बजट घोषणा 2020 में 100 अग्निशमन वाहन खरीदने हेतु 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कब? 2019-20 में और आप उत्तर क्या दे रहे हो? आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा 60 अग्निशमन वाहन और जिला कलक्टर द्वारा 40 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब खर्च हो गया न।

इसी तरह से, आपने एक प्रश्न के उत्तर में दिया सहकारिता विभाग में, लघु और सीमांत किसानों को अंशदायी पेंशन योजना। इसका पैसा बजट में रखा था। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। इस योजना में 32,709 किसानों का पंजीकरण किया, लाभ नहीं दिया है।

इसके बाद अगला प्रश्न है- राजकीय सहायता के अलावा वित्तीय संबल प्रदान करने के लिये सरकार जन सहभागिता और सी एस आर फण्ड, यह गौशालाओं को देने के लिये गौशालाओं को सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस पर भी खूब तालियां बजीं। इस योजनान्तर्गत किसी भी गौशाला को अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

फिर यह 2019 का ही राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन सम्मान योजना की घोषणा की गयी। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित कर योजना की क्रियान्विति की जाएगी। इसका मतलब काम हो गया न।

इसी तरह से, आपने यह एक और सवाल के जवाब में लिखा, पुराना विधान सभा भवन, बहुत मोटा अमाउंट नहीं था, पुरानी विधान सभा सवाई मानसिंह टाउन हाल में राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा। उक्त संग्रहालय के लिये 2 करोड़ की सहमति प्रदान की गयी। प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। अब हुआ क्या, यह अभी तक पता नहीं।

आपके स्वयं के जोधपुर के स्टेडियम में, आपके मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया कि 2 करोड़ आपने 2019-20 के बजट में रखा था, लेकिन अभी तक उसका टेंडर ही प्रोसेस नहीं हुआ है तो कहां गलती पर हैं। जब आपके जोधपुर में नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो सकता है। जब मैंने प्रश्न पूछा, तब बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, गलत परम्परा है। आपको कोई अधिकार नहीं है। सुनिए। प्लीज। गलत परम्परा है। आप सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान) गलत परम्परा है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल) असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा है। आपको समझ में नहीं आ रहा। यह कोई तरीका नहीं है। आप सैकण्ड टाइम एम.एल.ए. हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भंडारण की सुविधा, वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण करने की घोषणा की गयी। 100 गोदाम की घोषणा की गयी। प्रस्ताव प्राप्त होने पर 100 गोदाम बनाने थे और 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में बनाने थे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जाएगी। यह फरवरी, 2020 का उत्तर है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो हकीकत है उसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप भी अपनी जेब से पैसा मिलाकर उसमें नहीं लगाओगे लेकिन उसको छिपाकर हम केवल जनता के सामने यह पेश करना चाह रहे हैं कि हमने तो राजस्थान पूरा डुबो ही दिया और आप राजस्थान को तिराने के लिये सब प्रयत्न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके कारण से दु:ख होता है। अगर कोई सच्चाई को मानते हुए अपनी बात कहे, हमें कोई दु:ख नहीं होगा।

नरेगा में आपको जो 2100 करोड़ रुपया मिल रहा था, इस बार आपके बजट में 1988 करोड़ है, अर्थात् आपकी इसमें 111 करोड़ रुपये की कमी दिखायी गयी है।

यह जो हमारी बोर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसमें सड़क बनाने के लिये 135 करोड़ थे, आपने उसको घटाकर 76 करोड़ रुपया कर दिया। आवश्यकता महसूस नहीं होती क्या कि बोर्डर पर हमारी सड़क बने।

उच्च शिक्षा के बजट में 333 करोड़, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उसकी जगह अब आपको मिला 222 करोड़, यानी 111 करोड़ कम मिला है।

यह जो नि:शुल्क दवा का बजट मात्र 62 करोड़ रुपया बढ़ा और नीरोगी राजस्थान हो जाएगा। 62 करोड़ रुपये का बजट बढ़ा है, नीरोगी राजस्थान आप कर डालोगे? पहले मिला था 556, अब मिला है 619 करोड़ रुपया, इससे आपका नीरोगी राजस्थान हो जाएगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महिलाओं के लिये बजट में आपका 6.12 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी कोष एक हजार करोड़ का है, वह कहां है? उस एक हजार करोड़ का क्या उपयोग हुआ? वह क्या देखने के लिये बना है या किसके लिये बना है?

जनजाति विकास में, मैं सावधान करना चाहता हूं, यह भी बुकिंग है। अगर इसकी तह में जाओगे न तो 20 प्रतिशत भी खर्चा जमीन पर नहीं हुआ। यह मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा। वह अभी रास्ते में ही चल रहा है, क्योंकि मैं उसी एरिये में रहता हूं। जनजाति का जो बजट है, वह 344 करोड़ से घटकर 322 करोड़ पर आ गया है। 22 करोड़ की आपने इसमें कटौती की है।

नई भर्ती के बारे में आपने बहुत तालियां पिछली बार भी पिटवायीं और इस बार भी पिटवायीं। हकीकत को जानने का प्रयास करो कि वास्तव में यह नई भर्तियां हुईं या क्या हुआ इनका? नई भर्ती के बारे में आपने पिछली बार कहा था कि 75 हजार भर्ती करेंगे। ईमानदारी से जवाब दो तब बता देना उन 75 हजार के अगेंस्ट में कितनी भर्ती हो गयी? आज आपने फिर 53,181 की जो घोषणा की है, इनमें से कुछ उन पुराने वालों में सम्मिलित हैं। यह जो आपने देखा होगा कि सहकारिता विभाग की पहले 750 हुई, अब इस बार वापस एक हजार है। क्या यह 750 इसमें शरीक है या एक हजार इसके एक्स्ट्रा है? 1750 हो गयी क्या? चिकित्सा में 15 हजार की थी, 4,300 अब की बार बताया 69, इसमें सम्मिलित हैं क्या? पुलिस की 4 हजार की भर्ती का बताया, अब की बार 5 हजार की भर्ती बतायी। यही 4 हजार हैं जो 75 हजार में गिने गये हैं? पहले 75 हजार में काउंट किया, अब आप इनको 53 हजार में काउंट कर रहे हो ईमानदारी से। इसी तरह से चिकित्सा में पिछली बार 269 और अब की बार 573, स्वायत्त शासन में यह आपने नई की है घोषणा 1,039, मैं सोचता हूं कि यह 75 हजार की और 53 हजार की घोषणा है।

मेरे उदयपुर से आपको कोई नाराजगी है या मेरे से नाराजगी है, मुझे यह समझ में नहीं आया। मेरा संभाग इतना अभागा है क्या कि जिसके कारण से इस बजट में सारे उदयपुर संभाग का, चाहे कहीं के आंकड़े हो, किसी भी जिले का नाम उठा लेना, भगवान के लिये बता दो कि हम लोगों को इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संभाग में क्या पैसा स्वीकृत किया है। मैं अपना उदयपुर का बताता हूं जो आपने इस बजट में लिखकर बताया। मुझे यह कहा गया कि पिछली बार के बजट में भी 50 करोड़ रुपया उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु करने के लिये बजट घोषणा हुई। यहां का कोई अधिकारी, जो बैठा हुआ है, उसमें से एक पैसा भी उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिये खर्च हुआ है क्या? उपभोग जरूर हुआ होगा। मेरे उदयपुर के आयड़ के विकास के लिये इन्होंने बड़ी होशियारी से जो हमारे पास स्मार्ट सिटी का पैसा है या यू.आई.टी. का पैसा है और नगरपालिका का पैसा है, तीनों संस्थाओं का पैसा हमने आज से कोई डेढ़-दो महीने पहले स्मार्ट सिटी से 35 करोड़ रुपया लिया, 30 करोड़ रुपया यू.आई.टी. ने अपना मिलाया और 5 करोड़ रुपया नगरपालिका ने मिलाकर 75 करोड़ रुपया आयड़ के विकास के लिये दिया। उसको अपने खाते में लिखकर यहां ताली बजवाने का प्रयास किया, यह हकीकत है। फिर उसने कहा यह 25 करोड़ रुपया हम अफॉर्डेबल हाउस के जो मकान बने हैं उसमें पानी की सप्लाई के लिए देंगे, वो बजट ही यू.आई.टी. का है। आपका उसमें कोई बजट है ही नहीं।

मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे साथ आपने जिस प्रकार का बर्ताव किया, मैं सोचता हूं कि ये तो सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, कोई बात नहीं, कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, धरती फटेगी नहीं लेकिन यह हमारे साथ न्याय नहीं है। एक भी योजना बता देना।

मैं अब आपको सावधान कर रहा हूं। सावधान यह कर रहा हूं कि आपको जो अभी तक राजस्व प्राप्तियां हुईं वो केवल और केवल 55 प्रतिशत हुई हैं। जो अब तक राजस्व प्राप्तियां हुई हैं वो 55 प्रतिशत हुई हैं और राजस्व खर्चा जो अभी दिसम्बर तक हुआ है वो 33 परसेंट हुआ है, यह कैसे मेंटेन होगा इन दो महीनों में, तीन महीनों में कैसे होगा? अब तक मात्र लगभग एक लाख करोड़ का राजस्व आया है, फिर आप दो महीने में यह 56 हजार करोड़ रुपया कहां से ले आओगे, कैसे वसूल कर लोगे? कोई जादू है क्या है? अगर आप साल भर में एक लाख करोड़ रुपया वसूल कर सके तो अब 56 हजार करोड़ कैसे?

प्रस्तावित आय बढ़ोतरी का कोई आधार नहीं है, आप कोई आधार नहीं बता पा रहे हो। प्रस्तावित खर्चे, पिछले वर्ष के बराबर रखे। अगर महंगाई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भत्ता, आपने अभी घोषणा की, पहले वाला महंगाई भत्ता भी अभी कर्मचारियों को नहीं मिला है और अभी आपने घोषणा और की कि हम 12 में मिलाकर 17 परसेंट कर देंगे, इस बजट में बता देना कि इसमें जो 5 परसेंट महंगाई भत्ते की घोषणा करके हम सबसे जो ताली पिटवाई थी उस पैसे का एलोकेशन बजट में किस जगह लगा हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ वास्तव में न्याय हो रहा है।

यह जो ढांचागत विकास की अवधारणा को शायद मुख्य मंत्री जी भूल ही गये क्योंकि घोषणा के अम्बार में आधी से ज्यादा घोषणाएं तो पिछले वर्ष की हैं और केन्द्र द्वारा पोषित हैं। जिस केन्द्र को आप गालियां दे रहे हो ना इसमें से आपकी आधी योजनाएं तो केन्द्र द्वारा पोषित हैं।

आपने बहुत कहा रिफाइनरी, रिफाइनरी, रिफाइनरी, आप जिस गति से चल रहे हो न, पिछली बार 245 करोड़ दिया, इस बार 500 करोड़ दिया है, आपका 26 परसेंट शेयर है, 43 हजार करोड़ की योजना है, क्या आप इनको 10-15 साल में पैसे दोगे ताकि 10-15 साल में रिफाइनरी तैयार होगी? अगर रिफाइनरी को चार साल, पांच साल में तैयार करना है तो आपको बजट का भी आधार उसी से बनाना पड़ेगा। 500 करोड़ रुपये लगा तो बहुत अच्छा कि 500 करोड़ दे दिया लेकिन 500 करोड़ से ये रिफाइनरी, आपका 26 परसेंट का शेयर पूरा करेगा?

अब की बार देवनारायण योजना दफ्तर दाखिल हो गई कि नहीं हो गई? एक भी पैसा कहीं दिखाई देता है? मैट्रो का सैकण्ड फेज वाला जो आगे का बनना था उसका इस बजट में कहीं एलोकेशन है क्या?

रोज सवेरे जो भी बोलता है वह केन्द्र का रोना, केन्द्र असफल, यह हुआ, ठीक है अगर आपके तर्क में वजन है तो कोई समझने की कोशिश करेंगे।

मुख्य मंत्री अपने वित्तीय प्रबंधन को चौपट होने पर भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, मानो घर फूंक तमाशा देख रहे हैं।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2.28 परसेंट गिरा है और आज की तारीख में आपका हुआ है 5.05 परसेंट। राज्य सरकार ने देश भर में सर्वाधिक वैट दरों को शामिल, डीजल और पैट्रोल पर वैट का किया है। इससे न तो उद्योग को, न किसान को लाभ मिलेगा। कंपेरिजन में, हमारी पैरीफेरी में जो स्टेट हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनका वैट कम होने के कारण से हमारा जो आंकड़ा आया है वो 5 परसेंट डीजल और पैट्रोल हर साल जितना खपत होता है इस बार राजस्थान का कम खपत हुआ है और 5 परसेंट के आधार पर जो टैक्स हमको मिलना था अगर इसमें कुछ कम करते तो हमें मिलता।

आपने बहुत ताली लगाई कि एक परसेंट स्टांप ड्यूटी कम कर दी, किस पर? फ्लैट पर? कम नहीं की है, एक परसेंट फ्लैट पर रेट बढ़ाई है। जमीन पर तो आपने डी.एल.सी. कम की, दस परसेंट की लेकिन फ्लैट के ऊपर जो रजिस्ट्री करायेगा तो उसको एक परसेंट अतिरिक्त लगेगा। इसका मतलब जिस आदमी को भी 30 लाख का फ्लैट खरीदना है उसको उसी हिसाब से 30 हजार रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। पहले ही आपकी यह जो सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको आधी कीमत में बेचनी पड़ रही हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने बनाई होगी वो इसको आधी कीमत में बेच करके दिवालिया हो करके नहीं जाएगा लेकिन आपने इसको बढ़ाने का काम करके अच्छा काम नहीं किया। फिर आप यह कहते हो कि सरकार पारदर्शी है।

एक घटना मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला घोटाला निकला है, ए.सी.बी. ने जिसमें प्रयत्नपूर्वक चार महीने तक जूझे, लगभग 30 लोगों के टेलीफोन सर्वर में डाले और सुनने के बाद यह पता लगा कि लिंक कहां-कहां तक है, उस लिंक को खोलने का प्रयत्न किया लेकिन आपने उसको दफ्तर दाखिल कर दिया। यह राजस्थान के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए ठीक नहीं होगा।

अभी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार का जो स्थाई खर्चा है वो स्थाई खर्चा है 1 लाख 10 हजार 24 करोड़ रुपया, जो पहले था हमारा वेतन में, यह जो हमारे भत्ते वाला, ऋणों की किस्त है, ब्याज है, इसमें जो हमारा पैसा जाता था, पिछली बार 1 लाख 10 हजार करोड़ गया और इस बार आपका जाएगा वेतन भत्ते और इसमें 1 लाख 21 हजार 541 करोड़ रुपया जाएगा, तो विकास कहां से जाएगा?

राज्य के करों में गैर करों की आय तो मात्र 81 हजार 813 करोड़ है और बजट में आपने 92 हजार 867 करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह तो इन स्थाई खर्चों का क्रमशः 73 परसेंट और 76 परसेंट है। 76 परसेंट 2019-20 में और 2020-21 में, यह इसमें स्थाई खर्चे में चला जाता है जिसके कारण से विकास कहां से आएगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज्य सरकार ने स्वयं के करों में राजस्व व स्थाई प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाने की मजबूरी के चलते स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण के लिए मात्र, जो हमारी प्रोपर्टी बनने वाली है वह 19 हजार 472 करोड़ की बनेगी जो पिछले साल से 7.5 प्रतिशत कम है।

मैं फिर आपको एक बार इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं, यह जो आप बार-बार कह रहे हैं न केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार, मैं सोचता हूं कि पत्थर फेंक करके किसी आदमी की मदद नहीं ली जा सकती है। अगर मदद लेनी है तो हकीकत को मानते हुए मदद लेंगे। वैसे भी मैंने आपको कहा, इस बार आपको 51 हजार करोड़ रुपया, 41 पैसे होने के बाद भी 51 हजार करोड रुपया अपने को मिलने वाला है जो आपने बजट में 46 हजार करोड़ दिखाया है। आप वापस एक्चुअल में आर.ई. में जब जाएंगे तब आपके पास यह सरप्लस होगा और यह जो आपने खर्चा कम किया है 12 हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू में घाटा बता रहे हो, राजस्थान में इस साल सकल में 33 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा लेंगे तब जाकर आज का जो बजट है उस बजट को हम सही कर पाएंगे।

यह स्पष्ट है कि सरकार करों में आय बढ़ाने में पूर्णतया असफल रही है। हमारी वसूली कितनी हुई, हमने अपना रेवेन्यू कितना जनरेट किया और कितना वसूल हुआ है इसका भी हिसाब निकाल करके प्रयत्न करो कि जो हमें वसूल करना था वो हम कितना कर पाये और कितना हम नहीं कर पाये?

संग्रह कुल बजटीय खर्चों का मात्र 38 परसेंट और 2019-20 में केवल 39 परसेंट इकट्ठा हुआ है हमारे पास, 38 और 39 परसेंट।

राज्य के करों में गैर करों की आय, यह जो मैं आपको बता रहा था 2019 में 81 हजार 813 था और फिर राज्य का कुल खर्च 2 लाख 12 हजार करोड़, यह 38 परसेंट है और इस साल का 92 हजार 863 करोड़ रुपया करों से आयेगा और आपका कुल खर्चा 2.32 का है जो 39 परसेंट, यह पिछली बार का है। स्पष्ट है कि राज्य के राजस्व आय खर्चों को पूरा करने के लिए ही काफी नहीं है तो फिर मुख्य मंत्री घोषणा केंद्रीय सहायता और नये कर्जों के भरोसे ही होगी जिसमें से अधिकांश केंद्रीय घोषणाओं में से ही है।

पिछले वर्ष की गई 50 प्रतिशत घोषणाएं, मैं सही कह रहा हूं अगर आप ईमानदारी से अपने दोनों बजट भाषण देखें, यह मेरे पास दोनों हैं, इन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दोनों को रख करके पढ़ने के बाद आप अगर यह देखोगे कि वास्तव में इसमें धरातल पर कुछ उतार पाये कि नहीं उतार पाये, तो आपको इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट है कि पिछले वर्ष 50 प्रतिशत घोषणाएं तो बजट भाषण से बाहर नहीं निकलीं, बाकी बची हुई 50 प्रतिशत घोषणाओं में से आधी कागजों तक ही चली और शेष घोषणाएं वित्त पोषण के अभाव में धरातल तक नहीं पहुंचीं।

मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आप इसको एक बार फिर दिखाएं। हमारे सोर्स लगाएं और हमारी रेवेन्यू भी कलेक्ट करने का प्रयास करें। 2 महीने में 56 हजार करोड़ रुपये वसूल करेंगे तब जाकर हमारा जो बजट आपने घटा करके पेश किया उसकी भी पूर्ति हो पाएगी, बाकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।

आप भले ही मेरे पक्ष में रहें या ना रहें, मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता हूं लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं कि आपका यह बजट राजस्थान की बढ़ती हुई प्रगति को रोकने वाला बजट साबित होगा। विशेषकर नौजवानों को आपने कहीं भी यह नहीं दिखाया कि उसको जो 3500 रुपया वजीफा मिलने वाला है, 27 लाख बच्चे हैं और अभी आपने जो प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया, वो 1 लाख 62 हजार, उसमें से 58 हजार पहले की सरकार के चिन्हित वो बच्चे हैं जिनको हम पहले से स्कालरशिप दे रहे हैं तो आपकी यह बढ़ोतरी इतनी सी है, आपने 3500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से कहा। फंड का एलोकेशन कहां है? जहां से हमें यह लगे कि वास्तव में आपका यहां से एलोकेशन है, जहां से इस बच्चे को मिलेगा। आप किसान को न तो कर्जा दे सकते हो, न माफ कर सकते हो। खाली आंकड़ों का जाल आप दिखा रहे हो।

यह आपने जो फसल बीमा का किसान का नुकसान किया है, यह आपको और मुझे जिंदगी भर तक याद रहेगा। केवल हमारी कमी के कारण से, गलती के कारण से हुआ। आपदा राहत का पैसा तो केन्द्र सरकार भी देती है। मैं आपको लगभग 2700 करोड़ रुपया छोड़कर आया हूं। उसके बाद इस आपदा के तहत आप किसान को कम से कम समय पर पैसा दे देते। विशेषकर जो बारिश में खराबी हुई फसल की और अभी जो खराबी हुई उसके पेटे एक रुपया भी सरकार ने अगर किसान के खाते में डाला हो तो बता दें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कलक्टर के खाते में डाल दिया, उसको तो मैं मानता हू कि आपका कुछ पैसा कलक्टर के खाते में जमा हो गया लेकिन हकीकत में उस किसान को पैसा बंटा नहीं है।

आपने चाहे या अनचाहे ट्रैजरी को आदेश दे रखा है। हम विधायकों का फंड वह तो हमारी बड़ी मेहनत के बाद, पत्र लिखने के बाद रिलीज किया। जब हम कोई सैंक्शन निकालते हैं तो वह 4 बार कागज इधर से उधर घुमाता है। उसको जब तक 6 महीने नहीं लगते हैं, तब तक वह सैंक्शन नहीं निकलती है। इसका मतलब उस सीईओ का दोष नहीं है। सरकार से ही आदेश है कि धीरे-धीरे देना। आपके सारे ठेकेदार रोज सवेरे-शाम उस कलेक्ट्री के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके दर्द को वही पहचानता है जिसका बच्चा भूखा रहता है। उसने की तो ठेकेदारी, लेकिन पेमेंट नहीं होने के कारण उसकी गृहस्थी नहीं चल पा रही है। आपने पैसे को रोककर जाम कर रखा है। कहने के लिए, विकास के लिए केवल आंकड़ों से पेट भरता हो तब तो राजस्थान की जनता का पेट भर जाएगा। हकीकत में, ईमानदारी से कह रहा हूं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, अगर आपको विकास का पहिया कहीं चलता हुआ दिखता हो तो आप हमें बता दीजिए। हम मान जाएंगे कि आपने इस पैसे का सदुपयोग किया।

बाकी तो मैं एक तरह से यह कह सकता हूं कि यह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, बाल, महिला, युवा, पर्यटन को समाप्त करने वाला, जनजाति विरोधी बजट है। जिस प्रकार से आपने बजट में कटौती की है, राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य में डालने का आपका यह जो प्रयत्न है, जो कि आपने पहले भी किया। हमने इसको प्रयत्नपूर्वक निकाला है। मैंने आपको आंकड़े देकर बताया है।

वसुन्धरा जी को आप चार गालियां दे सकते हो, मगर मैं यह कह सकता हूं कि एक दिन भी उसने यह नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। जो भी प्रस्ताव लेकर गए, उस प्रस्ताव को उसने स्वीकृत किया। कहां से पैसे की व्यवस्था की, यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन उसने कहीं से भी की, लेकिन व्यवस्था की। उसने कभी भी यह नहीं कहा कि खजाने में पैसा नहीं है। इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 15)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मध्यान्ह पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किये जाने का निर्णय लिया। शेष कार्य चौदहवें प्रतिवेदन के अनुसार सदन में यथावत विचारार्थ लिए जाएंगे:-

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020	अनुदान की मांग संख्या- 1- 27- पेयजल योजना 2- 46- सिंचाई 3- 38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण -पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2020	1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020; एवं 2. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020; -पर विचार एवं पारण। 3. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च, 2020	अनुदान की मांग संख्या- 1- 16- पुलिस 2- 17- कारागार -पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2020	अनुदान की मांग संख्या- 1- 42- उद्योग 2- 23- श्रम और रोजगार -पर विचार एवं मतदान।

(डा. महेश जोशी)

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2020	1. राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण। 2. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2020 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

आय व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन इस सदन में प्रस्तुत बजट पर चर्चा हुई। करीब 95 पक्ष और विपक्ष के लोगों ने भाग लिया। इसमें निर्दलीय साथी भी हैं। सीपीएम के हैं। सभी पार्टियों के हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हैं कि जब बजट रखा गया तो मैंने महसूस किया पहली बार, इस बजट का जो स्वागत हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं, 7 संकल्प, लोगों ने एप्रिशिएट किया। लोगों ने कंटेस्ट किया। आपने किया, आपकी मर्जी है। मुझे बताइए आप कि जिस बजट की तारीफ इस रूप में हो, जो हालात देश में हैं आर्थिक रूप से और प्रदेशों में बनते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना शानदार बजट पेश करना। लोगों ने कहा, बैठे हैं हमारे साथी, हमें उम्मीद नहीं थी कि यह बजट ऐसा आएगा। यह कहा गया। उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार बजट आएगा। ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह आपका धर्म

(श्री अशोक गहलोत)

है कि आप उसकी आलोचना करो। मुझे कोई एतराज नहीं है। सुझाव अच्छे देंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा दृष्टिकोण खुला हुआ रहता है। सरकार आपकी आती है, कभी तो आप कहते हो कि कोड आफ कंडक्ट विधायकों का, बुलाते नहीं हैं मंत्री लोग। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हम तो बुलाते हैं। बुलाना चाहते हैं। अगर माननीय विधायक आकर वहां पर बैठते हैं तो अच्छा लगता है। माहौल भी वहां पर आपको अच्छा मिलता है क्योंकि हमारा कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। आप जब सत्ता में होते हो, पहली बात तो ये बुलाने का नाम ही नहीं लेते। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मुख्य मंत्री था। कभी किसी को नहीं बुलाया गया। भूले-चूके किसी को बुला लिया गया तो आप लोग माहौल ऐसा रखते कि वह जाकर वहां बैठ ही नहीं सकता। यह बात अलग रही।

अशोक लाहोटी जी ने पता नहीं किस सेंस में वहां पर मीटिंग के अंदर कुछ बातें कह दीं। तूफान आ गया पार्टी में, तूफान आ गया। उसको फटकार लगी। भाई, उसका क्या कसूर है? कोई माननीय सदस्य, अगर उसने अपने मुख्य मंत्री को, मुख्य मंत्री सबका होता है। पता नहीं, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। आधा घंटा ले लिया आपने आंकड़े बताने के लिए। यह आंकड़े तो छपे हुए हैं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आंकड़े तो सरकारी अधिकारी बनाते हैं। अकाउंटेंट जनरल आफ राजस्थान के हों, सीएजी दिल्ली के हों, सब देखते हैं। बजट वह बनता है, कितनी रेवेन्यू आएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितनी रेवेन्यू रिसीट है और कितना अपना एक्सपेंडिचर होगा? फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा? उससे आपका आईना दिखता है। बजट एक आईना होता है सरकारी सोच का।

बजट में जो संकल्प हमने रखे हैं, वह सोच-समझकर रखे हैं। आपने हर विभाग के बताए। आप यह नहीं मानते कि जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त हमने क्यों 50 परसेंट रेलवे को देना मंजूर किया हिन्दुस्तान में पहली बार? क्यों किया मंजूर? उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति शानदार थी। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक, दो में हमने भागीदारी निभाई। तीसरा केन्द्र सरकार ने खुद किया था, सरमथुरा- गंगापुर सिटी वाया करौली।

(श्री अशोक गहलोत)

आपकी सरकार के मुखियाजी ने अपने महल में टूरिज्म कैसे बढ़े उसके कारण से वहां से उसको कैंसिल करवा दिया लिख करके। यह क्यों भूल जाते हो आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): क्यों भूल जाते हैं यह? यह स्थिति क्यों बनी हमारी उस वक्त? हमने दवाइयां फ्री कीं। आप बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम जिन्दगी में एक तो तारीफ की किसी की। आप मुझे बताइये उन दवाइयों की आप तारीफ कर रहे थे और आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री कह रही थीं कि दवा नहीं, जहर है। जहर है, जहर की तारीफ आप क्यों कर रहे थे? वह पिछली वाली सरकार बदल गयी, वह जहर चालू क्यों रखा गया? चालू क्यों रखा गया? (व्यवधान) जिस रूप में बजट पेश किया गया, जिस रूप में एक के बाद एक स्कीमें लागू की गयीं, रिफाइनरी लायी गयी, अभी मैं आऊंगा रिफाइनरी पर, जो आप बोल रहे थे। एप्रिशिएट करने को कहेंगे आप, सरकार बदलते ही आपके मेमू कोच फैक्ट्री गायब, रेलवे प्रोजेक्ट्स गायब। इन्होंने पहले भी कहा है, रिफाइनरी पांच साल तक बर्बाद कर दी इसको, क्यों कर दी बर्बाद? यह 26 परसेंट भागीदारी क्यों? बिजली हमारी, तेल हमारा, जमीन हमारी, मैं पूछना चाहता हूं कि 26 परसेंट भागीदारी क्यों रखी उसमें? आरएमओ कहता है कि प्रोविजन नहीं किया गया। आप चिंता छोड़िये, यह भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का सामूहिक प्रोजेक्ट है, जोइण्ट वेंचर है, एचपीसीएल का और यहां की कम्पनी का। हम करेंगे, प्रोविजन करेंगे, हम अपना हिस्सा देंगे। यह मैं आपको कह सकता हूं कि आज कम से कम रिफाइनरी को हमारे दबाव में आपको शुरू करना पड़ा वरना वह रिफाइनरी ही गायब हो जाती यहां से। सरकार जब हमारी थी, आप अपने आंकड़े बता रहे हो, आप तो दिसम्बर में आये थे, दिसम्बर में ही हम अभी आये हैं। हमारा बजट पेश हुआ जुलाई के अंदर, अभी मोडिफाइड बजट, अभी उसको छह महीने ही हुए हैं, तो क्या छह महीने में आप उम्मीद करते हो कि सारे की घोषणा पूरी हो सकती है? हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं। जुलाई में पेश हुआ बजट हमारा, अभी हमारा नया बजट आया है और पिछले जो कर्जे छोड़कर गये थे आप तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये के आसपास, उसके बाद में हम हमारी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से। आप बार-बार कहते हो कि केन्द्र सरकार को गाली निकालते हो,

(श्री अशोक गहलोत)

आरोप लगाते हो उन पर, पैसा मांगते भी हो। पैसा हम नहीं मांगते हैं। संविधान के अंदर लिखा हुआ है, संविधान के अंतर्गत, आपको तो मालूम होगा, आपको तो जानकारी होगी, फाइनैंस कमीशन तय करता है, किस राज्य को कितना परसेंट पैसा मिलेगा केन्द्र से, वह पैसा उनको देना ही पड़ता है। एहसान नहीं करता केन्द्र, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप कैसे कह रहे हो कि कम पैसा, हम आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हम लोग क्या? आप आइए, बैठकर बात करते हैं, हम चलते हैं दिल्ली के अंदर, वित्त मंत्रीजी से मिलते हैं। पूछते हैं कि हम जो आंकड़े दे रहे हैं वह गलत हैं क्या? आज हमारे पैसे कट रहे हैं, सीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी का पैसा आ नहीं पा रहा है, दस हजार करोड़ रुपये अधिक का पैसा कट गया है, ग्राण्ट हमारी कट गयी है, यह तो फैक्ट है। यह तो फैक्ट है इसमें क्या छिपाने की बात है? उसको भी आप नकार रहे हो। एक तरफ आप नकार रहे हो, दूसरी तरफ आपकी सरकार खुद, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो राज्यों की स्थिति बिगड़ रही है, सब राज्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, केरल हो, और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा हमने अभी तक मैनेजमेंट कर रखा है अच्छा। आप देखियेगा कि दस राज्य ऐसे हैं, जहां पर स्पेसिफिक ड्राइंग फैसिलिटी अवेल्ड, आप भी इसे कर चुके हैं, वे हैं, आंध्र प्रदेश 1562 करोड़, छत्तीसगढ़ 1096 करोड़, गोवा 74 करोड़, केरल 330 करोड़, मणिपुर 46 करोड़, मिजोरम 72 करोड़, नगालैण्ड 477, पंजाब 43, तेलंगाना 1553, उत्तराखण्ड 628 करोड़ रुपये। हम अभी इस कैटेगरी में नहीं आये हैं।

दूसरा, जो वेज एण्ड मींस का होता है, उसमें भी 10 स्टेट आ चुके हैं, जहां तनख्वाह देने के लाले पड़ेंगे। वे हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, नगालैण्ड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखण्ड और 4 राज्य आ गये ओवरड्राफ्ट के अंदर, वे हैं इनका आपका खुद का बीजेपी का राज्य है हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल और पंजाब, यह स्थिति है। इस तरीके से राजस्थान अभी तक बचा हुआ है क्योंकि हमारा शानदार मैनेजमेंट है।

आप कहते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, केन्द्र सरकार तो मान रही है कि हम पैसा दे नहीं पा रहे हैं इसलिये उन्होंने हमें अभी छूट दी है। सब राज्यों की दी है छूट उन्होंने, आपको मालूम होना चाहिये कि जो पैसा मिलता

(श्री अशोक गहलोत)

है राज्यों को, लिमिट होती है कि कितना पैसा कौन राज्य कर्ज ले सकता है और उस लिमिट से कोई राज्य बाहर नहीं जा सकता। हमने रिक्वैस्ट की, हमारी रिक्वैस्ट को टर्न डाउन कर दिया। अब जब वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं, उन्होंने हमें छूट दी है, 3235 करोड़ रुपये की छूट दी है। यूपी को दी है, 10570 करोड़ रुपये की छूट दी है। बिहार को छूट दी है 5688 करोड़ रुपये की, यह पूरी लिस्ट मेरे पास में है। यह छूट क्यों मिली है? इससे आप समझ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े बताना दूसरी बात है, वे तो लिखे हुए हैं, उसमें नई बात क्या कह रहे हो, जो परसेंटेज आपके वक्त थी, वह कम हुई, ज्यादा हुई, आपके सामने है वो, उसमें कहने की क्या बात है? इसलिये मैं कहना चाहूंगा आपको उन आंकड़ों के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं। आंकड़े हैं, मैंने पढ़े, आपने पढ़े, दुनिया ने पढ़े होंगे, इंटरनेट पर आते हैं आजकल तो, बुक्स में लिखे हुए हैं, उसी से बजट पेश होता है आपका और उसी से इकोनोमिक सर्वे पेश होता है। सब लिखे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच-छह-सात महीने के अंदर आपने कई गिनाये कि शिक्षा विभाग में स्कूलें बंद हो गयी हैं, पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं खोले हैं। आप तो सरकार में लम्बे समय तक रहे हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं। स्टेडियम का कहा, मालूम पड़ गया आपको कि स्टेडियम के टेण्डर तक हो गये। स्कूलें बंद की आपने, हमने खोलना प्रारम्भ कर दीं। इनके आंकड़े मैं आपको गिनाने लगूं तो बहुत टाइम लग जायेगा आपके। आपका यह कहना कि प्राथमिक शिक्षा, 495 नई स्कूलें हमने पुन: शुरू कर दी हैं। माध्यमिक की 474 स्कूलें वापस शुरू कर दीं, आपने बंद कर दीं थी गत बार। आपने तो हमारी घोषणा थी 65 विद्यालयों की 2013-14 के अंदर, सरकार आपकी आयी, कोई स्कूल नहीं खोला आपने तो। क्रमोन्नत की स्कूल उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 379, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक 286, बजट 643 करोड़ रुपये। आप कैसे कह सकते हैं? आंकड़े तो सबके सामने हैं। कोई नई बात नहीं है।

माननीय हमारे राजेन्द्र राठौड़ साहब, आप जरा गौर फरमाओ। आपने कहा कि राज्य सरकार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद गत वर्ष में 1315 करोड़ रुपये कम हुआ। बता दिया आपने। अब मुझे बताइये ये टैक्नीकल बातें हैं, फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, 10,20,989 करोड़ रुपये का आकलन किया

(श्री अशोक गहलोत)

उन्होंने, वर्ष 2019-20 में जीएडीपी का 10,24,304 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया। चौथे वित्त आयोग ने किया था, फाइनैंस कमीशन ने किया था। फाइनैंस कमीशन का जो प्रोजेक्शन होता है और जो एक्चुअल होता है उसमें फर्क आता ही आता है। आपके वक्त में भी आता था, उसमें नयी बात नहीं है। हमने कोई नयी बात नहीं की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौथे वर्ष तक चलता है यह, चौथे वर्ष तक चलता है, चार वर्ष तक चलता है। चौथे वर्ष में शामिल होता है, इसमें मिनिस्ट्री आफ स्टेटिस्टिक्स भारत सरकार एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं मोस्पी, और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर आंकड़े फाइनल करते हैं जिसमें चार साल लगते हैं। आपने हमें पहले ही दोष देना शुरू कर दिया। यह आपके सामने आंकड़े हैं। आपके चालीस वर्ष में पहला मौका है जब योजना के अंतर्गत व्यय पिछले वर्ष से कम है, 6735 करोड़ रुपये की आपने योजना घटा दी, हमने कोई बात छिपायी है क्या? आपको मालूम है कि प्लान बजट बनता है, वह कभी हमने कम नहीं किया, हमने इस बार भी बढ़ाया है। यह आपने गलत कहा है कि पहली बार आंकड़े कम हुए हैं। उदय योजना, जो आपके वक्त बनी थी, उसमें अमाउण्ट होता है 14000 करोड़ रुपये से अधिक का, वह जोड़ा गया था पिछली बार, किश्तें दी गयीं लगातार। इस बार किश्तें जब देनी समाप्त हो गयीं तो प्लान के अंदर वह कैसे आयेगा? तो आज भी 8186 करोड़ रुपये का बजट ज्यादा पेश किया गया है। यह उदय योजना का प्रताप है जिसके कारण आपको यह बात कहनी पड़ी, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(18.00 बजे)

इसी प्रकार रिफाइनरी की बात आपने भी कही और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कही। मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं कि इसका जवाब तो आपकी तरफ से आज तक नहीं मिला कि 26 परसेंट में भागीदारी क्यों रखी आपने पांच साल के बाद? आज तक जवाब नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि अगली बार कभी मौका आये तो आप हमें, सदन और प्रदेश को जवाब दें। आपने इश्यु यह बनाया गया कि 26 परसेंट में भागीदारी क्यों रखी गयी है। सब कुछ हमारा था। कोई प्राइवेट कम्पनी थी क्या? भारत सरकार की कम्पनी थी एचपीसीएल। सरकार से सरकार का मामला था। भागीदारी कम-ज्यादा क्या होती है? स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सब्सिडरी कम्पनी है एसबीआई कैपिटल। जो उन्होंने कहा था, उसके आधार पर वह भागीदारी रखी गयी। क्या उसे हम

(श्री अशोक गहलोत)

गलत मानेंगे? यह तो क्रेडिबल सोसायटी है, कम्पनी है, सब्सिडरी है तो इस प्रकार से आपने पूरी जनता को गुमराह किया।

अब अचानक आपको लगता है कि चूंकि रिफाइनरी का काम चल रहा है। 20 हजार करोड़ रुपये के कामों की स्वीकृति जारी हो रही है। 10 हजार करोड़ रुपये के काम दे दिये गये हैं और ढाई हजार करोड़ रुपये के कामों पर पैसा खर्च हो चुका है। आपको यह तकलीफ हो रही है कि कहीं यह रिफाइनरी टाइम पर न बन जाए। आप यह दुआ करें कि हम सब लोग मिलकर यह रिफाइनरी टाइम पर बनाएं। यह सिर्फ हमारा काम नहीं है। हम सबका काम है। यह केन्द्र सरकार का काम है। एचपीसीएल कम्पनी उनकी है। 25 एमपी जिताये आप लोगों को जनता ने। क्या आपके 25 मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट कभी राजस्थान की पैरवी करते हैं वहां पर? कभी रेलवे की बात करते हैं कि पहले वाले प्रोजेक्ट्स क्यों बंद कर दिये? रिफाइनरी का काम जल्दी पूरा होना चाहिए, कभी बात करते हैं वे लोग?

ईस्टर्न कैनाल की जो 13 जिलों की योजना बनी, वह आपके वक्त में बनी। मुझे खुशी है इस बात की, मैं चाहूंगा जैसे हम लोगों ने रिफाइनरी को लेकर संघर्ष करने में प्रायोरिटी दी थी, आप क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? आप विपक्ष में हो। हम जब विपक्ष में थे, हमने रिफाइनरी का पीछा नहीं छोड़ा। हर चीज का मुद्दा उठाया हमने। रेलवे का भी उठाया हमने। आप क्यों नहीं उठा रहे हैं इस मामले को, क्योंकि सरकार आपकी है। कहीं आपके नम्बर नहीं कट जाएं, चिंता आपको यह है। चिंता आपको यह है। मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके, 13 जिलों के भविष्य का सवाल है, कम से कम आप आगे आएं, हम सब मिलकर जाएं।

प्रधान मंत्री जी जब जयपुर आये थे और बाद में अजमेर आये थे, उन्होंने दो घोषणाएं की थीं कि इसे मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया था। क्या आपका फर्ज नहीं बनता रिक्वैस्ट का? सरकार आपकी है वहां पर। हम सब मिलकर एक प्रयास करें। प्रधान मंत्री जी को कन्विन्स करें। हमारे जोधपुर से आने वाले माननीय लोक सभा सदस्य, जो वहां केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, विभाग उन्हीं का है। वे भी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे कामन मामले, जहां हम चाहेंगे कि राजस्थान का भला हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों या पानी की बड़ी योजना हो, इनमें क्यों नहीं हम मिलकर वहां दबाव दें। इस पर आप लोग चुप रहेंगे। इस पर आप लोग बात नहीं करेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

बजरी की बात आयी। किरण माहेश्वरी जी ने बात की, बाबूलाल नागर जी ने कहा और राठौड़ साहब तो चैम्पियन हैं ही। मैं पूछना चाहता हूं राठौड़ साहब आपसे, आप तो बहुत ही करीब थे मुख्य मंत्री जी के, यह बंद कैसे हुई बजरी? यह जंजाल पैदा क्यों हुआ? मैं स्वीकार कर रहा हूं, एक साल में अगर मैं किसी बात से दु:खी हुआ होऊंगा, आज भी दु:खी हूं, वह बजरी को लेकर हूं, क्योंकि जनता लुट रही है। 25 हजार का ट्रक 60-70 हजार में मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लम्बी कहानी है और 5 करोड़ रुपये प्रतिमाह बजरी माफिया किसे दे रहे थे, यह असली जांच का विषय है। प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये कहां जा रहे थे, यह बताएं मुझे आप। आप हमसे पूछते हैं कि बजरी का क्या कर दिया आपने। बजरी क्यों नहीं आ रही है?

आपने तो शान्ति मार्च को भी नहीं छोड़ा। मैं तो आपसे अपील करना चाहूंगा, दिल्ली में जिस रूप में आग लगी हुई है, पूरे देश के राज्यों में आग लगी हुई है, 15 लोग कल यूपी में मर गये, 28 लोग दिल्ली में मर गये। पता नहीं यह मुल्क किस दिशा में जाएगा? किस रूप में हालात बना रखे हैं मुल्क के, वह तो मैं समझता हूं कि सबके लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए। हम सब इंसान हैं। एक इंसान का मरना क्या होता है। पुलिस का हमारा एक हैड कांन्स्टेबल मर गया फतेहपुर का तो क्या बीती राजस्थानवासियों पर। चाहे हिन्दू हों, चाहे मुस्लिम हों, कितने लोग मारे जा रहे हैं।

गृह युद्ध कैसे शुरू हुआ? चुनाव में किस प्रकार से नारे लगाये गये थे- 'गोली मारो गद्दारों को', करंट जाएगा शाहीन बाग़ तक। पूरी तरह चुनाव का ध्रुवीकरण किया। पूरा फालआउट है। राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं अमेरिका के। कभी आज तक हुआ है इतिहास में, राष्ट्राध्यक्षों के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं जब देखते हैं कि वहां आग लगी हुई है तो। आये भी, गये भी, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, फायरिंग हो गयी। जहां रुके थे, वहां से 20 किलोमीटर पर फायरिंग चल रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति आ गये और चले गये और आज देश में आगजनी से पूरा मुल्क चिंतित है। किस प्रकार से ये दंगे रुकेंगे, किस प्रकार से जो एनआरसी, सीएए और एनपीआर इश्यु बन गये हैं देश में, उसके ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए हम लोगों को? आज शान्ति मार्च की आप आलोचना करते हैं? कमाल कर दिया। एक तो हमने उदाहरण पेश किया देश में कि

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान में 4-5 लाख लोग निकलकर शान्ति मार्च कर सकते हैं। जहां सरकारें आपकी पार्टी की हैं, वहां आगजनी हो रही है, फायरिंग हो रही है और यहां शान्ति मार्च निकल रहा है तो इसको आपको फ्लोर पर एप्रीशिएट नहीं करना चाहिए था?

आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया, मान लेते हैं, पर आपने तो पूरे देश का इंटरनेट बंद कर रखा है। (व्यवधान) मालूम है आपको, पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में इंटरनेट बंद रहता है। यह एक फीगर है। सोशल मीडिया का आप लोग जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, आपके नेताओं ने हजारों लोग बैठा रखे हैं पूरे देश में और जैसे ही कोई कमेंट आयेगा हमारा, टूट पड़ेंगे सब लोग। धन बल का खेल चल रहा है। चलने दें। टाइम आएगा तो मालूम पड़ जाएगा आप सबको। तीन दिन तक गृह मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी मौन। आग लग रही है, जल रहे हैं लोग, मर रहे हैं, घायल हुए जा रहे हैं। (व्यवधान) देश के अन्दर लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है और जैसे ही हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कल प्रेस कान्फ्रेंस की, दस मिनट में प्रधान मंत्री जी का ट्वीट आ गया, शान्ति बनाये रखें। आप तीन दिन तक कहां छिपे थे? क्या हो गया था आपको, बताएंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ तो धैर्य रखिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले हमारे माननीय विधायक श्री रामलाल शर्मा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैट्रो को चलाने की घोषणा की थी, सचिवालय तक मैट्रो चला दें। सचिवालय नहीं, हमारा फर्स्ट फेज भी, आप लोगों ने तो कसर छोड़ी नहीं काम धीमा करने की, कभी का वह पूरा हो जाता, आप लोग उसका उद्घाटन करते, हमें खुशी होती। पांच साल निकाल दिये, अब जाकर वह करीब-करीब पूरा हुआ है, जो फर्स्ट फेज का 'बी' भाग है वह।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, आपको तो लग रहा होगा कि हमने खाली कह दिया, पांच साल के राज में क्यों नहीं नाम लिया उसका? आपकी सरकार ने क्यों नहीं सैकण्ड फेज का काम शुरू किया सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक? क्यों नहीं शुरू किया अम्बाबाड़ी तक? कभी जुबान पर आयी बात आपकी? आपने मुख्य मंत्री को समझाया कभी कि द्रव्यवती नदी, क्या नाम रखा है

(श्री अशोक गहलोत)

उसका। अभी तक वह जी का जंजाल बनी हुई है राजस्थान में जयपुरवासियों के लिए आपकी यह नदी। मैं पूछना चाहूंगा कि मैट्रो का क्या हुआ, क्यों नहीं किया? हम फिर भी कहना चाहेंगे आपसे, हमने डीपीआर बनवायी है उसकी दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन से, जिससे पहले वाला, फर्स्ट फेज भी उसी ने पूरा किया था और हम चाहेंगे आप सबकी दुआओं से और सहयोग करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। हमारे साथ दिल्ली में चलोगे तो हम और भी खुश होंगे। तय आपको करना है कि चलना है या नहीं चलना है। चलने के क्या फायदे हैं, नहीं चलने के क्या फायदे हैं, नफा-नुकसान तो आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके देखें आप कि इस मैट्रो के लिए हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसका काम शुरू करें और मेरा सपना रहेगा, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि मैट्रो, सचिवालय का तो आपने सरकास्टिक-वे में कह दिया रामलाल शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि वह आपके चौमूं तक जाए। एक तरफ चाकसू, एक तरफ बस्सी, एक तरफ बगरू, एक तरफ गोविन्दगढ़-चौमूं, एक तरफ मनोहरपुर-शाहपुरा। चारों ओर जाए। यह जयपुर बड़ा मैट्रोसिटी बन गया है और हम लोग तो अगले 25 साल की कल्पना करने वाले हैं, आपकी तरह नहीं हैं कि सरकार बदली और सब प्रोजेक्ट के स्टाप लगा दिये, वे लोग हम नहीं हैं। हम तो अगर आपकी योजना कोई अच्छी लगती है तो आपकी योजनाएं भी हम बन्द नहीं करने वाले और अगर आप चाहोगे तो भी हम बन्द नहीं करेंगे, हम चालू रखेंगे।

13 जिलों वाला मामला बहुत इम्पोर्टेंट है पर जब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी वह सम्भव नहीं होगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करीब 38 हजार करोड़ का है और फिर और बढ़ जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप उसके अन्दर भागीदारी निभाएं। नेता, प्रतिपक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपकी भूमिका बड़ी हो सकती है। पर आप बार-बार कहते हो कि मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, कृपा करके यह मत कहो आप। आप इतने अच्छे इन्सान हैं, भावुक आदमी हैं पर कैमरा सामने आते ही पता नहीं आपको क्या हो जाता है। बाकी आप बहुत भावुक हैं, व्यक्तिशः मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं पर कैमरा आया नहीं और भड़क जाते हैं। पर मुझे कभी-कभी आशंका होती है जब आप बार-बार कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, मुझे लगता है कि कहीं आपको हाईकमान का कोई इशारा तो नहीं है क्योंकि शेखावत साहब

(श्री अशोक गहलोत)

जब यहां पर आपकी तरह थे तो वे उप राष्ट्रपति बन गये थे तो कहीं आपका इशारा हिज-एक्सीलेंसी बनने का या कुछ हो क्योंकि वैसे ही आप और कैलाश मेघवाल जी 75 के तो हो गये हो। इसलिए हो सकता है कि आपको इशारा हो वर्ना एक धमकी कोई नेता, प्रतिपक्ष कहे कि अगर यह गलत सिद्ध हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, छोड़कर चला जाऊंगा। बार-बार यह कोई कहता नहीं है। ऐसा कोई आपने गलत काम किया भी नहीं कि आप इस्तीफा देने की बात करो। आप तो खाली फीगर बता रहे हो और फीगर गलत कैसे हो सकते हैं। फीगर हमारी सरकार के हैं और इस्तीफा आप दे रहे हो, कमाल है। हमारी सरकार के आप फीगर बता रहे हो कि ये फीगर हैं और मैं गलत हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। फीगर तो हमारी सरकार के हैं इसका मतलब हमारी सरकार के फीगर इतने क्रेडिबल हैं यह मानना चाहिए, इतने विश्वसनीय फीगर हैं।

गुटखों पर प्रतिबन्ध की बात चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने की है। यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और इसकी घोषणा हुई थी पर जिस रूप में इसकी तैयारी होनी चाहिए उसमें कुछ कमी भी है, हम तैयारी करने लग गये हैं। बजट में मैंने कहा है कि मिलावट की आप लोगों ने चिन्ता की थी, मिलावट अपने आपमें बहुत बड़ी बीमारी है और मिलावटखोरों का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा हम लोगों को। हम चाहेंगे, इसलिए हर जिले के अन्दर लैबोरेट्री बने, अलग टीमें बनें। हमने कहा है कि सीएस लेवल पर हम कमेटी बनाएंगे। हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से इस काम को बड़े रूप में लाएं और गुटखा ही नहीं, पहले हमने ही बन्द किया, आपकी सरकार ने बन्द नहीं किया था। जो पान मसाला गुटखा था, जिसमें जर्दा होता था, तम्बाकू होती थी, वह हमारी सरकार ने ही बन्द किया था। हम चाहेंगे कि जो सादा गुटखा भी है उसके अन्दर भी जो कैमिकल्स होते हैं वे नुकसानदेह होते हैं। सब जगह लैबोरेट्री बनाकर सभी तरह की चीजों को, जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनका हम लोग इंतजाम करेंगे।

हमारे माननीय सदस्य, मदन दिलावर जी रामगंज मण्डी वालों ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। हमें बड़ी हंसी आती है जब यह कोई कहते हैं आप जैसे आदमी। आपकी पैदाइश, आपकी पार्टी की पैदाइश है वह आरक्षण के खिलाफ की सोच से हुई है, यह शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपकी उम्र कम होगी। जब जनसंघ बना था तब से भी और आरएसएस के हिसाब से भी, जब गोलवलकर साहब आपके हैड थे तब से उन्होंने आरक्षण का

(श्री अशोक गहलोत)

विरोध करना शुरू किया तो यह कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस का जन्म तो इन बातों से ही हुआ है। संविधान बनाने का सोच क्या था? शानदार जो संविधान बना अम्बेडकर साहब के वक्त में, पंडित नेहरू के वक्त में, मौलाना आजाद के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, गांधी जी के सान्निध्य में, वह ऐसे ही बन गया? उसमें साफ लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं और आपने आरोप लगा दिया कांग्रेस पर कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। मेरी सरकार 20 साल पहले बनी थी आप सबके आशीर्वाद से, तब हमने पहली बार 14 परसेंट आरक्षण का कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। उनको हमने रिक्वैस्ट की कि आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दें। समय आ गया है कि उनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमने कैबिनेट में 14 परसेंट का प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद में कमीशन बनते गये, वाजपेयी जी ने बनाया, फिर मनमोहन सिंह जी ने बनाया। अब जाकर जो 10 परसेंट लागू हुआ, उस बात की हमें खुशी है कि जो सपना हमने देखा था वह सपना अब पूरा हुआ है। राजस्थान के अन्दर जो प्रोब्लम आ रही थी वह पूरे देश के अन्दर प्रोब्लम थी। जो इसमें किन्तु-परन्तु है उसके कारण से सर्टिफिकेट मिल नहीं पाते हैं तो हमने तमाम तरह के हर्डल्स को खतम करके खाली 8 लाख की आय का जरिया रखा है। मैं अब आपसे मांग करना चाहूंगा, आपसे सहयोग लेना चाहूंगा कि क्यों नहीं हम सब मिलकर आर्थिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए केन्द्र सरकार से बात करें कि वे भी केन्द्र सरकार की नौकरियों के अन्दर, जैसे राजस्थान सरकार ने किया वही फार्मूला वहां एडॉप्ट करे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।

हमारे पदमाराम जी चौहटन, रामलाल जी चौमूं तो बार-बार सामने आ ही रहे हैं, रामलाल जी मीणा प्रतापगढ़, संजय शर्मा जी, बृजेन्द्र ओला जी, आप ठीक कह रहे थे कि आवारा पशुओं की प्रोब्लम बहुत बड़ी प्रोब्लम है। आप ठीक कह रहे थे कि नन्दीशाला का हमने एनाउंस किया था, छह महीने में नन्दीशाला बन नहीं सकती और यह काम बड़ा काम भी है। यह कोई पोलिटिकल पार्टी तो बना नहीं सकती और सरकार भी सहयोग कर सकती है तो हम चाहते हैं कि एनजीओ के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से, सबके सहयोग से एक सोच हमने रखी है।

(श्री अशोक गहलोत)

आपने कई बातें मुझे गिना दीं, मैं आपकी बात को मानता हूं, सब काम एक साथ नहीं हो सकते। डीपीआर भी बनती है, असेसमेंट भी होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आती है और काम शुरू होता है। जब दवाइयों की योजना मैंने शुरू की थी जिसकी आप तारीफ करते हो, डेढ़-दो साल लगे और उसका खामियाजा हमने क्या भुगता कि जब चुनाव आ गये तब तक योजना शानदार तरीके से लागू हो गई। और योजना लैपटाप की भी और अन्य योजनाएं भी साथ में आ गईं तो आप लोगों के नेताओं ने कहा कि रेवड़ियां बंट रही हैं चुनाव जीतने के लिए। आपने भी चुनाव से पहले किसानों के बिल में 10 हजार की सब्सिडी की घोषणा कर दी बिना किसी प्रोविजन के। आप मुझे प्रोविजन की बात बता रहे हो कि आपके प्रोविजन नहीं। प्रोविजन नहीं है तो आपकी अभी सरकार गई है, 12 हजार करोड़ का हमारे ऊपर भार छोड़कर गई है और अभी तक हम ठेकेदारों के बिल नहीं चुका पा रहे हैं तो प्रोविजन कहां था आपके पास में? कैसे कर दिया अनाउंसमेंट सड़कों का? आप मुझे यह बताइये कि बिना प्रोविजन के उस वक्त में जो फैसले किये गये उसके नतीजे आज तक सब भुगत रहे हैं और आप हमें कह रहे थे।

हमने कम से कम, गायों के लिए राजस्थान देश में पहला राज्य था मेरे वक्त में पिछली बार कि हमने गायों के लिए, गौशालाओं के लिए निदेशालय बनाया, वह पहली बार हमने बनाया। आपने उसका नाम बदलकर खाली विभाग लिख दिया, यही काम किया। हमारे आते ही हमने गौशालाओं का अनुदान दुगुना कर दिया है। कांफ्रेंस की गौशालाओं के तमाम प्रबन्धकों की और आगे भी हम चाहेंगे कि गाय पर कोई राजनीति नहीं हो बल्कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि आपके वक्त में आप देख रहे थे कि हिंगोनिया के अन्दर किस प्रकार से गायें मर रही थीं। गायें हजारों की तादाद के अन्दर मर रही थीं और राजस्थान इस बात को भूला नहीं है अभी, पर उसका दोष भी आप हमें दे रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उदयपुर के विधायक भी हैं। आपने पिछली बार कई मुद्दे उठाये थे। यह आपने ठीक कहा, हम लोग उनके जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि, एकदम जवाब देना संभव नहीं होता है किसी के लिए भी। पर, इतना मैं कह सकता हूं कि आपका हम सम्मान करते हैं क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करना, आपकी पार्टी का ही नहीं है, हम सबका

(श्री अशोक गहलोत)

फर्ज बनता है। हम लोग उसी पर चलते हैं, आपकी तरह नहीं चलते हैं कि आप जब चाहो कह दो, मैं तो छोड़कर चला जाऊंगा, हम नहीं जाने वाले। हम तो यहीं रहने वाले हैं।

आपने भिक्षावृत्ति का बहुत ढिंढोरा पीटा, कुछ नहीं होगा। आप बताइए, आपने तो एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए उस वक्त में। मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट जारी किया जा चुका है। जो एक्ट 2012 का था, वह भी हमारे वक्त का ही एक्ट था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भिक्षावृत्ति की समस्या सबके लिए नासूर की तरह होती है। गरीब आदमी भीख मांगता है, उसके ऊपर क्या बीतती है। क्या सुबह शाम खाता होगा। मैं नेता, प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा, आपने हमें कह दिया कि आपने कुछ नहीं किया। जयपुर के लिए हमने क्या किया, वह आपको अभी बताता हूं। हम लोगों ने 15 लाख रुपये का बजट रखा है। पुनर्वास गृह मार्च तक प्रारम्भ कर दिये जाएंगे। सब तैयारी हमने कर ली है।

मैं यह पूछना चाहता हूं आप लोगों से आप 5 साल तक सत्ता में रहे, एक्ट हमारे वक्त का बना हुआ था। एक्ट बनता है तो सभी के लिए बनता है, प्रदेशवासियों के लिए, आपने कभी चर्चा भी की कैबिनेट के अंदर? आपने कभी सोचा भी था इसको रखना चाहिए? भिक्षावृत्ति की चिंता की आपने उस वक्त में? पिछली बार आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त खड़े होकर कह दिया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। बिलकुल ठीक कहा आपने, कुछ नहीं हो रहा। 6-7 महीने का बजट, 7 महीने पहले रखा गया था, टाइम लगता है। हम लोग लगे हुए हैं इस काम में।

उदयपुर ट्रैफिक समस्या, यह कोई नई बात है क्या? चाहे यूआईटी हो, जेडीए हो या नगर निगम हो, सबकी स्कीमें को मिलाकर बजट में बात की जाती है। कोई छिपाने वाली बात तो नहीं होती है। आपने कहा एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। अब बताओ जुलाई में हम लोगों ने अनाउंस किया, मान लीजिए और तीन-चार महीने के अंदर डीपीआर**,** कंसल्टेंट नियुक्त हो गया, नवम्बर के अंदर और 49 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई वहां पर सड़क, पार्किंग कार्य के लिए। अब आप कहोगे वह तो यूआईटी, नगर निगम कर रही है। यह नहीं होता है। बजट बनता है चाहे कोई सरकार बनाओ, हमारे नीचे से काम हो रहे हैं आम तौर पर, आपने कहा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, 19 करोड़ 84 लाख के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। ये कार्य

(श्री अशोक गहलोत)

भले ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में चिह्नित, चिह्नित आपके वक्त में किये गये काम, हमारे वक्त में काम आगे बढ़ रहे हैं। इन-हाउस डीपीआर बनाना, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करना, निविदा लगाकर कार्य प्रारम्भ करना, समस्त कार्यवाही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई है। आपने सोचा होगा, आइडिया दिया होगा, आपका क्षेत्र है वह। इसके अलावा वहां पर जो आपकी ट्रैफिक कमेटी बनी हुई है। उसके अंतर्गत अभी 30 तारीख को मीटिंग हुई थी, दिसम्बर के अन्दर, करीब दो महीने पहले उसमें 65 करोड़ के काम हाथ में लेने का निर्णय लिया गया। देहली गेट से कोर्ट चौराहा, अश्लीन बाग़ की तरफ 25 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर, कुम्हारों के भट्टे पर सूरजपोल से बीएन कालेज तक 20 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और 20 करोड़ की लागत से सेवाश्रम चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ये कार्य पूरे होने की संभावित तिथि 31 दिसम्बर, 2021 रखी गई है। वैसे ये तो आपको मालूम ही होगा। मैं तो बता रहा हूं आपको क्योंकि आपने पूरे सदन को कह दिया हम कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं, खाली घोषणा करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है।

आपने कहा कोचिंग सेन्टर शुरू नहीं हो रहे हैं। वह भी गलत कहा। जुलाई में घोषणा की हमने, 6 महीने हुए, टीआरआई का वहां केन्द्र संचालित हो रहा है। पहले-पहले 25 छात्र-छात्राएं वहां पर लाभान्वित हो रहे हैं और आपने कहा कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्डिंग तो बन नहीं सकती है 6 महीने के अंदर। टीआरआई का केन्द्र शुरू हो गया और सागवाड़ा में आरकेसीएल के साथ एमओयू हो गया है और मार्च, 2020 से पहले पखवाड़ा शुरू हो जाएगा।

पशु चिकित्सा उप केन्द्र के बारे में आपने कहा, उस दिन भी बोले थे, आज फिर आपने वह रिपीट किया। 226 स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गये, लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया। सत्य इससे अलग है। 400 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की हमने घोषणा की थी और सितम्बर तक हमने पदों का सृजन करते हुए, उप केन्द्र खोलने की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए बजट का प्रावधान किया है। ऐसे ही होता है, टाइम लगता है उसके अन्दर।

इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बार-बार उठता है, प्रधान मंत्री जी बार-बार, जो किसान सम्मान निधि एनाउंस की गई थी। उस वक्त पार्लियामेंट्री चुनाव आ गये थे, तो आपकी गलती नहीं, जो आपके

(श्री अशोक गहलोत)

नेता प्रधान मंत्री खुद ही दोष देते फिर रहे थे देश भर के अंदर कि राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्य को-आपरेट नहीं कर रहे हैं जबकि सबसे अच्छे ढंग से अगर कोई सर्वे किया, उस जमाने के अंदर जिससे कि बाद में घोटाले सामने नहीं आएं। यूपी और गुजरात में घोटाला आया बाद में सामने। ये आपके वक्त में को-आपरेटिव के लोन बांटें तो डूंगरपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर घोटाले सामने आये थे। बेनीफिशियरी वह है जो कि मर गये हैं या विदेश में काम कर रहे हैं। बाद में हमारे वक्त में उनकी जांच शुरू हुई। उसी प्रकार से प्रधान मंत्री ने खुद ने कहा, को-आपरेट नहीं कर रहे हैं। कौन सरकार होगी, उनके किसानों का पैसा, चाहे केन्द्र दे या राज्य दे, हम चाहेंगे क्या, एक नया पैसा भी हम छोड़े वहां से, पर उस वक्त कैम्पेन चलाई हमारे खिलाफ, जबकि मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। किस प्रकार से शानदार तरीके से आज 67 लाख से ज्यादा किसानों के आवेदन प्राप्त हुए थे और 64 लाख 54 हजार 746 कृषकों के आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। सबने अच्छे से कर दिया, कोई करप्शन की शिकायत नहीं है और बाकी जो कुछ तकनीकी खामियों से उनको रोका गया, जिससे कि उनको चैक करके वापस आगे उसको बढाएंगे और अब तो नवम्बर, 2019 से आधार कम्पल्सरी कर दिया गया है। उसमें नाम का फर्क आता है, जब नाम का कार्ड बना आधार का, उसमें अब एप्लाई करता है किसान तो जो पीएम किसान पोर्टल खुद ही रोक देता है उसको, वो प्रोब्लम आएगी। हम प्रधान मंत्री को लिखेंगे, इसका कोई हल निकलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की योजना हर घर में जल पहुंचे, अच्छी योजना है। हम चाहेंगे इसमें आप हम सबका सहयोग करें। मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं, आपके खास मित्र भी हैं। आपके तो खास मित्र हैं तो कृपा करके आप उनको कहिएगा कि आप जो हैं 50:50 की हिस्सेदारी से काम नहीं चलेगा, कई साल लग जाएंगे। जब यूपीए गवर्नमेंट थी 90:10 का रेशो था, 90 परसेंट केन्द्र सरकार, 10 परसेंट राज्य सरकार देती थी। अब बताइये उसके बाद में पहले 60:40 किया गया, अब 50:50 कर दिया गया! इतना बड़ा खर्चा कोई राज्य उठा सकता है? वो भी राजस्थान जहां पर रेगिस्तानी इलाका है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कोस्ट आफ डिलीवरी बहुत ज्यादा लगती है एक गांव से दूसरे गांव तक सर्विस पहुंचाने में, क्योंकि यहां दूरियां बहुत हैं गांव-गांव के बीच में। यूपी की तरह नहीं है। ढाणियों में लोग रहते हैं। मैंने

(श्री अशोक गहलोत)

आपके मंत्री जी को पत्र लिखा भी है। मैं चाहूंगा कि आप सब सहयोग करें। राजस्थान में रेशो वापस, रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से, जैसे ये पहाड़ी इलाकों को दे रहे हैं, नोर्थ-ईस्ट को दे रहे हैं, उसी ढंग से हमें हिस्सा मिलेगा। तब जाकर इस काम को और तेज गति से हम आगे बढ़ा पाएंगे। ये मैं आपसे सहयोग चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गर्मी आ रही है। हमने अभी कंटिंजेंसी प्लान की योजना शुरू कर दी है और 421 वाहन ले लिए हैं, 2500 संविदाकर्मी स्वीकृत किये गये हैं। प्लान बन गया है। टैंकर्स के लिए प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 41 करोड़ ग्रामीण के लिए, 24 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र के लिए। 50 लाख की हमने छूट दे दी। एडिशनल चीफ इंजीनियर को अधिकृत किया है कि पानी में तकलीफ नहीं पाएं लोग। ये हमारी कोशिश रहेगी आप सबके सहयोग से।

नीरोगी राजस्थान, मैं उम्मीद करता था कि कम से कम नेता, प्रतिपक्ष इसकी तारीफ करेंगे, पर आप तो हर चीज को तौल रहे हैं। मेजें क्यों थपथपाई, आपने मेजों पर ही बड़ी दया दिखाई। लास्ट टाइम तो आपने रिप्लाई के अंदर, बापड़ी मेजें हैं। क्या ठाट हैं आपके बोलने के। मेजें थपथपाना तो एक मैसेज है, आपके लिए भी मेजें थपथपा रहे थे सब लोग क्योंकि आपने तो अशोक लाहोटी जी की जो क्लास ली है उसका सब लोगों को जोश आया होगा कि हमारी क्लास नहीं ले लो कहीं आप। आप तो नेता हो इसलिए आज ज्यादा ही जोश था लोगों के अंदर आपकी बातों का पहले के मुकाबले।

मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमने यह हिम्मत इसलिए की है, पहले मेडिकल दवाइयों की संख्या बढ़ाई हमने आते ही, आप लोग नहीं बढ़ा पाए। हमने टैस्ट फ्री कर दिए, उनकी संख्या और बढ़ा दी है। उसको और फैलाया है हम लोगों ने। 950 पीजी सीटें आ गई हैं राजस्थान में, 11 सुपर स्पेशलिटी की और 650 एमबीबीएस सीटें आना मायने रखता है। यह खाली आपके वक्त से नहीं आ रही है, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त से आ रही है और 30 मेडिकल कालेज खुलना मायने रखता है और प्रतापगढ़, राजसमंद, जालौर के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आपका उसमें सहयोग चाहिए हम लोगों को और इसीलिए हमने हिम्मत की है कि हम लोग इसमें थ्रस्ट एरिया बनाएं और घर-घर के अंदर यह मैसेज देवें कि कैसे लाइफ स्टाइल चेंज करने से या जो-जो

(श्री अशोक गहलोत)

मैंने आपको पिछली बार पूरा बताया था कि कैसे हमारी योजनाएं हैं, अभी मैं उनके अंदर नहीं जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस काम को हम सबके सहयोग से पूरा करें, जिससे कि आने वाले वक्त में हम लोग इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को दे सकें। जहां तक आपने कहा कि भामाशाह कार्ड, भामाशाह कार्ड अगर बदल भी गया है तो भी लोग उत्साह से उसके ऊपर आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, भामाशाह कार्ड का और कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरा, आपने जो कहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके आधार पर चल रहा था भामाशाह कार्ड। आपको यह जानकर खुशी होगी सदन को कि हम लोगों ने, जो अभी आयुष्मान भारत योजना थी भारत सरकार की, सरकार आपकी थी उस वक्त में भी पर आपने मना कर दिया उनको कि हम आपकी योजना स्वीकार नहीं करेंगे 5 लाख वाली। आपने 3 लाख वाली योजना चालू रखी। भयंकर जमकर करप्शन हुए। एकएक अस्पताल में हजार आपरेशन किसी चीज का हुआ है राजस्थान में तो एक अस्पताल में 900 हो गए, ऐसे-ऐसे केसेज भी सामने आये थे। हमने उस योजना को बंद नहीं किया है, हमने उसको आयुष्मान भारत को मिला दिया है भारत सरकार से बात करके, उससे हमारी संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वह भार आप ही उठाओगे तो हमने कहा कि हम मंजूर करते हैं तो आपके जो भामाशाह कार्ड की संख्या थी, वह होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर, एनएफएसए और भारत सरकार की योजना है वह होती है स्टेट इकोनोमिक कास्ट सैंसस एसईसीसी। अब चक्कर यह आ रहा है कि भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें संख्या बढ़ नहीं सकती है और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला है उसमें संख्या बढ़ सकती है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखा है प्रधान मंत्री जी को कि आप इस पर ध्यान दें जिससे कि अभी कई जो छूट गए हैं वह आयुष्मान भारत में भी नहीं आ पाएंगे और पहले उसमें थे ही नहीं, उनको जोड़ने की तजवीज होनी चाहिए। इसमें हम लोग लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग उसमें कामयाब होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग की मैंने बात की थी घोषणा करने की, वह हम लोग जल्दी ही करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बड़ा फैसला हमने किया है अभी कृषकों को दो ब्लाक में बिजली देने का, उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

जल्दी ही और हमारी कोशिश है कि जो छीजत है, जो पूर्व सरकार के वक्त में इनको लानी थी 15 परसेंट पर, उल्टा AT&C लोसेज हमारी सरकार में 2012-13 के अंदर थे वह बढ़कर 2018 में 24.72 परसेंट हो गए। इनको वापस हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी मार्च, 19 तक 21.87 परसेंट लाने के और आने वाले 2 सालों में 15 परसेंट तक लाने की हमारी योजना है।

इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि पावर जो है उस पर डिपेंड करता है उद्योग भी और कृषि भी और स्थिति यह है कि अब सोलर भी और विंड भी साथ में है। आगे हमारी योजना यह रहेगी कि हम किसी तरह किसान को जो वादा किया है उसको हम निभा सकें। 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और सब्सिडी जो दे रहे हैं 12000 करोड़ की उनको, वह और बढ़ जाएगी, अभी जो रेट बढ़ी है उसके बाद में, उसको हमने मंजूर किया है।

इस प्रकार से बाकी योजना जो हमने लागू की है फूड प्रोसेसिंग यूनिट कि वह अपने आप में अद्भुत योजना है। 10 हैक्टेयर तक कोई लैंड यूज चैंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में हमने जो प्रोत्साहन दिया है उनको इस बात का, मैं समझता हूं कि सदन को जानकर खुशी होगी कि जो कैपिटल सब्सिडी है, जो फैक्ट्री लगाएगा वहां पर अपने खेत पर उसको पचास परसेंट तक मशीनरी के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और जो आर्गेनिक खेती करेगा, उसको 40% सब्सिडी और मिलेगी ट्रांसपोर्ट की, यह हमारी योजना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग नीति हमने बनाई है राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पालिसी, 2019, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना (रिप्स), 2019, मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जिसमें 5 से 8% तक का अनुदान है ब्याज का नौजवानों को। एमएसएमई हमारी बहुत ही, सरकार बनते ही हमने जो कानून पास किया इसका, उसके अंतर्गत 3,406 लोगों ने एप्लाई किया है। उनको प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं। यह योजना हमारी है और मैं चाहूंगा कि इसमें हम सब सहयोग करें और कैसे इसको हम लोग कामयाब करें क्योंकि योजना में जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा और इसमें युवाओं को बैंकों से टाईअप करना बहुत जरूरी होगा और बैंकों की जो स्थिति है वह आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से वह बिहेव कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात जो उठाई है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने पिछली बार भी

(श्री अशोक गहलोत)

कहा था, अभी आपने इस बात को उठाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपये अगर हमने दिए हैं किसान कल्याण कोष से तो वह इसलिए देने पड़े हम लोगों को, आपको शायद जानकारी होगी या हो सकता है आपको जानकारी नहीं भी हो, 2019-20 में योजना की क्रियान्विति में हमने प्रोविजन रखा था 1,034 करोड़ का बजट के अंदर, प्रीमियम के लिए रखा था प्रोविजन। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि आपके शासन में 2017 के अंदर खरीफ 2017, रबी 2017-18, खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 इसमें आपका जो प्रीमियम बकाया था 921 करोड़ का, आप कल्पना कीजिए 921 करोड़ रुपये। 921.85 करोड़ बकाया थे, जो हमने प्रोविजन रखा था अभी 2019-20 के अंदर 1,034 करोड़ का, उसमें से हमें देना पड़ा 921 करोड़, मतलब करीब-करीब पूरा पैसा आपके वक्त की जो बकाया है उसको चुकाने में लग गए। इसलिए यह है और इसलिए चुकाया हमने जिससे क्लेम टाइम पर मिल सके। उलटा चोर कोतवाल को डांटे वह वाली बात हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और नेता प्रतिपक्ष ने कही थी इनपुट सब्सिडी के बारे में पिछली बार। मैं कहना चाहूंगा उस वक्त में भी आपने कहा और बड़े भावुक होकर कहते हैं आप लोग। पता नहीं किसानों का क्या है, उनको क्या स्थिति मिलती है। आप की सरकार थी, तब आप कहां चले गए, तब क्यों नहीं बोले आप?

आपको मैं बताना चाहूंगा, सूखा प्रभावित आदान-अनुदान, आप तो खुद मंत्री थे मेरे ख्याल से उसमें, 2015 का जो था वह अनुदान मिला है 20 मई, 2016 को मिली है इनपुट सब्सिडी। सूखा प्रभावित आदान-अनुदान 2016 का था वह मिला 8 सितम्बर, 2017 को यानी 9 महीने बाद में। सूखा प्रभावित आदान-अनुदान 2017 का वह मिला है 29 जून, 2018 को और माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा प्रभावित आदान-अनुदान 2019 का जो है, बाढ़ का भी और सूखा का तो 20 जनवरी को मिल गया हमारे वक्त में और बाढ़ का मिल गया 31 जनवरी को और आप किस रूप में हमें दोष दे रहे हैं, 6 से 8 महीने की देरी करते थे आप लोग और हम एक महीने में दे रहे हैं, जनवरी में दे रहे हैं हम लोग, तब भी आप हमारी शिकायत कर रहे हो।

अभी किसानों के लिये हमने एमएसपी में खरीददारी की, कोई शिकायत नहीं आई। आपके वक्त में लाइनें लगती थीं और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती थी, सबको मालूम है। यूरिया थानों में बिकता था।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, तमाम सदस्यों ने बहुत सारी बातें बताई हैं और जो सुझाव दिये हैं, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप निश्चिंत रहें। हमारे वक्त में हमने जो भी वादे किये हैं उनको निभाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे पर मुझे इस बात का दुःख जरूर रहेगा कि राजस्थान के हमारे नेता प्रतिपक्ष को देश में आज जो कुछ हो रहा है, उस पर भी दो बातें बोलनी चाहिये थीं। प्रदेश में आगे क्या होना चाहिये, कैसे यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे। पिछली बार आप बोल गये थे कि एफआईआर के लिये मना कौन करता है। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने यहां पर एक सर्वे करवाया था, एमआईटी, यूएसए वर्ल्ड की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके सहयोग से सर्वे हुआ। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी और 'Professor ESTHER DUFLO', यह उनकी मैडम हैं और हमारे यहां की एक आईपीएस आफिसर नीना सिंह, जो कि नोडल आफिसर थीं, इन्होंने उस वक्त सर्वे किया था कि राजस्थान में जनता पुलिस को घटनाओं की सूचना देने से कतराती है, नंबर एक। नंबर दो, मात्र 29 प्रतिशत घटनाओं को ही थाने में रिकार्ड किया जाता है। नंबर तीन, जबकि 71 प्रतिशत घटनाओं की सूचना थानों में नहीं मिलती है। आप उस दिन बहुत जोरजोर से बोल रहे थे, कोई मर्डर हो गया तो मना करेगा, कोई रेप हो गया तो मना करेगा। बड़े क्राइम में नहीं करते हैं। क्राइम कई तरह के होते हैं। लोगों पर क्या बीतती है जब थाने में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या आंकड़े हैं यह, आप बताइए। एफआईआर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक आर्टिकल लिखा, कोई मिस्टर चौधरी हैं। राजस्थान में क्राइम के हमारे आंकड़े बढ़ गये और हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि क्राइम के आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एफआईआर कम्पल्सरी कर रहे हैं। हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, हमें यहां की जनता की चिंता है, यह मैंने कहा था। आंकड़े बढ़ने से क्या हो गया, कम से कम उनको न्याय तो मिले। इसके लिये ताली नहीं बजाओगे आप? एनसीआरबी में आंकड़े राज्य ही भेजते हैं। बढ़ जाते हैं, आर्टिकल आते हैं राजस्थान यहां चला गया, वहां चला गया, हमें कोई चिंता नहीं है। हमने तय कर लिया है कि कितने ही आंकड़े बढ़ो, पर हम चाहेंगे कि एफआईआर अवश्य हो, अन्याय किसी के साथ नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन स्थिति से हम लोग चिंतित हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छा नहीं हो रहा है। रविन्द्र नाथ टैगोर ने

(श्री अशोक गहलोत)

कहा था मानवता राष्ट्रवाद से बड़ी है। अभी मानवता पर तो बहस छिड़ रही है। विवेकानंद जी को आप मानते हो, 127 साल पहले शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसने प्रताड़ितों तथा सभी राष्ट्रों और धर्मों के शरणार्थियों को अवसर दिया है। उनके नाम पर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। आप आज भी बहुत गर्व से उनका नाम लेते हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आजकल आप गांधी का नाम लेने लग गये, मन से या बेमन से, यह अलग बात है पर कम से कम लेने लग गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका भी कोई जवाब नहीं है, नौटंकी की भी कोई हद होती है कि आप गांधी और गोडसे को साथ ही लाते हो, कमाल हो गया। गांधी की बात भी करते हो, गोडसे की बात भी करते हो। गोडसे का मंदिर बनायेंगे, वह प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही है। वह हेगड़े क्या कह रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। यह तो आप लोगों का गजब का साहस है। हम दाद देंगे आपको, गांधी गोडसे साथ में। जिसने मर्डर किया, वह भी साथ में और जिसका मर्डर हुआ उसके साथ में।

देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, यह नारे लगाते थे। आज एलआईसी बिक रही है, एयर इंडिया बिक रही है, आईडीबीआई बिक रही है और आपके सुब्रहमण्यम स्वामी जो हमेशा हमारे खिलाफ चलते हैं, उन्होंने एयर इंडिया बेचने को राष्ट्र विरोधी कदम बताया। आपके बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, आपको मालूम ही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप बख्शो और सब मिलकर इस देश को बचाओ। चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, जैन हो, आपस में सब लोग मिल कर रहें। यह जो आपने सीएए का कानून पास करवाया है, उसमें धर्म के नाम पर जो भेदभाव किया, उससे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में केन्द्र सरकार की बदनामी हो रही है। अब धीरे-धीरे एहसास सबको होने लगा है, आपके नेताओं को होने लग गया है, नहीं तो होने लग जायेगा, यह स्थिति आ रही है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने यह बात कही थी, उनकी एक कविता थी, आपको मालूम ही होगा, गीतांजलि उनका एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है। कविता की प्रमुख पंक्तियों का हिन्दी सारांश इस प्रकार है। "भारत एक ऐसी भूमि है जहां आर्य, गैर आर्य, द्रविड़, शक, हूण, पठान तथा मुगल इस भूमि पर एक शरीर की तरह रह रहे हैं। भारत भूमि के दरवाजे पश्चिम के लिये खुले हैं। भारत भूमि पर आने वाले

(श्री अशोक गहलोत)

लोग अपने साथ अपनी संस्कृति का उपहार लेकर आते हैं।" देखिए आप कितनी बड़ी सोच थी उनकी। भारत भूमि पर आने वाले लोग अपने साथ अपनी संस्कृति का उपहार लेकर आते हैं। बाहर की संस्कृति यहां आकर समाहित हो जाती है। वह यहां आकर एक-दूसरे के साथ समाहित हो जाते हैं फिर इस भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। भारतीय मानवता के समुद्री तट पर हे आर्यों, हे हिन्दुओं, हे मुसलमानों, आप सभी आओ और यहां रहो। बड़ा दिल, यह है हमारी संस्कृति के संस्कार। अंग्रेजों, ईसाइयों तुम भी यहां आओ, आओ, आओ यहां रहो। ब्राह्मणों तुम भी यहां आओ और सभी का हाथ थामो, सबकी सोच को पवित्र करो। उन्होंने यहां तक कह दिया, हारे हुए राजाओं तुम भी यहां आओ ताकि तुम अपमान को भूल सको। बताइए आप, यह थी उस वक्त की सोच।

अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): घोषणाएं, माई गोड।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी, बूंदी के संबंध में, बूंदी में जो दुर्घटना हुई उसमें सदन की सबकी भावना थी कि वह बच्चे हैं, उनके संबंध में एक्स्ट्रा घोषणा करनी थी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप जो भी सुझाव देंगे, हमें मंजूर होगा। वैसे कल हम वहां पर जा रहे हैं, उनकी बैठक में भी जा रहे हैं और कोई पैकेज बनाकर हम क्या दे सकते हैं, पूरा पैकेज देंगे। आपकी संवेदना, हम सबकी संवेदना एक-सी है। बड़ी घटना हुई है वह, यह मैं मानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि कटारिया साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दिया कि बजट की जो घोषणाएं हैं वह कैसे अधूरी रह रही हैं। मैं नहीं चाहूंगा कोई घोषणा हो और मेजें थपथपाएं और बाद में काम नहीं हो। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि लिमिट में ही कुछ घोषणाएं करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी घोषणाएं एप्रोप्रिएशन बिल के वक्त देखेंगे, क्या कर सकते हैं। कुछ मामूली-सी घोषणाएं हैं क्योंकि माननीय सदस्यों ने बहुत ही प्रयास से मुझे लिखकर दिया है। प्रदेश में बामनवास (सवाई माधोपुर), लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर), उच्चैन (भरतपुर) में नगरपालिकाओं के गठन की मांग है, वह पूरी की जायेगी। राजकीय

(श्री अशोक गहलोत)

चिकित्सालय बालोतरा में सीसीयू, आईसीयू खोले जायेंगे। राजकीय चिकित्सालय हिण्डौन सिटी में 50 बैड की बढ़ोतरी की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेपऊ में 30 बैड से 50 बैड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोसल में 30 बैड से 50 बैड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में 50 बैड की बढ़ोतरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुरा (जयपुर) में 30 बैड से 50 बैड।

राज्य में कृषि विपणन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीकरी (भरतपुर), टिब्बी (हनुमानगढ़), सुलतानपुर (कोटा) व खातौली (कोटा), मांगरोल (बारां), कवई (बारां), कापरेन (बूंदी), पिलानी (झुंझुनू) एवं लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) में स्वतंत्र मंडी बनाने की घोषणा करता हूं।

सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज, पिण्डवाड़ा में 23 गांवों तथा 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की डीपीआर बनायी जाएगी।

राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोले जाएंगे।

राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ में नवीन विषय समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान खोले जाएंगे।

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ की जाएंगी।

मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कन्जर्वेशन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस बजट में हमारे द्वारा विभिन्न विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय विषय खोलने की घोषणा की गयी है। इस क्रम में पंचायत समिति हरेकीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय एवं कोटा, रसदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान विषय खोले जाएंगे।

दूदू, फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत करेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

चाकसू, जयपुर, नदबई, भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं।

ब्रिजपुरा, किशनपुरा, जयपुरा ग्राम पंचायत बालथल, बसेड़ी (धौलपुर) अरानी उपखंड इटावा को 33 केवी जीएसएस बनाए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों में से लगभग 2 हजार चिकित्सक उच्च शिक्षा एवं अन्य कारणों से अवकाश आदि पर रहते हैं। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी रह जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उक्त घोषणा के तहत 2 हजार नये पद चिकित्सा अधिकारियों के सृजित किये जाएंगे।

कई बार शहरों में घनी आबादी के क्षेत्रों में एंबुलेंस को पहुंचने में समय लगता है, जिससे समय पर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई होती है। इस समस्या का निपटान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति के पश्चात् के गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें, राज्य के दो जिले, जयपुर और जोधपुर के परकोटे के क्षेत्र के लिए बाइक एंबुलेंस हेतु पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।

राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कालेजों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जाएगी। उपरोक्त मशीन से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य का परीक्षण कर वंशानुगत विकृति एवं अन्य बीमारियों का समय पर रक्त पहचान और उपचार किया जा सकेगा।

राज्य के समस्त मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रखरखाव के लिए केंद्रीकृत आनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था से इन अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों के सुचारु रखरखाव की आनलाइन मोनिटरिंग व त्वरित मरम्मत सुनिश्चित की जा सकेगी।

मैं भरतपुर में स्टार्टअप इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा करता हूं, जिससे नवाचार बढ़ेगा व युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के निर्णय का राज्य सरकार स्वागत करती है। इसकी स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा। इनोवेशन क्लस्टर का समन्वयक आई.आई.टी. जोधपुर है। इस इनोवेशन सेंटर की स्थापना से क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये निवेश लाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह भारत सरकार की योजना है।

मैट्रो फेज-2 सीतापुरा से अंबाबाड़ी वाया टोंक रोड, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हास्टल, चांदपोल, पानीपेच, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है और यह पूर्णत: एलीवेटेड है, की डीपीआर तैयार कर ली गयी है और जल्दी ही इस काम को आगे की प्रक्रिया में चलाया जाएगा।

उदयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 5.78 लाख के लिए दैनिक जल मांग 114.5 एमएलडी है। जयसमन्द झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के अनुसार उदयपुर शहर हेतु वर्तमान जल मांग की आपूर्ति की जा सकेगी। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

जल योजना रामगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त आवश्यक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्गठन योजना 46 करोड़ 75 लाख रुपये की बनायी गयी है। इससे वर्तमान आबादी 67 हजार लाभान्वित होगी। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वर्ष 2013 में हमारी सरकार के द्वारा बीकानेर जिले की तहसील नोखा, बीकानेर में कुल 146 गांव, जिनमें नोखा तहसील के 137 गांव और बीकानेर तहसील के 9 गांव शामिल हैं। दो शहर नोखा और देशनोक को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव लागत 399 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी थी। इस परियोजना को घर-घर जल संबंध दिये जाने के प्रावधान के साथ संशोधित किये जाने पर 700 करोड़ रुपये की लागत आना संभावित है। इस परियोजना की नई डीपीआर बनायी जाएगी। इस योजना की क्रियान्विति से लगभग एक लाख शहरी आबादी, साढ़े 4 लाख ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। इसमें लगभग 76 हजार घर जल संबंध सैंक्शन किये जाएंगे।

प्रबंध वृत्त परियोजना से 2.08 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा खेती से सिंचाई, कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821

(श्री अशोक गहलोत)

गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना पर अब तक 2882.16 करोड़ रुपये व इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 608 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस हेतु 866 करोड़ रुपये रखने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान भाषा की फिल्मों की गुणवत्ता व लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण करने योग्य वातावरण सृजित करना आवश्यक है। अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित होने वाली राजस्थानी भाषा की फिल्मों को राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान देने के लिए कोई नीति नहीं है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा की फिल्मों के निर्माण पर दी जाने वाली अनुदान राशि पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नई नीति लायी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर कहकर अपनी बात खतम करता हूं:-

"मेरा कलाम नहीं किरदार उस मुहाफिज का,

जो अपने शहर को महशूर करके नाच करे

मेरा कलाम तो अमानत है मेरे लोगों का

मेरी कलम तो अदालत है, मेरे जमीर की।"

इसका अर्थ है - मेरा कलाम उस भक्षक की तरह नहीं है, जो अपने शहर को दुविधाओं से घिरा देखकर नाच करे। जैसा आज देश में हो रहा है। मेरी कलम अमानत है मेरे प्रदेश के लोगों की। उन्हीं के लिए कार्य करती है। मेरे जमीर की अदालत में मेरे कलम हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए तत्पर रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे जानकारी है। पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से दो सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। कल सरकार, बाड़मेर के पुलिस थाने में एक युवक की डैथ हुई, इस पर स्टेटमेंट देगी। चर्चा समाप्त हुई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18.57 बजे शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नवलगढ़ साइंस पार्क के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की कार्ययोजना

220. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ में साइंस पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पार्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा कितनी राशि व्यय कर कौन-कौनसे कार्य पूर्ण किये गये और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पार्क में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य शेष है? यदि हां, तो क्यों व कब से? अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम के निर्माण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ़ को राशि 10 लाख रुपये दिनांक 15.03.2019 को हस्तांतरित की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या उक्त विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013 से 2018 तक उक्त पार्क का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है? क्या सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त पार्क को अत्याधुनिक एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ कस्बे में विज्ञान पार्क की स्थापना की स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक 532-39 दिनांक 06.06.2012 के द्वारा जारी की गई थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)

(2) नवलगढ़ कस्बे में साइंस पार्क की स्थापना के लिए वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक स्थापना मद में राशि रुपये 476.49 लाख का प्रावधान किया गया था। विभाग द्वारा अब तक राशि रुपये 343.49 लाख का व्यय किया जा चुका हैं। पूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

(4) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ द्वारा उक्त पार्क में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

(5) जी नहीं। आमजन एवं विद्यार्थियों को विज्ञानं उद्यान में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है।

विज्ञान उद्यान में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जोधपुर जिले में पर्यटन के विकास हेतु स्वीकृत राशि

232. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ओसियां को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 में जिला जोधपुर में पर्यटन के विकास हेतु कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत ईको एडवेंचर सर्किट एवं डेजर्ट सर्किट प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिसमें जोधपुर जिले के ओसियां के पर्यटन विकास कार्य भी सम्मिलित हैं। प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में जोधपुर जिले के पर्यटन विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा स्मारकों के संरक्षण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास की गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने की योजना

233. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस-किस किस्म की भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस भूमि को किस-किस स्तर पर आबादी में परिवर्तित किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के किस-किस गांव में ऐसी कितनी - कितनी गैर आबादी भूमि है, जिन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गैर आबादी भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत तथा यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विकास हेतु भूमि सैट-अपार्ट किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर यदि भूमि राजस्थान भू-राजस्व काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 से प्रतिबंधित अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा विशिष्ट नियमों के तहत आरक्षित नहीं है तो भूमि आबादी विकास हेतु सैट-अपार्ट की जाती है। नियम 16 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में निम्नानुसार गैर आबादी भूमि है:-

तहसील	**गैर आबादी भूमि में**
बौंली	2835.17 है.
बामनवास	115.19 है.
कुल	2950.36 है.

जिसकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विकास हेतु भूमि सैट-अपार्ट किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर यदि भूमि राजस्थान भू-राजस्व काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 से प्रतिबंधित अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा विशिष्ट नियमों के तहत आरक्षित नहीं है तो भूमि आबादी

(राजस्व मंत्री)

विकास हेतु सैट-अपार्ट की जाती है। इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किये हैं जिसमें से परिपत्र दिनांक 26.05.2008 एवं 07.09.2017 की प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर में राशन की दुकानों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन

234. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नई राशन की दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन लिए गये हैं? यदि हां, तो किस-किस वार्ड में कब-कब व किस-किस नाम से आवेदन प्राप्त हुए? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में प्राप्त हुए आवेदनों में से किस-किसको राशन की दुकान का आबंटन किया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक दुकानें आबंटित कर दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा राशन की नवीन दुकान हेतु जनसंख्या व राशन यूनिट को आधार माना जाता है? यदि हां, तो उक्त आधार पर विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में कितनी नवीन दुकानें खोली जा सकती हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त आवेदन पत्रों की नामवार व वार्डवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आबंटन सलाहकार समिति के गठन होने के बाद नई दुकानों का आबंटन शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा 500 एनएफएसए राशनकार्ड एवं 2000 एनएफएसए यूनिट के आधार पर नवीन दुकान सृजित किये जाने का प्रावधान है। उक्त निर्देशों के तहत अलवर शहर में 26 नवीन उचित मूल्य दुकान खोला जाना प्रस्तावित है जिनका वार्डवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के बन्द विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने के लम्बित प्रकरण

235. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में जनवरी, 2019 के पश्चात् पूर्व में बंद किये गये किस-किस विद्यालय को पुन: प्रारम्भ करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, पाली द्वारा कब-कब शिक्षा निदेशालय बीकानेर या सरकार को पत्र लिखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस विद्यालय को कब-कब पुन: प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गई एवं किस-किस विद्यालय की किन-किन कारणों से प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद किये गये विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने वाले लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी अवधि में प्रारम्भ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिला में जनवरी, 2019 के पश्चात् समन्वित किये गये विद्यालयों को डी-मर्ज करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी(मु.) प्रारंभिक, पाली के पत्रांक: जिशिअ/प्राशि/पाली/डी-मर्ज/2019/137 दिनांक 25.2.2019 तथा जिशिअ/प्राशि/पाली/एकी/2019/102 दिनांक 04.2.2019 के द्वारा विद्यालयों के डी-मर्ज के प्रस्ताव निदेशालय बीकानेर को प्रेषित किये गये जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क-1"' "क-2" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.14(4)शिक्षा-1/एकीकरण/2014 पार्ट तथा प.17(5)प्राशि/आयो./एकीकरण/2019 दिनांक 24.2.2020 के द्वारा पाली जिले के परिशिष्ट "क-1" "क-2" में सम्मिलित प्रस्तावों में से निम्नांकित विद्यालयों को डी-मर्ज करने की स्वीकृति जारी की गई है-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम जिसे समन्वयन से मुक्त किया गया
1.	राप्रावि, बेरा निम्बडिया
2.	राप्रावि, चाण्डिया खुर्द (नया)
3.	राप्रावि, बोगासनी खुर्द

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम जिसे समन्वयन से मुक्त किया गया
4.	राप्रावि, रामर बेरा कांवलिया
5.	राउप्रावि, भोमियाजी का ओरण
6.	राप्रावि, खिन्दावास
7.	राउप्रावि, बेरा बुकिया
8.	राउप्रावि, आ.कालु
9.	राबाउप्रावि, आ.कालु
10.	सेमेठो राउप्रावि, निमाज
11.	राप्रावि, गोरिया बेरा
12.	बाबा रामदेव राउप्रावि, जैतारण
13.	राप्रावि, चौकीदारों की ढाणी अमरपुरा

शेष प्रस्ताव भी आर.टी.ई. नोर्म्स के तहत परीक्षणाधीन/प्रक्रियाधीन हैं।

(3) प्रश्नोत्तर बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रिक्त पद

236. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय व महाराणा प्रताप कृषि व अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) कितने रिक्त पदों पर अस्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कब की गई? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में शैक्षणिक संवर्ग के 63 एवं अशैक्षणिक संवर्ग के 172 पद रिक्त हैं। पदवार विवरण व पद कब से रिक्त हैं, के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

महाराणा प्रताप कृषि व अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में शैक्षणिक संवर्ग के 319 एवं अशैक्षणिक संवर्ग के 520 पद रिक्त हैं। पदवार विवरण व पद कब से रिक्त हैं, के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के संघटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों हेतु गेस्ट फैकल्टी के अन्तर्गत 364 व्यक्ति अगस्त, 2019 से कार्यरत हैं। अशैक्षणिक कार्यों हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न संघटक महाविद्यालयों एवं इकाइयों में कुल 255 अनुबन्धित कर्मचारी अप्रैल, 2019 से कार्यरत हैं।

महाराणा प्रताप कृषि एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में अस्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है अपितु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार समेकित वेतन पर 21 सेवानिवृत्त शिक्षकों को अगस्त, 2019 व तत्पश्चात् से रखा गया है एवं दिसम्बर, 2019 से 265 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रखा गया है।

रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर विचार कर अत्यावश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर कमिशनरेट में महिलाओं के अपहरण के दर्ज प्रकरण

231. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक जयपुर कमिशनरेट में नाबालिगों एवं महिलाओं के अपहरण, यौनाचार के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा कितने प्रकरणों में कार्यवाही कर ली गई एवं कितनों पर जांच विचाराधीन है? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्तावधि में कितनों की गिरफ्तारी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया तथा कितने की जांच जेरे तफ्तीस है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) नाबालिगों के अपहरण के कुल 673 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 576 प्रकरणों में अनुसंधान कर निस्तारण की कार्यवाही की गई एवं 97 प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है। थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(ब) महिलाओं के अपहरण के कुल 152 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 138 प्रकरणों में अनुसंधान कर निस्तारण की कार्यवाही की गई एवं 14 प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है। थानेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(स) नाबालिगों के यौनाचार के कुल 232 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 211 प्रकरणों में अनुसंधान कर निस्तारण की कार्यवाही की गई एवं 21 प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है। थानेवार विवरण परिशिष्ट स संलग्न है।

(द) महिलाओं के यौनाचार के कुल 376 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 332 प्रकरणों में अनुसंधान कर निस्तारण की कार्यवाही की गई एवं 44 प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है। थानेवार विवरण परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(2) पुलिस कमिशनरेट जयपुर में नाबालिगों एवं महिलाओं के अपहरण, यौनाचार में कुल 563 आरोपियों को गिरफ्तारी कर चालान पेश न्यायालय कर दिया गया है एवं कुल 176 प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'य' संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बसेड़ी की मडासिल व सरमथुरा ग्राम पंचायत में एनीकट का निर्माण

232. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेडी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की मडासिल व सरमथुरा ग्राम पंचायत में एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र की मडासिल व सरमथुरा ग्राम पंचायत का क्षेत्र पार्बती बांध के जलग्रहण (कैचमेंट एरिया) में स्थित होने से एनीकट बनाया जाना विचाराधीन नहीं है।

बांडी-सेंदड़ा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों का पुनर्वास

233. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांडी-सेंदड़ा बांध (भीनमाल) के डूब क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) में स्थित परिवारों का सरकार द्वारा डूब क्षेत्र से अन्यत्र पुनर्वास किया गया है? यदि हां, तो अब तक कुल कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है और कितनी राशि व भूमि मुआवजे के रूप में दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध के डूब क्षेत्र में स्थित सभी परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कुल कितने परिवार पुनर्वास से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुनर्वास से वंचित रहे शेष परिवारों का पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांडी-सेंदड़ा बांध (भीनमाल) के डूब क्षेत्र में स्थित परिवारों का डूब क्षेत्र से अन्यत्र कुल 281 परिवारों का पुनर्वासन किया गया है। बांध के उपयोग में ली गई अधिग्रहीत निजी भूमि के मालिकों को 140.385 लाख एवं बांध के डूब क्षेत्र व नीचे आई शेष भूमि का मुआवजा राशि रुपये 10.163 लाख का एवं मुडतरा सिली में 40'x60' फुट माप के 281 भूखण्ड, भूमि मुआवजे के रूप में दिये गये हैं।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां।

(3) उक्त बांध के परिवारों के पुनर्वास अन्तर्गत योग्य परिवारों के पुनर्वास का कोई प्रकरण जल संसाधन विभाग में लम्बित नहीं है।

मासलपुर (करौली) में गदाखार नाले पर एनीकट का निर्माण

234. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर के पास स्थित गदाखार नाले पर एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील मासलपुर के पास निर्मित गदाखार एनीकट के वन क्षेत्र में स्थित होने तथा इससे डायवर्जन हेतु निर्माण में निजी भूमि आने के कारण उक्त स्थान पर एनीकट निर्माण संबंधित कोई कार्य विचाराधीन नहीं है।

जैतारण में स्वीकृत सड़कें

235. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 2016 से जनवरी, 2020 तक कौन-कौनसी ग्रामीण व शहरी सड़कें स्वीकृत हुईं? उक्त में से कौन-कौनसे कार्य किस-किस संवेदक के द्वारा समयावधि में पूर्ण कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ग्राम काणूजा मुख्यालय से कालण जाने वाली स्वीकृत सड़क का कार्य किस संवेदक द्वारा किया गया?

(2) क्या सरकार संवेदक द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 से जनवरी 2020 तक स्वीकृत ग्रामीण व शहरी सड़कों का विवरण मय ठेकेदारों के नाम परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

ग्राम काणूजा मुख्यालय से कालणकला तक स्वीकृत सड़क का कार्य संवेदक मैसर्स सविन्द्रजीत सिंह, एए क्लास ब्यावर द्वारा किया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। बजट उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेजा ग्राम पंचायत (भीलवाड़ा) में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

236. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मेजा पंचायत समिति मांडल जिला भीलवाड़ा द्वारा आबादी भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को की गई है? क्या उक्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी मांडलगढ़ द्वारा की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मेजा द्वारा अतिक्रमण विधि अनुसार हटाने के उपरान्त भी अतिक्रमी द्वारा स्थानीय प्रशासन के संरक्षण से पुन: बार-बार अतिक्रमण किया जाता रहा है तथा पंचायत के उच्च अधिकारियों को शिकायत के उपरांत भी अभी तक ग्राम पंचायत की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर अतिक्रमियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराने की विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत मेजा पंचायत समिति मांडल जिला भीलवाड़ा द्वारा आबादी भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत पत्र द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा द्वितीय के पत्रांक 1223 दिनांक 23.10.2018 से बाबत परिवाद संख्या 275/2018 विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत मेजा पंचायत समिति मांडल प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 691 दिनांक 26.10.2018 से जांच कमेटी का गठन किया गया। उक्त क्रम में विकास अधिकारी, पंचायत समिति मांडल के द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 1305 दिनांक 03.07.2019 प्रेषित की गई है। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) संबंधित व्यक्ति का अतिक्रमण हटा दिया गया है। अन्य अतिक्रमण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) संबंधित व्यक्ति श्री रामेश्वर कीर/श्री भैरू लाल कीर द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत मेजा के द्वारा थाना मांडल में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 282/2017 दिनांक 10.10.2017 को दर्ज कराई गई। उक्त एफ.आई.आर. के संबंध में प्रस्तुत अंतिम फार्म रिपोर्ट (एफ.आर.) दिनांक 27.11.2017 की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जालौर में गोगामाड़ा को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना

237. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के गांव एलाना की सरहद में "गोगामाड़ा" नाम से लोक देवता गोगाजी का मंदिर स्थित है? क्या सरकार उक्त मंदिर को जोड़ने वाली सड़क को पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जालौर के गांव एलाना (पं.स. सायला) से 12.00 किमी. दूरी पर **"गोगामाड़ा"** नाम से लोक देवता गोगाजी का मन्दिर स्थित है। गांव एलाना से गोगामाड़ा तक का रास्ता वर्तमान में कच्चा है, जिस पर पक्की डामर की सड़क बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

डेगाना में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

238. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत प्रदेश के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों को उक्त योजना के अंतर्गत पक्की सड़क से जोड़ने का

(श्री विजयपाल मिर्धा)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी तथा मरुस्थल व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की एकल बसावटों व 500 मीटर परिधि के अन्दर आने वाली समूह बसावटों की उपरोक्त आबादी अनुसार डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है। तदनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 250 से अधिक की आबादी के समस्त गांवों/ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ जा चुका है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा-निर्देशानुसार विधान सभा क्षेत्र डेगाना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250 से अधिक आबादी के गांवों/ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट -1 पर अंकित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहपुर कस्बे में हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण

239. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फतेहपुर कस्बे में हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड बनवाने के लिये स्वीकृति जारी होने के उपरान्त भी अब तक सर्विस रोड नहीं बनवाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सर्विस रोड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीकर-बीकानेर पीपीपी प्रोजेक्ट के मूल स्वीकृत कार्य में सर्विस रोड का प्रावधान कन्सेशन एग्रीमेन्ट में नहीं लिया हुआ था। विभाग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

द्वारा आठ कस्बों (लक्ष्मणगढ़-3.431 कि.मी., फतेहपुर-4.006 किमी., रोलसाबसर 2.007 कि.मी., रतनगढ़-1.489 किमी., राजलदेसर-1.003 किमी., कितासर-1.004 कि.मी., श्रीडूंगरगढ़-4.00 कि.मी. व सेरूना-1.001 किमी) में सर्विस रोड हेतु चैन्ज आफ स्काप के तहत प्रपोजल स्वीकृति हेतु भिजवाये गये जिनके अनुसार फतेहपुर कस्बे में भी सर्विस रोड बनायी जानी सम्मिलित थी।

इस हेतु चैन्ज आफ स्काप के तहत मोर्थ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.07.2017 राशि रु. 54.60 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी। उक्त स्वीकृति राशि में यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्मिलित नहीं होने के कारण सर्विस रोड नहीं बनाई जा सकी। विभाग द्वारा चैन्ज आफ स्काप के तहत पुन: नया प्रस्ताव राशि रु. 71.83 करोड़ जिसमें सर्विस रोड़ हेतु राशि रु. 54.60 करोड़, यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु राशि रु. 11.62 करोड़, फतेहपुर वन क्षेत्र में कांटेदार तार की बाड़ हेतु राशि रु. 0.64 करोड़ एवं फतेहपुर में पेडिस्ट्रियन अण्डरपास हेतु राशि रु. 4.97 करोड़ का एक संशोधित प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर को भिजवाया गया था। उक्त संशोधित स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण उक्त कार्य नहीं हो सका।

(2) वर्तमान में फतेहपुर कस्बे में हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2019-20 में सम्मिलित है। इस हेतु तकमीना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाया गया है। उक्त तकमीने में फतेहपुर सहित कुल आठ कस्बों में सर्विस रोड निर्माण हेतु 54.49 करोड़, फतेहपुर में पी.यू.पी. निर्माण हेतु 5.16 करोड़, यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु 17.71 करोड़ एवं अन्य प्रावधानों सहित कुल 88.58 करोड़ के कार्य सम्मिलित हैं। उक्त कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त सर्विस रोड बनवाने का कार्य भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर निर्भर करेगा।

अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

240. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु अमृत योजना व स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्य प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो उक्त योजनाओं में क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अजमेर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु दो स्वीकृत पेयजल योजनाओं क्रमश: अमृत मिशन एवं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। परियोजनावार स्वीकृति विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) अमृत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूडसिको (राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन) की राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) की 9वीं बैठक दिनांक 30.03.2017 के द्वारा राशि रुपये 29.98 करोड़ की जारी की गई थी।

(ब) अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर द्वारा स्मार्ट सिटी निधि के तहत अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु जल प्रदाय एवं संबंधित कार्यों हेतु बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 49.96 करोड़ की दिनांक 13.10.2017 को जारी की हुई थी।

स्मार्ट सिटी एवं अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के संयुक्त क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मैसर्स विष्णु प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड, जोधपुर को राशि रुपये 103.39 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 09.05.2018 को जारी किया जा चुका है तथा इनके कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं का कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

उक्त स्वीकृत परियोजनाओं में प्रावधित कार्यों की वर्तमान प्रगति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में 33/11 जीएसएस हेतु स्वीकृत राशि

241. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू, पावा व पालडी जोड क्षेत्र में

(श्री जोराराम कुमावत)

33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत है? उक्त सब स्टेशनों हेतु कहां-कहां भूमि आबंटित की गई है? किस-किस स्थान पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हो गई है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू, पावा व पालडी जोड क्षेत्र में 33/11 केवी विद्युत उप चौकियों हेतु स्वीकृत राशि, व्यय राशि, आबंटित भूमि का स्थानवार व उक्त 33/11 केवी विद्युत उप चौकियों के कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले के पुरातत्व स्थलों का विकास

242. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में पुरातत्व विभाग की कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर स्थित है? विधान सभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का किस-किस कार्य के लिये व कहां-कहां उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभाग के अधीन स्थल आते हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे स्थल? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जोधपुर जिले के पुरातत्व स्थलों के विकास के लिये अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-अ पर वर्णित है।

(2) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान के संरक्षित स्मारकों की जमीन का उपयोग स्मारक में संग्रहित कला-पुरासामग्री की सुरक्षा एवं कला-पुरास्मारक/स्थल के संबंध में उपलब्ध जानकारी देशी-विदेशी पर्यटकों को देने के लिये किया जाता है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन कोई संरक्षित स्मारक नहीं है।

(4) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा संख्या 154 अन्तर्गत प्रदेश स्थित 09 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें फलौदी दुर्ग (जोधपुर) एवं शिव मन्दिर ओसियां (जोधपुर) भी सम्मिलित हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

243. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अलवर की विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि अलवर जिले की 467 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सोलर संयंत्र स्थापित किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूचना संलग्न हैं।

(2) ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सोलर संयंत्र लगाये जाने की परियोजना थी, जो वर्ष 2012-13 में पूर्ण हो गई।

वर्ष 2012-13 तक अलवर जिले में कुल 472 ग्राम पंचायतें थीं, जिनमें से 467 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सोलर संयत्र लगाये जा चुके हैं।

शेष 5 ग्राम पंचायतों में से 3 ग्राम पंचायतें नगरपालिका में परिवर्तित हो गई हैं तथा 2 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण 2012-13 के बाद पूर्ण होने के कारण सोलर संयंत्र नहीं लगाया जा सका।

(ऊर्जा मंत्री)

वर्ष 2012-13 के बाद नवसृजित ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवन के मानचित्र इस प्रकार तैयार किये गये हैं कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र से उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाएं भी पंचायत कार्यालय से उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

ग्राम पंचायतों के नवीन भवन मानचित्र में सोलर संयंत्र लगाने का प्रावधान नहीं है तथा इन भवनों में सोलर संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी नगर परिषद् में वेतन व संवेदकों के बकाया बिलों का भुगतान

244. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् बून्दी में वर्तमान में वेतन व संवेदकों के कितनी राशि के बिल बकाया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वेतन व बकाया अन्य भुगतान के साथ ही नगर परिषद् बून्दी को विकास कार्यों हेतु विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् बून्दी में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों की राशि रुपये 5 करोड़ 95 लाख, सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ राशि रुपये लगभग 3 करोड एवं 7वें वेतन आयोग के एरियर की राशि रुपये लगभग 2 करोड़, कुल 10 करोड़ 95 लाख रुपये बकाया चल रहे हैं। ठेकेदारों के 7 करोड़ 37 लाख रुपये के बिल बकाया चल रहे हैं। ठेकेदारों के बकाया बिलों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद् बून्दी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु प्रतिवर्ष चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य से अनुदान प्राप्ति व निकाय स्तर से शुल्क, सैस, कर इत्यादि की वसूली नगरीय निकायों की आय के मुख्य स्रोत हैं। विभागीय परिपत्र दिनांक 10.09.2014 एवं दिनांक 13.05.2015 के द्वारा निकायों को स्वयं की आय में अधिक से अधिक वृद्धि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परिपत्रों की

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगरीय निकायों को किसी प्रकार का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माणों के निस्तारण की कार्ययोजना

245. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जयपुर में संबंधित जोन कार्यालय व अतिक्रमण दस्ते में कार्यरत जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपने-अपने एरिये में गश्त कर आवासीय कालोनियों में किये जा रहे निर्माण कार्यों व अवैध निर्माण कार्यों की निगरानी की जाती है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से अब तक कितने अवैध निर्माण करने वालों एवं भवन निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध किये जा रहे निर्माण कार्यों पर क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर की महावीर नगर-II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा एवं जानकी विहार आवासीय कालोनी के ई-ब्लाक में किये जा रहे अवैध भवन निर्माण के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महावीर नगर-II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा में भूखण्ड संख्या 152 पर अवैध रूप से बहुमंजिला निर्माण किये जाने के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अवैध निर्माण को कब तक ध्वस्त कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जानकी विहार आवासीय कालोनी के ई-ब्लाक में एक भूखण्डधारी द्वारा विधान सभा आवासीय कालोनी, धावास की ओर सड़क मार्ग पर अवैध रूप से भवन निर्माण करवा लिया गया है? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण होने के विरुद्ध कौन जिम्मेदार है एवं अब कब तक उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राधिकरण, जयपुर एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा संबंधित जोन कार्यालय व अतिक्रमण दस्ते में कार्यरत जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

नगर निगम, जयपुर एवं प्राधिकरण, जयपुर में दिसम्बर, 2018 से अब तक अवैध निर्माणों एवं भवन निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध किये जा रहे निर्माण कार्यों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) (अ) जविप्रा क्षेत्राधिकार के महावीर नगर-II के भूखण्ड संख्या 152 पर किये गये अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर मौका निरीक्षण व जांच कर ग्राउण्ड+2 आवासीय निर्माण पर तृतीय मंजिल पर 2 कमरों का निर्माण करने पर दिनांक 02.12.2019 को जविप्रा अधिनियम, 1982 के तहत धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार अमल किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(ब) भू.सं. 287 महावीर नगर-II की कन्ट्रोल रूम में शिकायत प्राप्त हुई, जिसके संबंध में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया। मौके पर रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा था। कोई नया निर्माण चलता नहीं पाया गया।

(स) भू.सं. 112 महावीर नगर-II की शिकायत दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त होने पर जविप्रा के अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण के संबंध में उपायुक्त जोन-5 कार्यालय से चिन्हीकरण की रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(द) जानकी विहार आवासीय कालोनी, अजमेर रोड जेडीए द्वारा अनुमोदित योजना नहीं है। ई-ब्लाक विधान सभा आवासीय कॉलोनी, धावास की ओर सड़क मार्ग पर किये गये निर्माणों की वैधता अथवा अवैधता का निर्धारण योजना के नियमन एवं मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् सड़क इत्यादि के अलाइनमेंट पश्चात् ही तय किया जा सकता है। निर्धारण के बाद तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में मौके पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है तथा सड़क सीमा में कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है।

(य) जानकी विहार आवासीय कॉलोनी में ई-ब्लाक में अवैध निर्माण के संबंध में उपलब्ध संधारित रिकार्ड के अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार महावीर नगर-II के भूखण्ड

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संख्या 152 पर किये गये अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर मौका निरीक्षण व जांच कर ग्राउण्ड+2 आवासीय निर्माण पर तृतीय मंजिल पर 2 कमरों का निर्माण करने पर दिनांक 02.12.2019 को जविप्रा अधिनियम 1982 के तहत धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया गया। प्राधिकरण, जयपुर एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा संबंधित जोन कार्यालय व अतिक्रमण दस्ते में कार्यरत जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(4) जानकी विहार आवासीय कालोनी, अजमेर रोड जेडीए द्वारा अनुमोदित योजना नहीं है। ई-ब्लाक विधान सभा आवासीय कालोनी, धावास की ओर सड़क मार्ग पर किये गये निर्माणों की वैधता अथवा अवैधता का निर्धारण योजना के नियमन एवं मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् सड़क इत्यादि के अलाइनमेन्ट पश्चात् ही तय किया जा सकता है। निर्धारण के बाद तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में मौके पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है तथा सड़क सीमा में कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है। अत: कोई नया निर्माण नहीं होने एवं सड़क सीमा में रास्ता अवरुद्ध नहीं होने के कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में संचालित मैरिज गार्डनों से प्राप्त राजस्व

246. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्मार्ट सिटी कोटा में कुल कितने मैरिज गार्डन व मेस संचालित हैं? उक्त में से कितनों को स्वीकृति प्राप्त है तथा कितने बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे हैं? उक्त से नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मैरिज गार्डन व मेस से निकलने वाले कचरे पर किसी प्रकार का शुल्क वसूल किया जाता है? क्या निगम इनके द्वारा की गई गंदगी की देखरेख करता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्मार्ट सिटी कोटा में कुल 88 मैरिज गार्डन (विवाह स्थल) संचालित हैं। इनमें से 45 मैरिज गार्डनों का पंजीयन शुल्क जमा है। नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निगम कोटा द्वारा 03 मैरिज गार्डनों को अनुमति प्रदान की गई है। मैरिज गार्डनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। नगर निगम कोटा द्वारा स्मार्ट सिटी में संचालित हो रहे मेस का सर्वे नहीं होने के कारण अभी किसी भी मेस संचालन को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 लागू होने के पश्चात् मैरिज गार्डनों से वर्ष 2019-20 तक 32.00 लाख रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है।

(2) मैरिज गार्डन व मेस से निकलने वाले कचरे पर नगर निगम, कोटा द्वारा किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा मैरिज गार्डनों में हुई गन्दगी की मोनिटरिंग की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में सड़कों पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

247. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर की चारदीवारी में सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण हटाने हेतु विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? उक्त प्रावधानानुसार प्रत्येक दिन सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में गंदे पानी के निकास हेतु बनाई गई नाली, नालों एवं सीवर के रखरखाव हेतु क्या–क्या योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में जनसंख्या के आधार पर आगामी वर्षों में नाली, नालों और सीवर के सुधार हेतु क्या–क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? उक्त योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245(3) के अन्तर्गत नगर निगम, जयपुर, सतर्कता शाखा दस्ते द्वारा जयपुर शहर की चारदीवारी में सरकारी सड़क/सरकारी फुटपाथ आदि स्थलों से समय-समय पर अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। प्रतिदिन जयपुर शहर एवं चारदीवारी में से

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सतर्कता दस्ते द्वारा सतत रूप से अस्थाई अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

(2) जयपुर शहर में गन्दे पानी की निकासी हेतु बनाई गई नाली, नालों एवं सीवर के रखरखाव का कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से तथा नालों की सफाई का कार्य वर्ष में एक बार मानसून से पहले किया जाता है।

(3) नगर निगम, जयपुर द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नाली, नालों और सीवर लाइन का निर्माण व सुधार कार्य नियमित रूप से किया जाता है। इस हेतु नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष बजट उपलब्ध कराकर नाला/नालियों की सफाई की जाती है।

रेवदर में गैर मुमकिन रास्तों व तरमीम के लम्बित प्रकरण

248. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपखण्ड कार्यालय रेवदर क्षेत्र में गैर मुमकिन रास्तों के अलाटमेंट व तरमीम के प्रकरण लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन रास्तों के प्रकरण कब से व किस स्तर पर लम्बित चल रहे हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गैर मुमकिन रास्तों की पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा रास्तों की तरमीम करने, अलाटमेंट करने, रास्तों को मौके पर चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेवदर में बिलानाम भूमि में रास्ता अलाटमेन्ट के 7 प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत विचाराधीन हैं, जिन्हें निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही निस्तारित (निर्णीत) किया जाना है। इन 7 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। गैर मुमकिन रास्तों के अलाटमेन्ट व तरमीम का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। इन पत्रावलियों को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जान बूझकर नहीं रोका गया है। अत: इनके निस्तारण में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी दोषी नहीं है। पत्रावलियां न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खींवसर में भवन रहित चिकित्सालयों हेतु भूमि का आबंटन

249. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खींवसर के भूमि रहित स्वास्थ्य व चिकित्सा संस्थानों हेतु भूमि आबंटन के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलक्टर नागौर को पूर्व में पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जुलाई, 2019 से जनवरी, 2020 तक जिला कलक्टर नागौर को सांसदों द्वारा ज्ञापित लोक समस्याओं से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर कलक्टर द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, नागौर से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक खींवसर विधान सभा क्षेत्र के भूमि रहित स्वास्थ्य/ चिकित्सा संस्थानों हेतु भूमि आबंटन के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा लिखे गये पत्र जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए।

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के भूमि रहित स्वास्थ्य/चिकित्सा संस्थानों हेतु जमीन आबंटन को लेकर तत्कालीन विधायक महोदय खींवसर श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा दिनांक 03.04.2018 को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त पत्र जिला कार्यालय में प्राप्त होने पर जिला कार्यालय के पत्रांक 2048 दिनांक 05.04.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खींवसर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये जिसकी प्रति माननीय विधायक महोदय को भी प्रेषित की गई थी। संबंधित विभाग द्वारा भूमि आबंटन बाबत विभाग का मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त पत्र के अतिरिक्त अन्य जन प्रतिनिधियों के कोई पत्र जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(राजस्व मंत्री)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर व उपखण्ड अधिकारी, खींवसर को पुन: निर्देश दिये गये हैं कि भूमि रहित स्वास्थ्य/चिकित्सा संस्थानों हेतु मांग पत्र/जमीन आबंटन के प्रस्ताव शीघ्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(2) जुलाई, 2019 से जनवरी, 2020 तक सांसदों द्वारा ज्ञापित लोक समस्याओं से जुड़े 09 विभिन्न प्रकरण जिला कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलशहर नगरपालिका में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

250. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा योजना में माह जनवरी, 2020 तक नगरपालिका सादुलशहर द्वारा कितने पात्र लोगों को जोड़ा गया एवं कितनों के आवेदन निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में नए पात्र आवेदकों को जोड़ा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सादुलशहर द्वारा माह जनवरी 2020 तक 15278 पात्र लोगों को तथा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से 3179 पात्र लोगों सहित कुल 18457 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया। उक्तावधि में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा 79 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है।

(2) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015 में निर्देशित अपीलीय प्रक्रिया द्वारा सतत रूप से पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर में बी.पी.एल. परिवारों को देय सुविधाएं

251. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बीपीएल परिवारों को वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना में वर्तमान में कितने व्यक्ति व परिवार पात्र हैं? उनको क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में खाद्य विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को 5 किग्रा गेहूं प्रति यूनिट 1 रु. प्रति किग्रा की दर से प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 4.97 करोड़ लाभार्थी एवं 1.11 करोड़ परिवार हैं। उक्त परिवारों में से बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रु. किलो गेहूं एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों को 2 रु. प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

बीपीएल परिवारों को गेहूं वितरण में प्राप्त शिकायतें

252. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय किस दिनांक से लागू किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त दिनांक के पश्चात् भी बीपीएल परिवारों से दो रुपये में गेहूं देने की प्रदेश में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च, 2019 से बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रु प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण शुरू किया गया है। उक्त तिथि के बाद बीपीएल परिवारों को 2 रु. प्रति किलो की दर से गेहूं देने की आई शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा में अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के लाभार्थी

253. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्र व छात्राओं को लाभान्वित करने तथा स्वस्थ रहने में सहयोग मिले, इस हेतु अन्नपूर्णा नि:शुल्क दूध योजना प्रारम्भ की गई थी जिससे छात्र व छात्राओं को स्वस्थ रहने में सहयोग मिले? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में चल रहे कितने स्कूलों में कितने-कितने छात्र व छात्राओं को अन्नपूर्णा दूध योजना से लाभान्वित किया जा रहा है? स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम में उक्त क्षेत्र में दूध उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों का विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दूध दिया जा रहा है।

शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित 443 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 32609 छात्र-छात्राएं अन्नपूर्णा नि:शुल्क दूध योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत भीलवाड़ा जिले में निम्नांकित एजेन्सियों द्वारा दूध उपलब्ध कराया जा रहा है:-

1 शहरी क्षेत्र में - भीलवाड़ा सरस डेयरी, भीलवाड़ा

2 ग्रामीण क्षेत्र में–महिला अन्नपूर्णा दुग्ध सहकारी समिति

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर शहर में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश

254. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उदयपुर शहर में सत्र 2013-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

14 से अब तक 25 प्रतिशत कोटे में कितने बालक-बालिकाओं का नामांकन निजी विद्यालयों व सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में किया गया? वर्षवार व विद्यालयवार बच्चों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शिक्षा सत्र 2013-14 से अब तक जिन निजी विद्यालयों व सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों ने अपने विद्यालय में 25 प्रतिशत कोटे में बच्चों को प्रवेशित नहीं किया, उनके विरुद्ध DEO द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उदयपुर शहर में सत्र 2013-14 से अब तक 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों के वर्षवार विद्यालयवार पते सहित विवरण प्रारम्भिक शिक्षा की सूची परिशिष्ट "क" एवं माध्यमिक शिक्षा की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश न देने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मुण्डावर के विद्यालयों में रमसा के तहत कक्षा-कक्षों का निर्माण

255. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रमसा के माध्यम से कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जाता है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में किस–किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी व कहां-कहां कितने कक्षों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2019 तक स्वीकृत कक्षों के निर्माण कार्यों का विवरण एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

खानपुर के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

256. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजकीय महाविद्यालय खानपुर में किस-किस संवर्ग में कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, खानपुर में शैक्षणिक संवर्ग में कुल 10 पद स्वीकृत हैं व 06 पद रिक्त हैं तथा अशैक्षणिक संवर्ग में कुल 11 पद स्वीकृत हैं व 09 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है। उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को राजकीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त राशि

257. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मदवार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त ग्रांट में से किस-किस मद में कितनी राशि का उपयोग किस-किस सक्षम स्वीकृति की अनुपालना में किस निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्रांट राशि के उपभोग का व्यय विवरण सक्षम स्तर तक भेजा जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक भेज दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मदवार प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

1	New Construction	700 Lakhs
2	Renovation	700 Lakhs
3	Equipment	600 Lakhs

(2) इस ग्रान्ट में निम्न मदवार राशि का उपयोग कर लिया है:-

1	New Construction	56782899/-
2	Renovation	38562667/-
3	Equipment	47166690/-

उक्त राशि उपयोग की स्वीकृति कुलपति महोदय की अनुशंषा पर नोडल अधिकारी रूसा द्वारा विश्वविद्यालय के विभागों को जारी की है तथा नियमानुसार निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया।

(3) उक्त व्यय ग्रान्ट राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2019 राशि रु. 14,25,12,256.00 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रूसा, जयपुर को भेजा जा चुका है। शेष राशि के योजना के तहत उपयोग की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है जिस बाबत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बुहाना तहसील में काबिज परिवार की गैर कानूनी बेदखली

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन नियम 295 के तहत ग्राम ढाणा बाग तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं खसरा नं 137 पर बहुत वर्षों से काबिज परिवार को बिना नोटिस दिए दिनांक 11-11-2019 को बेदखल कर दिये जाने के संबंध में वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

दिनांक 11-11-2019 को खसरा नं. 137 ढाणा तहसील बुहाना ने वन विभाग की रक्षित भूमि बताकर काबिज परिवार के पक्की दीवार, लोहे का गेट व निर्मित स्थल को तोड़ दिया गया जबकि खसरा नं. 137 में बने पिन नम्बर 1606/137/1607/137 में प्राइवेट व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। खातेदारी भी जमाबन्दी के आधार पर जिला कलक्टर ने 8-11-2019 को जांच के आदेश दिए थे लेकिन 8 तारीख को कलक्टर ने SDM को रोकने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव के कारण 11-11-2019 को आनन-फानन में अतिक्रमण मानकर धवस्त कर दिया व काबिज परिवार को बेदखल कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा समय पर जमाबन्दी के कागज भी उपलब्ध करा दिये थे लेकिन वन विभाग ने बेदखली की कार्यवाही कर दी। वन विभाग में पुराने खसरा नं. 137 रकबा 05247 है। राजस्व रिकार्ड में पुराना खसरा नं. 137 ग्राम सिंघाना में था जिसके खसरा नं. 589, 590, 600 बने हैं। इसके बाद ग्राम सिंघाना से नया राजस्व ग्राम ढाणा बना जिससे खसरा नं. 600 रकबा 0.50 है, का नया खसरा नं. 436 बना जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सरकारी भूमि सिवाय चक है। वन सीमा लाइन ग्राम ढाणा के खसरा न. 436 बने हैं। वन विभाग का सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण आये दिन वन विभाग अपनी जमीन मानकर नोटिस देता रहता है और ग्रामीणों को वन भूमि पर अतिक्रमण मानकर तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर देता है। इस संबंध में दोषी तहसीलदार व SDM के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

अतः सदन के माध्यम से ऐसे प्रश्नगत विषय की ओर वन मंत्री जी का ध्यान नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित कर रहा हूं।

सधन्यवाद।

सुभाष पूनिया

(सूरजगढ़)

फतहनगर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर कस्बे में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की योजना थी। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर ने 2014 में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर केन्द्र के लिये छह बीघा जमीन आबंटन की आवश्यकता बताई थी जिस पर नगरपालिका ने छह बीघा जमीन नि:शुल्क आबंटन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। भूमि का आबंटन पत्र व पट्टा चिकित्सा विभाग को सौंप दिया गया है। नगरपालिका द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन के बाद कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर सनवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में आपातकालीन एम्बुलेन्स सुविधा 108 का केन्द्र न होने से कॉल करने पर 13 किमी दूर मावली से एम्बुलेंस उपलब्ध होती है, जिससे आपात स्थिति में कई बार रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर सहायता नहीं मिल पाने से उसका प्राणान्त हो जाता है। फतहनगर क्षेत्र का प्रमुख नगरपालिका क्षेत्र है। यहां पर एम्बुलेन्स 108 का केन्द्र होना आवश्यक है। फतहनगर कस्बे में ट्रोमा सेन्टर के अभाव में दुर्घटना व आपातकालीन मामलों में रोगियों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती और वे असमय ही सुविधा के अभाव में काल -कवलित हो जाते हैं। मेरा निवेदन है फतहनगर में ट्रोमा सेन्टर का भवन बन चुका है। इस भवन को बने लगभग 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है लेकिन आज तक ट्रोमा सेन्टर प्रारम्भ नहीं हुआ है। कृपया जन हित व जन स्वास्थ्य के जुड़े इस विषय को प्राथमिकता प्रदान कर जनता को सुविधा उपलब्ध कराएं।

धर्मनारायण जोशी

(मावली)

थानागाजी के महाविद्यालयों में शिक्षकों की अध्यापन के प्रति उदासीनता

महोदय,

मैं, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी व राजगढ़ में

महाविद्यालय अंचल है। वहां पर अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं ग्रामीण अंचल से आते हैं।

महोदय, महाविद्यालय के सहायक आचार्य छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत काल्पनिक हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में दिखा देते हैं परन्तु वास्तव में छात्र-छात्राएं कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते हैं क्योंकि कक्षाओं में पढ़ाने वाले सहायक आचार्य कालांश समय में महाविद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं।

महोदय, महाविद्यालय में शिक्षक उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन लम्बे समय से खराब है। इन महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्रतिदिन जयपुर, अलवर, दिल्ली व दौसा से आवागमन करते हैं तथा महाविद्यालय में देरी से पहुंचते हैं तथा समय से पहले चले जाते हैं जिससे मेरे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को भारी नुकसान हो रहा है।

महोदय, महाविद्यालयों में नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था है परन्तु कोचिंग महज खानापूर्ति व कागजों में ही चलती है व मजबूरन राजगढ़ महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं कालेज समय में शहर में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर मे पढ़ते है व गरीब छात्र-छात्राएं प्रतिमाह दस हजार तक फीस देते हैं।

अत: महोदय से अनुरोध है कि विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन कार्यशैली वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यों की जाँच करवाकर की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करवाने का श्रम करें।

कान्ति प्रसाद

(थानागाजी)

रानीवाड़ा में कृषि कनेक्शनों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

महोदय,

जालौर जिले सहित प्रदेश में अनु. जन जाति (भील आदि) वर्ग निवास करता है, जो कृषि पर ही निर्भर है। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही खराब है। कृषि के लिये भूमि तो है, मगर कृषि कनेक्शन नहीं, जिसका कारण उनको कृषि कनेक्शन में आरक्षित वर्ग में नहीं रखा जाकर सामान्य वर्ग में रखा गया है।

अनु. जन जाति की राजस्थान में 2011 की जनसंख्या 92 लाख 38 हजार 534 है। इसमें जालौर जिला जो कि पिछड़ा जिला है जिसमें अनु. जन जाति की आबादी 1 लाख 78 हजार है। इसमें वर्ष 2001 की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अनु. जन जाति वर्ग को कृषि कनेक्शन की आवश्यकता होने पर उसके आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में जमा किया जाता है और वह अपनी पत्रावली के नम्बर आने का इन्तजार करता है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अनु. जन जाति वर्ग की वर्तमान में करीब 350 से अधिक पत्रावलियां कृषि कनेक्शन के लिए पैण्डिंग पड़ी है। अनु. जन जाति वर्ग के द्वारा प्रतिवर्ष करीब 100 पत्रावली प्रत्येक जिले में कृषि कनेक्शन के लिये जमा होती हैं।

अतः निवेदन है कि जालौर जिले सहित प्रदेश के कृषि कनेक्शन के लिये अनु. जन जाति वर्ग की जमा कृषि कनेक्शन की पत्रावलियों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार मंगवाई जाकर उस अनुसार आरक्षण श्रेणी से कृषि कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता है।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

बालोतरा के राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नाहटा राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बालोतरा आसपास के 4 उप खण्ड के 400 से अधिक गांवों और 70-80 की त्रिज्या के भू-भाग में विभिन्न 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों से आने वाले मरीजों के लिए एक तरह से रेफरल और बड़ा एक मात्र 150 बैड का चिकित्सालय है। इसमें प्राय: 170-180 मरीज भर्ती रहते हैं। यहां रिफाइनरी, वस्त्र कारखाने, नेशनल हाईवे नं. 25,325, मेगा हाईवे, स्टेट हाईवे 28, 28ए 68 हाईवे होने से प्रायः हादसे होते रहते हैं परन्तु संसाधनों एवं सुविधाओं के अभाव में ज्यादातर मरीजों को जोधपुर के लिए रेफर किया जाता है। इससे आमजन को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूरी और समय पर उपचार नहीं मिलने से जान से हाथ धोना पड़ता है।

गरीबों के हितैषी हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्री जी जसोल हादसे पर 24 जून, 2019 को बालोतरा प्रवास पर पधारे, तब स्थिति को देखा है और बालोतरा में 150 से 200 बैड में क्रमोन्नत करने, ट्रोमा सेन्टर, ब्लड बैंक, हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। ट्रोमा सेन्टर, ब्लड बैंक, आईसीयू एवं डायलिसिस और 5 मौहल्ला क्लीनिक की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे जनता को राहत मिलेगी। स्थानीय जनता आपकी आभारी है। धन्यवाद।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से विनम्र आग्रह है कि वर्तमान में नाहटा चिकित्सालय को 200 बैड तक क्रमोन्नत करने, 250 केवी का जनरेटर एवं रूफ टोप सौर ऊर्जा संयंत्र, आईसीयू के 70 लाख की बजट स्वीकृति, सीवरेज के लिए 50 लाख की बजट स्वीकृति जारी करने के साथ ही 10 रेजीडेन्ट चिकित्सकों के साथ ही चिकित्सकों एवं तकनीकी पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने का श्रम कर स्थानीय जनता को राहत प्रदान कर अनुग्रहीत कराएं।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

आहोर में नदी पर पुल का निर्माण

महोदय,

आहोर विधान सभा क्षेत्र के भूती रोडला रोड पर नदी से वर्षा ऋतु के समय हमेशा रास्ता बंद हो जाता है। इससे उस क्षेत्र के करीब भूती, रोडला, कंवला, वलदरा, कवराडा, मुलेवा आदि 9 गांवों का रास्ता बंद हो जाता है। इन गांवों में वैसे भी कोई सुविधा नहीं है। चिकित्सा सुविधा नहीं है। यहां से दूसरे बड़े अस्पताल में जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, प्रसव के समय महिलाओं को सुविधा नहीं मिलने से दम तोड़ना पड़ता है।

एक बार तो एक पुरुष की मृत्यु हो गई, पत्नी पीहर में थी, पत्नी अपने हमसफर के अंतिम संस्कार एवं अंतिम समय में उसके दर्शन भी नहीं कर पाई।

अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान बार-बार आकर्षित भी किया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया करके इस रोड पर पुल बनाकर आम जन को राहत दें जिससे इनको भी लगे कि हम भी आधुनिक भारत में जी रहे हैं। अन्यथा अध्यक्ष महोदय, इन सभी भूती के

आस-पास रहने वाले गांव वालों को हमेशा बिना कारण से जिन्दगी से हाथ धोना पड़ता है। कभी डिलीवरी केस तो कभी दुर्घटना में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि भूती रोडला पुल की घोषणा इस बजट सत्र में करके समस्या से निजात दिलवाने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

छगनसिंह

(आहोर)

आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों के बैकलाग की भर्ती

महोदय,

SC/ST के लोगों को अन्य वर्गों के समान सामाजिक दृष्टि से उन्नयन हेतु संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यह व्यवस्था कि SC/ST के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो अनन्त काल तक यह पद खाली रहते थे तथा तथा समय-समय पर अभियान चलाकर तथा बैकलाग की गणना कर पद भरे जाते थे, परन्तु 17 जनवरी, 2013 को कांग्रेस की सरकार ने आदेश जारी कर SC/ST के अभ्यर्थी ना मिलने पर 3 वर्ष तक की वेकेंसी को सामान्य वर्ग से भरने की बात कही गई। कांग्रेस की सरकार इतने पर ही नहीं रूकी और हाल ही में 23 जनवरी, 2020 को 2 साल तक रिक्त पदों को सामान्य वर्ग से भरने का प्रावधान किया गया है। इससे बैकलाग के पद समाप्त कर दिये जायेंगे तथा भविष्य में SC/ST के बैकलाग के पदों को खतम करने का षड्यंत्र रचकर SC/ST के साथ अन्याय करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। जब-जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने SC/ST के लोगों का शोषण व अन्याय किया है।

प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 11 सितम्बर, 2011 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए SC/ST के आरक्षण को 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। इस आदेश के प्रभाव से कई अधिकारियों को पदावनत किया गया और आज भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहीं नहीं, SC/ST के लोगों से इतनी ईर्ष्या है कि 12 सितम्बर, 2012 को एक आदेश जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर भी SC/ST के अभ्यर्थी द्वारा यदि कोई छूट ली जाती है तो अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अपनी ही श्रेणी में रखा गया जबकि सामान्य में रखा जाना चाहिए था।

इससे पूर्व भी SC/ST से धर्मान्तरित लोगों को भी SC/ST का लाभ देकर SC/ST के आरक्षण को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा गया था।

मदन दिलावर

(रामगंज मण्डी)

डीएमएफटी की नियमित बैठक बुलाया जाना

महोदय,

निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) में अध्यक्ष संबंधित जिला प्रमुखों को नियुक्त कर रखा था। फरवरी, 2019 में जिला प्रमुखों के स्थान पर जिला कलक्टर को डीएमएफटी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगस्त, 2019 में जिले के प्रभारी मंत्री को डीएमएफटी का अध्यक्ष बनाया गया है।

इस प्रकार पृथक्-पृथक् आदेश जारी करने के कारण वर्तमान में एवं विगत वित्तीय वर्ष से प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) के कोष में करोड़ों रुपयों की राशि जमा है। जिला स्तर पर लम्बे समय से इसकी मीटिंग नहीं होने के कारण इस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। विकास कार्यों पर राशि का उपयोग नहीं होने के कारण उसमें लगभग 18 जिले प्रभावित हो रहे हैं। जो कार्य पूर्व में स्वीकृत हो गये, जिनके टेण्डर एवं वर्क आर्डर भी जारी हो गये तथा कार्य भी प्रारम्भ हो गए, उन कार्यों को भी पिछले 13 माह से बिना किसी कारण के अचानक बन्द कर दिया गया है, जिससे जनता परेशान हो रही है।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि जो कार्य प्रारम्भ हो गये थे, जिनको बिना किसी कारण से बन्द कर दिया गया, उन्हें पुनः अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाएं और जिला स्तर पर लम्बे समय से मीटिंग नहीं हो रही है, उससे संबंधित जिला अध्यक्ष को निर्देशित कर मीटिंग अविलम्ब बुलाने के आदेश प्रदान करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

किरण माहेश्वरी

(राजसमंद)

नादड़ी ग्राम पंचायत में सीवरेज लाइन का निर्माण

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत नादड़ी में सीवरेज नहीं होने से वहां का जल स्तर काफी बढ़ गया है और वर्तमान समय में यहां लाखों की संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। यहां के निवासियों को मकान बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत: जन भावनाओं एवं परेशानियों को देखते हुए यहां ग्राम पंचायत नादडी में सीवरेज लाइन डलवायी जाये जिससे लोगों की उपरोक्त समस्या का हल हो सके।

महेन्द्र विश्नोई

(लूणी)

मुण्डावर में सड़कों का निर्माण/मरम्मत

महोदय,

मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत नई सड़कों के निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने के उद्देश्य से निम्न बिन्दुओं की ओर निवेदन करना चाहूंगा:-

(1) वर्ष 2018-19 में तत्कालीन सरकार द्वारा नोन पेचेबल मद में कई सड़कों की स्वीकृतियां जारी की गईं। कार्य अधूरे पड़े हैं।

(2) वर्ष 2017-18 में गौरव पथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किमी. सीसी सड़क बनाने के लिए स्वीकृतियां जारी की गई, लेकिन कार्य अधूरे पड़े हैं एवं कई सड़कों के कार्य चालू करके ठेकेदारों द्वारा बन्द कर दिये गये।

(3) वर्ष 2017-18 में मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृतियां जारी की गईं, लेकिन कार्य अधूरे पड़े हैं।

(4) वर्ष 2018-19 में 15-15 किलोमीटर की न्यू रोड्स के नाम से विधान सभा क्षेत्र में 8 सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। इनका निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया।

इनके अलावा भी कई सड़कों की स्वीकृतियां जारी की गईं। सड़क निर्माण के कार्य प्रारम्भ किए गए। वर्तमान में सड़क निर्माण के कार्य ठेकेदारों ने बन्द कर दिये हैं जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों से मिट्टी उड़ती रहती है। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों के किनारे मिट्टी उड़ने से फसलें और पेड़-पौधे खराब हो रहे हैं। सड़क किनारे रहने वाले लोगों को अस्थमा की बीमारी होने लगी है।

स्वीकृति के पश्चात् भी सड़कों के निर्माण नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

अतः मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त सभी सड़कों को तुरन्त बनवाकर जनता को राहत प्रदान कराएं।

मंजीत धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि तत्कालीन सरकार ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II प्रतियोगिता परीक्षा-2013 का विज्ञापन अगस्त 2013 को जारी किया था। परीक्षा का आयोजन वर्ष 2014 में हुआ था जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने RPSC द्वारा जारी उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर, मूल उत्तरकुंजी से अलग मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय में SB रिट दायर की थी जिसका फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में सितम्बर 2015 को आया था। इसके बावजूद RPSC ने माननीय उच्च न्यायालय में DB रिट दायर कर दी थी जिसका फैसला भी अभ्यर्थियों के पक्ष में अक्टूबर 2016 को आया। फिर RPSC ने माननीय उच्च न्यायालय के डबल बैंच के फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में बेरोजगार अभ्यर्थियों के विरुद्ध SLP दायर कर दी जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए मुरारीलाल शर्मा बनाम RPSC के SB के निर्णय को यथावत रखने का फैसला जुलाई 2018 को सुनाया था।

इस फैसले के बाद RPSC ने नौ माह बाद भर्ती का संशोधित परिणाम मार्च 2019 को जारी करते हुए 583 नवीन अभ्यर्थियों को शामिल कर इनके दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेज दिये। आज तक 11 माह बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नही दी जा रही है, जिससे परेशान बेरोजगार अभ्यर्थी दिसम्बर 2019 से निरन्तर 80 दिनों से बीकानेर निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं।

अत: महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाकर समस्या का निस्तारण कराएं।

सधन्यवाद।

नारायण बेनीवाल

(खींवसर)

थर्मल पावर प्लांट्स में वित्तीय अनियमितता

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लाटों के द्वारा निविदाओं में योजनाबद्ध तरीके से लागत को बढ़ाकर आमजन के धन का न केवल दुरुपयोग किया गया वरन् निविदा की पात्रता शर्तों को एक पार्टी के पक्ष में बनाकर छोटे-छोटे ठेकेदारों को निविदा की पात्रता के अयोग्य बताकर बेरोजगार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में कोल हैण्डलिंग प्लांट के परिचालन का ठेका वर्ष 2019-20 के लिए राशि रुपये 23.00 करोड़ में उसी कम्पनी को दिया गया है, जिसे पिछले दो-तीन वर्षों से दिया जा रहा था, जबकि यही ठेका पहले छोटे-छोटे 40-50 ठेकेदारों को 8.00 से 9.08 करोड़ रुपये में दिया जाता था। वर्ष 2016-17 में 10.10 करोड़ रुपये की राशि रेलवे को डेमरेज के रूप में दी थी, जिसे भी निविदा में शामिल किया गया जिससे वर्ष 2017-18 में यह ठेका राशि 18.24 करोड रुपये की हो गई।

कालीसिंध पावर प्लांट में 2x600 MW के कोल हैण्डलिंग प्लांट का वार्षिक परिचालन का कार्य पूर्व वर्ष में विभिन्न ठेकों के माध्यम से लगभग 6.00 करोड़ रुपये में दिया जाता रहा है। वह अब 8.21 करोड़ रुपये में दिया गया।

इसी प्रकार सूरतगढ़ थर्मल प्लांट के कोल परिचालन के कार्य का वार्षिक ठेके की निविदाओं को तीन बार बदनीयती से विभिन्न बढ़ती हुई दरों पर निकाला गया। निविदा में नई पात्रता शर्तें जोड़ते हुए पूर्व के छोटे ठेकेदारों की पात्रता समाप्त कर व जन हित को ध्यान में न रखकर एक ही कम्पनी को ठेका दिया गया है।

अतः उक्त समस्या के समाधान के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रताप सिंह

(छबड़ा)

बस्सी की सड़कों का नवीनीकरण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्रति पिछली सरकार द्वारा सड़कों के

मामले में बहुत भेदभाव बरता गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण स्टेट हाईवे नं-2 जो कि दौसा से तूंगा होते हुए चाकसू जा रहा है। इसमें गत सरकार ने दौसा और चाकसू क्षेत्र में आने वाली सड़कों का तो नवीनीकरण कर दिया, लेकिन बस्सी क्षेत्र में आने वाला इस सड़क का भाग भटेरी से रूपाहेड़ी वाया तूंगा क्षेत्र को छोड़ दिया गया। क्षेत्र की जनता इस सड़क के छोड़े गये भाग के कारण सात वर्ष से अत्यन्त परेशान हो रही है।

इसी प्रकार 1. भूड़ला पाटन जटवाडा, 2, बांसखोह फाटक-भूडला, 3. बाड़ा पदमपुरा-सांभरिया, 4. मूडली अचलपुरा-कोटखावदा, 5. बस्सी-बापूगांव-देवगांव-काशीपुरा-मुन्दाहेडी, 6. गढ़ की कोठियां-हाथीपुरा-मन्दरपुरा-बावड़ी का वास सड़क भी अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि गत सरकार द्वारा किये गये भेदभावपूर्ण विकास से त्रस्त जनता को राहत दिलाएं और उक्त सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप चौड़ाई एवं नवीनीकरण किया जाये।

कृपया अनुमति प्रदान करें।

लक्ष्मण मीणा

(बस्सी)

चित्तौड़गढ़ जिले में सड़क का पुनर्निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बजट घोषणा 2017-18 में भदेसर चौराहा-कन्नौज-सावा-शंभुपुरा-गिलुण्ड घटियावली से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 को जाने वाले 34.5 किलोमीटर की अति महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी जिसे राज्य सरकार के SM & R मद से बनाया जाना सुनिश्चित किया गया था तथा उक्त सड़क मार्ग का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था। उक्त सड़क मार्ग के निर्माण के निमित्त पूर्व में बनी हुई सड़क को तोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया किन्तु सरकार से बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य को उसी क्षतिग्रस्त अवस्था में रोक दिया गया है जिस कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। आपातकालीन मरीज व गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सा सुविधा के अभाव में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में उक्त सड़क की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है जिससे

आम जन काफी आक्रोशित है। उक्त सड़क मार्ग के कार्य को केवल इस कारण से रोक दिया गया है क्योंकि यह कार्य जनहित को देखते हुए गत भाजपा सरकार में स्वीकृत किया गया था और सत्ता परिवर्तन के बाद उक्त सड़क मार्ग की महत्ता को गौण कर दिया गया लेकिन सरकार के ध्यान में यह बात लाना नितांत आवश्यक है कि उक्त सड़क मार्ग चित्तौड़गढ़ विधान सभा की जीवन रेखा है जो पूरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ को आपस में जोड़कर सुव्यवस्थित करती है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त सड़क मार्ग के रुके हुए भुगतान को जारी कर शीघ्र ही पुनः कार्य प्रारम्भ कर यहां के आम जन को राहत करने का कष्ट करें।

चन्द्रभान सिंह आक्या

(चित्तौड़गढ़)

रूपवास में न्यायिक सेवाओं का विस्तार

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास के रूपवास कस्बे की ओर करना चाहता हूं। रूपवास उपखण्ड मुख्यालय पर विगत कई वर्षो से ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट का संचालन महीने में सिर्फ 6 दिन किया जाता है जिससे यहां के क्षेत्रवासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। नियमित ए.डी.जे. कोर्ट के अभाव में प्रकरणों का निस्तारण करने में बहुत अधिक समय लगता है तथा यहां पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट के अभाव में पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं को भी प्रतिदिन करीब 50 किलोमीटर दूर बयाना जाना पड़ता है जिससे धन एवं समय दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए यहां पर ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट को नियमित करने के साथ ही अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को ए.सी.जे.एम. कोर्ट में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

धन्यवाद

अमर सिंह

(बयाना)